राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 04] पन्द्रहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का चालीसवां दिवस [संख्या: 18

मंगलवार,

03 मार्च 2020

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

स्थगित प्रश्न

(मंगलवार, 18 फरवरी 2020)

कोटा सम्भाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों के स्वीकृत पेंशन प्रकरण

120. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को कितने दिनों में पेंशन स्वीकृत की जाती है?

(2) विगत 5 वर्षों में कोटा संभाग में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के पेंशन स्वीकृत करवाने व पेंशनरों के फिक्सेशन के कितने प्रकरण पेंशन विभाग में आये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की पेंशन कब-कब प्रारम्भ की गई और पेंशनरों के फिक्सेशन कब-कब किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में कई प्रकरणों में पेंशन स्वीकृत करने व फिक्सेशन में विलम्ब हुआ है? यदि हां, तो सरकार दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) विगत 3 वर्षों में सरकार को पेंशन विभाग, कोटा सम्भाग में सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों की कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं?

(श्री संदीप शर्मा)

सरकार द्वारा उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के कार्यालय से सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग में प्राप्त होने पर दस्तावेज पूर्ण होने की स्थिति में एक माह की अवधि में पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी किये जाते हैं। परीक्षण के दौरान दस्तावेज अपूर्ण पाये जाने पर उक्त दस्तावेज पूर्ण करने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी के सम्बन्धित कार्यालय को लौटा दिये जाते हैं।

(2) विगत 5 वर्षों में कोटा संभाग में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की पेंशन के 10464 एवं पेंशनर्स के फिक्सेशन के 31164 प्रकरण प्राप्त हुए। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) वांछित सूचना का वर्षवार संख्या विवरण परिशिष्ट-2 में उल्लेखित है।

(4) जी हां। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 89(3) में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। सेवानिवृत्ति के उपरांत यदि दो माह पश्चात् भी पेंशन स्वीकृत नहीं की जाती है तो विलम्ब की अवधि के लिए 9 प्रतिशत ब्याज की दर से सेवानिवृत्त कर्मचारी को भुगतान किये जाने का प्रावधान है। साथ ही जिस अधिकारी/कर्मचारी का दोष पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही कर वसूली किये जाने का प्रावधान है। उक्त कार्यवाही सेवानिवृत्त कर्मचारी के सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के द्वारा की जाती है।

(5) गत तीन वर्षों में सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि परिशिष्ट-2 में आपने निस्तारित हुए प्रकरणों की जानकारी दी है, लेकिन कितने प्रकरण निश्चित समय सीमा से अधिक समय में निस्तारित हुए? मंत्री जी आंकड़े बताएं। बिन्दु संख्या-4 में

(श्री संदीप शर्मा)
आपने स्वीकार किया है कि कोटा में विलम्ब हुआ है। यदि विलम्ब हुआ है तो आपने कोटा में किसी अधिकारी या कर्मचारी पर कोई कार्यवाही की है तथा किसी प्रकार की कोई वसूली की है जैसा कि नियम में है? कृपया मंत्री जी अवगत कराएं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 31.12.2019 को 408 पेंशन प्रकरण बकाया थे। 01.03 की स्थिति के अनुसार इसमें 303 प्रकरणों के पेंशन आदेश जारी किए जा चुके हैं और 105 प्रकरण शेष रहे। इन शेष 105 प्रकरणों में 39 प्रकरण माह फरवरी, 2020 में आक्षेप पूर्ति उपरांत प्राप्त हुए हैं, जो प्रक्रियाधीन हैं और 66 प्रकरण विभागों को दे दिये गये हैं और उनसे आना वापस शेष है। जहां तक सवाल इस बात का है, आपने कहा कि किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की गई तो 4 शिकायतें मिली थीं, जिनका निस्तारण कर दिया गया। एक अधिकारी के खिलाफ शिकायत, जो कोटा संभाग में तीन वर्षों से कोषालय, कोटा के कनिष्ठ लेखाकार के विरुद्ध पेंशन समाज, शाखा चेचट से प्राप्त हुई थी कि कार्मिक का व्यवहार असंतोषप्रद था। सम्बन्धित कार्मिक को नोटिस दिया जाकर भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने की हिदायत दी गई। कार्मिक का नाम था श्याम माहेश्वरी, कनिष्ठ लेखाकार।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पेंशन स्वीकृत करने में आपने एक माह का नियम बना रखा है, लेकिन 80 साल की उम्र में पेंशनर को अतिरिक्त पेंशन वृद्धि के लिए आवेदन करना पड़ता है और 80 साल की उम्र में पेंशनर परेशान होता है, धक्के खाता है। क्या सरकार ऐसे बुजुर्गों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए उनको स्वत: ही पेंशन वृद्धि का लाभ मिल जाए, इसके लिए कोई नियम बनाने का विचार रखती है? जो पेंशनर हैं उनकी मेडिकल डायरी की लिमिट है, वह भी 25 हजार है और गम्भीर बीमारी की स्थिति में उनका काफी पैसा खर्च हो जाता है। क्या सरकार पेंशनरों की मेडिकल डायरी की लिमिट बढ़ाने का विचार रखती है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बढ़ा दी न। सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पहले सेवानिवृत्ति प्राधिकारी के द्वारा आदेश जारी किये जाते हैं और कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा एनओसीज जारी की जाती हैं कि कोई जांच तो

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

उसके खिलाफ नहीं है। इसके साथ-साथ जो उसने प्रमाण पत्र भरे हुए हैं वे सही भरे हुए हैं या नहीं है, पेंशन कर्मचारी के खिलाफ सेवा पुस्तिका में सेवानिवृत्ति की तारीख में कोई आक्षेप तो नहीं हैं, ये सब कुछ किये जाते हैं और 6 माह के पूर्व पेंशन विभाग को भेजने का प्रावधान है। पेंशन विभाग कर्मचारी के विभाग से पेंशन प्रकरण प्राप्त होने पर पूर्ण सही होने की स्थिति में एक माह की अवधि में पेंशन आदेश, पीपीओ, जीपीओ और सीपीओ को जारी करेगा। यदि कोई आक्षेप है तो एक माह की अवधि में उसको सम्बन्धित विभाग के द्वारा लौटा दिया जाएगा। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक सवाल इस बात का है कि देर से दिये जाते हैं तो अगर छह महीने के पश्चात् पीपीओ जारी होता है और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की तरफ अगर मान लीजिये कोई कमी नहीं रही तो उसको 9 प्रतिशत का ब्याज दिया जाता है। आपने पूछा है कि कोटा संभाग में 9 प्रतिशत का ब्याज कितना दिया गया तो 14 विभागों के 24 अधिकारियों और कर्मचारियों को विलम्ब के लिए ब्याज के रूप में 50 लाख 27 हजार 335 रुपये का भुगतान किया गया है।

जहां तक आपने बताया कि मेडिकल डायरी का बढ़ाया जाए तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, सरकार का पेंशनर को सेम-डे, जिस दिन वह रिटायर होता है, उसी दिन पेंशन देने का निर्णय है। आपके इस पेंशन में कुछ डिले है जो आपने बताया है और अभी आपने कहा कि हमें 50 लाख रुपया ब्याज देना पड़ा तो इसका मतलब कहीं न कहीं यह 50 लाख सरकार को अनायास लगा तो इसके लिए कोई न कोई उत्तरदायी तो होना ही चाहिए जिसके कारण से सरकार को 50 लाख रुपया एक्स्ट्रा ब्याज का देना पड़ा।

दूसरा, यह जो आप बता रहे हैं कि जिनका फिक्सेशन होना है वो 31164 हैं और आज की तारीख तक भी जो पैण्डिंग हैं वो 11865 हैं, 2015 से लेकर अब तक, तो इसके लिए भी कोई दोषी है या नहीं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जहां तक आपने फिक्सेशन की बात कही है तो 1865 प्रकरण

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

बकाया थे 31.12.2019 तक। उसमें फिर जनवरी और फरवरी, 2020 में 852 और नवीन प्रकरण प्राप्त हो गये तो कुल मिलाकर ये 2717 हो गये। इन 2717 में से 745 का निस्तारण हो चुका है। अब सवाल यह रहता है कि फिक्सेशन देर से हुआ, उसके कारण क्या हैं? मोटे तौर पर जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे वे नगरपालिका के हों, चाहे पंचायती राज के हों, चाहे आपके विधान सभा के हों, चाहे लोक सभा के हों, ज्यादातर ड्यूटी कनिष्ठ लेखाकारों की लगाई जाती है और यह काम उन्हीं का होता है, इसलिए उस वजह से होता है और कुछ पद भी रिक्त होने की वजह से इस काम में डिले होता है और इसमें कोई दोराय नहीं कि डिले नहीं होता है, होता है। लेकिन जो फिगर मैंने दिये थे वे 1972 ही अब तक फिक्सेशन के बकाया हैं।

फिक्सेशन के मामले में राज्य सरकार के ज्ञापन 6.6.2018 के अनुसार पेंशनर जिस पे-स्केल में सेवानिवृत्त हुआ है उसको सातवें वेतन आयोग के अनुसार फिक्स करने के लिए 31.12.1990 तक के प्रकरण पेंशन विभाग के सम्भागीय कार्यालयों के द्वारा और 1.1.1991 के पश्चात् सेवानिवृत्त पेंशनर के पेंशन फिक्सेशन सम्बन्धित कोषाधिकारियों के द्वारा किये जाते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह 50 लाख रुपये का आपको जो ब्याज चुकाना पड़ा, इसका कारण यह है कि कहीं तो चूक हुई है इसलिए चुकाना पड़ा तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है जो सरकार को बिना बात के 50 लाख रुपये का घाटा भरना पड़ा?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यदि यह सिद्ध हो जाता है कि विलम्ब के लिए कोई अधिकारी या कर्मचारी उत्तरदायी है तो उसके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। माननीय मंत्री जी, ये पूछ रहे हैं कि 50 लाख रुपये की आपने पैनल्टी दी, इसके लिए कोई अधिकारी जिम्मेदार है क्या?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जी, साहब।

श्री अध्यक्ष: आपने अपने उत्तर में बताया कि 50 लाख रुपये की पैनल्टी आपके विभाग ने इसलिए दी कि डिले पेमेंट हुआ। इसके लिए कोई जिम्मेदार है क्या? यह पूछ रहे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपको यही तो जवाब दे रहा हूं, विलम्ब के लिए यदि यह सिद्ध हो जाता है...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, 50 लाख रुपये आपने पेमेन्ट किया है, किसलिए पेमेंट किया है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पेमेंट इसलिए किया कि उसको 9 परसेंट का ब्याज देना पड़ रहा था।

श्री अध्यक्ष: तो, क्यों देना पड़ा, माननीय मंत्री जी। प्लीज, एक मिनट आप सुनें, आप बैठें। सरकार ने नियम बनाया है कि जिस दिन रिटायर होगा, उस दिन उसको पैसा दे देंगे। पैसा नहीं देने के कारण...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): एक महीने बाद।

श्री अध्यक्ष: एक महीने बाद। नहीं देने के कारण सरकार को 50 लाख रुपये पेमेंट करने पड़े, तो यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए थी। उसके लिए कोई न कोई बाबू, क्लर्क कोई जिम्मेदार होगा। यही तो पूछ रहे हैं कि कितनों के खिलाफ कार्यवाही की?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं भी वही निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: संख्या बताएं, मान्यवर। आप रूल बता रहे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह सिद्ध हो जाता है कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी दोषी है तो उसके विरुद्ध सिविल सेवा (सीसीए) नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, यह प्रश्न नहीं है। 50 लाख रुपये दिये, यह तो फैक्ट है। राजकीय कोष से 50 लाख रुपये गये हैं। यदि समय पर वह काम करता तो 50 लाख नहीं जाते। तो, ऐसे कौन से आदमी थे, जिनकी लापरवाही के कारण 50 लाख देना पड़ा?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेरे पास है नहीं सूचना उन अधिकारियों की, क्योंकि यह तो सवाल था भी नहीं।

श्री अध्यक्ष: वही तो पूछ रहे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सवाल था भी नहीं। जहां तक सवाल इस बात का है कि अधिकारियों के नाम बताएं तो मैं लिस्ट भेज दूंगा आपके पास।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। कटारिया जी, आप सीनियर हैं, प्रश्न की लिमिट है। प्रश्न की लिमिट है, आप समझते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपने बहुत मदद की। एक सैकण्ड, मेरा तो यही है कि 50 लाख रुपये जो राज्य के खजाने से किसी अधिकारी की गलती के कारण से गया। क्या सरकार उनको आईडेंटिफाई करके, सूची सदन पटल पर रखेगी?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): भिजवा दूंगा।

प्रश्न संख्या 277

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। लक्ष्मण मीणा।

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें)

उन्होंने इशारा कर दिया है, बोला नहीं है, कार्यवाही करेंगे। अगला प्रश्न। अशोक लाहोटी।

एडोप्ट हैरिटेज योजनान्तर्गत किलों को गोद लेने की योजना

278. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में एडॉप्ट हैरिटेज योजना लागू है? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत कौन-कौनसे हैरिटेज भवन व किलों को कब-कब कम्पनी व संस्था के एनजीओ द्वारा गोद लिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने उक्त संस्थाओं से MOU किया है? यदि हां, तो MOU की प्रति सदन की मेज पर रखें।

कला, साहित्य, संस्कति एवं पुरातत्व मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जी हां। एडॉप्ट 'ए' हैरिटेज योजना भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है। भारत सरकार से प्राप्त सूचना अनुसार राज्य में किसी भी हैरिटेज भवन व किले को किसी भी कम्पनी/संस्था द्वारा गोद नहीं लिया गया है।

(2) जी नहीं।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो इन्होंने बताया कि योजनाओं के द्वारा कोई गोद नहीं लिया गया लेकिन, मैं पूछना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि जब यह योजना प्रदेश में लागू है, योजना केन्द्र की हो या राजस्थान की, आपने पिछले वर्ष घोषणा की थी कि राज्य में पर्यटन नीति लागू की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें। भारत सरकार का मामला है, प्रश्न बनता ही नहीं है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): नहीं ये लागू है प्रदेश में, साहब।

श्री अध्यक्ष: मना कर चुके हैं मंत्री जी। उत्तर पढ़ें न आप।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या राज्य सरकार ने राजस्थान की जो पर्यटन नीति बनाई है, उसमें इस चीज को शामिल किया गया है? क्या राजस्थान की पर्यटन नीति में और उसके अंतर्गत भी इस योजना को रखा गया है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): भारत सरकार द्वारा वक्त-वक्त पर इससे संबंधित जो मीटिंग बुलाई, उसमें हमारे अधिकारी गये। अध्यक्ष महोदय, हमारे पास कोई प्रस्ताव आएगा, तभी तो उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव आया नहीं, लेकिन भारत सरकार ने जरूर पर्यटक स्थल के लिए बहुभाषी हिन्दी, अंग्रेजी, कोरियन, जापानी एवं चीनी आडियो गाइड विकास के लिए आमेर किला से संबंधित एजेंसी को रेस्बर्ड टैक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड 24 दिसम्बर, 2018 को पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार एवं इस रेस्बर्ड टैक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के बीच में एक एमओयू हुआ है, लेकिन अभी तक वह क्रियान्वित नहीं हुआ है। यहां पर उसकी कोई गतिविधि नहीं चल रही है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री राजकुमार।

नवलगढ़ में ए.डी.जे. कोर्ट की स्थापना

279. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में दिनांक 01 जनवरी, 2018 के पश्चात् कहां-कहां पर किस-किस प्रकार के नये न्यायालय सृजित किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(डा. राजकुमार शर्मा)

(2) क्या यह सही है कि नवलगढ़ शहर में काफी मुकदमे लंबित हैं जिसके कारण आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? क्या सरकार उक्त शहर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय सृजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) प्रदेश में दिनांक 01 जनवरी, 2018 से दिनांक 12.02.2020 तक सृजित न्यायालयों की सूची प्रदर्श-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि नवलगढ़ शहर में काफी संख्या में मुकदमे लंबित हैं।

किसी स्थान पर नवीन अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायालय (ए.डी.जे. न्यायालय) की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त होने पर, निर्धारित मानदण्ड के अनुसार उस क्षेत्र के 1000-1200 प्रकरण लम्बित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही की जा सकती है।

वर्तमान में नवलगढ़ क्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायालय स्तर के सुनवाई योग्य लंबित प्रकरणों की संख्या मात्र 272 है जो कि निर्धारित मानदण्ड 1000-1200 से काफी कम हैं।

पूर्व में नवलगढ़ में अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायालय सृजन का प्रकरण तत्समय नवलगढ़ क्षेत्र के लंबित प्रकरणों की संख्या 439 को देखते हुए नवलगढ में ए.डी.जे. न्यायालय सृजन का प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय की कमेटी द्वारा खारिज कर दिया गया था।

भविष्य में अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय (ए.डी.जे. न्यायालय) की स्थापना हेतु माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त होने पर, निर्धारित मानदण्ड के अनुसार 1000-1200 प्रकरण लम्बित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही नवलगढ़ में ए.डी.जे. न्यायालय की स्थापना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने खण्ड-1 में जवाब दिया है कि सूची संलग्न की है। इतने-इतने कोर्ट हमने खोले हैं तो वे किन मापदंडों के आधार पर खोले हैं? जो बता रहे हैं मंत्री

(डा. राजकुमार शर्मा)

जी, वे आधार उस पर फिट नहीं बैठते, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिनको भी मिला है, अच्छी बात है। हमारे नवलगढ़ में जो 262 लंबित प्रकरणों की सूची भेजी अधिकारियों ने, बिलकुल भी सहमत नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, माननीय सदस्य।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): यही कह रहा हूं। इन्होंने +++ भेजा है।

श्री अध्यक्ष: यहां पर उसके लिए अलग तरीका है। यहां पर प्रश्न पूछें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): 650 से अधिक मामले लंबित हैं, आपने पहले भेजा था, सरकार ने 2011 में। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं आपके माध्यम से, एक बार पुन: माननीय उच्च न्यायालय को सरकार की तरफ से प्रस्ताव भिजवा दें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं, किसी भी स्थान पर नवीन न्यायालय की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श, प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंड के अनुसार प्रकरण लंबित होने पर ही तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही की जा सकती है। जहां तक सवाल इस बात का है, आप कहते हैं कि साहब, वहां पर इतना केस वर्क है।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि डीजे, एडीजे, न्यायालयों के मापदण्ड बना रखे हैं। वे मापदण्ड इस प्रकार से हैं कि डीजे/एडीजे न्यायालयों की स्थापना कब होगी, जब 1000 से लेकर 1200 तक केसेज हों। सीजेएम और एसीजेएम न्यायालयों की स्थापना के लिए 1200 से 1500 केसेज होने चाहिए और सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों की स्थापना के लिए 1700 से लेकर 2000 तक की होनी चाहिए।

नवलगढ़ में, जो कि जिला झुंझुनूं क्षेत्र के एडीजे न्यायालय स्तर पर 88 फौजदारी प्रकरण और 184 दीवानी प्रकरण, कुल 272 प्रकरण लंबित हैं। आज की तारीख में उसका ब्रेक-अप भी, मैं देना चाहता हूं जिला और सैशन न्यायालय झुंझुनूं में 47 फौजदारी केसेज हैं, 94 दीवानी केसेज हैं, कुल मिलाकर 141 केसेज तो वहां पर हैं। अपर जिला एवं सैशन न्यायालय, झुंझुनूं में 32 फौजदारी हैं, 36 दीवानी हैं और कुल मिलाकर 68 केसेज हैं। तीसरा अपर जिला एवं सैशन न्यायालय झुंझुनूं में 9 तो फौजदारी केसेज हैं, दीवानी

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

केसेज 54 हैं, कुल मिलाकर 63 हैं। इस प्रकार से 272 हैं। जहां तक सवाल इस बात का है आपने कहा कि 2011 नहीं, 2015 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था। अब विधायक महोदय यह चाहते हैं कि साहब एक बार और प्रस्ताव भेज दो, तो भेज देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री रामलाल शर्मा।

जीरो बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना

280. श्री रामलाल शर्मा (चौमू): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीरो बजट प्राकृतिक खेती की योजना बनाई गई है? यदि हां, तो उक्त योजना के लिए वर्ष 2019-20 में कितनी राशि व्यय की गई तथा उक्त योजना प्रदेश के किस-किस जिले में प्रारम्भ की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत किसानों को जागरूक करने, प्राकृतिक खाद तैयार करने व प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? यदि हां, तो किस-किस जिले में? उक्त कार्यक्रमों पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीरो बजट प्राकृतिक खेती की योजना बनाई गई है। वर्ष 2019-20 के लिए राशि रुपये 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके विरूद्ध अब तक रुपये 28 लाख 12 हजार का व्यय किया गया है। यह योजना टोंक, सिरोही व बांसवाड़ा जिले में प्रारम्भ की गई है।

(2) जी हां। इस योजना के अंतर्गत किसानों को जागरूक करने, प्राकृतिक खाद तैयार करने व प्रशिक्षण देने के लिए टोंक, सिरोही व बांसवाड़ा जिलों के कार्मिकों की तीन आमुखीकरण कार्यशाला, इन जिलों के 100-100 कृषकों को ओर्गेनिक महोत्सव, उदयपुर में कृषक भ्रमण तथा एक रिसोर्स परसन कार्यशाला आयोजित की जाकर प्राकृतिक खेती के लिए प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक जानकारी दी गई है। साथ ही 20 हजार कृषकों को ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण के लिए 400 ग्राम पंचायत स्तरीय (दो दिवसीय) कृषक

(कृषि मंत्री)

प्रशिक्षणों का आयोजन करने की कार्य योजना के अंतर्गत अब तक 141 ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षणों का आयोजन कर सात हजार पचास कृषकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। शेष ग्राम पंचायत पर प्रशिक्षण प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार आयोजित गतिविधियों पर अब तक राशि रुपये 28 लाख 12 हजार का व्यय किया जा चुका है। योजना अनुसार पांच दिवसीय एक्सपोजर भ्रमण, कृषकों को प्राकृतिक खेती को अपनाने हेतु बीज, पौधे, आदान उत्पादन इकाई, मल्च सामग्री इत्यादि पर अनुदान सहायता उपलब्ध करवाये जाने की कार्यवाही जारी है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने बजट में प्रावधान 2 करोड़ रुपये का रखा, उसमें से 28 लाख रुपये खर्च किए हैं तो एक तो यह कि 28 लाख रुपये जो आपने खर्च किए, यह सिर्फ महोत्सव, कृषक भ्रमण और कार्यशाला आयोजन करने में ही किए या इसके अंदर आपने प्रावधान भी रखा था कि हम प्राकृतिक खाद तैयार करके किसानों को किट वितरण करने का काम भी करेंगे? क्या 28 लाख रुपये सिर्फ भ्रमण, महोत्सव और कार्यशाला पर खर्च किए या प्राकृतिक खाद तैयार करके उनके किट वितरण करने का काम भी किया?

दूसरा, मेरा इसी के साथ यह है कि आपने यह प्रावधान सिर्फ 3 जिलों तक सीमित रखा था। क्या अब आने वाले वर्षों के अंदर तीन जिलों को बढ़ाकर सम्पूर्ण राजस्थान में करना चाहते हैं और क्या आप दो करोड़ के प्रावधान को भी बढ़ाकर इसका बजट अतिरिक्त और एडिशन करना चाहते हैं?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जितना बजट हमने रखा था, उसको हम खर्च नहीं कर पाए, पर मैं सदन को यह बताऊंगा कि जो कार्य योजना बनी उसमें हमारे अधिकारियों द्वारा उन 2-3 स्टेट्स का दौरा किया गया जहां यह परंपरागत खेती चल रही है, जिसको जीरो बजट कहते हैं। अध्ययन करने के बाद में कार्य योजना बनी। उस कार्य योजना के बाद में अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया और उसके बाद में फिर ग्रामीण स्तर पर इसको आगे बढ़ाया गया। यह बात भी सही है कि इसमें जैविक खाद या जैविक रसायन तैयार करना था, उसका किसानों को थोड़ा लेट प्रशिक्षण दिया गया। उसकी कार्यवाही चालू है। कल मैंने अधिकारियों से पूछा

(श्री लालचन्द कटारिया)

कि इसकी प्रगति रिपोर्ट क्या है तो उन्होंने कहा कि 28 लाख का जो इसमें आंकड़ा दिया है, उसके बाद में यह लगभग करीबन पचास लाख के आसपास इसका खर्चा हुआ है अभी तक। मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि वर्ष 2020-21 में हमने इसका 5 करोड़ का प्रावधान रखा है और उसमें जो भी माननीय सदस्य चाहें, हम तो चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जिले जोड़ें और बाकी जो यह शिथिलता रही है उसके लिए मैंने अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। आने वाले वर्ष में इसमें और जिलों को शामिल करते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री लाखन सिंह।

करौली में डी एम एफ टी के अंतर्गत स्वीकृत कार्य

281. श्री लाखन सिंह (करौली): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला करौली में डीएमएफटी के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 व वर्ष 2019-20 में कितनी-कितनी राशि जमा हुई एवं उक्त वर्षों में किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि, किस-किस विधान सभा क्षेत्र में व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त जिले में डीएमएफटी के अन्तर्गत कितनी राशि जमा है? क्या जमा राशि का प्रतिवर्ष विकास कार्यों हेतु व्यय किये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो जनवरी, 2019 के बाद जिले में किस-किस विधान सभा क्षेत्र में किस-किस मद में, किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि की स्वीकृतियां जारी की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री) (खान मंत्री के स्थान पर): (1) करौली जिले में डीएमएफटी के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में राशि रुपया 194.82 लाख एवं वर्ष 2019-20 (दिनांक 31.01.2020 तक) में 239.42 लाख रुपये जमा हुए हैं। दिनांक 31.01.2020 तक उक्त फण्ड में से सिलिकोसिस बीमारी से 239 पीड़ित श्रमिकों/मृतक श्रमिक आश्रितों को राशि रुपये 411 लाख का भुगतान किया गया है। विधान सभावार विवरण निम्नानुसार है:-

(श्री परसादी लाल)

क्र.सं.	**विधान सभा क्षेत्र**	**श्रमिकों की संख्या**	**व्यय की गई राशि (लाखों में)**
1	हिण्डौन	45	93
2	करौली	137	237
3	सपोटरा	56	80
4	टोडाभीम	1	1
	कुल	239	411

(2) करौली जिले में डीएमएफटी फण्ड में दिनांक 31.01.2020 तक राशि रुपये 122.44 लाख शेष हैं। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के नियम 15 में ट्रस्ट फण्ड में जमा राशि के व्यय किये जाने के प्रावधान निहित हैं। माह जनवरी, 2019 के बाद ट्रस्ट फण्ड से सिलिकोसिस बीमारी से 88 पीड़ित श्रमिकों/मृतक श्रमिक आश्रितों को कुल राशि रुपये 186 लाख का भुगतान किया गया। विधान सभावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**विधान सभा क्षेत्र**	**श्रमिकों की संख्या**	**व्यय की गई राशि (लाखों में)**
1	हिण्डौन	20	49
2	करौली	48	99
3	सपोटरा	20	38
4	टोडाभीम	0	0
	कुल	88	186

श्री लाखन सिंह (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो डीएमएफटी की राशि है वह सारी राशि सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए खर्च की गई है, बाकी इसका अलग से भी फंड है। यह राशि और किस-किस मद में खर्च करने का प्रावधान है?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 2016 में जो डीएमएफटी फंड के नियम बनाए उसमें यह राशि विभिन्न सामाजिक कार्यों में खर्च की जाती है, विशेषकर अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने सिलिकोसिस फंड के लिए स्पेशल जो नीति बनाई है उसमें सबसे टाप प्रायोरिटी सिलिकोसिस

(श्री परसादी लाल)

पीड़ित परिवारों को, श्रमिकों को दी गई है। उनको, बीमार श्रमिक को 3 लाख रुपये और डैथ हो जाने के बाद उसको 2 लाख रुपये और दिए। बाकी जो इसमें कार्य कराए गए हैं, सड़कें हैं, पेयजल के हैं, दूसरे जो काम हैं वह इस तरह के काम हैं, कोई भी सड़क है, कहीं भी सामाजिक काम उस क्षेत्र में जहां पर डीएमएफटी फंड कलेक्शन होता है, वहां पर यह काम कराए जाते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय, यह जो आपका डीएमएफटी फंड है यह आपने सिलिकोसिस में इसमें केवल और केवल जो अपना फंड है डीएमएफटी का इसी में से खर्च करना है सिलिकोसिस पर या जो इसको अपने यहां नौकर रखता है काम के लिए रखता है, उस मालिक की भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? या सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही है सिलिकोसिस के बारे में या उस मालिक की भी कोई जिम्मेदारी है जिसके यहां वह काम कर रहा है?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता, प्रतिपक्ष पूछ रहे हैं श्रमिकों के लिए मालिकों की भी कोई जिम्मेदारी है, मालिक जिम्मेदारी ले या नहीं ले पर सरकार की जिम्मेदारी निश्चित रूप से बनती है इसीलिए यह सिलिकोसिस पालिसी नयी बनाई गई है माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश के बाद और इसमें हम उसको नियमानुसार जितनी सहायता है उतनी सहायता दे रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह बहुत बड़प्पन है आपका कि वह कुछ नहीं करेगा तो हमको तो करना ही है, यह तो समझ में आता है, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि जो यह काम करता है और जहां इस प्रकार की बीमारी होने की सौ परसेंट गारंटी है वहां उस मालिक को भी क्या सरकार पाबंद करेगी या उसके ऊपर भी इसका कुछ भार डालेगी? ऐसा करेगी तब जाकर के इन लोगों की जिंदगी बचेगी, बाकी तो आप पेमेंट करते जाओ और वह बीमार करता जाए, तो हल क्या निकलेगा।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता, प्रतिपक्ष का सवाल बहुत सटीक है। यह लापरवाही होती है खान मालिकों के द्वारा। उनकी लापरवाही से वह ध्यान नहीं देते हैं न इस तरह के इंतजामात करते हैं। अगर इस तरह की जो लापरवाही मिली है, यह उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, हम चाहेंगे कि उनको भी इस तरह के निर्देश देंगे, श्रमिकों के लिए

(श्री परसादी लाल)

इलाज की समुचित व्यवस्था करें, पूरी उनकी सुरक्षा करें, इस तरह के विभाग को निर्देश जारी करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री चंद्रभान सिंह आक्या।

सिनेमाघरों में खाद्य पदार्थों की विक्रय दरों पर नियंत्रण

282. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में संचालित विभिन्न मल्टीप्लेक्स एवं सिनेमाघरों में संचालित कैंटीनों (जलपान गृह) में बेचे जाने वाले खाद्य उत्पादों के मूल्य अथवा दरों पर सरकार का नियंत्रण रहता है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में कई सिनेमाघरों एवं उनमें संचालित कैंटीनों (जलपान गृह) में उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले पेय पदार्थ एवं खाद्य पदार्थों को बाजार मूल्य अथवा उन पर मुद्रित दर से कई गुणा अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या एवं कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त में नियम विरुद्ध बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे उक्त खाद्य पदार्थों की दरों पर नियंत्रण रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) जी नहीं। विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (केन्द्रीय अधिनियम) के अन्तर्गत जारी विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बन्द वस्तुएं) नियम, 2011 के तहत डिब्बा बन्द वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दर पर विक्रय करने संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(2) राज्य के सिनेमाघरों एवं उनमें संचालित कैन्टीन में डिब्बा बन्द वस्तुओं को अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक पर विक्रय करने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी हां। प्राप्त डिब्बा बन्द वस्तुओं को अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक पर विक्रय करने संबंधी प्राप्त शिकायत पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, भले ही पर्यटक स्थल हो, रोडवेज बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो या टाकीज हो, जहां-जहां भी यह पेय पदार्थ या खाद्य सामग्री बिकती है, वास्तव में वहां बहुत ज्यादा ओवर रेट, ज्यादा पैसा लेकर वह बेचते हैं, तो सरकार कहती है कि ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली, कोई आदमी पानी की बोतल खरीदेगा तो वह शिकायत नहीं करेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): सरकार अपने लेवल पर कोई कार्यवाही इन पर करवाकर इनको पाबंद करेगी या नहीं करेगी?

श्री अध्यक्ष: शिकायत नहीं तो कार्यवाही क्या करें?

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): सार्वजनिक लेते हैं, वह ओपनली लेते हैं, तो एक बार मंत्री महोदय, सरकार अपने लेवल पर करवाकर पाबंद करे कि यह ज्यादा रेट नहीं लें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें आप। अगला प्रश्न, श्री गणेश घोघरा।

डूंगरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में रोडवेज बसों का पुनः संचालन

283. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार जिला डूंगरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में पथ परिवहन निगम की पूर्व में संचालित बसों का पुन: संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

परिवहन मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): जी हां। सरकार की घोषणा "ग्रामीण परिवहन बस सेवा का विस्तार करते हुए दूर-दराज के गांवों/ढाणियों को बस सेवा से जोड़ना" के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण मार्गों का सर्वे कर संचालन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, टीएसपी क्षेत्र जनजाति बहुल क्षेत्र है वहां आवागमन की काफी समस्या आती है। बच्चों को स्कूल व कालेज जाने में काफी दिक्कत आ रही है, इसलिए यह बसें कब तक चालू हो जाएंगी?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) बिलकुल ठीक कह रहे हैं, खटारा एक दिन में नहीं हुई हैं, पांच साल में हुई हैं। ग्रामीण परिवहन सेवा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, प्लीज आप चेयर को देखकर एड्रेस करें।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष जी, वह पीछे से बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह तरीका नहीं है। आप अपना एड्रेस करें, उनका काम वह करेंगे।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नाराज नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब मैं अगला प्रश्न पुकार लूंगा।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण परिवहन सेवा को लेकर सरकार बहुत चिंतित है। ग्रामीण परिवहन सेवा पिछली सरकार के समय बंद कर दी गई। उसके बाद से लगातार ग्रामीण परिवहन सेवा को लेकर ...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, स्पेसिफिक प्रश्न है, डूंगरपुर में चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, सीधा प्रश्न है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): ग्रामीण परिवहन सेवा पूरे राजस्थान में चलाएंगे और डूंगरपुर में भी चलाएंगे।

श्री अध्यक्ष: थैंक यू, अगला प्रश्न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर नहीं आया। प्रश्न यह था क्या सरकार जिला डूंगरपुर में ग्रामीण क्षेत्रों में पथ परिवहन निगम की पूर्व में संचालित बसों का, पूर्व में कितनी चल रही थीं और आज कितनी चल रही हैं, यह बताओगे तो प्रश्न का उत्तर हुआ। पहले कितनी चल रही थीं और आज कितनी चल रही हैं, यह बताओगे तो समझ में आएगा कि कितनी बंद हो गईं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने बहुत अच्छा सवाल किया है। जो पथ परिवहन सेवा की बसें डूंगरपुर में पहले चल रही थीं, बाद में बंद कर दी गईं,

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

अब नई बसें हमने खरीद ली हैं और जल्दी ही यह जो पथ परिवहन निगम की बसें बंद हुई हैं वह चालू कर दी जाएंगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं विनम्र भाव से पूछ रहा हूं पहले कितनी चल रही थीं और आज कितनी चल रही हैं तब हम समझ पाएंगे कि इतनी बंद हुईं और वह वापस चलेंगी।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): मैं विपक्ष के नेता महोदय कटारिया साहब की बात से सहमत हूं। जो आप पूछ रहे हैं वह मैं पूरा समझ रहा हूं और वही जवाब मैंने परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न करके दिया है कि कितनी चल रही थीं, कितनी बंद हो गईं। आपके पास नहीं है, माननीय सदस्य के पास जवाब है और वह जवाब मैंने उनको दिया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जवाब हमारे पास भी आता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, माननीय मंत्री जी, आप बैठें। इसमें कोई परिशिष्ट नहीं है, आपने जो जवाब दिया है उसमें परिशिष्ट नहीं है। प्रतिपक्ष के नेता महोदय यह पूछ रहे हैं कि आपके पास जानकारी हो कि डूंगरपुर में पहले कितनी बसें चलती थीं और कितनी नहीं चल रहीं, इसका सिम्पल सा जवाब है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): मेरे पास जानकारी है, आपकी आज्ञा हो तो....

श्री अध्यक्ष: संख्या बोलो न आप।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): मैं पढ़कर बता दूं।

श्री अध्यक्ष: बोलो न आप।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): डूंगरपुर से सागवाड़ा चलने वाली बस जुलाई, 2018 में बंद कर दी गई। डूंगरपुर से रतनपुर-बांसवाड़ा बस बंद कर दी गई। डूंगरपुर से बांसवाड़ा बंद कर दी गई। डूंगरपुर से चाड़ोली, डूंगरपुर से आसपुर, डूंगरपुर से सागवाड़ा, गलियाकोट, डूंगरपुर से रतनपुर, डूंगरपुर से हिम्मतपुर बस बंद कर दी गई। अध्यक्ष महोदय, विधायक महोदय ने जो स्पेसिफिक एक बस चलाने की डिमांड की थी...

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, बैठें प्लीज।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): मैं बोल रहा हूं, यह नोट करना है तो कर लो।

श्री अध्यक्ष: आप प्लीज बैठें, प्लीज बैठें, ऐसे नहीं। सीधा प्रश्न है, डूंगरपुर में इतनी चल रही थीं, इतनी बंद हैं, बस खतम।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): संख्या गिनकर बता देता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, माननीय सदस्य, अगला प्रश्न।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं बता देता हूं, अध्यक्ष महोदय, बताने दो न यह +++ रहे हैं, इनके +++ का जवाब तो देने दो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें पहले, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): यह +++ रहे हैं, +++ का जवाब तो दूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। अमृतलाल मीणा।

सलूम्बर में बी.पी.एल. परिवारों के बालकों का निजी विद्यालयों में प्रवेश

284. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि आर.टी.ई. के तहत पच्चीस प्रतिशत प्रति वर्ष बीपीएल परिवार के बालकों को निजी विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है एवं उनका सम्पूर्ण पुनर्भरण सरकार द्वारा किया जाता है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी व झल्लारा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 में किन-किन निजी विद्यालयों में किन-किन बालकों को प्रवेश दिया गया व सरकार द्वारा किन-किन विद्यालयों को कितनी राशि दी गई? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): जी हां। विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी व झल्लारा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 में 302 बालक-बालिकाओं को प्रवेश दिया गया, जिनका पंचायत समितिवार विवरण निम्नानुसार है:-

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	पंचायत समिति	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या
1	सलूम्बर	सलूम्बर	139
2		सराडा	31
3		सेमारी का कुछ भाग	45
4	खेरवाड़ा	सेमारी का शेष भाग	30
5	धरियावद	झल्लारा	57
		कुल योग	**302**

उक्त सूचना का विधान सभा क्षेत्र सहित पंचायत समितिवार सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

वर्ष 2019-20 की प्रथम किश्त का भुगतान प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है वर्ष 2019-20 समाप्त होने वाला है, 302 बालक जो बीपीएल परिवार के हैं, निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं और आप यहां परिशिष्ट 'क' में लिख रहे हैं प्रथम किश्त का भुगतान प्रक्रियाधीन है, 20 दिन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): आप वर्ष 2019-20 की प्रथम किश्त का भुगतान कब तक करेंगे? कितनी किश्तों में भुगतान किया जाना है? प्रथम किश्त बताई है, बाकी कितनी किश्त हैं उन बालकों के लिए और 2019-20 का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा और 2019-20 की कितनी राशि का भुगतान करना है, 302 बालक हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है उसमें एक ही बात है कि जो विरासत में आप लोग छोड़कर गये थे ...(व्यवधान) आराम से, आराम से, तसल्ली करो मैडम बैठी हैं आज तो, तसल्ली करो। 138 करोड़ 47 लाख 41,473 रुपये आप वर्ष 2018-19 का छोड़कर गये थे, जो आप भुगतान नहीं कर पाये, अब सरकार ने 53 करोड़ रिलीज किये हैं। पहले आपकी छोड़ी हुई देनदारी देंगे, फिर नये लोगों को हम पैसे देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, स्पेसिफिक प्रश्न है, 302 बच्चों का और 2019-20 की पहली किश्त अभी तक नहीं मिली है, 20 दिन बाकी हैं, उसका बताओ आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रथम किश्त के रूप में इनको 2800 रुपये के हिसाब से 8 लाख 50 हजार रुपये के लगभग पैसे देने हैं। लेकिन चूंकि जिसके पहले बकाया हैं, 2018-19 के बकाया हैं, अगर उनको नहीं देकर इनको देंगे तो यह न्याय नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्रश्न के संदर्भ में, प्रश्न सीधा 302 के बारे में पूछा है, 302 की 2019-20 में किश्त देनी थी, आपकी किश्त के नियम हैं, 20 दिन बचे हैं, पहली किश्त नहीं मिली। आप खाली 302 के बारे में बताओ कि इन 302 के बारे में क्या करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, 302 को जैसे ही यह बजट पारित हो जाएगा, हम लोग जो यह पुरानी देनदारी छोड़ गये, उसको भी देंगे और इन 302 को भी पहली किश्त देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। (व्यवधान) माननीय राठौड़ साहब, आप सीनियर लीडर हैं, मंत्री रहे हैं, can I extract from the Minister? Please understand it. You have to appreciate it and आप दूसरे तरीके से लेकर आएं। यह तरीका नहीं है, go on repeating. We have the limit of a question. सुश्री दिव्या मदेरणा (अनुपस्थित)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं ने प्रश्न पूछ लिया, वही भावना हमारी है और कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी, आप वरिष्ठ हैं, मंत्री रहे हैं, can I extract from the Minister? Can I compel them? आप इसको दूसरे तरीके से लेकर आएं। दूसरे तरीके से इश्यू को लेकर आएं then we will discuss it.

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना कर रहा हूं अगर इस प्रकार के उत्तर आएंगे तो हमारा सवाल पूछने का मंतव्य खतम हो जायेगा। केवल सलूम्बर और सलूम्बर में भी 302 बच्चों के बारे में भी अगर सरकार यह नहीं बता सकती कि कितनी किश्तों में पेमेंट करते हैं, पहली किश्त में कितना पैसा जाना है, उसका हिसाब नहीं दे सकते और इन बच्चों को टोटल कितनी किश्तों में, कितना रुपया जाना है, यही अगर नहीं बता सकते तो फिर क्या फायदा प्रश्न पूछने का।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन 302 बच्चों को हम लोग अप्रैल में पेमेंट दे देंगे।

प्रश्न संख्या 285

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। सुश्री दिव्या मदेरणा।

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री खुशवीरसिंह।

बी.पी.एल. सूची से वंचित परिवारों का पुनः सर्वे

286. श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार बेसलाइन सर्वे अथवा बी.पी.एल. सूची से वंचित रहे परिवारों के नाम पुन: सर्वे करवा कर जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार के पास उक्त से वंचित रह गये परिवारों की सूची है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पिछली बेसलाइन बी.पी.एल. सर्वे कब करवाया गया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उप मुख्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (1) जी नहीं। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार बीपीएल सर्वे करवाया जाता है। पूर्व में इसकी पंचवर्षीय योजना काल (2002-2007) के लिए वर्ष 2002 से बीपीएल सर्वे हुआ था। ग्राम सभाओं में अनुमोदन उपरांत बीपीएल सूची सितम्बर 2006 में प्रकाशित की गई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सेक सर्वे 2011 में किया गया है जिसकी अन्तिम सूची का प्रकाशन अप्रैल, 2016 में किया गया है। बीपीएल सूची 2002 (ग्रामीण) में शामिल होने से वंचित रहे परिवारों के लिये भारत सरकार के निर्देशानुसार बीपीएल सैन्सस 2002 (ग्रामीण) में पात्र परिवारों को शामिल करने हेतु द्विस्तरीय अपील का प्रावधान है। इसके अनुसार प्रथम अपील संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं द्वितीय अपील जिला कलेक्टर को की जा सकती है। अपील प्रक्रिया द्वारा ही बीपीएल सूची 2002 में पात्र परिवारों को शामिल किया जा सकता है। परिशिष्ट-1

(उप मुख्य मंत्री)

(2) जी नहीं। बीपीएल सैन्सस 2002 के चयन हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार 13 आर्थिक एवं सामाजिक सूचकों के आधार पर सर्वे करवाकर 52 अंकों में से अंक प्रदान किये गये थे। सर्वे से प्राप्त अंकों के आधार पर आरोही क्रम में सूचियां तैयार कर भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा तक आने वाले परिवारों को एकल कट आफ स्कोर के आधार पर शून्य से 12 अंक तक प्राप्त करने वाले समस्त एवं 13 अंक प्राप्त करने वाले आंशिक परिवारों का बीपीएल सूची 2002 (ग्रामीण) में चयन किया गया था। ग्राम सभाओं में अनुमोदन उपरांत बीपीएल सूची सितम्बर, 2006 में प्रकाशित की गई थी।

अपील प्रक्रिया द्वारा ही बीपीएल सूची 2002 में पात्र परिवारों को शामिल किया जा सकता है।

(3) पिछला बीपीएल सर्वे 2002 में किया गया था, जिसका प्रकाशन सितम्बर 2006 में किया गया। बीपीएल सर्वे 2002 के पश्चात् भारत सरकार के निर्देशानुसार सैक सर्वे 2011 में कराया गया तथा सैक सूची को 2016 में लागू किया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो 2002 के सर्वे में वंचित रह गये हैं, प्रथम अपील, द्वितीय अपील, उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय में करने के लिए आपने लिखा है तो क्या वे परिवार जो सर्वे में वंचित रह गये, अपील कर सकते हैं?

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह एक निरन्तर प्रक्रिया एवं अपील ऑनगोइंग है। इसमें लगातार छंटनी होती रहती है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 22 लाख 47 हजार 981 परिवार थे। इसमें द्वितीय अपील के बाद 5 लाख 19 हजार परिवार और जुड़ गये हैं। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूं कि यह अपील हर क्षेत्र में लगातार जारी है और कलेक्टर ही इसको रिजेक्ट या एक्सैप्ट करता है। यह ऑनगोइंग प्रोसस है। चूंकि सैक सर्वे हो चुका है, उसको हम मानक बनाकर काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बिहारीलाल।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा सौर ऊर्जा क्रय की दर कम करने की योजना

287. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा जारी आदेश क्र. JDVVNL/MD/CE (RA&C) Ju/2019 & 20/D643 द्वारा घरों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर लगाये गये सोलर एनर्जी प्लांट्स से उत्पन्न बिजली के उपयोग के उपरान्त शेष बिजली के लिये प्रति यूनिट 3.14 रुपये की भुगतान व्यवस्था को बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा 3.14 रुपये प्रति यूनिट से सस्ती बिजली उपलब्ध कराने का कोई समझौता किया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्णय से सौर ऊर्जा का प्रसार बाधित हुआ है? यदि हां, तो उक्त निर्णय लिये जाने के क्या उद्देश्य हैं? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

ऊर्जा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जी नहीं। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत घरेलू प्रतिष्ठानों पर लगाये गये सोलर एनर्जी प्लांट्स से उत्पन्न विद्युत के लिए उपयोग से अधिक पर प्रति यूनिट 3.14 रुपये की भुगतान व्यवस्था को बन्द नहीं किया गया है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी संशोधन के तहत जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा घरेलू श्रेणी में 100 यूनिट से अधिक विद्युत इंजेक्ट होने पर ही प्रति यूनिट 3.14 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। उक्त संदर्भ में जारी किये गये आदेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। सौर ऊर्जा के प्रसार को उपरोक्तानुसार किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल में घरों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, दोनों के बारे में पूछा गया है। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर पढ़ा है, वह सिर्फ घरों के बारे में है। उसकी पुष्टि के लिए इन्होंने परिशिष्ट 'अ' पर लिखा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछ रहा हूं कि आपके पास जो जवाब है, वही जवाब मेरे पास है। आपने जो उत्तर दिया है, उसकी

(श्री बिहारीलाल)

पुष्टि में और नीचे जो सर्कुलर लगा हुआ है, उसमें पेज 1 of 3, उसके बाद सीधे 3 of 3, बीच का 2 नंबर पेज कहां है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, जो अपेंडिक्स दिया है, उसमें पहला और तीसरा पेज है, दूसरा नहीं है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): दूसरा पेज किसी कारण से नहीं आया होगा, मैं उसको पढ़कर बता देता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने केवल डोमेस्टिक के बारे में सूचना दी है। इनके दूसरे पार्ट कॉमर्शियल के बारे में सूचना नहीं है, कॉमर्शियल के बारे में जवाब दें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): कामर्शियल के बारे में विद्युत विनायमक आयोग ने जो आर्डर निकाला है, उसमें वाणिज्यिक उपयोग में भवन या होटल्स वगैरह आ रहे थे, उसके लिए मना किया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्रश्न का जवाब पूरा आना चाहिए।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): मैं इनको प्रोवाइड करा देता हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठें, आप सीनियर मिनिस्टर हैं। प्रश्न में इन्होंने डोमेस्टिक और कामर्शियल दोनों का पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में कॉमर्शियल के उत्तर के बारे में कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूं कि प्रश्न को स्थगित किया जाता है। अगली बार इस पर रिव्यू रखेंगे।

(स्थगित)

अगला प्रश्न। श्री धर्मनारायण जोशी।

फतहनगर (उदयपुर) में आवासन मण्डल की आवासीय योजना

288. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार जिला उदयपुर के फतहनगर कस्बे में राजस्थान आवासन मंडल की आवासीय योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): जी नहीं। वर्तमान में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उदयपुर जिले के फतहनगर कस्बे में आवासीय योजना हेतु भूमि की अनुपलब्धता के कारण कोई आवासीय योजना बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि फतहनगर नगरपालिका में पांच पंचायतें ऐसी हैं, जो नगरपालिका क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। सरकार वहां से भूमि अधिगृहीत कर, फतहनगर राजस्थान की तीसरी बड़ी मंडी है, कोटा और निम्बाहेड़ा के बाद। मेरी आपसे प्रार्थना है कि वहां जमीन अधिगृहीत कर क्या सरकार आवासन मंडल के मकान बनाने का विचार रखती है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जैसा आपने बताया कि पांच गांव जुड़ गये हैं। इसे दिखवा लेंगे। अगर भूमि उपलब्ध होगी और वहां रिक्वायरमेंट होगी तो प्लान बनाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री मेवाराम जैन।

बाड़मेर में नि:शुल्क पशु दवा योजनान्तर्गत पशुओं का इलाज

289. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बाड़मेर में वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री नि:शुल्क पशु दवा योजना में कितने पशुओं का निशुल्क इलाज किया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में कितने पशु चिकित्सालय व पशु उप केन्द्र संचालित हैं तथा उक्त में कितने कार्मिक कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) बाड़मेर जिले में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 20 लाख 38 हजार 1 सौ 59 एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 के माह जनवरी, 2020 तक 12 लाख 4 हजार 8 सौ 26 पशुओं का पशुधन नि:शुल्क आरोग्य योजना अन्तर्गत नि:शुल्क उपचार किया गया।

(2) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में 1 बहूद्देश्यीय पशु चिकित्सालय, 4 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय एवं 5 पशु चिकित्सालय (कुल 10 पशु चिकित्सालय) एवं 21 पशु चिकित्सा उप केन्द्र स्वीकृत हैं। इनमें कार्यरत कार्मिकों का संस्थावार एवं नामवार विवरण परिशिष्ट-1 एवं 2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि बाड़मेर में पशु चिकित्सक व पशुधन सहायक के रिक्त पद कब तक भरे जाएंगे? बाड़मेर के गादान में अभी एक नयी नंदीशाला खुली है और उसकी आपने स्वीकृति भी दी है। वहां पर बाड़मेर शहर के सारे पोलीथिन खाये

(श्री मेवाराम जैन)

हुए पशु उसके अंदर हैं। आप उसमें पशु चिकित्सक एवं पशुधन सहायक कब तक नियुक्त कर देंगे?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में जो पशुधन सहायकों की भर्ती हुई है, उसमें बाड़मेर जिले में 115 पशुधन सहायक लगाये गये हैं। इनके विधान सभा क्षेत्र में 13 पशुधन सहायक लगाये गये हैं। दो उप केन्द्र खोले हैं और जैसा कि आपने गोशाला का जिक्र किया है, हमारे पास अभी 125 कर्मचारी और आने हैं, जिनके कागजों की स्क्रूटनी चल रही है। उसमें से तुरंत ही इनके यहां लगा दिये जाएंगे। पशु चिकित्सक की बात रही तो उसमें 29 अप्रैल को 900 पदों के लिए भर्ती का रिटर्न टैस्ट हुआ है, उसके बाद पशु चिकित्सक भी लगा दिये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, संजय शर्मा।

सरस डेयरी प्लांटों पर दूध में मिलावट की शिकायतें

290. श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विगत पांच वर्षों में प्रदेश के सरस डेयरी प्लांटों पर दूध में मिलावट किये जाने के मामले उजागर हुए हैं? यदि हां, तो किस-किस डेयरी प्लांट में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में सरस डेयरी के किस-किस प्लांट से दूध के कितने नमूने लिये गये एवं उनमें से कितने नमूनों में मिलावट पाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मिलावटी दूध किन-किन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा आपूर्ति किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री) **श्री प्रमोद भाया** (गोपालन मंत्री के स्थान पर): (1) जी नहीं। गत पांच वर्षों में आरसीडीएफ से सम्बद्ध जिला दुग्ध संघों के किसी भी प्लांट पर सरस द्वारा उत्पादित दूध में मिलावट का कोई भी प्रकरण नहीं है।

(2) गत पांच वर्षों में आरसीडीएफ से सम्बन्धित जिला दुग्ध संघों के प्लांट से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा कुल 93 दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के नमूने लिये गये, उनमें से अलवर जिला दुग्ध संघ

(श्री लालचन्द कटारिया)

में 02 नमूने अमानक पाये गये। टोंक दुग्ध संघ में एक नमूना अमानक पाया गया। दुग्ध संघवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) गत पांच वर्षों में जिला संघों द्वारा जांच के दौरान कुल 2664 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के दूध में मिलावट पायी गयी। दुग्ध संघवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 3 में माननीय मंत्री जी ने माना है कि 2664 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के दूध में मिलावट पायी गयी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी और नहीं की गयी तो क्यों? इसके साथ-साथ आने वाले समय में दूध मिलावट नहीं हो, उसके लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाने की मंशा रखती है?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है 2664 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के दूध में मिलावट पायी गयी, यह बात सही है। यह जो मिलावट पकड़ी जाती है, ये नीचे के स्तर पर पकड़ी जाती है, उसको डेयरी के माध्यम से वहां पर एक किट दिया हुआ है, जब मिलावट का पता चलता है तो डेयरी वाले या जिला दुग्ध उत्पादक संघ है, वह इसको नष्ट कर देता है और खाली ड्रम किसान को पकड़ा देता है। यह पहली प्रक्रिया है। यदि वह दुबारा पकड़ा जाता है तो उसको चेतावनी दी जाती है और बोर्ड उसके जुर्माने का फैसला करता है। यदि वह तीसरी बार भी पकड़ा जाता है तो उस संस्था को रद्द कर दिया जाता है और एडीएम के यहां प्रकरण भेजा जाता है। उसके बाद यदि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो नमूने लिये जाते हैं, उन नमूनों का प्रकरण जुडीशियल होता है, वह जुडीशियरी में भेजा जाता है और वहां पर सज़ा का प्रावधान है। आजीवन सज़ा का प्रावधान भी है और नीचे के लेवल पर 25 हजार से 5 लाख का प्रावधान एडीएम के यहां है।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न दुबारा इसलिए पूछा क्योंकि ज्यादातर उन लोगों को परेशान किया जाता है, जो चेयरमैन के साथ नहीं चलते। भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर फिर पैसे का लेन-देन करके उनको मुक्त कर दिया जाता है। मेरा सीधा-सीधा प्रश्न था कि 2664 सहकारी समितियों में कितनों पर विभाग ने कार्यवाही की? इसकी जानकारी मंत्री महोदय दे दें।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अलवर में दो नमूने पाये गये। उनमें से एक केस खाद्य सुरक्षा अधिकारी, एडीएम, अलवर के यहां विचाराधीन है। दूसरा जो प्रकरण है, वह सीएमएचओ में यहां लंबित है। 29.07.2019 से एडीएम अलवर के पहले केस हैं, वे पैंडिंग है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी की भी मंशा है, कई बार मुख्य मंत्री जी ने कहा भी है और आपने भी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं व्यक्तिश: सदन के सभी सदस्यों को निवेदन करूंगा कि ये बहुत गंभीर प्रश्न है, मिलावट का जो मामला है, यह आदमी के मानव जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यदि आपको कोई भी शिकायत मिले तो सज़ा के जो भी प्रावधान नियमों में हैं, उसको हम विभाग द्वारा दिखवाएंगे। आप निश्चित तौर पर बताएं, इस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: संजय जी।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष जी, अभी हाल ही में हमारे अलवर डेयरी के माननीय अध्यक्ष को भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के कारण बर्खास्त किया। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जैसा बता रहे हैं, अलग से सवाल है, परंतु फिर भी आपने इसको सदन में उठाया है, मैं निश्चित तौर पर क्वेश्चन आवर के बाद में अधिकारियों को बुला लूंगा, आप बैठकर बात कर लेना। जो भी होगा, उसका निस्तारण कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न श्री ओमप्रकाश।

महुवा में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी

291. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र व्यक्तियों को कितना अनाज दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला दौसा में उक्त योजना के अंतर्गत खाद्य सूचियों का पुनरीक्षण किया गया है तथा कुछ व्यक्तियों के नाम सूची से हटाए हैं? यदि हां, तो कब? विधान सभा क्षेत्रवार हटाये गये नामों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले के उक्त विधान सभा क्षेत्रों में

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

कई व्यक्ति जांच में पात्र भी पाए गए हैं लेकिन उनका नाम सूची में अब तक नहीं जोड़ा गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त व्यक्तियों को खाद्य सूची में पुन: जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र महुवा में वर्तमान में किस-किस ग्राम पंचायत से कितने-कितने व्यक्ति खाद्य सूची में सम्मिलित हैं? ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय परिवारों को 35 किग्रा प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह एवं बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं अन्य पात्र परिवारों को 5 किग्रा प्रति यूनिट प्रतिमाह के हिसाब से गेहूं दिया जाता है।

(2) जी हां। दौसा जिले के विधान सभा क्षेत्रों में उक्त योजना के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा सूची में से हटाये गए अपात्र व्यक्तियों का विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। विभागीय आदेश दिनांक 05.11.2015 में निर्देशित अपीलीय प्रक्रिया द्वारा पात्र लोगों का नाम जोड़ा जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(4) विधान सभा क्षेत्र महुवा में वर्तमान में खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल व्यक्तियों की ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जन-सुनवाई के दौरान माननीय विधायकों के पास जो भी शिकायतें आती हैं। उन शिकायतों को माननीय मंत्री महोदय को हम लोग भिजवाते हैं। क्या मंत्री महोदय की उन शिकायतों पर कार्यवाही करने की मंशा है या नहीं?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जो नियमानुसार है, पात्रता की श्रेणी में जो आते हैं, उनको हमारे यहां भेजें, हमारे डीएसओ के यहां भेजें, जो भी अधिकारी हैं सक्षम स्तर पर, समावेशन की सूची में आता है तो उनका हम नाम जोड़ते हैं और जो भी प्राब्लम आपकी दूसरी है, जिनके खिलाफ आपको लगता है, उनके खिलाफ कार्यवाही नियमानुसार की जाती है।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। इस विधान सभा के सदस्य माननीय मंत्री महोदय को कोई शिकायत भेजते हैं, मेरा एक प्रश्न कर रहा हूं, उस पर यस या नो में जवाब चाहिए मुझे कि आप कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं, हां या नहीं?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नियमानुसार है तो काम करेंगे, अगर नियम में नहीं आता है तो क्या करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): सर, एक मिनट। बस एक ही प्रश्न पूछा है। दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी यह जनता से जुडे हुए मुद्दे हैं। एक राशन डीलर जिसको 25 किलो गेहूं प्रार्थी को देना है। वह राशन डीलर दो किलो-ढाई किलो चीनी खरीदता है मार्केट से...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): मैं वही कह रहा हूं। ढाई किलो चीनी खरीदता है और ढाई किलो चीनी 25 किलो के गेहूं के बदले देकर अंगूठा लगवा लेता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए माननीय सदस्य।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): मैं वही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: क्या प्रश्न पूछ रहे हैं आप?

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): अगर इस तरह की आपके पास जानकारी आती है, उसमें 450 रुपये का घोटाला होता है। मैंने एक महीने पहले...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अगला प्रश्न, श्री जोराराम कुमावत। प्रश्न पूछ रहे हैं या क्या कर रहे हैं आप?

सुमेरपुर के ग्रामों में बस स्टैण्ड पर बसों का ठहराव

292. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के ग्राम पालडी जोडपुल, नेतरा, बिरामी, केनपुरा, ढोला, किरवा, डिंगाई, गुन्दोज सहित कई गांव स्थित हैं, जहां पर पुल बने हुए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार बसों का

(श्री जोराराम कुमावत)

ठहराव सर्विस रोड पर निर्मित बस स्टैण्ड पर करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

परिवहन मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा प्रश्नगत गांवों में जहां एनएच पर पुल बने हुए हैं, वहां सर्विस रोड पर निर्मित बस स्टाप से सवारियां उतारने/चढ़ाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि प्रश्नगत गांवों में जहां एनएच पर पुल बने हुए हैं, वहां सर्विस रोड पर निर्मित बस स्टाप से सवारियां उतारने/चढ़ाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। क्या इन गांवों के अलावा प्रश्नगत गांवों जिसमें पालड़ी, नेतरा, बिरामी, केनपुरा, ढोला, किरवा, डीगई, गुंदोज, इसके अलावा भी जहां पुल बने हुए हैं और सर्विस रोड बने हुए हैं, वहां पर भी राजस्थान राज्य पथ परिवहन की बसें नीचे सर्विस रोड पर, बस स्टैंड पर रोकने की व्यवस्था सरकार करेगी?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सर्विस रोड पर बस रोकने के निर्देश पूरे राजस्थान में दिये गये हैं। जहां पर भी सर्विस रोड पर बस स्टैंड बने हुए हैं, जनता की सुविधानुसार वहां पर रोका जा सकता है। निर्देश जारी कर दिये गये हैं। माननीय सदस्य को स्पेसिफिक और कोई गांव वगैरह बताने हैं तो आप मेरे साथ मिल लें, वहां बसें रोकने की व्यवस्था कर दी जाएगी।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया। अगला प्रश्न। आपकी बात मान ली, और क्या बचा है अभी।

विद्यालयों के ढांचागत निर्माण पर व्यय राशि

293. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा विगत बजट में विद्यालयों के ढांचागत निर्माण हेतु 1500 करोड़ रुपये की राशि व्यय करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक उक्त हेतु कितने विद्यालयों को कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने कार्यों के टेंडर व कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं तथा अब तक कितनी राशि व्यय हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री वासुदेव देवनानी)

(3) उक्त में से शेष राशि कब तक व्यय होगी व उससे कब तक कार्य पूर्ण हो जाएंगे? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) जी हां। राजकीय विद्यालयों में चरणबद्ध रूप से आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु 14000 से अधिक अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि कक्षों, 23 नवीन भवनों के निर्माण तथा 83 भवनों की वृहत् मरम्मत के कार्य करवाये जाने की विगत बजट में घोषणा की गई है।

अब तक राज्य सरकार द्वारा 4996 राजकीय विद्यालयों के लिए कुल राशि 1581.83 करोड़ रुपये आबंटित (स्वीकृत) की गई, जिसका जिलेवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त 4996 राजकीय विद्यालयों के कार्यों में से 4713 राजकीय विद्यालयों के कार्यों के टेण्डर व 3648 राजकीय विद्यालयों के कार्यों के कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं तथा अब तक राशि 205.22 करोड़ का व्यय किया जा चुका है, जिसका विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(3) शेष राशि व्यय की जाकर समस्त कार्यों को चरणबद्ध रूप से मार्च, 2022 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न है कि इस 1500, जो आपने 81 करोड़ की बात की है, इसमें कितना केन्द्र का अंश है, कितना राज्य का अंश है? पहले तो यह स्पष्ट करें। दूसरा, एक वर्ष में अब तक जो आपने टेंडर जारी किये हैं इसमें कितने कमरे बनने वाले हैं, कितनी प्रयोगशालाएं बनने वाली हैं, कितने पुस्तकालय बनने वाले हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो योजना है इसके तहत जो 1581 करोड़ रुपये उसमें पीएबी के अंदर 1181.74 करोड़ रुपये नवीन कार्यों के लिए हैं और 400 करोड़ रुपया आरआईडीएफ 25 में जो हमने लिये हैं, जो केन्द्र से हमें पीएबी के द्वारा जो राशि मिलती है, उसमें 60:40 का अनुपात होता है। जो नाबार्ड है, उससे राज्य सरकार लोन लेकर भवन है या जो भी है, बनाती है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैंने दो प्रश्न पूछे थे। इसमें भी एक बात मैं पूछ रहा हूं कि इसमें से कितनी राशि केन्द्र से आ चुकी है?

(श्री वासुदेव देवनानी)
आपने 2022 तक का दिया है। आपके पास जो राशि पड़ी है, उसका क्या उपयोग करने वाले हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है, वह मैं बताना चाहता हूं कि ये जो 900 करोड़ रुपये से अधिक आप स्पिल ओवर में छोड़कर गये थे। वह पैसे हम लेकर के आए हैं। (व्यवधान) एक मिनट आराम से।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं वही तो पूछ रहा हूं कि राशि केन्द्र से अब तक कितनी आई है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। इधर देखकर जवाब दीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): 900 करोड़ रुपये से ज्यादा आप स्पिल ओवर में छोड़कर गये थे। वह पैसे हम केन्द्र से लेकर के आए हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं अगला प्रश्न करूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप पूछना चाहते हो, एक-एक चीज बता सकता हूं। कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। नाबार्ड जो आरआईडीएफ 23 है, उसमें 5 साल के अंदर 608.45 करोड रुपया लेकर आए थे, केवल आप खर्चा कर पाए 139.52 करोड़ रुपये और हम जो पैसे लेकर के आए हैं, व्यय किया है हमने, आप वाली राशि में से भी हमने 149.52 रुपये खर्च कर दिया और जो 400.09 करोड़ रुपया हम लेकर आए हैं, उसमें से भी 192.68 करोड़ रुपया हम खर्च कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इतनी राशि आई है। वह पीडी अकाउंट में पड़ी है, खर्च ही नहीं कर रहे हैं।

सरकारी भर्तियों में अन्य राज्यों का कोटा

294. श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकारी भर्ती में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का कोई कोटा निर्धारित है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त भर्ती में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का कोई कोटा निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और कितना तथा नहीं, तो क्यों?

(श्री जगदीश चन्द्र)

(2) जनवरी, 2014 से अब तक सरकार द्वारा RPSC व RSSB द्वारा करवाई गई भर्तियों में कितने प्रतिशत बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ऊर्जा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई गई भर्तियों में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के चयन के प्रतिशत का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई भर्तियों में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के चयन के प्रतिशत का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में पिछले 10 दिनों में सड़क दुर्घटनाओं में काल कलवित हुए चार मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिलवाये जाने के संबंध में।

(2) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से 2018 में हुई मुकेश कानूनगो पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या के बाद पत्नी को अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री रामस्वरूप लाम्बा, सदस्य की ओर से संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर जोन, डा. सुरेश कुमार भण्डारी के विरुद्ध कार्य के प्रति लापरवाही के अनेक मामले लम्बित होने के बावजूद कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से दरीबा क्षेत्र में हिन्दुस्तान जिंक स्मैल्टर की लैंड माइन्स से कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती, 2018 में 10 वर्ष से अधिक समय से संविदा पर कार्य कर रहे नर्सिंग कर्मियों को अनुभव का लाभ दिये जाने के संबंध में।

(6) श्री जोगेश्वर गर्ग, सदस्य की ओर से जालौर ज़िले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बोकड़िया, सांचौर में नवीं क्लास की दो छात्राओं के साथ शिक्षक द्वारा अश्लील हरकत किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना से नहीं जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की पंचायत समिति छबड़ा व छीपाबड़ौद की ल्हासी पेयजल परियोजना में बरती जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से उदयपुर ज़िले की जयसमंद झील के भटवाड़ा टापू पर कथित तौर पर आदिवासी परिवार की जमीन को अवैध तरीके से खरीदकर होटल बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में बालिका अपहरण की बढ़ती घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से ताड़केश्वर मन्दिर, चौड़ा रास्ता जयपुर में गैस सिलेण्डर फटने से हुई दो लोगों की मौत से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से प्रदेश में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में अधिकारियों की लापरवाही के कारण भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में फंसने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(13) श्री गोपीचन्द मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के ग्राम ऊरना के देवनारायण समेलिया बांध के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से सीकर व जयपुर में CAA,

(श्री अध्यक्ष)

NRC व NPR के विरोध में धरना दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(15) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से बीकानेर ज़िले में राष्ट्रीय राजमार्ग 754 K के लिए अवाप्त की गई भूमि का उचित मुआवजा दिये जाने की मांग को लेकर पिछले 165 दिनों से चल रहे धरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(16) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से डेढ़ दशक पूर्व पाकिस्तान से अजमेर आये 23 परिवारों को नागरिकता नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(17) श्री बलवीर सिंह लूथरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के गांव 22 पी.टी.डी. के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्‌यालय के अध्यापकों द्‌वारा कथित रूप से 10वीं एवं 12वीं की तीन दलित छात्राओं के साथ दुष्कर्म का वीडियो वायरल होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(18) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से वर्ष 2012-13 में तलवण्डी स्थित उड़िया बस्ती के विस्थापितों को मकान आबंटन न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(19) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से सिरोही ज़िले में अस्पताल में भर्ती बलात्कार की पीड़िता का घटना के 12 दिन बाद अनादरा पुलिस द्‌वारा मुकदमा दर्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती अनिता भदेल, श्री बलवीर सिंह लूथरा, श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल एवं श्री संयम लोढ़ा को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री हमीरसिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना के ऐतिहासिक तीर्थ भीमगौड़ा का संरक्षण एवं संवर्द्धन किये जाने के संबंध में।

(2) श्री गोपीचंद मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसपुर की तीनों पंचायत समितियों में ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में।

(3) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से छबड़ा-कुम्भराज सड़क के अधूरे पड़े कार्य से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(4) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाली की कतिपय प्रमुख सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने सहित मरम्मत करवाये जाने के संबंध में।

(5) श्री कालूराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग में गागरीन पेयजल योजना से वंचित गांवों को जोड़े जाने के संबंध में।

(6) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली में अधिकांश सरकारी स्कूलों के भवनों के क्षतिग्रस्त होने के कारण अनहोनी की संभावना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से प्रदेश में विभिन्न भर्तियों के लिए होनी वाली परीक्षाओं में शिड्यूल्ड एरिया के छात्रों का परीक्षा केन्द्र शिड्यूल्ड एरिया में ही दिये जाने के संबंध में।

(8) श्री जगदीश चन्द्र, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में गाजर मंडी खोले जाने के संबंध में।

(9) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम सामोद स्थित क्षतिग्रस्त राजोला बांध का पुनर्निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(10) श्रीमती निर्मला सहरिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के केलवाड़ा कस्बे के राजकीय महाविद्यालय को पी.जी. महाविद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

(11) श्री मोहन राम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नागौर में प्रधानमंत्री सड़क योजना से वंचित 250 से अधिक आबादी की ढाणियों को सड़कों से जोड़े जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(12) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से राज्य सरकार द्वारा जन-घोषणा पत्र के अनुसार लघु एवं मध्यम दर्जे के गैर सरकारी विद्यालयों को प्रोत्साहन, संरक्षण एवं संवर्धन दिये जाने के संबंध में।

(13) श्रीमती कल्पना देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा से गुजरने वाली चम्बल नदी की नहर की दीवारों को ऊंचा करवाये जाने के संबंध में।

(14) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में पेयजल समस्या का समाधान करवाये जाने के संबंध में।

(15) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई पुलियाओं की मरम्मत करवाये जाने के संबंध में।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

उपरोक्त सभी प्रस्ताव पढ़े हुए माने जाएंगे।

(पढ़े हुए माने गए प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

पर्ची

आज दिनांक 03/03/2020 को शून्यकाल में बोलने हेतु 36 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नानुसार हैं।

(1) श्री संजय शर्मा, अलवर ज़िले में हो रहे अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्रीमती शोभा चौहान, जवाई जल परियोजना का पुन: उद्धार कर पानी की कमी को दूर करने के संबंध में।

(3) श्री अमृतलाल मीणा, विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में स्वीकृत पेवर सड़कों का कार्य चालू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में

(4) प्रदेश में लगातार बढ़ रही घरेलू गैस सिलेंडर विस्फोट की घटनाओं से जान माल की हो रही क्षति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

माननीय सदस्या श्रीमती अनिता जी बोलें, उसके पहले मेरा निवेदन है कि हमने सोच-समझकर आज की डिमांड, शिक्षा की डिमांड है, शिक्षा की

(श्री अध्यक्ष)

डिमांड में दो हैड, जिसकी आज तक चर्चा नहीं होती है, स्पोर्ट्स और साइंस, इन दो पर चर्चा की। माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आज चर्चा इन दो पर ही होगी। शिक्षा का मतलब स्कूल पर नहीं होगी। इसलिए हमने सोच-समझकर, नये सदस्यों को जानकारी रहे कि शिक्षा, कला एवं संस्कृति एक डिपार्टमेंट हैड है लेकिन बजट को देखने में कौन-कौनसे हैड होते हैं, पिछले लंबे समय से इस हैड के अंतर्गत आने वाला विभाग, जो बाद में जाकर विभाग बन गया। स्पोर्ट्स के बारे में चर्चा नहीं होती, इसलिए आज स्पोर्ट्स की चर्चा रखी है, उसका हैड लिख रखा है।

दूसरी चर्चा रखी है वैज्ञानिक अनुसंधान। इसलिए आज की चर्चा में इन दो हैड पर ही चर्चा की जाएगी। इसलिए शिक्षा के संबंध में स्कूल, कालेज, टैक्नीकल एजुकेशन के संबंध में आप अपने विचार व्यक्त नहीं करें। कट मोशन उन्हीं के स्वीकार किए गए हैं। बाकी कट मोशन को रिजेक्ट किया गया है, जिससे नये सदस्यों को बजट की जानकारी करने का अवसर मिल सके। इसलिए सोच समझकर डिमांड रखी है। माननीय मंत्री जी भी ध्यान रखें। इन दो के मंत्री जवाब देंगे। श्रीमती अनिता भदेल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

पाकिस्तान से अजमेर आये 23 परिवारों की नागरिकता का प्रकरण

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस संवेदनशील मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। निश्चित रूप से नागरिक संशोधन बिल के बाद, पाकिस्तान से भारत आए ऐसे नागरिकों को उम्मीद थी कि उनको नागरिकता मिलेगी। इसी संदर्भ में मैं कुछ उदाहरणों के स्वरूप में निवेदन करना चाहूंगी।

रीना बाई पत्नी मनोज आडवानी, रीना बाई करांची व मनोज आडवानी अजमेर के रहने वाले हैं, इन दोनों ने विवाह किया। विवाह का सर्टिफिकेट भी बनाया गया, इनके दो बेटियां भी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): बार-बार आवेदन करने के बावजूद भी इनको नागरिकता नहीं मिल रही। लगभग 11 साल 2 माह हो गए इनको भारत आए हुए दो साल पहले इन्होंने आवेदन भी कर दिया, लेकिन 2

(श्रीमती अनिता भदेल)

साल 7 माह के उपरांत भी इनको नागरिकता नहीं मिल रही है। ये बार-बार विभागों के चक्कर काट रहे हैं कि किसी तरह से नागरिकता मिल जाए। क्योंकि शादी के उपरांत इनकी दो बेटियां भी हुई हैं तो मां की नागरिकता तो पाकिस्तान की बोल रही है, पिता की नागरिकता हिन्दुस्तान की बोल रही है। दोनों बच्चियां भारत की नागरिक हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब कभी परिवार में बात होती है तो निश्चित रूप से बेटियां जैसे-जैसे बड़ी हो रही हैं, वैसे-वैसे मां को चिंता है कि मैं पाकिस्तान की नागरिक हूं, भारत की नागरिक कब कहलाऊंगी। इस वजह से उनको जो पीड़ा होती है इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आगे उदाहरण देती हूं। सारिका देवी w/o मनोज सोनी, इन्होंने तीन साल एक महीने पहले आवेदन किया। भारत आये हुए इनको 15 साल 11 महीने हो गये। तीसरा उदाहरण देती हूं, कविता देवी w/o नेमीचन्द सोनी, इन्हें भी तीन साल एक महीना हो गया आवेदन किये हुए और भारत आये हुए इनको 15 साल 11 महीने हो चुके हैं।

इसी प्रकार माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हंसराजजी के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। कराची से 16 साल पहले ये भारत में अजमेर आये। अजमेर आ करके पुलिस लाइन क्षेत्र में इन्होंने स्वर्णकार का व्यापार शुरू किया। इनका पूरा परिवार, जिसमें उमेश सोनी और उनकी पत्नी कविता सोनी, ये सारे परिवार के लोग यहां आ चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन भी उन्होंने किया है। उनके आवेदनों की जांच भी हो गई। आप साक्ष्य के रूप में देखना चाहें तो ये आवेदन-पत्र, जो उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया है, उनकी कापियां भी मैं ले करके आई हूं। उसके बावजूद भी इनको नागरिकता नहीं दी जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि जब कभी भी उनके लोंग टर्म वीजा की अवधि समाप्त हो जाती है और उसके बाद में उनको आवेदन करना होता है तो लोंग टर्म वीजा की अवधि में यदि एक दिन की भी डिले हो गई तो जो पैनल्टी होती है, वह पैनल्टी की राशि उनको चुकानी होती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि एक तो पैनल्टी की राशि को किसी तरह से समाप्त किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कुछ और उदाहरण हैं। मैं उन सबका उल्लेख करना चाहूंगी। रमा देवी हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अनेक का उल्लेख करने की जरूरत नहीं है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 23 लोग हैं।

श्री अध्यक्ष: आपने मेन बात बता दी।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 23 लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप 23 का उल्लेख नहीं करेंगे। 23 की बात हो गई।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): किरण देवी हैं, उनको भी, क्योंकि अलग-अलग इंडिविजुअल आवेदन सबके मांगे जाते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, पारिवारिक रूप से आवेदन नहीं मांगे जाते ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव में जनरल बात होगी, एक-एक का नहीं होगा, प्लीज।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, एक बार सदन के ध्यान में आ जाए, सदन के फ्लोर पर आ जाए। (व्यवधान) किरण देवी हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, माननीय सदस्य, प्लीज। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बात हो गई। 23 परिवारों के सम्बन्ध में सरकार को उनको नागरिकता देने की कार्यवाही करनी चाहिए। आपने बात कह दी। (व्यवधान) नाम आपके पास हैं। आप हाउस में ले कर दें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): बिलकुल, एक लास्ट में निवेदन कर रही हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी बात को स्वीकार करते हुए।

एक मुनेश जेठानी हैं, जो डाक्टर है, जिसने डाक्टर की डिग्री पाकिस्तान से ली है, लेकिन वह जब प्रैक्टिस कर रहा था तो कट्टरपंथी संगठनों के दबाव में आ करके उसको वहां से छोड़ना पड़ा। वह अपनी पत्नी और दोनों बेटियों सहित आज हिन्दुस्तान में निवास कर रहा है, अजमेर में निवास कर रहा है। यहां प्रैक्टिस भी कर रहा है। छह साल होने के बाद में वह, लीगली पहले 11 साल होने के बाद में, यह नियम था कि वह आवेदन कर सकता था लेकिन अब उसको 7 साल हो गये। वह जनवरी, 2013 में आया। जनवरी, 2020 में उसको पूरे 7 साल हो गये। प्रक्रिया यह है कि वह आवेदन के लिए, पहले आवेदन मांगते हैं कि आप आवेदन करो लेकिन उनसे

(श्रीमती अनिता भदेल)

आवेदन नहीं मांगा जा रहा है कि आप आवेदन करो तो जब तक उनसे आवेदन नहीं मांगा जाएगा, तब तक वह कैसे आवेदन करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस परिवार से भी आवेदन मांगा जाए, ताकि उनकी पत्नी और दोनों बच्चे भी आवेदन कर सकें। इसी प्रकार से जो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बस, हो गया। (व्यवधान) You have to appreciate it. On Sthagan, I'll not allow it. नहीं, हो गया अब। समाप्त हुआ। बलवीर सिंह लूथरा। It's too much माननीय सदस्य, हो गया। प्लीज न, न। प्लीज, आपकी बात हो गई। (व्यवधान) आप सब चीजें, नाम, ले-डाउन कर दें। जो प्रक्रिया पूरी करनी है, उसको सरकार फालो करेगी। बात हो गई, माननीय सदस्य। माननीय बलवीर सिंह लूथरा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठें आप, सीनियर लीडर हैं। आप सीनियर हैं, प्लीज। आपकी बात मान ली मैंने। आप बैठें। (व्यवधान) आपकी भावना इस सम्बन्ध में आ गई। 23 नागरिकों के सम्बन्ध में आप चिंतित हैं। उनके सम्बन्ध में सरकार ध्यान देगी, जो नागरिकता की प्रक्रिया है, उसको पूरा करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद।

रायसिंहनगर के गांव 22 पी.टी.डी. के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की दलित छात्राओं के साथ दुष्कर्म का वायरल वीडियो

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के अंतर्गत मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के गांव 22 पी.टी.डी. के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में तीन दलित छात्राओं के साथ छेड़छाड़, दुर्व्यवहार, अश्लील हरकतें व दुष्कर्म करने का उसी के विद्यालय के तीन अध्यापकों द्वारा, तीन छात्राओं के साथ, जिसमें एक दसवीं की छात्रा थी, दो बारहवीं की छात्राएं थीं। इसका अश्लील वीडियो जारी होने के बाद ग्रामीणों में गुस्सा फूटा, परिजनों में गुस्सा फूटा। उसके बाद स्कूल पर ताला लगा दिया। तालाबंदी की गई, घेराबंदी की गई और पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई। इसके अगेंस्ट में विद्यालय स्टाफ द्वारा भी एक टीचर से ग्रामीणों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया गया और राजकाज में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाया गया। ग्रामीणों द्वारा, परिजनों द्वारा बच्चियों के साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए, अश्लील हरकतों के बारे में,

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

वीडियो के बारे में जो एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई, आज तक वह ऑनलाइन नहीं हुई जबकि मास्टर्स द्वारा उन ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था, उसकी एफ.आई.आर. दर्ज हो गई और ऑनलाइन शो कर रही है जबकि ग्रामीणों द्वारा जो एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई, वह शो नहीं हो रही है। इसका मतलब पुलिस प्रशासन सन्देह के घेरे में है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह बहुत ही संवेदनशील विषय है। गांवों में आज एक अध्यापक को, एक शिक्षक को देवता से कम नहीं मानते। उस शिक्षक के द्वारा ही यदि ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है, अश्लील हरकतें की गई हैं, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं, इसके खिलाफ जो भी धाराएं बनती हैं, चाहे वह 76 की है, एस.सी., एस.टी. की है, पॉक्सो एक्ट की, सभी धाराओं में मुकदमा दर्ज करके दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए और अध्यापकों को गिरफ्तार किया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

तलवण्डी स्थित उड़िया बस्ती के विस्थापितों को मकान आवंटन

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

मैं नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा और माननीय मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, सम्माननीय कोटा से आने वाले यू.डी.एच. मिनिस्टर साहब, आदरणीय धारीवालजी, कांग्रेस के समय में, 2012 की बात है, तलवंडी, कोटा के अन्दर उड़िया बस्ती करके एक कालोनी हुआ करती थी, जो कई बरसों से वहां निवास कर रही थी। वहां के लोगों का नगर विकास न्यास, कोटा के द्वारा पुनर्वास किया गया। स्वाभाविक है, पुनर्वास होता है, उन्हें मकान भी दिये गये। वे सभी लोग, जो उड़िया बस्ती की महिलाएं, पुरुष थे, वे झाडू-पोंछा करने वाले परिवार थे। उस समय की क्या कमियां रहीं, क्या खामियां रहीं, मैं किसी सरकार के ऊपर किसी तरह का कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहती। जो दस्तावेज मेरे पास हैं, उनकी पूरी फाइल है। मैंने खुद ने सरकार के कर्मचारियों के साथ मिलकर सर्वे करवाया तो उस सर्वे में इतनी खामियां रहीं कि 65 परिवार, जो आज भी वहां के निवासी थे, उनके दस्तावेज उनके पास हैं, उनके आधार कार्ड हैं, उनके राशन कार्ड हैं, वहां पर उनके बच्चों का

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

स्कूल में एडमिशन है। इस तरह के दस्तावेज होने के बावजूद भी वे 65 परिवार मकान से वंचित हो गये।

उनको जब मकानों का आबंटन किया गया तो एक बहुत बड़ी कमी रही कि जो लोग वहां के निवासी नहीं थे, मैंने जब सर्वे करवाया तो एक परिवार के लोगों को ही 18 मकानों का आबंटन हुआ। यह बहुत बड़ी खामी रही। साथ-साथ कुछ ऐसे भी लोग थे, अभी 3 साल पहले जब उनका सर्वे हुआ तो पता लगा कि जिन बच्चों का जन्म नहीं हुआ था, जो अभी 2-2, 3-3 साल के हैं, उनके नाम से भी, मतलब अनुमान के नाम से मकानों का आबंटन कर दिया गया। कोटा के सभी अधिकारियों को इस बात का मालूम है। मेरा आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदय, धारीवालजी यहां पर विराजमान हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि एक बार दुबारा जांच करवाइए। पूरी फाइल डाकूमेंट्स सहित मैं आपको खुद अपने हाथों से सौपूंगी। उसमें क्या कमियां रहीं, उन्हें अगर मकान देते हैं तो जो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो सड़कों पर टेंट लगाकर रह रहे हैं, उन्हें अपना एक आशियाना मिलेगा। साथ ही, जो 15-15 लाख रुपये का उनके ऊपर कर्जा चढ़ गया, वे झाड़ू-पोंछे करने वाले हैं, वे बैंक के ब्याज सहित किश्त नहीं चुका पा रहे। सरकार कुछ ऐसा विचार करे कि उन्हें पी.एम. आवास योजना के अंतर्गत जो मकान मिलते हैं, उसमें एडजस्ट किया जाए ताकि उनका कर्जा चुके।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, हो गया, प्लीज।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

सिरोही में बलात्कार की पीड़िता का अनादरा पुलिस द्वारा देर से दर्ज मुकदमा

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अत्यंत व्यथित करने वाली आपराधिक घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। सिरोही जिले के अनादरा पुलिस थाने के अंतर्गत अनुसूचित जाति की एक युवती और उसका भाई दूसरे के खेत पर हिस्सेदारी पर काम करते थे। भाई किसी सामाजिक कार्य से पड़ोस के दूसरे गांव में गया हुआ था। जब वह वापस लौटा तो उसकी बहन खेत के अन्दर

(श्री संयम लोढ़ा)

बेसुध पड़ी मिली। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको ले करके अनादरा के हास्पिटल में गये तो वहां कम्पाउंडर मिला। कम्पाउंडर ने कहा कि नहीं नहीं, आगे ले जाओ। वहां से उसको आबू रोड के निजी चिकित्सालय में ले जा करके भर्ती कराया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और जहर देकर उसको मारने का प्रयास किया गया। वह लड़की आबूरोड के अस्पताल में 12 दिन भर्ती रही, उसको होश नहीं आया। वेंटिलेटर पर उसको कई दिन रखा गया और जहर निकालने के लिए उसके गले में पाइप फिट किया गया।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, सब अपनी-अपनी जगह पर बैठें। फिर वह परपज ही डिफीट हो जाता है। वह आदमी बोलता है, उसे सुनें। आप प्लीज, अपनी-अपनी जगह पर बैठें। माननीय मंत्रीजी, वह आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उनका ध्यान तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहें, प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि वह बच्ची वेंटिलेटर पर रही। सिरोही के एस.पी. साहब को डाक में एक गुमनाम पत्र मिला जिसमें यह लिखा गया कि इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और इसको जहर दिया गया है। रूटीन में डाक देखते-देखते वह डाक एस.पी. साहब के सामने आ गयी। यह भी हो सकता था कि उनके सामने वह डाक नहीं आती और सीधी ही कागजों में, फाइलों में चली जाती, लेकिन उसको देखने के बाद वह स्वयं वहां आबूरोड के अस्पताल में गये। लड़की होश में नहीं थी। उसके गले में पाइप लगा हुआ था, जिससे वह बोल भी नहीं सकती थी। उसके भाई ने इशारों से समझकर, जब उन्होंने इस गुमनाम पत्र के बारे में लड़की के भाई से कहा तो उसने पुष्टि की कि बलात्कार की घटना हुई है। अगले दिन डीवाई.एस.पी. (एस.सी., एस.टी.) वहां पर बयान लेने के लिए गये, मेडिकल बोर्ड बना, लड़की की मेडिकल जांच भी हुई और बाद में वह राड भी लड़की की हट गयी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक लड़के ने तो उसके साथ बलात्कार

(श्री संयम लोढ़ा)

किया और लड़की ने यह स्टेटमेंट दिये हैं कि दूसरे लड़के ने उसको जहर पिलाया। पुलिस ने एक लड़के को तो गिरफ्तार कर लिया और दूसरे को गिरफ्तार किया नहीं। मैं आपसे यही निवेदन करना चाह रहा हूं कि अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास, यह व्यवहार में हमें दिखाई नहीं पड़ता है। कमजोर तबके का आदमी इतना भयभीत है कि इतना जघन्य अपराध होने के बाद भी यह परिस्थिति सामने आयी। यह तो किसी अन्य व्यक्ति ने एस.पी. को वह गोपनीय चिट्ठी भेज दी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह विनती करना चाहता हूं कि उस पीड़ित परिवार ने निजी अस्पताल में इलाज करवाया है, उसका काफी खर्चा भी हुआ होगा। अभी तक सरकार की ओर से किसी तरह की उसको कोई सहायता नहीं दी गयी। एक अपराधी अभी भी भाग रहा है, जिसने हत्या करने का प्रयास किया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अब यह भी पता नहीं चल रहा है कि उस बच्ची के साथ कितने लोग बलात्कार में शामिल रहे हैं या हत्या में भी और लोग शामिल रहे हैं? इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह विनती करूंगा कि आप जयपुर से एक उच्चाधिकारी को भेजें जिससे इस तरह के जघन्य अपराध के मामले में सरकार की प्रतिबद्धता का एक संदेश जा सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री संजय शर्मा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

अलवर में हो रहा अवैध खनन

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका हृदय के अंतर्मन से बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का अलवर जिले में हो रहे अवैध खनन की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारा अलवर जिला अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है और यह अरावली पर्वतमालाएं जहां एक ओर पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी हैं वहीं दूसरी ओर अवैध खनन माफिया

(श्री संजय शर्मा)

इनको दिन-रात तोड़ने में, छीलने के काम में लगे हुए हैं। यदि मैं अवैध खनन माफियाओं के दुस्साहस की बात करूं तो प्रतिदिन लगभग ढाई सौ से तीन सौ डम्पर, ट्रैक्टर, ट्रालियों के माध्यम से पत्थर को तोड़कर अवैध खनन माफिया दिल्ली और हरियाणा भेजने का काम कर रहे हैं। चाहे तिजारा हो, चाहे रामगढ़ हो, चाहे टपूकड़ा हो, आस-पास का जो क्षेत्र है, उसके साथ-साथ इनका दुस्साहस इतना बढ़ गया कि अलवर शहर से लगता हुआ जटियाना गांव जो अलवर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में लगता है, उससे लगभग दो-तीन किलोमीटर दूर माइनिंग, खनिज विभाग का आफिस है, दो किलोमीटर दूर सदर थाना है, शिवाजी पार्क थाना है और वहां पर लगातार अवैध माइनिंग हो रही है, ब्लास्टिंग हो रही है और पहाड़ के पहाड़ गायब कर दिये गये हैं और पहाड़ गायब करने के बाद वहां पर प्लाटिंग का काम करना शुरू कर दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, फोरेस्ट सर्वे आफ इंडिया के सर्वे के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 225 खनन स्थल हैं अलवर में, अरावली की पहाड़ियों में लगभग 5 करोड़ 22 लाख मीट्रिक टन खनिज अवैध रूप से निकाला जा चुका है, जिसके कारण से राजस्थान सरकार के खनन विभाग को 430 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अवैध खनन माफियाओं का इतना दुस्साहस है कि डम्पर को इतनी तेज गति से चलाते हैं कि उसके सामने यदि कोई भी व्यक्ति कार, गाड़ी लेकर आ जाता है तो उसको कुचलने से भी वह डरते नहीं हैं।

अभी एन.जी.टी. ने माननीय जिला कलेक्टर महोदय को 19 मार्च, 2020 को जमानती वारंट से तलब किया है क्योंकि एस.डी.एम., रामगढ़ ने एक गलत एफिडेविट पेश करके एन.जी.टी. को गलत तथ्य पेश किये जिसके कारण उन्होंने जिला कलेक्टर को आगामी 19 मार्च, 2020 को जमानती वारंट के माध्यम से तलब किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करूंगा कि आप सरकार को यह निर्देशित करें कि अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ नकेल कसे और अरावली पर्वतमाला को बचाने का प्रयास सरकार करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शोभा चौहान।

जवाई जल परियोजना का पुनरुद्धार कर पानी की समस्या का समाधान

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपका ध्यान मेरी सोजत विधान सभा क्षेत्र के पानी की समस्या की ओर दिलाना चाहती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के इतने लंबे अरसे बाद भी आज तक शुद्ध पेयजल के लिए वहां की जनता तरस रही है। जवाई बांध से पानी की सप्लाई तो होती है, लेकिन वह 15 दिन में एक बार होती है और इंसान को जीवित रहने के लिए कम से कम और चीज मिले या नहीं मिले, लेकिन स्वच्छ जल तो जरूरी है। सोजत की जनता शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं होने के कारण वहां के अंतिम छोर की जो ग्राम पंचायतें हैं, राजोला कला, चौपड़ा, दूरासती, रेपड़ावास, सरदारसमंद, खारियानी, सूरायता इन पंचायतों के लोग महीने में एक बार ही जवाई का पानी पी पाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना गंदा और बदबूदार नाड़ी और तालाबों का पानी होता है, उसी पानी को छानकर महिलाएं अपने सिर पर लेकर आती हैं और वहां पर बच्चों के लिए स्कूल में भी पानी की समस्या है। मैं यह कहती हूं कि इंसानों के लिए भी इतनी मुश्किल है तो फिर जानवरों और पक्षियों का वहां पर बच पाना मुश्किल है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं, पहले भी मैंने इस सरकार को पिछली बार अवगत कराया था तो अधिकारियों ने वहां पर बहाना बनाया कि पाइप लाइन खराब है या सप्लाई नहीं हो रही है, इस तरह का बहाना करके टाल देते हैं और समस्या अभी जस की तस बनी हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि इस समस्या का समाधान दांतीवाड़ा योजना को चौपड़ा फिल्टर से जोड़ा जाए ताकि वहां की समस्या का समाधान हो सके और पचास हजार की जनसंख्या को शुद्ध पानी मिल सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अमृतलाल मीणा।

सलूम्बर में स्वीकृत पेवर सड़कों का कार्य

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में 2018 में स्वीकृत करीब सौ से अधिक पेवर की सड़कें हैं, उनका अभी तक डामरीकरण नहीं हो सका है जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी है। लांबा पीपला से सेमारी रजौर तक का, खाखरिया सम्पर्क सड़क, सम्पर्क सड़क थाना से नठारा बड़ा चौराहा, सड़क चांवण से बंडोली, पलोदड़ा से जावर माइन्स, पाड़ला, चांवड़ से ससेई दर्जनपुरा पाल से टिकमवाबसी, सराड़ा, झाड़ोल से डिंगरी, झाड़ोल से वेजपुर, झाडोल से घरमाला घाटी, कंतोड़ा से वीरपुरा, बस्सी से कंतोड़ा, खैराड़ से करावली, लोधा से ईड़ाना, गिंगला से उथरदा, अदवास से वगूरूआ, अदवास जावद से सेमाल, मैथूडी और कालीमगरी से गामड़ापाल, मल्लाड़ा से गोपालपुर की सड़क, घुडियोवाड़ा की सड़क, खैरुआ की सड़क, पलोदड़ा, पलूना की सड़क, ओड़ा से बगरूवा, ईटाली, सेमारी से रठौड़ा और सलूम्बर से बेडावल यह बहुत लम्बी सड़क है, करीबन ये 80-90 सड़कें हैं, लेकिन ऐसी जो सात सड़कें स्वीकृत हैं वर्ष 2013-14 में वन क्षेत्र में, लेकिन उनमें अभी तक भी कार्य शुरू नहीं हो पाया है। जो नठारा बड़ा चौराहा से, गोठापानी, मंडाज से कलात, मंडाज से राताखेत और सराड़ा बलुआ रोड से हरघाटा यह सड़कें स्वीकृत हुई हैं इनको जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए और उस क्षेत्र में सड़कों का पेवरीकरण करने के लिए आदेश देकर सड़कों का निर्माण कराएं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

प्रदेश में लगातार बढ़ रही घरेलू गैस सिलेंडर विस्फोट की घटनाएं

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अत्यन्त लोमहर्षक घटना की तरफ दिलाना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर में आस्था का केन्द्र ताड़केश्वर मंदिर है और कल अल-सुबह ताड़केश्वर मंदिर में ज्यों ही वहां के पुजारी परिवार श्री गोविंद नारायण की पत्नी ने अपने गैस सिलेंडर को चाय बनाने के लिए ऑन किया तो वह एक आग के गोले में तब्दील हो गया और उसके बाद दो व्यक्तियों की वहीं पर मृत्यु हो गयी और दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पहली घटना नहीं है। इस राजधानी के अंदर गैस सिलेंडर से धमाका होकर काल-कवलित होने वाली यह तीसरी घटना है। इसी 13 जनवरी को क्रांतिनगर इलाके में, 24 जनवरी को जवाहर नगर में, 18 जनवरी को पोलोविक्ट्री में, यही नहीं यह सिलसिला पूरे राजस्थान में चल रहा है।

20 फरवरी को सीकर के शेखपुरा मोहल्ले के अंदर एक गैस सिलेण्डर के फटने से सात लोग काल-कवलित हुए। 20 फरवरी को ही मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र के अंदर वार्ड नंबर 55 के अंदर एक पूरा घर उड़ गया और एक महिला की मृत्यु हो गयी। भरतपुर के अंदर एक कार, जिसके अंदर अवैध रूप से सिलेण्डर लगा रखा था, वह बीच बाजार में फट गयी। मैं समझता हूं कि औसतन हम देखें तो एक वर्ष के अंदर ऐसी 200 घटनाएं हो रही हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उज्जवला योजना आयी। राजस्थान के अंदर इस उज्जवला योजना के कारण आज एक करोड़ दो लाख परिवार इस गैस कनेक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं और सुरक्षा के जो मापदण्ड हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, गैस सिलेण्डर रूल्स बने हुए हैं 2016 के, उसमें जो गाइडलाइन जारी की है सुरक्षा के मापदण्ड के अनुसार, उसमें जब गैस का कनेक्शन और सिलेण्डर कोई लेकर आता है तो उस कंपनी के प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वह उसको चूल्हे से जोड़कर जाए, वह रेगुलेटर सहित उस चूल्हे की जांच करे, परंतु आज तक जांच नहीं होती।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही जब यह प्लांट, जिसमें यह गैस सिलेण्डर भरते हैं, उसमें भी गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक सिलेण्डर का सर्टिफिकेशन एक अधिकारी करता है, जिसकी देखरेख में ये भरे जाते हैं परंतु आप देख रहे हैं, आज किसी मोहल्ले में चले जाओ तो एक कोने में गैस सिलेण्डर का अवैध व्यापार करते हुए मिलेंगे और अध्यक्षजी, यही नहीं, राजस्थान पत्रिका ने कई बार चेताया 'जनता की जान हथेली पर है, घरेलू गैस सिलेण्डर की गुणवत्ता मौत बन सकती है' और जो गैस कनेक्शन की हैल्पलाइन है, इसकी जिम्मेदारी है कि जब कभी गैस के लीकेज की सूचना दी जाती है, प्रतिदिन 400 सूचनाएं तो राजधानी में दी जाती हैं। कभी भी एक बार भी टेलीफोन उठाने का काम नहीं है। इसका कारण यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक 'The Explosive Substances Act, 1908' का, उसके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सैक्शन-3 में punishment for causing explosion likely to endanger life or property, इसका इस्तेमाल कभी पुलिस करती ही नहीं है और इसके साथ ही जो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट बना हुआ है, उसके सैक्शन-5 में कलेक्टर की जिम्मेवारी है कि वह वैरिफिकेशन करे और वैरिफिकेशन के पश्चात् मुआवजा उस कंपनी से दिलवाए। इसलिए मेरी मांग है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से चाहूंगा कि आज एक बार इन गैस कंपनियों के साथ मीटिंग करो। एक दिन की बात नहीं है। आज कितनी बड़ी संख्या के अंदर अवैध रूप से गैस के सिलेण्डर को गाड़ी में लगाकर लोग यात्रा कर रहे हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

भरतपुर की घटना आपको ध्यान में होगी। बीच बाजार में मेरी खुद के विधान सभा क्षेत्र में बूटिया रोड पर एक गैस के कनेक्शन से जुड़ी हुई गाड़ी चलती हुई जा रही थी, उसमें अचानक विस्फोट हो गया। यह घटना सामान्य नहीं है। आज हरेक आदमी डरा हुआ है। पत्रिका एडिटोरियल लिख रहा है और सरकार ने एक बार भी इस गैस की कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक नहीं की। आप सुरक्षा के लिए इंतजाम करो और यह जो एक्सप्लोसिव एक्ट और पब्लिक लायबिलिटीज एक्ट है, इसके अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही करो।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। 131, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: नोट अलाउड। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल के सेवानिवृत्त कार्मिकों को पेंशन परिलाभ

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सुप्रीम कोर्ट तक निर्णय हो जाने के बाद भी पेंशन लाभ नहीं दिये जाने के संबंध में ध्यान आकर्षित करूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल के कर्मचारियों को पेंशन की योजना का लाभ देने के उद्देश्य से दिनांक 01.04.1994 को भविष्य निधि योजना के स्थान पर कर्मचारी पेंशन विनियम, 1994 लागू करने का निर्णय लिया, जिसकी सरकार ने 28.05.1994 को स्वीकृति दी। 19.12.1994 को कर्मचारियों से विकल्प मांगे गये और जो अंशदान जमा था, उसको वापस मांगा गया। 27.02.1996 को राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल के निष्पादक मण्डल ने यह निर्णय लिया कि यह भविष्य निधि योजना ठीक है, यह कर्मचारियों के हित में है या पेंशन निधि योजना। उसके बाद में 2014 तक किसी ने कुछ भी, न कर्मचारियों ने मांग की और न ही सरकार ने निर्णय लिया। 2014 में ये लोग कोर्ट में गये और कोर्ट में जाने के बाद में 29.11.2017 को हाई कोर्ट का फैसला कर्मचारियों के हित में आया। उसके बाद में सरकार ने निर्णय लिया कि हमें डी.बी. में जाना है, वह डी.बी. में गये और 12.04.2018 को इनकी डी.बी. में भी खारिज हो गयी, मण्डल की तरफ से जो डी.बी. में अपील की गयी थी। फिर उसके बाद में एस.एल.पी. का निर्णय लिया गया सरकार के द्वारा। एस.एल.पी. भी 03.01.2019 को खारिज हो गयी। फिर फाइनेंस में जब लोग गये तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा, वित्त विभाग ने कहा कि इसकी आप रिव्यू कीजिए और रिव्यू में गये तो 16.10.2019 को वह रिव्यू भी खारिज हो गयी। रिव्यू खारिज होने के बाद में प्रक्रिया चली और 08 जनवरी, 2020 को वित्त विभाग ने इस आशय की शर्त के साथ में स्वीकृति दी कि जो पैसा इनके पेंशन में दिया जाएगा, वह पाठ्यपुस्तक मण्डल वहन करेगा, सरकार वहन नहीं करेगी। चूंकि 08.01.2020 के बाद में यह प्रक्रिया चल रही है और फाइल प्रशासनिक आधार पर निर्णय करने के उपरान्त हम मण्डल की ई.सी. और जे.सी. में निर्णय लेंगे और इन कर्मचारियों की बीच में कुछ दिन तक वह पत्रावली भी नहीं मिली थी, जिसमें इन्होंने विकल्प दिये थे। उसको भी एक कमेटी बनाकर जब तय किया गया कि यह कमेटी जिम्मेदारी तय करेगी, तब यह पत्रावली मिली है। यह एक-डेढ़ महीने का जो समय लगा है, वह प्रक्रिया में लगा है। अब चूंकि ई.सी. और जे.सी. की मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद में निर्णय लेकर एक सेल बनेगा कि पेंशन के इन कर्मचारियों को देने के लिए जो सेवानिवृत्त पेंशन विभाग में कर्मचारी थे, हम लोग माननीय मुख्य मंत्रीजी से

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सेवानिवृत्त कर्मचारियों की इस सेल में नियुक्ति करवाकर उसके बाद इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाएगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उन पेंशनरों के बारे में सोचता हूं कि जितना न्यायालय में पाठ्य पुस्तक मण्डल जा सकता था, हाई कोर्ट में गये, फिर हाई कोर्ट की डबल बैंच में गये, फिर सुप्रीम कोर्ट में गये, फिर रिव्यू पिटीशन में गये और उसके बाद हरेक में निर्णय उनके पक्ष में हुआ। उसके बाद यह फाइल फाइनेंस में गयी। फाइनेंस ने भी इसकी स्वीकृति दे दी। उसके बाद यह था कि इनके पास 50 करोड़ का फण्ड इस बारे में पड़ा है जिससे यह मुश्किल से 145 या 147 लोग होंगे, लेकिन आप विचार करो कि यह 2014-15 से जो रिटायर हो चुका, 2020 तक अगर वह मुकदमा ही लड़ता रहे तो उसके बाल-बच्चे गुजारा कैसे करेंगे? मैं सोचता हूं और कोई दूसरा प्रश्न नहीं है, क्योंकि सारे निर्णय उनके पक्ष में हुए हैं सरकार कितना जल्दी से जल्दी, जो फण्ड उनके पास पडा है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल ने अपनी सहमति दी हुई है, फाइनेंस ने फाइल क्लियर कर दी है कि पाठ्य पुस्तक मण्डल अपने फण्ड से दे तो सरकार अब इन पेंशनरों को कब तक, क्योंकि फाइल बिलकुल कमप्लीट बनी हुई पड़ी है पिछले दो-ढाई महीने से, कब तक उनको पेंशन का लाभ दे देंगे, इतना ही जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता, प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से उनको पेंशन मिलनी चाहिए जब सरकारों का फैसला है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आप 13.12.1993 से लेकर 30.11.1998 तक रहे और जब ई.सी. हुई तो उसमें निर्णय लिया गया कि यह विस्तार से देखेंगे कि कौन सी योजना कर्मचारियों के हित में है और उसकी जे.सी. में आपने उसका अनुमोदन किया और उसके बाद में जो हाई कोर्ट में गये, डी.बी. में गये, एस.एल.पी. में गये, जहां भी गये, वह वासुदेव देवनानी जी 26.10.2014 से लेकर 11.12.2018 तक थे तो जितना कोर्टों में विलम्ब हुआ या अनिर्णय की स्थिति रही, वह आपके समय में रही है। ज्यों ही एस.एल.पी. रिव्यू पिटीशन खारिज हुई हमारी, उसके बाद में हमने तत्काल निर्णय ले लिया और 08 जनवरी को फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस शर्त के साथ में कि पैसे मण्डल भरेगा,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

स्वीकृति दे दी और हमने भी सहमति दे दी। यह सही है कि इनका निर्णय जब 1994 में हो गया तो यह इतने साल तक क्यों चला? लेकिन उस वक्त अनिर्णय की स्थिति थी या पैसे नहीं थे, दोनों में से जो भी स्थिति थी।

श्री अध्यक्ष: अब तो आप काम की बात बताओ कि जो पाठ्य पुस्तक मण्डल के पास पैसा उपलब्ध है, वह रिलीज करेंगे?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): शीघ्र इस प्रक्रिया को पूरा करके इन कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। याचिका का उपस्थापन। श्री कैलाशचन्द्र मीणा।

याचिका

गढ़ी में माही की नहरों की सफाई एवं क्षतिग्रस्त नहरों का निर्माण

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में माही की नहरों की सफाई एवं क्षतिग्रस्त नहरों का निर्माण करवाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अमीन खां।

बाड़मेर के गांव देतानी से गागरिया स्टेशन तक की सड़क को ग्रीफ को देना

श्री अमीन खां (शिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बाड़मेर जिले के गांव देतानी से गागरिया स्टेशन तक की सड़क को ग्रीफ को दिये जाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री रामस्वरूप लाम्बा।

अजमेर के ग्राम मांगलियावास को उप-तहसील का दर्जा

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अजमेर जिले के ग्राम मांगलियावास को उप-तहसील बनाये जाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: आय-व्ययक पर चर्चा, माननीय मंत्री जी। सारी, एक मिनट रुक जाओ। श्री गोपी चन्द मीणा।

जहाजपुर के एम.डी.आर. 56 रोपा से क्रोटाज मार्ग की मरम्मत

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की सड़क एम.डी.आर. 56 रोपा से क्रोटाज मार्ग के पूर्णतया क्षतिग्रस्त होने से आये दिन हो रही दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, यह रखवा देते हैं फिर बोल देना।

माननीय मंत्री जी मांगों पर प्रस्ताव रखेंगे। श्री अशोक, युवा मामले एवं खेल मंत्री।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति की प्रस्तुति

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 330,98,13,71,000 (अक्षरे तीन सौ तीस अरब अठानवे करोड़ तेरह लाख इकहत्तर हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 24 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अध्यक्ष: श्री कल्ला साहब।

मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवाएं की प्रस्तुति

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 62,48,85,000 (अक्षरे बासठ करोड़ अड़तालीस लाख पिचासी हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 11 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री छगनसिंह और मोहन राम चौधरी, जो पाइंट आफ इंफोर्मेशन है, सम्बन्धित मंत्री को जाकर अपनी बात बता दें, हाउस में चर्चा नहीं। श्री शंकर सिंह जी रावत, बताएं।

सूचना

ब्यावर विधायक को जान से मारने की धमकी

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा विधान सभा में सवाल पूछने पर जान से मारने की धमकी के सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। साहब, आप थोड़ा समय भी देवें।

मैं शंकर सिंह रावत, सम्राट पृथ्वीराज चौहान का वंशज हूं, जो कि पूरे राजस्थान में रावत समाज से जाना जाता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपनी काम की बात बोलो, कहां पर जा रहे हो? आप विधायक हो, अपनी बात बोलो, क्या इश्यू है?

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सर, वो ही बता रहा हूं, 4 लाइन का है, यह ज्यादा नहीं है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं ऐसे नहीं। माननीय कटारिया जी...

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): साहब, उसमें ये लिखा है ये सवाल उठाने पर, जो रूपनगर गांव की घटना हुई है उसको मैंने यहां चर्चा की थी सरकार के सामने, दूसरा कोई आरोप नहीं था, कोई प्रकार की बात नहीं, जो क्षेत्र में घटना घट रही है उससे सम्बन्धित सवाल था।

उसमें निवेदन है कि हम सब सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, पूरा समाज इस क्षेत्र में रहता है। वहां पर कई गोत्र हैं, अलग-अलग जाति में जो रावत समाज के हैं, चीता, मेहरात, काठात, घोड़ात, इस प्रकार सैकड़ों गोत्र हैं वो सब रावत समाज से जाने जाते हैं। उसमें एक करण सिंह जी काठात जो काठा जी करणा जी की डांग से जाना जाता है, करणा जी डांग में रूपनगर भी शामिल है, रूपनगर के लोग सभी के काठात भाई हैं, उसमें कोई मुसलमान नहीं है, जिसका इतिहास में जागा की पोथी में आज भी विवरण सुनाया जाता है। जिले के 36 जात के, समाज के लोग आपस में प्रेम से रहते हैं, हिन्दू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई-भाई, उसमें इन्होंने जो जहर घोलने का काम किया है, प्रशासन के द्वारा रूपनगर में इज्तिमा की परमिशन देकर मिठास में जहर घोला है जिसमें मुस्लिम भाई भी रहते हैं ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने प्रश्न किया, सीधा माननीय सदस्य, आप मुझ से मिले, माननीय सदस्य, आप मुझ से चैंबर में मिले हैं उस बात को बोलें आप। आप किस पर जा रहे हैं?

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): उसमें इस प्रकार की मैंने सरकार को सूचना दी थी, हुकुम। उस सूचना में मैंने ऐसा कोई प्रकार का कार्य नहीं किया था, जिसकी सूचना देने पर मुझे वापस धमकी मिली है। इसमें इमरान नाम के लड़के ने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर फर्जी आई.डी. से या खुद की आई.डी. है, उसमें भाई लोगों शंकर सिंह रावत पंगा करे, बोले इज्तेमा से उसकी कोई आपत्ति है तो उसकी मां का नाम लेकर जो गंदी गाली दी है उसको मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, अगर आये तो दिल्ली जैसे चुप रहना, हड्डियों को तोड़ देना सालों को, हम भी मोहम्मदी हैं, हिन्दू जिसका सपोर्ट करे, उन्होंने ऐसा फेसबुक पर डाला है, उससे मुझे बड़ी आत्मग्लानि हुई है।

(12.46 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

हमारे समाज में भी सभी जाति के लोग रहते हैं, हम सब आपस में भाईचारे से रहते हैं। इसकी सूचना मैंने 28 फरवरी को विधान सभा में सरकार के सामने दी और उसके फेसबुक पर मुझे मारने के लिए धमकी दी है।

सभापति महोदय, बहुत बड़ा समाज है, एक शंकर सिंह को मारेंगे, लाखों शंकर सिंह हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि दोषियों पर कार्यवाही होनी चाहिए और प्रकरण की सी.बी.आई. जांच होनी चाहिए।

इसी प्रकार एक प्रकरण जो जवाजा थाने में दर्ज हुआ है उसके ऊपर भी फेसबुक आई.डी. किसके नाम की है और फर्जी, जिसको एडमिन है उसको पुलिस पकड़ नहीं रही है और दूसरे की फार्मेलिटी करके 151 में ही उसको गिरफ्तार करके छोड़ा जा रहा है।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें, नेता महोदय बोलेंगे।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि निश्चित तौर पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, विषय यह था कि इन्होंने इस बात की सूचना इस सदन के माध्यम से दी थी कि वहां इस प्रकार की कोई एक्टिविटीज हो रही है जहां धर्मांतरण की संभावना है, इस बात को उन्होंने हाउस में जानकारी के माध्यम से दी। उस बात के आधार पर उनको जो धमकी भरा एसएमएस आया इनके ही मोबाइल पर, मैं सोचता

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हूं यह सदन की अवहेलना है, अपमान है और इसलिए माननीय सदस्य इसको प्रिविलेज मोशन के माध्यम से लेकर के आएं ताकि उन सब लोगों के इस विधान सभा में ट्रायल हो सके, जिन लोगों ने इस प्रकार की धमकी दी और जो हमको अधिकार प्राप्त है विधान सभा के फ्लोर का, उसका जो दुरुपयोग उसने किया है, उसको यह एहसास हो कि विधान सभा में कोई विषय उठाने के बाद किसी को भी इस प्रकार की धमकी दी नहीं जा सकती है।

मैं माननीय सदस्य को भी कहना चाहूंगा कि एक प्रिविलेज मोशन बना करके इस विषय को हाउस में रखें ताकि प्रिविलेज कमेटी इस बारे में फैसला करेगी।

श्री सभापति: मैं यह निर्देश देता हूं कि सरकार इस मामले को संज्ञान में ले और इसकी जांच कराये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय।

श्री सभापति: विराजिए आप। इसकी जांच करायें और सदन में बताएं। डा. जितेंद्र सिंह।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24 व 11 पर विचार

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है जो सदन में मैं समझता हूं कि स्पेसिफिकली आनरेबल स्पीकर साहब ने गेम्स और साइंस के जो हमारे अलग से उन्होंने बोलने का मौका दिया है।

माननीय सभापति महोदय, almighty has given grey matter equal to everybody. दिमाग में, सभापति महोदय, ग्रे और व्हाइट मैटर होता है, grey matter denotes the intelligence तो भगवान ने सबको ग्रे मैटर बराबर दिया है लेकिन जिस तरह से हमारे टीचर, कोच ये आएंगे, तो निश्चित रूप से बच्चे का एक जो स्वरूप होता है वो मां से ही शुरू होता है then it goes to teachers and then coaches.

सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि गेम्स, यह आवश्यक क्यों है। सभापति महोदय, हमारा बचपन खो गया, हमने हमारे बच्चों का खेलना बंद कर दिया। घर में एक-एक बच्चे होते हैं, उसके ऊपर सब प्रेशर डालते हैं कि

(श्री जितेन्द्र सिंह)

डाक्टर बन, इंजीनियर बन, आईआईटीयन बन। सभापति महोदय, मानसिक तनाव में बड़ी खतरनाक स्थिति है, कोई बच्चा फांसी से लटक रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं शोर्ट में बताना चाहूंगा। कोटा में एक मेरे बैचमेट हैं वो साइकेट्रिक्ट हैं डा. एम.एल. अग्रवाल, उन्होंने अपना नंबर दे रखा है कि कोई मानसिक तनाव में आये तो इस नंबर पर फोन करें। माननीय सभापति महोदय, उनके पास एक बच्चे का मोबाइल आया कि मैं चंबल ब्रिज पर खड़ा हूं और मैं नीचे जम्प कर रहा हूं। उन्होंने पूछा क्यों, कि मेरे मां-बाप चाहते हैं मैं डाक्टर बनूं, मैं पी.एम.टी. में फेल हो गया। अब मेरे सामने सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कन्विंस करते-करते सिविल ड्रैस में पहुंचकर उसको बचाया।

अब बच्चों का डायवर्जन इस मोबाइल से दूर करना पड़ेगा। छोटे-छोटे बच्चे आंख गड़ाये बैठे हैं, खेल सब भूल गये, ग्रामीण खेल अंधकार में चले गये। सवा सौ करोड़ के भारत में हम लोग एक गोल्ड मैडल को तरस गये। अफ्रीकन कंट्रीज, छोटे-छोटे यूरोपियन कंट्रीज हमसे कहीं ऊपर हैं मैडल टैली में और अमेरिका, चाइना और रशिया का तो कोई मुकाबला ही नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं रशिया गया था और मुझे वहां 3 महीने रहने का मौका मिला, मेरे दामाद वहां एम्बेसी में उच्च अधिकारी थे। मैंने वहां की मेडिकल यूनिवर्सिटी, उनकी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी देखी, पांच-पांच साल के बच्चों को वो टेकअप करते हैं कि इसको जिमनास्टिक में जाना चाहिए, उसको बास्केटबाल में जाना चाहिए, वो पहले से सलेक्ट कर लेते हैं।

ऐसा नहीं है कि राजस्थान में प्रतिभाएं नहीं हैं। हमारे खुद के हाउस में कृष्णा पूनियॉ जी बैठी हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में डिस्कस थ्रो में गोल्ड मैडल लिया, वर्ल्ड नंबर 6 हैं। हमारे दो माननीय सदस्य हमारे पीछे बैठे हैं कैलाश त्रिवेदी जी और हंगामी लाल जी, जो जिम्मी जॉर्ज इंडिया के वालीबाल के कैप्टन थे, उस टीम के सदस्य हैं, मैं समझता हूं कि मेजें थपथपा कर इनका स्वागत करना चाहिए कि असेंबली में हमारे ऐसी-ऐसी प्रतिभा भी आई हैं।

सभापति महोदय, अब ये आवश्यक है, पांच करोड़ रुपये का बजट खेल के लिए सफिशिएंट नहीं है। एक तरफ तो हम चाहते हैं कि हमारा शरीर

(श्री जितेन्द्र सिंह)

स्वस्थ बने, स्वस्थ शरीर तो जब बनेगा, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने नो बैग डे रखा, उस दिन कोई पढ़ाई नहीं होगी, गेम्स होंगे और उस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मेरा तो आपसे ये भी आग्रह है कि गेम्स के मार्क्स भी उनके कक्षा के अंदर जुड़ने चाहिए। ये नितांत आवश्यकता है।

अभी शिक्षा मंत्री जी तो नहीं हैं, लेकिन मेरा स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब से कहना है कि आप खुद पोलो के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। हमारे यहां हर पंचायत में खेल मैदान होना चाहिए। हर स्कूल के पास, बच्चों के पास खेलने के साधन होने चाहिए। सरकार के पास तो पैसा नहीं है। 5 करोड़ का बजट है। सरकार बहुत लंबा-चौड़ा खर्च नहीं कर सकती। स्पोर्ट्स के लिए हरियाणा, पंजाब की तर्ज पर 2 परसेंट रिजर्वेशन दिया है। इस रिजर्वेशन से हमारे बच्चे इंस्पायर होंगे।

सभापति महोदय, मैं तो हमेशा यह कहता हूं कि क्रिकेट का बुखार छोड़ो। क्रिकेट में दिल्ली, बंबई और बंगलौर वाले नंबर नहीं आने देंगे। नेशनल गेम्स में जो हमारे ग्रामीण गेम्स हैं, कबड्डी में इंडिया वर्ल्ड चैंपियन है। हमें कबड्डी में गोल्ड मैडल मिलता है। हम तरस जाते हैं। हाकी में पता नहीं कहां चले गए।

सभापति महोदय, अब यह आवश्यक है कि प्ले ग्राउंड्स के लिए अगर सरकार नहीं दे सकती, सारे विधायक यहां बैठे हैं, मैंने स्वयं मेरी 41 पंचायतों में मेरे विधायक कोष से 5-5 लाख रुपया दिया है। 25 स्कूलों में जाकर आया हूं। उनमें 5 लाख से फर्स्ट राउंड में ग्राउंड का समतलीकरण होगा, ट्रैक बनेगा और गेम्स के सारे उपकरण वहां पर मौजूद रहेंगे। ग्रामीण प्रतिभाएं एक से बढ़कर एक हैं। ग्रामीण प्रतिभाओं की कमी नहीं है।

सभापति महोदय, हमारी जो इंडिया की बास्केटबाल टीम थी, उसके कैप्टन राधेश्याम, वह सीकर के थे। सीकर के ही इरफान अली और कितने-कितने तगड़े बास्केटबाल के प्लेयर हुआ करते थे। वालीबाल में जाखड़ और अन्य हैं, वह इंडिया टीम के कैप्टन रहे थे, निश्चित रूप से हमारे पास में प्रतिभाएं हैं।

सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कल्पना ही नहीं कर सकते। मैं 2013 में मंत्री था और सवाई मानसिंह स्टेडियम में एथलेटिक्स के

(श्री जितेन्द्र सिंह)

गेम्स हो रहे थे। एक बच्ची 100 मीटर रेस में फर्स्ट, 110 हर्डल में फर्स्ट और उसके बाद मैराथन में फर्स्ट आई। जब मैं उसको गोल्ड मैडल देने आया तो मैंने कहा कि तुम तो खेतड़ी की हो। मैंने उससे कहा कि यह हर्डल कहां से सीखी? लड़की का कहना था कि मैं तो कूंचों पर कूद-कूद कर सीखी हूं। आप कल्पना करिए, रोशन कुमारी के 51 गोल्ड मैडल हैं कक्षा 9 से लेकर के एम.ए. तक।

सभापति महोदय, मेरी विधान सभा की टावरिंग लड़की 5 फुट 11 इंच लंबी, वह शाट पुट में नेशनल गोल्ड मैडलिस्ट है। जब उसके पिताजी का देहांत हुआ तो मैं बैठने के लिए गया तो मेरी आंख में आंसू आ गए। उस खिलाड़ी के पास एक टूटा सा छप्पर था और एक कमरे का मकान था। मैंने कहा बेटी, यह मकान है तुम्हारा? खिलाड़ियों का यह हश्र होगा क्या? मेरे से जो मदद हुई, की। इन सबको आगे लाना पड़ेगा।

सभापति महोदय, गेम्स के अंदर, catch them young, रोमानिया, रशिया, चाइना में 5-5 साल के बच्चों को जिम्नास्टिक, वालीबाल और बास्केटबाल में ट्रेंड करते हैं। इस तरह से हम सबको करना पड़ेगा। यह आउट आफ टर्म जो अपाइंटमेंट है एथलेटिक्स का, जो डायरेक्ट गोल्ड मैडल नेशनल लेवल पर लायेगा, वह पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनेगा। यह माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो 2 घोषणाएं की हैं, यह गेम्स के क्षेत्र में बहुत बड़ी चीज है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने झुंझुनूं को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दी है। राजस्थान के बहुत टाप महाराजा करणी सिंह जी, शूटिंग के अंदर रहे। बीकानेर के अंदर उन्होंने शूटिंग रेंज बनाई। उससे हमारे लोगों में उत्साह रहा। हमारे राज्यवर्धन सिंह जी ओलंपिक में सिल्वर मैडलिस्ट रहे हैं। राजस्थान के अपूर्वी चंदेला, सुश्री अवनी लेखरा, दिव्यांश सिंह अच्छे खिलाड़ी हैं।

सभापति महोदय, हमारे पैरा ओलंपिक हैं उनमें सुंदर गुर्जर है। वह मेरी विधान सभा क्षेत्र का एक लड़का है। इसका हाथ amputated है। पैरा ओलंपिक में जेवेलिन थ्रो में उसका सलेक्शन हुआ है। देवेन्द्र झाझड़िया हैं। इस तरह के आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स तो हैं ही। अदरवाइज नंबर आफ मैराथन खेलने वाले हैं। हम राजस्थान के अंदर अगर टीम बनाएं तो इंडिया की टीम के अंदर गोपाल सैनी हैं। कबड्डी की आधी टीम राजस्थान की है, जो कि नेशनल गेम्स खेलती है।

(श्री जितेन्द्र सिंह)

सभापति महोदय, यह बहुत बड़ा कदम है लेकिन इसको प्रमोट करने के लिए सरकार के साथ माननीय विधायकों को भी लगना पड़ेगा। मैंने मेरे विधायक कोष से एक करोड़ रुपया स्कूलों के ग्राउंड तथा स्पोर्ट्स के लिए दे दिया है।

सभापति महोदय, 1966 में वर्ल्ड कप फुटबाल हो रहा था। ब्राजील वर्ल्ड चैंपियन था। पुर्तगाल को कोई जानता नहीं था। पुर्तगाल ने ब्राजील को हराया। सेमी फाइनल में उनका मुकाबला कोरिया से हो रहा था। कोरिया से वह तीन गोल से हार रहे थे। लेकिन उनका एक खिलाड़ी नीग्रो था यूसेबियो। उसने लगातार 4 गोल किए। जब वहां का सबसे बड़ा ब्रिज बना जैसा कि अपने यहां हावड़ा ब्रिज है। जब वह ब्रिज बना तो सालासर आए, उन्होंने सोचा कि यह मेरे नाम से ही उद्घाटन हो रहा होगा। जब उसका उन्होंने फीता काटा तो bridge was named for Eusebio. मेरा आपसे कहना है कि यह आउटस्टैंडिंग पर्सनेलिटीज हैं।

मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, मेजर बाबूसिंह स्टेडियम जिन्होंने ओलंपिक में कंट्री का नाम रोशन किया है। इस तरह से यह आउटस्टैंडिंग पर्सनेलिटीज हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की। यह जब नेशनल गेम्स में आते हैं तो जो स्टेडियम या खेल मैदान बनें, यह वास्तव में उन बच्चों के नाम से होने चाहिए ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिले। अगर वह हमारे नेताओं के नाम से या अन्य के नाम से बनेंगे तो उसमें वह बात नहीं हो पाएगी।

सभापति महोदय, मेरा अपने साथियों को भी नम्र निवेदन है कि एटलिस्ट अपने विधायक कोष का हिस्सा दें। इससे यंग जनरेशन निश्चित रूप से आपको याद करेगी। It will be a political help and it is the help of government also. मेरा आग्रह है कि इसको निश्चित रूप से करें।

सभापति महोदय, नैक्स्ट जो इंपोर्टेंट चीज है, वह है साइंस। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे जिले में मेरा विधान सभा क्षेत्र शिक्षा में सबसे बैकवर्ड था। कालेज कहीं भी नहीं था। मैं कालेज का जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं दूसरा जिक्र कर रहा हूं। मैं हायर एजुकेशन में आया तो वहां पर कालेज खुला। बड़े सेठ, साहूकार हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे कंट्री में बाल वैज्ञानिकों में राजस्थान नंबर वन पर आया है। पूरे कंट्री में झुंझुनूं जिला नंबर वन पर आया है। झुंझुनूं में मेरे विधान सभा क्षेत्र के 400 बाल वैज्ञानिक

(श्री जितेन्द्र सिंह)

सलेक्ट हुए हैं जहां शिक्षा का कोई लेना-देना नहीं था। CEERI-Pilani ने बड़े-बड़े वैज्ञानिक दिए हैं।

सभापति महोदय, एक आपके रिलेटिव हैं डा. सुरेन्द्र पाल, आप तो जानते होंगे। BITS, Pilani से पास आउट हैं। जितने भी सैटेलाइट जाते हैं, आर्य भट्ट से लेकर के लास्ट तक, उन सबका ग्राउंड कंट्रोल हैड, बंगलौर के डा. सुरेन्द्र पाल हैं, जो साधारण परिवार से हैं। एक हैं डा. रामरतन, जितना आपटिक्स बना है आर्य भट्ट से लेकर, सब उनके बनाए हुए हैं। वह सारे के सारे झुंझुनूं शेखावाटी के हैं।

अभी हाल ही में मेरे पास एक लड़की आई। वह वैज्ञानिक थी। वह इसरो में है। ह्यूस्टन से फोन आया। मेरे दामाद ह्यूस्टन में हैं। वह सेक्रेटरी वन हैं। वह बोले कि एक बच्ची बात करना चाहती है। मैंने बात की। अमेरिका की एक साइंस कंसर्न ने, एक बड़ी फर्म ने उस लड़की को अवार्ड किया है। उसका एक करोड़ रुपया पैकेज है। वह बच्ची बिलकुल गरीब परिवार से है। हमें साइंस की आवश्यकता है।

अभी जो बच्चों के साइंस के सब्जेक्ट हैं, कम्प्यूटर साइंस है, इन सबको हमें डवलप करना पड़ेगा। राजस्थान जैसे बैकवर्ड स्टेट में हमारे जो बीज उगते हैं। उसके अंदर पता करना पड़ेगा कि कौन-कौनसी फसल आ सकती है। यह हमारे पास अलग से लैब होनी चाहिए ताकि पोल्यूटेड पानी नहीं हो। हर जगह लैबोरेट्रीज होनी चाहिए। ब्लाक हैड क्वार्टर्स पर होनी चाहिए। हम स्वस्थ तभी रह सकेंगे। यह क्रास इन्फैक्शन जितने भी होते हैं, हेपेटाइटिस तथा अन्य रोग जो भी फैल रहे हैं, मूल कारण इसका होता है पोल्यूटेड वाटर। साइंस की लैब हर जगह होनी चाहिए, जिसके अंदर हमारे मोस्टली जो रुमेटेड डिफेक्ट हो जाते हैं, यह जितने भी पानी संबंधित रोग हैं, यह लैबोरेट्री वहां होनी चाहिए।

सभापति महोदय, हमारे यहां पीटीआई की बहुत ज्यादा कमी थी। करीबन साढ़े 15 हजार थर्ड ग्रेड थे, 2600 सैकंड ग्रेड थे। कोच सिर्फ 26 हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 500 कोच हायर किए हैं। वह कोचिंग देंगे हमारे बच्चों को। मैं समझता हूं कि यह दोनों महत्वपूर्ण सब्जैक्ट्स पर चर्चा हुई है।

स्वयं जब हमारे प्रेसीडेंट कलाम साहब आए थे तो हम सब लोग गए थे। मैंने कलाम साहब से बात की थी। मैंने कहा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के

(श्री जितेन्द्र सिंह)

2 वैज्ञानिक डा. रामरतन और डा. सुरेन्द्र पाल हैं। उन्होंने कहा कि वह दोनों मेरे कलिग रहे हैं। कस्तूरीरंजन आए तो उन्होंने कहा कि वह मेरे कलिग रहे हैं। इन लोगों ने पूरे देश में राजस्थान का नाम किया है।

सभापति महोदय, हमारी आवश्यकता है कि हम सवा सौ करोड़ के देश में एक गोल्ड मैडल को तरस रहे हैं। राजस्थान को हमें आगे ले जाना है। हमें catch them young करते हुए जनरेशन को आगे ले जाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सरकार नहीं करती है तो एज ए विधायक हम लोगों को करनी पड़ेगी। बाकी साइंस में जिस तरह से हमारी प्रतिभाएं, निश्चित रूप से ब्रिलिएन्स हैं, मेरे जैसे बिलकुल एक छोटे से बैकवर्ड एरिया से इंडिया में नम्बर वन वैज्ञानिक रह सकते हैं तो पूरे राजस्थान में क्यों नहीं रह सकते? माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(13.00 बजे)

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 24 के अंतर्गत शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अंदर खेलकूद तथा युवा सेवाएं तथा मांग संख्या 11 पर विचार कर रहे हैं। ये दोनों मांगें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई भी हैं। यह भारत युवाओं का देश है, लगभग 52 परसेंट युवा हैं। राजस्थान में भी लगभग 3 करोड़ युवा हैं। इनकी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, जिनकी चिंता करना, व्यवस्था करना और उनको पूरा करना यह हम सबका दायित्व बनता है। वैसे भी युवा इस देश और समाज की रीढ़ होते हैं, इनके अपने सपने होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, उत्साही होते हैं और खेल के माध्यम से इनकी युवा शक्ति का असली ढंग से उपयोग किया जा सकता है। स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर के अंदर ही होता है। खेलकूद हमारे जीवन का अंग है और मनुष्य को मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से स्वस्थ रखना है तो उसके लिए खेलकूद जरूरी है और मेरा मानना है कि नियमित रूप से जो खेलकूद से जुड़ा है वह समय के महत्व को भी समझता है। उसे पता है कि इतने समय का खेल है, इतने समय में खेल खेलना है, यह खेल 45 मिनट का है, 20 मिनट का है। समय की इम्पोर्टेंस का उसे हर सैकण्ड का पता होता है। लेकिन दुर्भाग्य से आज युवाओं में खेलकूद के स्थान पर अन्य गतिविधियां हावी होती जा रही हैं, टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम,

(श्री वासुदेव देवनानी)

इंटरनेट पर गेम, कम्प्यूटर पर गेम, उधर युवाओं का रुझान बढ़ रहा है जिससे शारीरिक गतिविधियां नहीं हो पातीं तो इसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन सबको सारी खेलकूद की सुविधाएं मिलें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण डवलप हो, इसकी नितांत आवश्यकता है। शरीर स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट रहेगा तब जाकर हम गांधीजी के और मोदीजी के सपनों, श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना सम्भव कर पाएंगे। हम विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नम्बर पर हैं। चाइना हमसे आगे है। जब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत है। उसमें हमने घोषणा तो कर दी कि ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक वाले को तीन करोड़, रजत पदक वाले को दो करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को एक करोड़ रुपये देंगे। घोषणा तो हो गयी लेकिन क्या यह चिन्ता हुई कि राजस्थान से किस प्रकार से ओलम्पिक गेम्स में खिलाड़ी खेलने जाएंगे, उसकी तैयारी के लिये क्या-क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसकी तैयारी के लिये कितनी राशि की आवश्यकता होगी, कौन-कौनसी सुविधाओं की जरूरत होगी, इन सबके और उनके चयन की चिंता करने की आवश्यकता है जिसकी कोई व्यवस्था हो। इसके लिए स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालयों के युवाओं को प्रोपर अवसर मिले।

कहा गया कि शिक्षा का यह भाग है, मेरा मानना है कि शिक्षा खेल के साथ जुड़ी है और खेल शिक्षा के साथ जुड़ा है। दोनों का आपस में जो सम्बन्ध है, उसमें करने के लिए स्कूल और कालेज और विश्वविद्यालयों में प्रतियोगिताएं तो आयोजित होती हैं, लेकिन उनमें अधिकांश केवल औपचारिक बनकर रह जाते हैं। कैलेण्डर में होता है कि स्कूल में ये प्रतियोगिताएं होंगी लेकिन कितने प्रतिशत विद्यार्थी उसमें भाग लेते हैं, कितना स्कूल का स्टाफ उस समय उपस्थित रहता है और उस स्कूल के अंदर सुविधाएं कितनी हैं, संसाधन कितने हैं, तो आएगा कि केवल ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। सुविधाएं हैं ही नहीं और इसके कारण से मैं जिस बात के आधार पर शिक्षा मंत्रीजी और खेल मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा, मेरे पास युवा मामले और खेल विभाग का प्रतिवेदन है। इस प्रतिवेदन में खेल का जो बजट है, वह 2019-20 में 15 करोड़, इस बार 20 करोड़ रुपये का बजट है और इसके अंदर विशेष बात है कि बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं कि हम खेल गतिविधियां बढ़ाएंगे, लेकिन खेल गतिविधियों में गत बार 10 करोड़ 70 लाख रुपये थे और इस बार केवल 8 करोड़ रुपये। इसका मतलब आप खेल गतिविधियों के लिए बजट

(श्री वासुदेव देवनानी)

ही नहीं रख रहे हो तो गतिविधियां होंगी कैसे? इसका मतलब गतिविधियों का आपके मन में कोई भाव ही नहीं है, केवल घोषणाएं करना और यहां बातें करना, उसी में आपका मन है। आपने तय किया कि हर पंचायत समिति में स्टेडियम निर्माण करेंगे। एक स्टेडियम का निर्माण कितने में होता है? साधारणतया डेढ़ करोड़ से दो करोड़ रुपये लगते हैं और आपने पूरे राजस्थान में स्टेडियम निर्माण के लिए जो बजट रखा है वह केवल दो करोड़ छियासी लाख। इसमें आप एक या दो ही स्टेडियम निर्माण कर पाएंगे तो सारे राजस्थान के जो तहसील के अंदर है, उसमें स्टेडियम के लिए कितना बजट चाहिए, उसकी कोई चिंता नहीं, उसका कोई बजट नहीं। उसकी कोई व्यवस्था नहीं है बजट के अंदर।

यदि मैं कहूं कि एकेडमियों की बात की, एकेडमियां तो 16-17 हैं, उन एकेडमियों का बजट कितना है, केवल 3 लाख रुपये उन 17 एकेडमियों का बजट है। 3 लाख में से किस-किस एकेडमी को क्या दोगे, क्या उससे एकेडमी काम कर पाएगी? वहां जो कर्मचारी काम कर रहे होंगे, उनके वेतन का क्या होगा? प्रतिनियुक्ति पर भी होगा तो क्या होगा? मतलब उनकी कोई चिंता इस बजट में नहीं की गयी है। इसका मतलब है कि सरकार की जो घोषणाएं हैं वे सिर्फ कागजी साबित होंगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगी और इससे खेल गतिविधियों में जो कटौती हुई है, इससे न तो प्रतिभाओं को तराशा जा सकेगा और न कोई उनको आगे बढ़ा सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, यही हाल आज पूरी शिक्षा व्यवस्था का है। शिक्षा में भी बड़ी-बड़ी घोषणाएं कीं, जो शिक्षा से जुड़ी हुई हैं खेल शिक्षा में भी इस बार पहले की तुलना में 1.6 परसेंट बजट कम है। खेल में बजट कम, शिक्षा में बजट कम तो मेरे स्कूल से पढ़ने वाले विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय तक आते हैं उनको किस प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी? जब आप खेल को बढ़ावा देने की बात करेंगे तो जो युवा आज की तारीख में बेरोजगार होता है उसका मन शिक्षा में नहीं लगता है। डिग्री कोर्स में वह एडमिशन तो ले लेता है, लेकिन न तो उसको नौकरी मिल रही है और न उसको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। वह खेल की ओर कैसे डाइवर्ट होगा? केवल दो वर्षों का आंकड़ा जो सरकार ने एक प्रश्न के उत्तर में मुझे दिया है, 2018 में पंजीकृत हुए 1 लाख 81 हजार बेरोजगार और 2019 में पंजीकृत हुए 6 लाख 2 हजार 136, यानी पांच गुणा, आपकी बेरोजगारों की संख्या बढ़ गयी, बेरोजगार सड़क पर घूमेगा, अपनी नौकरी की तलाश करेगा या खेल की ओर डाइवर्ट होगा? खेल

(श्री वासुदेव देवनानी)

की ओर उनको बढ़ाने की आवश्यकता है। बेरोजगारों की चिंता की जाए, युवाओं की चिंता की जाए। युवाओं के बेरोजगारी भत्ते की जिस प्रकार की बात है, टोटल 27 लाख में से केवल आप डेढ़ लाख को दे पाये हैं। वह डेढ़ लाख के अलावा और क्या करेंगे, पहले उनको नौकरी दो या बेरोजगारी भत्ता दो। सरकार की मंशा थी, उस मंशा की ओर उनको डाइवर्ट करेंगे तो उसका मन स्वस्थ होगा तो उसका स्वस्थ शरीर होगा, इसकी चिंता करने की आवश्यकता है, इसकी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। चूंकि विश्वविद्यालय के युवा खेलों में भाग लेते हैं, लेकिन मुझे बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ता है कि आज विश्वविद्यालय राजनीति के अखाड़े बने हुए हैं। खेल की चिंता तो है नहीं। युवा शक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। अभी हाल ही में जयपुर में राहुलजी की जो युवा आक्रोश रैली हुई उसमें प्राध्यापकों को कहा गया, प्रिंसिपल्स को कहा गया कि आप एनसीसी, एनएसएस, होस्टल्स के युवाओं और खिलाड़ियों को जयपुर भेजो, उनको टार्गेट दिये गये। इस तरह खिलाड़ी खेल खेलेगा या इनके टार्गेट में आएगा? इन प्रिंसिपल्स को ट्रांसफर का डर दिखाया गया, दबाव में लाया गया और यहां तक कि अजमेर की जब मैं बात करता हूं, उस प्रिंसिपल को 100 लोगों को जबरन सीएल देकर बस भरकर यहां लाना पड़ा। यानी हम युवाओं के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। युवाओं को राजनीति से ऊपर रखो। और तो और, एक शिक्षक गुट के महामंत्री ने इस राजस्थान में, मैं नाम नहीं लूंगा, तीन-तीन मंत्रियों के हवाले से अपील जारी की है। इस तरह से सेवा नियमों की तो धज्जियां उड़ायीं, अराजकता का वातावरण भी बना और राजनीति का खुले आम नंगा नाच हुआ। इस प्रकार का यदि हम करेंगे तो विश्वविद्यालय में खेलों में खिलाड़ी किस तरह से उभर कर सामने आएंगे? उनका ध्यान, उनका कंसंट्रेशन युवा गतिविधियों में रहे, खेल में रहे और उसमें भी बहुत बड़ी बात है, उनकी स्वायत्तता पर अतिक्रमण हो रहा है। यूनिवर्सिटीज के अंदर खेल अधिकारी, बोर्ड का सचिव और खेल बोर्ड प्रभारी होता है, साधारणतया वह शारीरिक शिक्षक होता है और जब वाइस चांसलर उनके पास यूनिवर्सिटी में नहीं होता तो वे उच्च शिक्षा विभाग से मांग करते हैं, लेकिन बिना वाइस चांसलर के मांग किये केवल अपने चहेतों को वहां पर फिक्स करने के लिए हमने डायरेक्टरेट से सीधे आदेश निकाले। मैं केवल अजमेर की एमडीएस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। वहां राजकीय महाविद्यालय की भूगोल की शिक्षिका को खेल बोर्ड सचिव बनाया गया। क्या वहां पर दूसरे किसी शारीरिक शिक्षक को नहीं बना सकते थे? यदि

(श्री वासुदेव देवनानी)

विश्वविद्यालय में नहीं है तो किसी भी अपने सम्बन्धित महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षक की मांग करते। भूगोल की शिक्षिका क्या खेल बोर्ड के सचिव का काम कर पाएगी? यह मेरा आग्रह है, यदि हम इस पर चर्चा करवा रहे हैं तो निश्चित रूप से कम से कम इस प्रकार की राजनीति का उपयोग न करके छात्रों को इसका टूल नहीं बनाएं।

वहां पर कुछ शिक्षक हैं, वे कर्तव्य बोध पखवाड़ा मनाने की अनुमति मांग रहे हैं, लेकिन हम नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, कि साहब यह हमारे कैलेण्डर में नहीं है जबकि कैलेण्डर के अलावा कई प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। खिलाड़ियों के कार्यक्रम भी तो हम लोग करेंगे। कार्यक्रम करने चाहिए। यदि कोई अच्छी बात करता है अपने कर्तव्य बोध की और उसे आप अनुमति नहीं दें तो यह राजनीति से प्रेरित है। यदि कोई बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा है, तब तो नहीं देंगे और कांग्रेस की गतिविधि का आया तो ले जाएं परमिशन। इस प्रकार से इस पर रोक होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आज जब मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, विश्वविद्यालय बच्चों से काफी खेलों के लिए पैसे वसूल करते हैं, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है? वहां की 18 टीमों को एक पैसा नहीं दिया गया। अपने व्यक्तिगत खर्च से वे टीमें भाग लेने के लिए गयी हैं। जब यूनिवर्सिटी के वीसी से बात करते हैं तो वह कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। किस प्रकार से खेल में आगे बढ़ेंगे? अपने पैसे से गरीब तो नहीं जा सकता। केवल पैसे वाले ही जा पाएंगे। फिर यदि मैं आगे बढ़ूं तो आपका खेल विश्वविद्यालय, 2013 में झुंझुनूं में राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय बनाने की बात हुई थी। जमीन भी आबंटित हो गयी। ओएसजी का भी निर्माण हो गया, लेकिन आज 2020 आ गया। हम सरकारों पर आरोप लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हमारी सरकार थी और हम कह देंगे कि आपकी सरकार थी, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि खेलों और शिक्षा के मुद्दों को राजनीति से ऊपर रखें। कहीं कमी है तो हम एक-दूसरे से शेयर करें। उसे ठीक कैसे कर सकते हैं, उस पर बात करें, लेकिन आपके पांच साल में नहीं हुआ, हमारे दो साल में नहीं हुआ। हम कह देंगे डेढ़ साल में नहीं हुआ, फिर यही बात चलेगी। आज इस खेल विश्वविद्यालय का दोनों बजटों में किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं

(श्री वासुदेव देवनानी)

रखा गया है, जहां तक मेरी जानकारी है। वास्तव में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान में खेल विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है। मेरा तो आग्रह है कि इसके लिए झुंझुनूं में तो आप प्रारम्भ करें ही, अजमेर में भी एक खेल विश्वविद्यालय सबसे बढ़िया केन्द्र है। आगे बढ़ें तो राजस्थान के जो सम्भाग केन्द्र हैं सात, उनमें खेल विश्वविद्यालय प्रारम्भ होंगे। आपके खिलाड़ी तैयार होंगे। आपको ओलम्पिक में जाने के लिए खिलाड़ी मिलेंगे। अच्छी प्रतिभाएं मिलेंगी, लेकिन यदि हमने इस प्रकार का प्रयोग नहीं किया तो निश्चित रूप से हमारे युवाओं की जो आशाएं-आकांक्षाएं हैं, सरकार की मंशा है, पूरे हाउस की मंशा है, वह पूरी होती हुई तो दिखाई नहीं देती।

माननीय सभापति महोदय, 2015 में समन्वित स्टेडियम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत यह तय हुआ कि हम तहसील स्तर पर स्टेडियम निर्माण और विकास का काम करेंगे। सरकार गम्भीर नहीं दिखती। जैसा मैंने कहा, केवल 2 करोड़ 86 लाख रुपये का इस बजट में प्रावधान रखा है। उससे तो एक या दो स्टेडियम बनेंगे, लेकिन आज राजस्थान में तहसील स्तर कितने हैं? जहां तक मेरी जानकारी है, 245 के आसपास हैं। 245 में जो आपके स्टेडियम बनें तो उसके लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी, एक दिन में नहीं बनेंगे मैं भी मानता हूं, लेकिन मंशा तो हो। हम फिगर तो बनाएं कि चार वर्षों में सब बना देंगे। इतना बजट हम अलाट करेंगे। मुख्य मंत्री से बात करें, तब जाकर होगा।

खेलकूद हेतु एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि इसमें जिला स्तर पर किसी तरह का बजट और सामग्री का आबंटन नहीं होता। जब जिला स्तर पर आप आबंटन नहीं करेंगे, उसके लिए बजट नहीं देंगे तो जिलों में किस प्रकार से खेलकूद की व्यवस्थाएं होंगी? हो नहीं पाएंगी।

आपने ही एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि 2019-20 में तो उदयपुर सम्भाग और बाकी सम्भागों में किसी तरह के बजट का प्रावधान ही नहीं है। जब बजट का प्रावधान नहीं है तो फिर क्यों इसका जिक्र कर रहे हैं? क्यों इसकी चर्चा करवा रहे हैं? मैं समझता हूं कि जब खेल मंत्री जवाब देंगे तो इन मुद्दों पर भी वे प्रकाश जरूर डालेंगे।

(श्री वासुदेव देवनानी)

मुझे लगता है कि सरकार गम्भीर नहीं है। खेल मंत्री भी क्या करें, खिलाड़ी हैं, इसीलिए प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन मुख्य मंत्री जी या वित्त मंत्री जी इन्हें पैसे देंगे, तब कर पाएंगे। मुख्य मंत्री जी का ध्यान केवल संघ और मोदी जी को गाली देने में और सीएए का विरोध करने में रहता है। वे अपने ऊपर के लोगों को खुश रखते हैं। मंत्री लोग सीएम को खुश करने के लिए इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। जम्मू-कश्मीर पर चर्चा करेंगे, दिल्ली चुनावों पर करेंगे, एनआरसी की करेंगे, सीएए की करेंगे, पर खेल की नहीं करेंगे। सीएम अपने आकाओं को खुश करें और मंत्री सीएम को खुश करें और यहां का युवा अपने आपको ठगा-सा ही महसूस करे। उसके साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? युवाओं के साथ क्यों छलावा कर रहे हैं? जरा इस पर तो कहीं न कहीं चिंता होनी चाहिए।

बाकी समय कुछ अगर बचता भी है, उसमें तुष्टीकरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। राष्ट्रीय महापुरुषों, राष्ट्रीय खिलाड़ियों का आज कहां सम्मान हो रहा है? राष्ट्रीय महापुरुषों का अपमान करना, आज सावरकर को गाली देना, उनके नाम से वीर हटाना, इस प्रकार केवल एक ही परिवार के नेताओं को महिमामण्डित करने से ध्यान हटाएंगे, तब युवाओं की ओर ध्यान दे पाएंगे। युवाओं के लिए जब मैं स्कूलों की बात करता हूं तो स्कूलों के अंदर यदि ऊपर के पद भरे हुए होंगे, फाइनेंस सैंक्शन कौन करेगा? फाइनेंस डीडी सैंक्शन करेगा, फाइनेंस डीईओ सैंक्शन करेगा, उसमें आधे से ज्यादा पद खाली हैं। वहां पर 50 परसेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात थी। हमने स्पेशल अनुमति लेकर 100 परसेंट पद भर दिये थे। आप भी वह कर सकते हैं, लेकिन आज आधे पद खाली पड़े हैं, जिसके कारण नीचे का प्रिंसिपल या कोई अधिकारी साइन कराने जाता है तो खेलकूद प्रतियोगिताओं में कैसे जाएंगे, इसकी चिंता करनी पड़ेगी।

हम पिछले पांच वर्ष में शिक्षा को दूसरे नम्बर पर ले आये थे। हमने सोचा था कि आप भी प्रयास करेंगे और राजनीति से ऊपर उठकर एक नम्बर पर ले आएंगे इसे, लेकिन जिस प्रकार के हाल देख रहा हूं, पूत के पांव पालने में ही नजर आ रहे हैं। किसी प्रकार की कोई सम्भावना नहीं लगती। बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर दीं स्कूलों में खेल शुरू करने के लिए। आपने उस समय कहा, अंग्रेजी मीडियम के स्कूल हम शुरू करेंगे। करें, लेकिन वहां व्यवस्था तो करें। हमने विवेकानन्द माडल स्कूल खोले, एक-एक, छह-छह, सात-सात करोड़ के

(श्री वासुदेव देवनानी)

खेल के मैदान भी 134 ब्लाक में हमने बनाये और आपने क्या किया, नकल तो करने की कोशिश की कि हम स्कूल अंग्रेजी माध्यम के खोलें, लेकिन खोला क्या, उन्हीं हिन्दी मीडियम के स्कूलों को बंद करके, बिना खेल मैदान के, उन्हें अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बना दिये। कहां जाएंगे बच्चे? आप जाकर माडल स्कूल के ग्राउण्ड देखें। माडल स्कूल बनाते न आप। 134-150 जो भी आपको बनाने थे। जरा बजट तो देते, लेकिन इसके लिए किसी प्रकार का बजट का प्रावधान नहीं किया गया और केवल वर्तमान स्कूलों को लेकर जनता को भ्रमित किया। हम अंग्रेजी स्कूल खोल रहे हैं, खोलें, अच्छा है, लेकिन खोलकर के व्यवस्था तो करें। उसके लिए खेल के मैदान रखें, पीटीआई रखें, कुछ अध्यापक तो रखें। वह नहीं करेंगे।

बच्चे पौष्टिक कैसे बनेंगे? भारत सरकार ने मिड-डे मील शुरू किया ताकि बच्चों का कुपोषण न हो। आगे खेल के मैदान में भी जा सकें, लेकिन मुझे बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि आज वहां पर उस पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है। ठेकेदार वहां पर चक्कर लगा रहा है। उसके साथ, हमने दूध की योजना शुरू की। दूध प्रोपर मिले बच्चों को, तब तो जाकर दूध पीकर वे मैदान में उतरेंगे, लेकिन उस दूध में भी पानी मिलाने की सैकड़ों शिकायतें मिल रही हैं। शिक्षा मंत्री मौन धारण किये बैठे हैं।

बच्चियां खेलने के लिए स्कूल आएं, यह जरूरी है, लेकिन स्कूल कब आएंगी, जब उन्हें ट्रांसपोर्ट वाउचर मिलेगा। हमने ट्रांसपोर्ट वाउचर शुरू किया, लाखों बच्चियों को देते हैं। पिछले कई महीनों से ट्रांसपोर्ट वाउचर नहीं दिया जा रहा है। बच्चियां स्कूल में काफी कम आने लग गयीं। खिलाड़ी कैसे बनेंगी बच्चियां? उन्हें खिलाड़ी भी बनाना है। उसकी चिंता करने की आवश्यकता है। इसके लिए पीटीआई मूल होता स्कूलों में। उसके कितने पद खाली हैं? हमने आकर प्रारम्भ किया था भरने का। आप 31 हजार नये अध्यापक भरने की बात कर रहे हैं। उससे कितने पीटीआई आएंगे? पीटीआई के पद आप भरेंगे, इसकी कोई भी व्यवस्था ही नहीं है। पीटीआई का पद नहीं भरेंगे, आपके स्कूलों में पीटीआई नहीं होंगे तो खेल कौन कराएगा?

आपने अब सैटरडे का किया, लेकिन गतिविधियां चलाने के लिए खेल भी हैं। खेल के लिए पीटीआई की तो आवश्यकता है। पीटीआई भी नहीं देंगे। फिर स्कूल की व्यवस्था ठीक चले तो उसके लिए स्कूल फैसिलिटी ग्रांट, जो

(श्री वासुदेव देवनानी)

हमारे समय में 5 हजार-12 हजार थी, हमने साढ़े 12 हजार से एक लाख कर दी थी, वह समय पर स्कूल पहुंचे, तब उसमें से पैसा खर्च हो सके। माननीय सभापति महोदय, फरवरी तक केवल 25 परसेंट की ही राशि सैकण्डरी-सीनियर हायर सैकण्डरी तक पहुंची है। अब आप मार्च में कब पहुंचाओगे? वे मार्च में करेंगे? कौनसी फैसेलिटी करेंगे? पढ़ने के लिए डस्टर और चाक ही नहीं होगी तो खेल में उनका मन कौनसा खिलाड़ी लेकर जाएगा। इस तरह की स्थिति आज जो बनी हुई है, मैं समझता हूं कि पूरी तरह सरकार इसमें कोई गम्भीर दिखाई नहीं देती। इसलिए, आवश्यक है कि इस पर पुनर्विचार करके गम्भीरता से विचार करो।

माननीय सभापति महोदय, युवा मामले हैं, युवा बोर्ड सरकार ने बनाया हुआ है, लेकिन आज वर्तमान में युवा बोर्ड की स्थिति क्या है? पिछले सवा साल से युवा बोर्ड का गठन नहीं हुआ। अध्यक्ष नहीं, मैम्बर्स नहीं हैं और सारी गतिविधियां ठप्प पड़ी हैं। पूरे युवा बोर्ड की जो स्थिति है, केवल सदस्य सचिव है और वह भी प्रतिनियुक्ति पर भरा हुआ है और दो क्लास फोर के लोग लगे हुए हैं तथा इससे आपका युवा बोर्ड चल रहा है। उद्देश्य तो युवा बोर्ड के अच्छे हैं, युवा बोर्ड का गठन करके युवाओं की गतिविधियां चलानी चाहिए जिससे नई ऊर्जा आती है, कई प्रकार के काम आते हैं लेकिन आपने उसकी कोई चिन्ता नहीं की कि हम युवा बोर्ड का गठन तो करें। आपको जिसको करना है करो, आपकी सरकार है लेकिन युवा बोर्ड का गठन करके मैम्बर्स तो बनाओ ताकि उसकी गतिविधियां तो प्रारम्भ हों, परन्तु उसकी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और तो और 2018 में यूथ आइकान के अन्तर्गत हमने आईटी, पर्यावरण सुरक्षा सहित दस श्रेणियों की युवा प्रतिभाओं का चयन किया, उनको वहां पर सम्मान देने के लिए भारत सरकार की योजना थी, उनको चयनित किया, बजट सैंक्शन हो गया, लेकिन आचार संहिता लग गई, इसलिए उनको नहीं मिल पाया, लेकिन आज इस सरकार ने आते ही उसको ठण्डे बस्ते में डाल दिया। इसमें राजनीति क्यों कर रहे हो? भारत सरकार के थे और श्रेणीवार सारे अधिकारियों ने चयन किया, उसमें न कोई बीजेपी का है, न कोई कांग्रेस का है लेकिन उनको भी हम यदि अवार्ड नहीं देंगे तो उनको फिर प्रोत्साहन कैसे मिलेगा? ये खिलाड़ी कैसे आगे आएंगे? इस तरह से मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इसमें राजनीति न करके इस

(श्री वासुदेव देवनानी)

बात को देखें और इन आइकान के इन श्रेणी की प्रतिभाओं को आप सम्मानित करें।

दूसरा, परम्परागत खेल तो लुप्त ही हो गये। हाकी भी अपना परम्परागत है। फुटबाल, वालीबाल तो चल रहे हैं, लेकिन पुराने परम्परागत खेल थे जैसे सितोलिया, हथदड़ा, गिल्ली-डंडा, खो-खो, कई तरह के खेल थे जो गलियों में खेलते थे और संसाधनों की आवश्यकता नहीं थी लेकिन बच्चे खेलते थे। लेकिन हमने धीरे-धीरे इन सारे खेलों को समाप्त कर दिया और जब परम्परागत खेल नहीं होंगे, संसाधन होंगे नहीं और खिलाड़ी कुछ खेलेंगे नहीं तो उनका शारीरिक विकास होगा नहीं तो फिर निश्चित रूप से विकास भी नहीं होगा और अपने सपने भी पूरे नहीं होंगे।

स्कूलों में हम टूर्नामेंट कराते हैं, शिविर में कैलेण्डर होता है, मेरे पास दायित्व रहा है, लेकिन वह किसी प्रकार से औपचारिकता होकर रह जाते हैं। उसमें भी आप बच्चों को देते कितना हो खिलाड़ी भत्ता? वे कह देंगे कि आपके समय में कम था और हमने कुछ बढ़ाया। वास्तव में मार्केट के अनुसार या उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कितना भत्ता बढ़ना चाहिए एक खिलाड़ी के लिए, ताकि वह एक दिन में अपने शरीर में जितनी एनर्जी वह लगाता है उतनी एनर्जी तो उसको मिल सके पर एनर्जी की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले 70 थे, हमने 100 किया और अब 150 है लेकिन खिलाड़ी जो दूर जाता है, आता है, रहन-सहन की व्यवस्था होती है उसमें खर्चा होता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): जल्दी कर रहा हूं। उसमें किसी प्रकार की कोई चिन्ता नहीं। एकेडमियों के बुरे हाल हैं, जैसा मैंने कहा कि केवल 3 लाख रुपये आपने एकेडमियों के लगाये हैं। उसमें भी जो आवासीय एकेडमियां हैं। उसमें मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि आपका जोधपुर में बालक फुटबाल एकेडमी है, उसमें 30 में से केवल 23 बच्चे रह रहे हैं, बालिका बास्केटबाल है उसमें 25 में से केवल 7 बच्चियां आवासीय हैं, बाकी बच्चियां क्यों नहीं है? इसकी कहीं नीचे मानिटरिंग होनी चाहिए कि कौन उसमें प्रयास नहीं कर रहा है। बालक साइकिलिंग का है उसमें 30 में से केवल 11 बच्चे हैं। माननीय सभापति महोदय, इसकी कहीं कोई चिन्ता नहीं है।

(श्री वासुदेव देवनानी)

अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो इसी प्रकार राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्, उसमें दो पुरस्कार दिये जाते थे, एक महाराणा प्रताप पुरस्कार, जिसमें 1982-83 से 2017-18 तक 170 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। 2018-19 हेतु आज 2020-21 में आवेदन मांगे गये हैं। दो साल तक क्या हुआ? सरकार सोती रही। इसी तरह गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। क्या उनका नाम महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ के नाम से है इसलिए आपको कोई आपत्ति होगी और उसके भी आवेदन अब मांगे जा रहे हैं। उनको भी केवल एक लाख रुपये देते हैं और उसमें भी सरकार मौन है। इन दोनों पुरस्कार के आवेदन जल्दी मांगकर उनको टाइम से दोगे तो अगले साल के फिर मांग पाओगे।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): उसके साथ 3 से 5 जनवरी तक आपने स्टेट गेम्स कराये, बहुत अच्छा किया, लेकिन 1500 से अधिक आज भी ऐसे तकनीकी अधिकारी हैं जिनको टीए, डीए नहीं मिला।

इसके साथ ही मैं अजमेर की कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। अजमेर में हमने एक वर्ष पहले नया स्टेडियम बनाया, लेकिन आज वह उद्घाटन के लिए तरस रहा है। सवा साल से आप समय तो निकालो, उसका उद्घाटन तो करो ताकि उसका उपयोग तो हो। आप करो उद्घाटन, हमें शौक नहीं है कि हम करें, लेकिन आप करें।

डे-बोर्डिंग योजना बनाई। कबड्डी एकेडमी शुरू की, खिलाड़ियों का ट्रायल भी हुआ, लेकिन वह केवल बन्द बस्ते में चला गया।

मेरे यहां चन्दबरदाई नगर का बड़ा खेल स्टेडियम है। करोड़ों की लागत से स्टेडियम बना।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, मैं विषय के आगे जा ही नहीं रहा हूं। 45 लाख रुपये से उसमें सिंथेटिक टेनिस कोर्ट बनाया गया। आज उसका रख-रखाव न होने के कारण उसमें घास उग रही है। यानी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है।

मैं बच्चियों का मुद्दा उठा कर अपनी बात समाप्त करूंगा। बच्चियों को हमने कहा था कि खेल में तो सेनिटरी नैपकिन भी हम देंगे। 2016 से 12 से 19 वर्ष की 20 लाख किशोरियों को 8 करोड़ नैपकिन देते थे, लेकिन गत कई माह से 35 हजार स्कूलों तक यह नैपकिन समय पर नहीं पहुंच रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें। कनक्लूड करें, माननीय सदस्य।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): समग्र शिक्षा अभियान का अंश, जो राज्य का अंश होना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। तो मेरी संक्षेप में मांग है कि खेल विश्वविद्यालय बने। नरेगा के काम चल रहे हैं तो नरेगा के साथ जोड़ो, उसके तहत स्कूलों में ट्रैक बनाये जाएं, प्रतियोगियों का भत्ता बढ़ाया जाए, जिलों को समग्र खेल बजट आबंटित किया जाए।

अब मैं साइंस की एक मिनट में बात करके पूरा करूंगा क्योंकि साइंस भी इसमें विषय है। कई ग्रामीण स्कूलों में साइंस लैब नहीं है। उन ग्रामीण स्कूलों में साइंस लैब खुले, वहां साइंस क्लब बने, पर्यावरण क्लब हैं उनको सक्रिय बनाया जाए। अजमेर की बात करूंगा तो उसमें साइंस पार्क हमको मिला, शिलान्यास हो गया पर वह साइंस पार्क आज तक शुरू नहीं हुआ जबकि 2020 के मार्च तक पूरा करना था। उसमें राज्य का अंश नहीं मिला, केन्द्र से पैसा आया हुआ पड़ा है। इसलिए राज्य का अंश मिलाकर उसमें राजनीति न करें और उसको पूरा करें। इसमें मेरी आपसे मांग है कि इसको पूरा करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री कैलाश त्रिवेदी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): राजसमन्द के अन्दर गांवों में कोई स्टेडियम नहीं बने और जो बने हैं उनमें स्पोर्ट्स ग्राउण्ड पर बाउण्ड्रीवाल बनाएं। डीएमएफटी के फण्ड से पंचायतों के अन्दर खेल मैदान बनाएं, राज्य स्तरीय सुविधाएं बढ़ाएं और साथ में छबड़ा में अधूरा स्टेडियम पूरा करें। मेरी तीन मांगें हैं यूथ हास्टल बने....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें, सहयोग करें। फिर कल की तरह होगा कि कई माननीय सदस्य बोलने से रह जाएंगे। अंकित नहीं होगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): खेल मैदानों में अतिक्रमण है वह अतिक्रमण तो खेल मैदान से हटाएं। मैं कहता हूं कि अतिक्रमण आप हटाओ, जमीन का आबंटन करो। आखिर में कहूंगा कि आपके यहां खेल है तो विद्यालयों में सूर्य नमस्कार कराओ। सबसे बढ़िया है कि योग दिवस 21 जून को कराओ तब जाकर आगे बढ़ेगा। साथ में सरकारी नौकरियों में दो परसेंट खिलाड़ियों का जो कोटा है इसको भी बढ़ाया जाए। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, जितना समय दिया, उसी में मैंने पूरा किया है, मैं आगे

(श्री वासुदेव देवनानी)

नहीं गया। आपसे निवेदन है कि मंत्री जी इसका जवाब दें। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप तो अध्यापक रहे हैं, टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरह से करना चाहिए कि साइंस पर आप बोल नहीं पाए और तब से आप पूरा बोल भी रहे हैं।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मेरा एक छोटा-सा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति: विराजिये, मैंने नाम पुकार लिया। श्री कैलाश चन्द त्रिवेदी। विराजिये माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज, विराजिये आप। आपको बोलना है, आपका बोलने में नम्बर है, विराजिये आप। माननीय सदस्य, एक दफे जब आसन कोई बात कहे तो आप बैठ नहीं सकते? बार-बार आप उसी बात को रिपीट कर रहे हो। मत करिये आप, नये आदमी हो, सीखिये आप। माननीय श्री कैलाश चन्द त्रिवेदी।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): सभापति महोदय, मांग संख्या 24, 11 पर चर्चा हो रही है, खेल पर चर्चा हो रही है, खेल मैदान पर चर्चा हो रही है। अभी अजमेर से आने वाले पूर्व मंत्री महोदय बहुत लच्छेदार चर्चा में भाग ले रहे थे। खुद शिक्षा मंत्री थे तब इनको यह जानकारी नहीं थी क्या कि गिल्ली डंडा लुप्त हो गया है, मारदड़ी के मीठे लड्डू लुप्त हो गये हैं और खेलों की क्या दुर्दशा है, क्या अव्यवस्था है? आज जब यह खेलों की चर्चा हो रही है तो खेल इस हिन्दुस्तान की जान है और खेल से ही किसी भी देश की पहचान है, लेकिन खेल हमारे प्रदेश में लुप्त होते जा रहे हैं। लुप्त क्यों हो रहे हैं? हमारी व्यवस्थाओं के कारण हो रहे हैं। पूर्व में जो व्यवस्थाएं थीं उनमें हमने कटौतियां की हैं, कमियां की हैं और उनको बढ़ाने का प्रयास नहीं किया।

मैं खुद खिलाड़ी बना, बचपन से एक छोटे से गांव में रहने वाला व्यक्ति, बचपन में खेलने जाता, घरवाले भी डांट फटकार करते। स्कूल की जो उस वक्त की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था से मैं खिलाड़ी बना। स्कूल की व्यवस्था थी कि स्कूल के अंदर पहली से पांचवीं, पांचवीं से आठवीं और

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

आठवीं के बाद नौवीं से बारहवीं तक जो बच्चे हम पढ़ते थे, उनमें अलग-अलग दलीय व्यवस्था कर रखी थी। चार तरह के दल बनते थे, प्रताप दल, सुभाष दल, पटेल दल, गांधी दल। उन दलों की प्रतिदिन खेलकूद प्रतियोगिता होती थी। एक घंटे का पीरियड होता था, जिसमें खेलकूद सिखाए जाते थे और कम्पीटिशन की भावना पनपती थी। कम्पीटिशन की भावना पनपती थी और उस कम्पीटिशन से हम लोगों का खेल में रूझान बढ़ता था और हम लोग खेल में आगे निखार करते थे।

इसके साथ-साथ ग्रामीण खेलकूद भी होते थे। ग्रामीण खेलकूद होते थे, गांव के ब्लाक स्तर पर खेलकूद होते थे, जिला स्तर पर खेलकूद होते थे, स्टेट लेवल पर होते थे, नेशनल लेवल पर होते थे। आज वे सारी खेलकूद की प्रतियोगिताएं समाप्त कर दी गई हैं। ग्रामीण खेलकूद भी बंद और स्कूलों की दलीय व्यवस्था भी बंद है। स्कूलों में अलग-अलग दल बनाकर अगर बच्चे खेलेंगे तो निश्चित तौर पर उस स्कूल में, फिर उस ब्लाक की स्कूलों में, फिर जिले की स्कूलों में जो प्रतिस्पर्धा होगी, जितना बच्चा खेलेगा ओर जितनी प्रतियोगिता और जितने टूर्नामेंट खेलेगा, उतना ही खेल में निखार आएगा।

गर्मी की जब छुट्टियां होती थीं। गर्मी की छुट्टियों में हम लोग जो खिलाड़ी थे। हम लोगों के लिए गर्मी की छुट्टियों में कैम्प लगते थे। कभी तो हम माउंट आबू खेलने के लिए दो-दो महीने वहां रहते थे, कभी हम नेशनल कैम्पों में जाते थे, कभी स्टेट के कैम्पों में रहते थे, कभी यहां एसएमएस में हम खेलते थे, कोचिंग कैम्प अटैण्ड करते थे। आज कोचिंग कैम्पों की व्यवस्था मृत-सी हो गई है।

मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने और मंत्री जी ने इस बजट में खेलों को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था की है, जो उन्होंने हिट राजस्थान और फिट राजस्थान की बात की है। मुझे यह लगता है कि वास्तव में देश के अंदर स्मार्ट सिटी बनाने की कोई सोच रखता है, लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री हिट राजस्थान और फिट राजस्थान बनाने की सोच रखते हैं। इस देश को, प्रदेश को आज जरूरत है तो हिट राजस्थान की और फिट राजस्थान की है। प्रदेश का हर बच्चा और बच्ची फिटनेस में फिट होगी और हिट होगी तो अपना देश अपने आप हमेशा स्मार्ट बनेगा। जिसका देश स्मार्ट है, उसको कोई स्मार्ट सिटी की जरूरत नहीं है। वह अपने आप देश को

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

चरम सीमाओं पर अपने आप मजबूत कर देगा। बच्चा-बच्ची हमारे देश का स्मार्ट होना चाहिए, उस ओर हमारा ध्यान नहीं है। हम स्मार्ट सिटी बनाकर, सड़कें बनाकर, भवन बनाकर क्या करना चाहते हैं? चित्र नहीं चरित्र अच्छा चाहिए। भवन नहीं भावना अच्छी चाहिए। भावना अगर हमारी अच्छी नहीं होगी, इसमें मुख्य मंत्री जी की जो भावना है, खेलों के प्रति यह भावना बहुत अच्छी है। उनका चरित्र बहुत अच्छा है। वे यह चाहते हैं कि बच्चे हमारे फिट बने, राजस्थान के हिट बने।

नीरोगी राजस्थान में भी जो बजट-बजट की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक ही निवेदन कर रहा हूं कि नीरोगी राजस्थान का बजट भी, उसमें बजट की जरूरत नहीं है। आप हर प्रदेश के बच्चे-बच्ची को फिटनेस से फिट कर देंगे तो वह बीमार ही नहीं होगा। बीमार ही नहीं होगा तो हास्पिटलों की जरूरत ही नहीं होगी, डाक्टरों की जरूरत ही नहीं होगी। बच्चा बच्ची बीमार हो तभी तो नीरोगी राजस्थान का काम है, डाक्टरों का काम है। नीरोगी राजस्थान क्यों बनाना चाहते हैं मुख्य मंत्री जी, नीरोगी राजस्थान की कड़ी में ही यह हिट और फिट उनका नारा है। यह हिट और फिट के संदर्भ में मुख्य मंत्री जी ने जो व्यवस्था दी है। यह व्यवस्था बच्चों के लिए दी है। उसमें बरसों बाद 500 कोच संविदा पर लगाकर के, तो मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि ये जितने भी आप कोच लगा रहे हो, इनको ब्लाक स्तर पर लगाओ और ब्लाक स्तर पर लगाकर, गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के लिए कोचिंग कैम्प लगाओ, कोचिंग कैम्प लगाकर बच्चे वहां खेलें और साल भर वह कोच रहे और हर ब्लाक पर आपका कोच रहे और सारे खेलों का ज्ञान हो।

पुराने टाइम में, अभी वे कह रहे थे। आप सूर्य नमस्कार सिखाओ। सूर्य नमस्कार और आपके योग, इन योग की कहीं जरूरत ही नहीं है, न आपके सूर्य नमस्कार की जरूरत है। तब पी टी का पीरियड होता था, फिजिकल टीचर होता था, वह सारी एक्सरसाइज और पी टी कराता था। वह पी टी ही आपके आज के योग हैं। जो बाबा रामदेव जी कर रहे हैं। उस पी टी में सारे नेशनल कैम्पों में, जितनी भी हम एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें आप योग कहो या एक्सरसाइज कह लो, ये हमारे नेशनल की एक्सरसाइज है। जितने भी फिजिकल टीचर के पद हैं, उन सारे फिजिकल टीचर्स को आप यह इंस्ट्रक्शन दें कि सभी 15 मिनट का पीरियड रखें, चाहे आधे घंटे का पीरियड रखें और बच्चों को प्रार्थना के बाद फिजिकल एक्सरसाइज कराएं। बच्चे जब

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

फिजिकल एक्सरसाइज करके जाएंगे तो आप यह मानकर चलो कि बच्चे आते ही एकदम तंदुरुस्ती महसूस करेंगे, ताजगी महसूस करेंगे। कोई भी खिलाड़ी खेलकर आता है तो उसमें ताजगी और उत्साह का जोश रहता है।

अभी हमारे मंत्री महोदय फैडरेशन कप में आये। नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला फैडरेशन कप, जब मैं हिंदुस्तान जिंक में लगा, उस वक्त हिन्दुस्तान जिंक में स्पोर्ट्स कोटे में मुझे लिया गया। आज जो नौकरी की बात कर रहे हैं कि दो परसेंट आरक्षण और नौकरी के लिए खिलाड़ी घूमते फिर रहे हैं। उस वक्त एक जमाना था, जब हम लोगों को हिन्दुस्तान जिंक बुला रही थी, जितेन्द्र सिंह जी, खेतड़ी कापर बुला रही थी, रेलवे बुला रही थी, बैंक बुला रहे थे, श्रीराम बुला रही थी, खिलाड़ियों को हर संस्था बुलाकर नौकरियां दे रही थी। हिन्दुस्तान जिंक में रहते हुए हमने जो फैडरेशन कप का आयोजन किया, जो नार्थ इंडिया का पहला टूर्नामेंट था। उस टूर्नामेंट के आयोजन में जो खेल का स्तर था, उस स्तर में और अभी जो टूर्नामेंट हुआ चित्तौड़ में, खिलाड़ियों के स्तर में बहुत ज्यादा कमी आई। वह कमी इसलिए आई कि अभ्यास की कमी हो गई। खेल के ऊपर सरकारों का रुझान खतम हो गया। जब तक सरकार इंट्रेस्ट नहीं लेगी और खेलों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं नहीं बनाएगी तो मेरा यह मानना है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो योजना बनानी है उसमें हर तहसील स्तर पर स्पोर्ट्स स्कूल खोल दिये जाएं, आप इंग्लिश स्कूल खोल रहे हैं, आप सब्जैक्ट खोल रहे हैं, आप डाक्टर बनाना चाह रहे हैं, आप कलेक्टर बनाना चाह रहे हैं, आप एसपी बनाना चाह रहे हैं, आप सारे अफसर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वे अफसर पढ़ लिख जाएंगे, मरियल टाइप होंगे, चक्कर खाकर गिरेंगे, चोर आगे दौड़ेगा और थानेदार पीछे घूमता रहेगा, ये स्थिति होगी। अगर आपका हर बच्चा फिट होगा, अगर आपका बच्चा तंदुरुस्त होगा, सरकारी कर्मचारी तंदुरुस्त होगा तो ताजगी से वह अपने काम को ज्यादा अच्छा अंजाम दे सकेगा। हमारा यह कहना है कि आप स्पोर्ट्स स्कूल खोलें, स्पोर्टस स्कूल खोलकर के उस एरिये के जितने भी खिलाड़ी बच्चे हैं, वे उस स्पोर्ट्स स्कूल में रहे और खेलों के प्रति अलग-अलग खेलों के अलग-अलग स्कूल खुल जाएं और जिले के अंदर वे बच्चे खेल प्रतियोगिता में भाग लें।

अभी मुख्य मंत्री जी ने खेलों को बढ़ावा देने की भावना से, जो अभी हाल में यहां एसएमएस स्टेडियम में 18 खेलों के 8 हजार खिलाड़ी आये थे,

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

इसकी सब तरफ तारीफ हो रही है। इसी तर्ज के ऊपर जो बंद हो चुके थे, ब्लाक स्तर के खेलकूद, राज्य स्तर के खेलकूद और जिला स्तर के खेलकूद, मैं मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसको पुन: चालू किया और इसमें फण्ड की व्यवस्था भी करें और इन खेलों को पुन: चालू करके और अच्छे खेलों का प्रदर्शन हो, अच्छे खिलाड़ी हमारे प्रदेश में तैयार हों, ऐसी मेरी सोच है। वैसे खिलाड़ियों के लिए खेल एक लोकतंत्र की भी कड़ी है। लोकतंत्र में जिस तरह से नेता के कंट्रोल में उसके सारे माननीय सदस्य हैं, इधर वाले सदस्य सदन के नेता के कंट्रोल में हैं और उधर वाले नेता, प्रतिपक्ष के कंट्रोल में हैं। खिलाड़ियों का भी जो कप्तान होता है उसके कंट्रोल में उसकी टीम होती है। टीम भावना से वह खेल खेलते हैं और उसके बाद खिलाड़ी एक ऐसी चीज है जो संविधान की मूल भावना की जो मैंने बात कही है कि संविधान की मूल भावना को खिलाड़ी समझता है। धर्मनिरपेक्ष देश में खिलाड़ी की टीम में सभी जातियों के खिलाड़ी होते हैं, अलग-अलग जिलों के खिलाड़ी होते हैं, अलग-अलग प्रदेशों के खिलाड़ी होते हैं, अलग-अलग खानपान के खिलाड़ी होते हैं, अलग-अलग भाषा के खिलाड़ी होते हैं, लेकिन वह अपना काम्बिनेशन सैट करके और वह इस हिन्दुस्तान के लिए खेलते हैं तो यह जो हमारे भारत का संविधान कहता है, वह अगर कहीं झलकता है तो वह खेल के अंदर झलकता है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब संविधान की मूल भावना अगर खेलों में झलकती है तो हमें उन खेलों को मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट का अलोकेशन करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स स्कूल खोलने चाहिए और पुरानी जो व्यवस्था है, जो स्कूलों में दल बनाकर प्रतिस्पर्धा की जो भावना पूर्व में थी, वह पुन: चालू करनी चाहिए।

नो बैग डे, सभापति महोदय, अभी मैं क्षेत्र के स्कूलों में गया हूं। मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि 10 स्कूलों में मैंने नो बैग डे की बच्चों से बात की। बच्चों को मैंने कहा कि शनिवार को बैग नहीं लाओगे। सिर्फ खेलोगे, कूदोगे, नाचोगे, गाओगे तो बच्चे इतने खुश हुए। मैंने कहा कि यह फैसला अशोक गहलोत जी ने किया है, अच्छा किया कि नहीं? तो उन्होंने खुद ने यह कहा कि अशोक गहलोत जिंदाबाद, जिसने हम बच्चों के बारे में यह पहली बार सोचा है इस राजस्थान की विधान सभा के सदन में। जब हम कर्मचारियों के लिए 5 दिन का कार्य दिवस रखकर 2 दिन की छुट्टी रख रहे हैं तो बच्चे

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

सोमवार से लेकर शनिवार तक बस्तों का बोझ उठाते हैं और संडे को होमवर्क करते हैं। एक दिन बच्चे अगर फ्री होंगे तभी तो वह शारीरिक फिट हो पाएंगे तो यह हिट राजस्थान और फिट राजस्थान और नीरोगी राजस्थान के अंदर मील का पत्थर साबित होगा नो बैग डे। याद रखना मेरी बात को लेकिन इस नो बैग डे का दुरुपयोग नहीं हो। अध्यापक भी वहां आएं और फिजिकल टीचर भी आएं और जहां फिजिकल टीचर कम हैं, शिक्षा मंत्री जी अभी नहीं हैं, लेकिन जहां फिजिकल टीचर कम हैं, उन फिजिकल टीचर्स के लिए उस स्कूल में कोई भी खिलाड़ी अगर किसी सब्जैक्ट का टीचर है तो उसको खेल इंचार्ज बना करके फिजिकल टीचर की वहां व्यवस्था करवा करके और उस विद्यालय में नो बैग डे के तहत रोज खेल प्रतियोगिताएं और कम्पीटिशन की भावना हो। अभिभावक भी देखें। हमारे मंत्री जी अभी चित्तौड़गढ़ में थे, खेल समापन में और मुझे भी इनके साथ जाने का मौका मिला था। पुराने लोगों की सोच, पुरानी सरकारों की सोच यह थी बच्चों के खेल के प्रति कि खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब और पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। लेकिन हमारे मुख्य मंत्री ने और हमारे मंत्री ने यह साबित किया है कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, लेकिन खेलोगे, कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। लाजवाब तब बनोगे जब आप खेलोगे, कूदोगे। पढ़-लिखकर के तो आप खाली नवाब बनोगे लेकिन नवाब बनकर भी चक्कर खाकर गिर आओगे तो अगर मजबूत नवाब बनना है तो लाजवाब बनना जरूरी है। लाजवाब बनने के लिए खेलों को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है और स्पोर्ट्स स्कूल की जो भावना है वह सभी जगह पर हो।

मेरे क्षेत्र में गंगापुर नगरपालिका क्षेत्र है, सबसे बड़ा कस्बा है उसमें खेल स्टेडियम नहीं है तो मैं मंत्री जी से और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि गंगापुर में आप खेल स्टेडियम बनाएं। बड़े कस्बों में खेल स्टेडियम बनाएं और माननीय सभापति महोदय, आपने देखा होगा, माननीय सदस्य जितेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि कबड्डी में हमारी टीम नेशनल में है, फलां में नेशनल में है, बास्केटबाल में है या वालीबाल में है, मैं पूछ रहा हूं कि हाकी का क्या हो रहा है, फुटबाल का क्या हो रहा है? यह सारे फुटबाल, हाकी जैसे गेम लुप्त होते जा रहे हैं क्योंकि खेलने के लिए फील्ड नहीं है और आजकल बच्चों को तराशने का काम पीटीआई भी नहीं कर पा रहे हैं और अभिभावक भी नहीं समझ पा रहे हैं। बच्चा अगर छोटी उम्र में भी लात मारता है, लात मारते हुए चलता है, जूते रोज फाड़कर ला रहा है तो परिवार वाले समझते हैं कि यह

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

संभलकर नहीं चलता है, रोज जूते फाड़कर लाता है। आपको यह समझना पड़ेगा, उसके अध्यापक को यह समझना पड़ेगा कि यह बच्चा जो लातें मार रहा है यह फुटबाल का खिलाड़ी बनने वाला है। यह बच्चा जो रोज पत्थर फेंक रहा है यह निशानेबाज बनने वाला है, लेकिन हम उसको रोकते हैं कि यह पत्थर क्यों फेंक रहा है, यह लाते क्यों मार रहा है। रोज जो हाथ-पैर मारता है वह अच्छा तैराक बनने वाला है, लेकिन हम उन चीजों को पकड़ नहीं पा रहे हैं तो मैं यह चाहता हूं कि ऐसे जो प्रशिक्षक कोच लगा रही है सरकार, तो वह इस ओर ध्यान दे।

खेल मैदान, विद्यालय की जो भूमि है उसमें जहां भी अतिक्रमण है तो वह हटा करके नरेगा के माध्यम से खेल मैदान बना दिए जाएं और खेल मैदानों के साथ-साथ स्टेडियम जहां बन सकते हैं वहां स्टेडियम बना दिए जाएं। स्पोर्ट्स के लिए कई भामाशाह तैयार हैं। अभी जो फैडरेशन कप हुआ वह भामाशाहों ने करवाया है। कोई कमी नहीं है पैसों की। खिलाड़ियों के लिए पैसा देने के लिए सब तैयार हैं, क्योंकि खेल को देखना चाहते हैं। खेल आपको जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ाता है और आपको स्वस्थ शरीर रखने के लिए हम भाषण देते हैं, स्वस्थ मस्तिष्क का निवास स्वस्थ शरीर में होता है तो स्वस्थ शरीर होगा कैसे? खेलों से। मूल खेलों के ऊपर हमको इस राजस्थान में ध्यान देना है। पहली बार मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में जो यह चीजें दी हैं यह बहुत सराहनीय है। 'खेल साथ रखिएगा जिंदगी की शाम में, उम्र महसूस ही नहीं होगी सफर के इस मुकाम में।' आपको महसूस नहीं होगा कि मेरी उम्र बढ़ रही है, खेल साथ रखिए आप। खेलिए, रोज शाम को खेलिए। अभी मंत्री जी विधायकों के खेल, अफसरों के खेल, सभी प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं तो मंत्री जी की भी यह भावना है कि किस तरह इस प्रदेश के अंदर ...(व्यवधान) क्रिकेट कराओ।

श्री सभापति: कृपया शांत रहें। माननीय सदस्य। सिर्फ आप ही बोल सकते हैं बैठे-बैठे? आपका अधिकार है बैठे-बैठे बोलने का?

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): गिल्ली डंडा ही ठीक है। (व्यवधान) तो यह जो खेल की भावना है और ग्रामीण खेल जो पुन: हमें प्रारम्भ करने हैं, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और ग्रामीण स्टेट चैंपियनशिप भी पुन: प्रारम्भ करनी चाहिए जो बंद हो गई है।

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि खिलाड़ियों के भत्ते, खिलाड़ियों के दैनिक भत्तों में मुख्य मंत्री जी ने 500 की जगह एक हजार और 300 की जगह 600 रुपये भत्तों में बढ़ोतरी की है। जस्ट दुगुना भत्ता बढ़ाया है। यह जो सराहनीय कदम मंत्री जी ने और मुख्य मंत्री जी ने उठाया है खिलाड़ियों के प्रति, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और हमारे अन्तर्राष्ट्रीय खेलों के लिए जो राशि बढ़ाई है ओलंपिक खेलों के लिए जो राशि बढ़ाई है, जो स्वर्ण पदक जीतने वाले को 75 लाख रुपये मिल रहे थे उसकी जगह 3 करोड़ और जो सिल्वर मैडल वाले को 50 लाख रुपए मिल रहे थे उसकी जगह मुख्य मंत्री जी ने दो करोड़ रुपये किए हैं और जो ब्रॉन्ज मैडल वाले को 30 लाख रुपये मिल रहे थे उसका एक करोड़ रुपये किया है तो माननीय सभापति महोदय, इससे यह महसूस होता है कि मुख्य मंत्री जी की भावना खेल के प्रति है और उनका रुझान है।

इस खेल के लिए खेल मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय तीनों की एक कमेटी बना ली जाए और तीनों का सेल बनाकर के और एक कमेटी बनाकर पूरे राजस्थान में खेलों के ऊपर एक ऐसी विस्तृत चर्चा हो कि तीनों विभाग मिलकर खेलों में चाहे फील्ड का काम हो, चाहे स्टेडियम का काम हो, चाहे खिलाड़ियों के कोचिंग कैंपों का काम हो, चाहे खिलाड़ियों की व्यवस्थाओं का काम हो, चाहें स्पोर्ट्स स्कूलों को चलाने का काम हो, सब व्यवस्थित तरीके से चले। उसमें नगरपालिका क्षेत्र में आप नगरपालिका क्षेत्र के जो यूडीएच के मंत्री हैं उनको भी आप इनवॉल्व कर लें, शहरी क्षेत्रों में हमारी जो यूआईटी और नगर परिषदें हैं उनके पास काफी पैसा है, सरकार का पैसा भी है। चारों मंत्री मिलकर अगर वास्तव में हम हिट राजस्थान, फिट राजस्थान और नीरोगी राजस्थान बनाना चाहते हैं तो नीरोगी राजस्थान में खेल मील का पत्थर साबित होगा और हमारे बच्चे बिलकुल स्मार्ट बनेंगे। राजस्थान के बच्चे जहां भी खेलने जाएंगे, अन्य प्रदेशों के लोग उन्हें देखेंगे कि राजस्थान की टीम आ रही है, राजस्थान की टीम बड़ी खतरनाक है, उसका एक डर और भय जो पूर्व में था, वह वापस कायम हो सकेगा। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यह चाहता हूं कि हर रेवेन्यू विलेज पर खेल मैदान हो और हर महीने खेल प्रतियोगिताएं हों। खेल प्रतियोगिता होगी तभी खेलों में निखार आयेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: आप भी तो नेशनल प्लेयर थे। श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, अपने महबूब नेता भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी का पुण्य स्मरण करते हुए मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मैं विद्यार्थी था, उन्होंने देश की हुकूमत संभाली और मेरी समझ से 1947 के बाद के प्रजातांत्रिक इतिहास में वह देश के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी सरकार का फोकस छात्र और नौजवानों पर किया।

सभापति महोदय, आपको याद होगा नई शिक्षा नीति पर उन्होंने बहस शुरू की। उन्हीं के कार्यकाल में देश की नई शिक्षा नीति आई। वो ही वह शख्स थे जिन्होंने राष्ट्रीय युवा नीति की रचना की। नौजवानों के लिए युवा एवं खेल मामलात मंत्रालय हिन्दुस्तान की हुकूमत में पहली बार खुला, तो उनके कार्यकाल में खुला और हम सभी जानते हैं कि 18 साल के नौजवानों को मताधिकार दिया तो वह स्वर्गीय राजीव गांधी की सोच थी। कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े नेताओं ने उनको यह सलाह दी थी कि आप यह मत कीजिए, इनका कोई ठिकाना नहीं है यह किस तरफ चले जाएंगे, लेकिन राजीव गांधी यह चाहते थे कि हर सत्ता को यह स्मरण रहे कि हमें देश के नौजवानों के हित में काम करना है और नौजवानों के पास वोटिंग राइट है। उनके हित में अगर काम नहीं किया तो वह हुकूमत को बदल देंगे और तमाम विरोध के बाद भी उन्होंने 18 साल के मताधिकार का हक दिया।

सभापति महोदय, इंटर कालेज लेवल पर, इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पर, वेस्ट जोन के लेवल पर, नेशनल लेवल पर, यह जितने युवा महोत्सव की कल्पनाएं शुरू हुईं वह राजीव गांधी की देन थी। इसी जयपुर शहर में मुझे याद है 1986 में वेस्ट जोन का यूथ फेस्टिवल हुआ था और इसके बाद अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई नगर में नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ तो पूरे देश की सोच, पूरे स्टेट की सोच नौजवानों की तरफ लाने का काम उन्होंने किया।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने इस बार सरकार संभाली, मैं हमारे खेल मंत्री जी को किसी तरह का दोष नहीं दूंगा। अपनी ओर से वह बैस्ट एफर्ट कर रहे हैं। संसाधन सीमित हैं, सरकार की ओर से दिया गया आय व्ययक अनुमान, अनुदान मांग का विवरण हमारे सामने है। उनके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन इन परिस्थितियों के बीच में जिस ढंग से काम करने की ऊर्जा सरकार दिखा रही है, मुख्य मंत्री जी दिखा रहे हैं, मंत्री दिखा रहे हैं, मैं उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, हमारे खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था तो पहले से ही थी लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा था। बहुत गिनी चुनी संख्या में कभी कोई हमारा खिलाड़ी सरकारी नौकरी पा जाता था लेकिन उनके रास्ते में जो अड़चनें आ रही थीं, अशोक गहलोत की सरकार ने उन अड़चनों को दूर करने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, पहले उसी खिलाड़ी को नौकरी मिलती थी जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भाग लेता था। अशोक गहलोत की सरकार ने इसमें परिवर्तन किया और राष्ट्रीय स्तर के खेलों में जो राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उस खिलाड़ी को भी सरकारी नौकरी के लिये पात्र बनाया। स्कूलों में जो नेशनल गेम्स में गया और अवार्ड लेकर आया है, उसको उसका पात्र बनाया। हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों को उसका पात्र बनाया और इंटरनेशनल लेवल पर कौनसी बाडी, कौनसे गेम में खेलने वाला पात्र होगा, उसको क्लेरिफाई किया। इतना ही नहीं, विभागों का भी दायरा बढ़ाया। पहले जितने विभाग इसके लिये नौकरी देने में सक्षम थे, उसकी भी संख्या बढ़ाई जिससे हमारे खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताऊंगा। 2013 में अशोक गहलोत जी की सरकार खेल नीति लाई। वह खेल नीति लागू होती तो राजस्थान की जनता के बहुत हित में होती। माननीय सभापति महोदय, क्रिकेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। बीसीसीआई को लेकर, आईपीएल को लेकर जो परिस्थितियां बनीं, जस्टिस लोढ़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। जस्टिस लोढ़ा की कमेटी ने क्या सिफारिशें कीं, अगर हम उसका अवलोकन करेंगे तो राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने अपनी खेल नीति में जिन बातों को शामिल किया था, लगभग हूबहू सुप्रीम कोर्ट के सामने जस्टिस लोढ़ा की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में उन बातों को शामिल किया। हमारी स्पोर्ट पालिसी में था कि खेल संघों का ड्यूरेशन 12 साल होना चाहिए और बीच में कूलिंग पीरियड होना चाहिये, यह का यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा।

माननीय सभापति महोदय, 70 साल से ज्यादा उम्र का कोई व्यक्ति संघ का चुनाव नहीं लड़ सकेगा, यह हमारी पालिसी में था, यह का यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, एक खेल संघ में पदाधिकारी रहने वाला दूसरे खेल संघ में पदाधिकारी नहीं रह सकेगा, यह भी हमारी इस खेल नीति में था और वही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, अरबों रुपये क्रिकेट के खेल में आते हैं। राजस्थान तो इस दृष्टि से इतना सक्षम नहीं था, लेकिन यह माननीय मुख्य मंत्री जी की दूरदर्शिता थी कि वह उस स्पोर्ट पालिसी में सारे खेल संघों को आरटीआई के दायरे में लाए। आज तो दिल्ली में एक ऐसी हुकूमत सरकार में बैठी हुई है जिसने आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट करके, आरटीआई के कानून को कमजोर करने का काम किया, नागरिकों के अधिकारों को कमजोर करने का काम किया और आरटीआई की उस सर्वोच्च संस्था जिसको हम सूचना आयोग कहते हैं, उसकी नियुक्तियों को भी प्रभावित करने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, 25 परसेंट खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट संघ में पदाधिकारी होने चाहिए, यह हमारी स्पोर्ट पालिसी में था और उन्हीं बातों को सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई में लागू किया है।

माननीय सभापति महोदय, अभी मुझ से पूर्व वक्ता कह रहे थे कि राजस्थान में तीन करोड़ नौजवान हैं। अपनी सरकार का बखान भी कर रहे थे। हम भी अपनी सरकार का बखान कर सकते हैं, लेकिन सरकार की ओर से हमें जो डाकूमेंट दिया गया है, वह उतना उत्साह पैदा नहीं करता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा हम सबको गंभीर होना चाहिए। मैं एक छोटी-सी घटना आपको बताना चाहता हूं। मैं गंगटोक जा रहा था। बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरा और वहां से बाई रोड जब जा रहा था, पूरे रास्ते मैंने देखा कि खेल के मैदान हैं और फुटबाल खेलते हुए बच्चे हैं बंगाल में, मन खुश हो गया। हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारे यहां अधिकांश पंचायतों में ऐसे मैदान भी नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि हम सब लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक अवसर पैदा करें जिससे राजस्थान में हमारे बच्चों को हम खेल की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा सकें।

(14.00 बजे)

सभापति महोदय, खेल से मतलब सिर्फ यही नहीं है कि शरीर फिट रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मैं आपको निवेदन करूं कि आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि किसी खिलाड़ी ने आत्महत्या कर ली है। आज हमारे 14 साल के बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, 17 साल के बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। उनको क्या चिंता होती है? उनका व्यक्तित्व कमजोर होता है, इसलिए ऐसा कर लेते हैं। सभापति महोदय, खिलाड़ी कभी आत्महत्या नहीं करते हैं, क्योंकि वह रोज जीतता है और रोज हारता है। हारना सीख जाता है। उसके

(श्री संयम लोढ़ा)

सामने कैसी भी चुनौती आये, खिलाड़ी कभी आत्महत्या नहीं करते। आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से पूरे राजस्थान के सारे अभिभावकों को विनती करना चाहता हूं कि अनिवार्य रूप से अपने बच्चों को रोजाना एक घंटे खेलने के लिए जरूर भेजें।

अभी हमारे मित्र युवा गतिविधियों की बात कर रहे थे। हम सरकार से क्या युवा गतिविधियां चलवायेंगे? स्टेट यूथ बोर्ड, 2018-19 का बजट प्रोविजन 70 लाख रुपये, 2019-20 का बजट प्रोविजन 70 लाख रुपये और 2019-20 का एक्चुअल क्या है? मंत्री जी मात्र 10 लाख रुपये, आप क्या यूथ एक्टिविटी चलाएंगे? इस साल का आपका प्रोविजन 50 लाख रुपये है। कौनसी दुनिया में ले जाकर नौजवानों को खड़ा करना चाहते हो? आप जमीन के धरातल पर आओ और सच्चाई से बात करो। हमारे बच्चों को इस तरह की दिलासा देने की कोशिश मत करो। यूथ एक्टिविटी को चलाना है तो बजट का प्रोविजन करो। बजट नहीं है। मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से विनती करुंगा, प्रतिपक्ष के नेता से विनती करूंगा कि आप दोनों बैठिए और हम सब विधायकों के विधायक कोटे से 25-25 लाख रुपये आप यूथ और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को दीजिए। हमारे बच्चों को अवसर मिलने का मंच हर लिहाज से, चाहे यूथ एक्टिविटी हो, चाहे स्पोर्टस एक्टिविटी हो, वह बनना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, यूथ एक्टिविटी का 2019-20 का क्या प्रोविजन था, 230 लाख रुपये। पिछले साल बीजेपी की सरकार से आपने ज्यादा रखा है, 172 लाख रुपये की तुलना में 230 लाख रुपये। वास्तविक बजट क्या रहा? मात्र 20 लाख रुपये। हम कहां पर खड़े हैं? अब आपने फिर 150 लाख रुपये का प्रोविजन किया है। आपने पिछला खर्चा तो नहीं किया है।

अब आप खेल गतिविधियों पर आ जाएं। 2018-19 में 1515 लाख रुपये का खर्चा हुआ, आपने 2019-20 में 1300 लाख रुपये का प्रोविजन किया और वास्तविक बजट 1070 लाख रुपये रखा। अभी आपने क्या प्रोविजन किया है, मात्र 800 लाख रुपये। आप ये क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि एससी, एसटी, इन्होंने तो कोई प्रोविजन नहीं किया। आपने 2019-20 में किया 529.17 लाख रुपये और आपका एक्चुअल 200 लाख रुपये। आपने क्या प्रोविजन किया है, पिछले 529 लाख रुपये की तुलना में मात्र 358.76 लाख रुपये। टीएसपी एरिया में आपने 522.88 लाख रुपये का प्रोविजन किया और

(श्री संयम लोढ़ा)

आपका एक्चुअल 200 लाख रुपये है। क्या आप संवैधानिक बाध्यता की अवहेलना नहीं कर रहे हैं? क्या आपको संवैधानिक बाध्यता के हिसाब से इसमें 13 परसेंट जो शेयर बनता है, उसके मुताबिक स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए पैसा नहीं देना चाहिए? उसका भी आप उल्लंघन कर रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र के नौजवानों के स्पोर्ट्स के लिए आपको जो पैसा देना चाहिए, वह पैसा आप नहीं दे रहे हैं। मंत्री जी, अब की बार भी आपने मात्र 354 लाख रुपये का प्रावधान किया है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बीच में विधायक के रूप में गोल्ड विनर, अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी कृष्णा पूनियाॅ जी भी हैं। मैं अभी खिलाड़ियों को इनाम देने की लिस्ट पढ़ रहा था। जो स्वीकृतियां आपने खिलाड़ियों के लिए जारी की। 2018-19 में 14 करोड़ रुपये जारी किये गये और अभी आपने 3 करोड़ 15 लाख रुपये जारी किये हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कारपोरेट से लें। मंत्री जी, आप तो खुद समक्ष हैं, आपका इतना प्रभाव क्षेत्र है, आप चाहें तो इसके लिए पैसे जुटा सकते हैं। (व्यवधान) अच्छी बात है, आप जवाब में बता देना।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम थी, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान। हमारे स्टेट का क्या टारगेट था? 8 हजार 686 ग्राम पंचायतों में अब हमको खेल मैदान बनाना है। अशोक गहलोत जी की सरकार ने पहले साल 2008-09 में 818 बनाये, फिर 502 बनाये। 2013 में सरकार बदल गयी। श्री नरेंद्र मोदी प्रधान मंत्री के रूप में आसीन हुए और 1 अप्रैल, 2014 को वह योजना बंद कर दी। 2008-09 में आपने पूरे राजस्थान की ग्राम पंचायतों के अंदर 708 क्रीड़ा शिविर भी लगाये थे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आपने जो अपने विभाग की बजट विवरणिका उपलब्ध करवायी है, 2018-19 में 70.34 करोड़ रुपये का बजट प्रोविजन था, 2019-20 में 56.97 करोड़ रुपये और आपका है 40 करोड़ रुपये, यह घटते क्रम में है।

माननीय सभापति महोदय, आपने ये घोषणाएं तो की हैं। ओलम्पिक में आप स्वर्ण पदक विजेता को 75 लाख रुपये से 3 करोड़ रुपये देंगे, रजत पदक विजेता को 50 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये देंगे, कांस्य वाले को 30 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये देंगे। मानकर चल रहे हैं कि नहीं आएंगे। यह

(श्री संयम लोढ़ा)

मानकर चल रहे हो कि कोई अवार्ड आने वाला ही नहीं है। कुछ तो पैसा रख लेते, उम्मीद रख लेते कि हां भई कोई एक-आधा अवार्ड आएगा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने 500 कोच लगाने की घोषणा की है और आपने जो भत्ता बढ़ाया है, उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं।

अभी आपकी सरकार आने के बाद यह अच्छी खबर थी। असम में जो गेम्स हुए, उसमें राजस्थान ने अच्छा परफोर्म किया। हमने 51 पदक जीते, स्वर्ण भी जीते, रजत भी जीते। लेकिन माननीय मंत्री जी, आप देखना कि टेबिल टेनिस और लॉन टेनिस में हमारी जीरो परफोर्मेंस क्यों रही? राजस्थान इसमें बैटर रहा है। लॉन टेनिस तो राजस्थान में खासतौर पर जयपुर में तो बहुत अच्छे ढंग से चलता रहा है।

मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि आपने 17 जगहों पर अकादमियों की स्थापना कर रखी है, अलग-अलग ढंग की हैं। जिसमें कई जगहों पर तो आपके प्रशिक्षक ही नहीं हैं। कई जगहों पर जो रहने वाले बच्चे हैं, उनको खाने-पीने की भी दिक्कतें हैं। कई जगहों पर आपकी अकादमियां किराये के भवन में चल रही हैं। माननीय मंत्री जी, मैं एक चीज नहीं समझ पाता हूं कि आपके पास माउंट आबू के अंदर ऐतिहासिक धरोहर है पोलो ग्राउंड, जहां पर अंग्रेजों के जमाने से पोलो के मैच हुआ करते थे। उस पर आपकी कृपा क्यों नहीं हुई? सिरोही में आपके पास स्टेडियम के लिए जमीन अलोटेड है। शिवगंज में भी आपके पास इनडोर स्टेडियम के लिए जमीन अलोटेड है। इतनी अकादमियां आपने दूसरी जगह खोलीं। आप ग्रीष्मकालीन शिविर 61 साल से माउंट आबू में लगा रहे हैं। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरी बहन भी वहां उस कैम्प में गयी थी। वह बास्केटबाल खेलती थी। तत्कालीन मुख्य मंत्री जी भैरोंसिंह जी शेखावत ने माउंट आबू के अंदर स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स का शिलान्यास किया था। मैं खुद जाकर वहां लगा हुआ पत्थर देखकर आया था। आप उसे बनाइये। पूरे राजस्थान के बच्चे वहां पर आते हैं। उनको हम एक अच्छा माहौल दे सकें, अच्छी सुविधाएं दे सकें। माउंट आबू आने का सारे बच्चों में अट्रेक्शन भी रहता है। एक नहीं, अगर आप वहां व्यवस्था बढ़ाएंगे तो अनेकानेक कैम्प वहां पर लग सकेंगे, अनेकानेक आयोजन हो सकेंगे। 2008 में पोलो मैच हुआ था, मैं उसमें मौजूद था। आप स्वयं पोलो के खिलाड़ी हैं। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप समय निकालें। माउंट आबू को उसकी विरासत, उसकी वह गौरवशाली प्रतिष्ठा फिर से अता फरमाएं जिससे माउंट आबू पुन: उस केन्द्र के रूप में विकसित हो सके।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि राजस्थान के खेलों में यह अराजकता कौन लेकर आया है। आपको याद होगा कि यह प्रोविजन किया गया था कि वही व्यक्ति खेल संघ का चुनाव लड़े, जो राजस्थान का मूल निवासी हो। अब ये राजस्थान के मूल निवासी होने के प्रावधान को किसने हटाया? ये ही पिछली बीजेपी की सरकार ने डोमिसाइल की शर्त हटाई। पहले बाप के लिए हटाई, फिर बेटे के लिए हटाई। सालों साल राजस्थान की क्रिकेट अदालतों के दरवाजे पर जाकर खड़ी रही। हमारे खिलाड़ियों को न रणजी खेलने का मौका मिला, न दलीप ट्राफी खेलने का मौका मिला, न कोई और खेलने का मौका। जिला स्तर पर क्रिकेट के टूर्नामेंट बंद हो गये सालों-साल। बीसीसीआई से पैसा आना बंद हो गया। यह सब पाप किसने किया? सिर्फ +++

माननीय सभापति महोदय, अभी मैं अख़बार में पढ़ रहा था स्विस बैंक ने खातों का ब्यौरा मांगा। ये स्विस बैंक के हीरो को राजस्थान की क्रिकेट का हीरो बनाने वाले कौन लोग थे? माननीय सभापति महोदय, किस तरह की अराजकता क्रिकेट अकादमी के ग्राउण्ड पर हुई, लेकिन इस सरकार ने आने के बाद वह सारी दुविधा खतम की। सारी अड़चनें खतम कीं। सामान्य तरीके से क्रिकेट के चुनाव हुए। श्री वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने। आईपीएल के मैच भी शुरू हुए। जयपुर में नया क्रिकेट का स्टेडियम बनाना, उदयपुर में क्रिकेट का स्टेडियम बनाना, पिछली अशोक गहलोत की सरकार जमीन आबंटित करके गई। पैसा भर कर गई और आपने उस जमीन को निरस्त करने का पाप किया था, उस जमीन को निरस्त करने का। अब फिर वह रास्ता खुला है जिसके माध्यम से...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने...

श्री सभापति: आप विराजिए। माननीय सदस्य, आप विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आरोपों की बौछार कर दी। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि अगर किसी पर आरोप लगाने हैं तो ...(व्यवधान) नोटिस लेकर आएं। आज जो सदन के सदस्य नहीं है। हमारी परम्पराएं रही हैं, हमारे नियम हैं। इस प्रकार के अनर्गल आरोप ऐसे सीनियर लोगों के साथ, आप यह भी बता देते कि ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप उस भगोड़े के लिए आकर के खड़े हुए हैं यहां। उस भगोड़े के लिए जिसके लिए भारत सरकार ने रैड अलर्ट कर रखा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): 000

श्री सभापति: माननीय उपनेता महोदय, आप विराजिए। एक मिनट विराजिए। माननीय सदस्य सब विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। कुछ परम्पराओं का पालन कर लीजिए। अंकित नहीं हो रहा है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

श्री सभापति: मैं बार-बार आपसे आग्रह कर रहा हूं, विराजिए आप। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: आप विराजिए। मैं कुछ बोलूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। माननीय उपनेता महोदय, विराजिए। मैं कुछ बोलूं। सहयोग करिए। मैं कुछ बोल रहा हूं। प्लीज सहयोग करिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री सभापति: विराजिए। किसी का भी अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्या, विराजिए।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): 000

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री सभापति: माननीय उप नेता महोदय, अपने सदस्य को बोलें कि बैठें वे। विराजिए। आप तो काफी लंबे समय से आ रहे हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से आग्रह करना चाहूंगा, सदन के कुछ नियम-कायदे बने हुए हैं। किसी भी माननीय, पूर्व सदस्य हो या वर्तमान हो, किसी के खिलाफ यदि कुछ भी बात आपको कहनी है तो नियमों में आना पड़ेगा। नियमों में पहले आप लिखित में देंगे कि मुझे फलां मंत्री के खिलाफ या मुख्य मंत्री के खिलाफ या किसी माननीय विधायक, माननीय सदस्य, मैं अलाउ नहीं करूंगा, आप लिखित में दीजिए। आप दीजिए कि मैं इनके खिलाफ यह बोलना चाहता हूं ताकि मंत्री अपनी बात कहें या जो भी माननीय सदस्य हैं, अपनी बात कहें। माननीय सदस्य ने जो भी कुछ ऐसा कहा है, जो नियमों में है, विलोपित किया जाए। माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें। विराजिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं तो हमेशा नियमों में ही बोलता हूं और आपकी आज्ञा का हमेशा पालन करता हूं। जब खेल की बात चलेगी तो राजस्थान के क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के बारे में एक बार नहीं, हजार बार इस सदन के अंदर बात होगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं अलाउ नहीं करूंगा। कुछ भी अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: आप सब बैठिए। आप सब विराजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, आप हमको समय सीमा में बांधते हो। 15 मिनट में बांधते हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप सब विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: आप इनको बोलने दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हमारे पहले वक्ता को भी आपने 25 मिनट पर टोक कर बैठा दिया, हम बैठ गये। बाकी सबको आप दस मिनट दे रहे हैं, वह भी हमने स्वीकार कर लिया तो इनके लिए भी कोई समय-सीमा है या नहीं है? अगर नहीं है तो फिर हमारे लिए भी नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: मैं अलाउ नहीं करूंगा। विराजिए। सब विराजिए। माननीय सदस्या। आपके नेताओं के माध्यम से जो भी मेरे पास पर्चियां आई हैं, निर्दलीय विधायक जो भी पहली बार बोल रहा है, उसको 20 मिनट दिए हैं। आपके माननीय सदस्य जो प्रथम वक्ता थे, वे 35 मिनट बोले, कांग्रेस की तरफ से जो माननीय सदस्य पहली बार बोले, वे 12-13 मिनट बोले। मुझे किसी बात में इंटरेस्ट नहीं है कि कौन कितना बोल रहा है। आप लोग जो भी अच्छी बात बोल रहे हैं, मुझे स्वयं भी रुचि है कि सदन अच्छी बात सुने। इधर-उधर की यदि कोई आदमी फेंक रहा है, यदि आपने लिखकर दिया है, तब भी मैं उसको अलाउ नहीं करूंगा। मैं यह चाहता हूं कि सदन परम्पराओं से चले, नियमों से चले। कल भी कई माननीय सदस्य बिना बोले रह गये। आपके उप-नेता महोदय भी बिना बोले रह गये। माननीय अध्यक्ष महोदय

(श्री सभापति)

आएंगे, अपनी व्यवस्था देंगे कि 8 बजे आपके मंत्री का रिप्लाई होना है। जो लोग नये आ रहे हैं, आप उनको बोलने का अवसर दें। मैं फिर आग्रह करूंगा पूरा राजस्थान आपको यू ट्यूब पर देख रहा है। जितनी गंभीर बात आप कहेंगे, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, तीस साल से मैं भी इसी सदन में हूं, मैंने भी इस सदन से ही सीखा है। यहां जो कुछ सीखना है, उसके लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं है। जो कुछ अच्छी बात आप सीखेंगे, वह यहीं से सीखेंगे। राजस्थान आपसे अपेक्षा करता है। साढ़े सात करोड़ में से दो सौ लोग आप हैं। अपना महत्व समझिए कि कितने महत्वपूर्ण लोग हैं आप। आप इतना कैजुअल लेते हैं हाउस को। मैं यहां आपके लिए चार-साढ़े चार घंटे क्यों बैठा रहूं? क्यों बैठा रहूं? यह सज़ा क्यों भुगतूं मैं यहां पर बैठकर? मैं सिर्फ इसलिए बैठता हूं कि सदन में जो भी माननीय सदस्य आए हैं वे अपनी बात शालीनता से कहें, नियमों में कहें और पूरी परम्पराओं का पालन करते हुए कहें। सदन की गरिमा भी बनी रहे। सदन की गरिमा इन कुर्सी-टेबल और इसकी सुंदरता से नहीं है। सदन की गरिमा इस बात से है कि आप कितना अच्छा बोलते हैं, आप कितना नियमों का पालन करते हैं? मैं भी सदन का सदस्य रहा हूं। मुझे बड़ा दुख होता है माननीय नेता महोदय, जब एक सदस्य किसी दूसरे वक्ता के सामने से इधर से उधर गुजरता है। जब किसी का मन होता है इधर से उठकर उधर आ जाता है, जब किसी का मन होता है उधर से उठकर इधर आ जाता है। हमें भी उन माननीय नेताओं ने सिखाया है जो यहां बैठे थे। उन्होंने कहा कि परम्पराओं का पालन करो। 30 साल में कुछ सीखा है, इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। बारबार आपको टोकना पड़ रहा है, बार -बार कहना पड़ रहा है। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? आसन आपको व्यवस्था देता है कि विराजिए, आप नहीं बैठते। आसन आपको बार-बार कहता है आसन पैरों पर, आसन अपनी सीट पर खड़ा हो जाए क्या यहां? यह ड्यूटी माननीय अध्यक्ष महोदय की है, वह सुबह से शाम तक बैठें यहां? उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी कि मैं यहां सभापति के पैनल पर आऊं, यहां बैठकर, साढ़े चार घंटे लगातार आपकी बात सुनता रहूं। पांच पांच घंटे यहां बैठता हूं। आपकी यदि इसी बात में रुचि है कि आपको सिर्फ अखाड़ा बनाना है, मैं अलाउ नहीं करूंगा। इन फालतू बातों से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। सदन नियम और परम्पराओं से चलेगा। कोई आदमी चाहता है कि मैं

(श्री सभापति)

फलां व्यक्ति हूं और अपनी मर्यादा तोड़ दूंगा तो मैं न इधर अलाउ करूंगा न इधर अलाउ करूंगा।

माननीय गर्ग साहब, जब मैं कहूं कि आपको बैठना है तो आप समय सीमा का ध्यान रखेंगे। यह आक्षेप सुनने को मैं तैयार नहीं हूं कि आपने उनको इतना टाइम दे दिया, उनको इतना दे दिया। मेरे लिए आप सब बराबर हैं। सब मेरे मित्र हैं, माननीय विधायक हैं। अब आप हाथ खड़ा नहीं करेंगे। आप बार-बार अपना हाथ ऊपर करते हैं, मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगता। आपके नेता महोदय बोल रहे हैं, आपके उप नेता बोल रहे हैं, पीछे से आप कभी हाथ, कभी गर्दन, कभी इधर, कभी उधर। माननीय जोगेश्वर गर्ग, आपको 15 मिनट का समय दिया है। आप समय का पालन करेंगे और ध्यान रखेंगे।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि मैं सही बोलूंगा, अच्छा बोलूंगा, इसलिए प्लीज आप कोई टोकना मत।

श्री सभापति: वचनों में कहां दरिद्रता है। वचनों में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा है वचनों में कहां दरिद्रता है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अब आप थोड़ा शांत मूड में आ जाइये।

श्री सभापति: वचनों में हम दरिद्रता रखेंगे? भगवान ने किसी को गोरा रंग दिया है, किसी को काला दिया, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को मोटा बनाया, वाणी तो हम सबको अच्छी दी है। वाणी का यदि हम सही इस्तेमाल नहीं कर सकते, बड़ा खेद है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, आसन का धन्यवाद कि उन्होंने वैज्ञानिकों और खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करने के लिए इतना पर्याप्त समय दिया। ये विषय हमेशा अछूते रह जाते हैं। वैज्ञानिक और खिलाड़ी ऐसी चीज है जो किसी फैक्टरी में पैदा नहीं होते हैं। कोई किसी को वैज्ञानिक या खिलाड़ी बनाना चाहे तो नहीं बना सकता। ईश्वरीय प्रेरणा से, प्राकृतिक रूप से ही बनते हैं। वैज्ञानिक पढ़ लिखकर बनते हैं यह तो ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक जन्मजात भी होते हैं। इस देश की धरती पर ऐसे अनेकों जन्मजात वैज्ञानिक हुए हैं और हो रहे हैं, हमारा ध्यान उधर नहीं जाता है। मैं नाम लेना चाहूंगा, तखतगढ़ में स्वर्गीय पी.एल. मिस्त्री हुआ करते थे, पाली ज़िले का एक छोटा सा कस्बा है तखतगढ़, पी.एल. मिस्त्री अंगूठा छाप थे, बाद में साक्षर हुए।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

लेकिन विज्ञान में उनका दिमाग इतना चलता था कि उन्होंने ऐसी-ऐसी चीज़ें बनाई जो बड़े-बड़े वैज्ञानिक नहीं बना पाए। एक पटरी पर दो ट्रेन आमने सामने आ गई, तो अपने आप उनको ब्रेक लग जाएंगे, यह सिस्टम 50 साल पहले ही उन्होंने बना लिया था। इस देश का दुर्भाग्य है कि देश उस सिस्टम का अभी तक उपयोग नहीं कर पा रहा। इस प्रकार के वैज्ञानिक अब भी पैदा होते हैं।

अलवर ज़िले का 12वीं कक्षा का बालक मुझे याद आ रहा है। व्हाट्सएप के मुकाबले का उसने एक एप बनाकर दे दिया। मैंने उस एप को डाउनलोड किया और चलाया तो वह सफलतापूर्वक चला। कोई कमी नहीं उसमें और व्हाट्सएप में। अलवर का बालक, साधारण परिवार का बालक।

एक बालक के बारे में अख़बार में पढ़ा था, किसान का बेटा है। उसके पिताजी खेती करते है, ट्रैक्टर चलाते हैं, ज्यादा उम्र हो गई, ट्रैक्टर चलाने में उनको तकलीफ होने लगी। उस बच्चे ने अपने पिताजी की उस तकलीफ को दूर करने के लिए ट्रैक्टर को चलाने वाला रिमोट, घर बैठे घरेलू सामान से बना दिया। वह कोई इसरो में नहीं गया। उसने रिमोट बनाकर अपने पिताजी को दे दिया, उस रिमोट से ट्रैक्टर चलते हुए मैंने वीडियो में देखा है तो इस तरह के वैज्ञानिक गांव-गांव में हैं। कुछ लोगों की हेरेडिटी, कुछ लोगों के खून में विज्ञान है, उन विद्यार्थियों की हम पहचान करें, उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने की हम व्यवस्था करें। अक्सर उलट होता है, उनको डांट डपट कर बिठा दिया जाता है कि तू क्या जानता है, किताब में तो यह लिखा है। किताबी ज्ञान से आगे भी बहुत कुछ होता है। ऐसे वैज्ञानिक को पहचान कर हम आगे बढ़ाएं तो मैं समझता हूं कि यह राज्य व देश के हित में होगा।

खेलों की बात करें, राजनीति विज्ञान भी है जो कालेजों में पढ़ाई जाती है, पालिटिकल साइंस और राजनीति एक खेल भी है। उस खेल को 72 साल से देश खेल रहा है। कई लोग अच्छे से खेलते हैं, कई लोग फाउल भी खेलते हैं। दुनिया के सारे खेलों में फाउल खेलने वाले को तुरंत आउट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। राजनीति एक ऐसा अजीब खेल है, यहां फाउल खेलने वाला ही ज्यादा सफल होता है, वह ज्यादा आगे बढ़ता है, उसकी कोई व्यवस्था बनाने की अपने को कोशिश करनी चाहिए।

खुशी होती है, गर्व होता है जब आदरणीय अशोक चांदना और कृष्णा

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

पूनियॉ जी, राज्यवर्धन सिंह, गौतम गंभीर जैसे लोग, इस राजनीति के खेल में भी सफल होकर आगे बढ़ पाते हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। सरकार को धन्यवाद देता हूं कि एक खिलाड़ी को उन्होंने खेल मंत्रालय का काम दिया वर्ना अक्सर यह होता है कि जिसने जिंदगी में बैट नहीं पकड़ा, वह यह तय करता है कि कौन खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा। खेल संघों की राजनीति है, इसके बारे में गहनता से विचार किया जाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे खेल संघों में हमने विवाद देखे हैं, बहुत सारे खेल संघों में, ज़िले से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कई लोग कुंडली मार कर बैठे हैं, हटते ही नहीं हैं, जबकि खेल में उनका कोई योगदान नहीं है। जिंदगी में कभी नहीं खेले, उनकी सात पीढ़ी में कोई नहीं खेला, लेकिन उस खेल का सारा निर्णय वह करते हैं, सारा कंट्रोल उनके हाथ में होता है। इसके कारण भी हमारी खेल प्रतिभाएं बहुत जगह पिट रही हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस प्रदेश का खेल मंत्री रहा। माननीय भंवर लाल जी शर्मा कैबिनेट मंत्री थे और मैं उनके साथ राज्य मंत्री था। उस समय मुझे भी खेलों को समझने का अवसर मिला। खेलों को तो समझ लिया, खेल की राजनीति नहीं समझ पाया। खेल की राजनीति से खेलों को मुक्त कराने की बहुत गंभीर आवश्यकता है, उसके लिए हर तरफ से प्रयास किए जाने चाहिए।

आरसीए में इतने लंबे-चौड़े विवाद चले, जिसकी चर्चा अभी हो रही थी। यदि पहले ही बता देते कि वैभव जी को लाने से ही आरसीए शांत होगा, तो पहले ही ले आते हम। फिर वही बात आती है। मुझे वह खबर पढ़कर बहुत दु:ख हुआ, जिस कपिल देव के नेतृत्व में भारत पहली बार वर्ल्ड कप जीत कर आया था, वह कपिल देव वीसीसीआई का चुनाव लड़ता है और हार जाता है, वह अंदर नहीं घुस पाया। खिलाड़ियों का निर्णय करने के लिए खिलाड़ी नहीं पहुंच पाता और गैर खिलाड़ी निर्णय करते हैं। उसके कारण से हमारी प्रतिभाएं पिटती हैं।

सरकार अपने आपको बड़ा खेल हितैषी कह रही है। मेरे सामने 2019-20 का बजट है, बिन्दु क्रमांक 135, उम्मेद स्टेडियम जोधपुर में दर्शकों की सुविधा के लिए शैड निर्माण करने हेतु 2 करोड़ प्रस्तावित है। पिछले हफ्ते एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने बताया कि उम्मेद स्टेडियम में शैड का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। अगर इस हफ़्ते में कर दिया हो तो पता नहीं। पिछले बजट की घोषणा की यह हालत है।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

मैं कल कृष्णा जी से बात कर रहा था कि आप खेल से जुड़ी हुई हैं, सजीव जुड़ी हुई हैं आपने बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है। आपने अपने क्षेत्र में खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ काम करवाए होंगे, कुछ हमको भी बताइये, हम भी करवाएं। उन्होंने कहा कि गए साल के बजट में एक स्टेडियम का प्रावधान हुआ था कि राजगढ़ में स्टेडियम बनेगा। मैंने पूछा कि बन गया क्या? वह थोड़ी-सी हिचकिचाने लगी, मैंने पूछा क्या हुआ, बना नहीं क्या तो उन्होंने कहा कि अभी तो काम ही शुरू नहीं हुआ। आप घोषणाएँ खूब कर रहे हैं। कर्मवीर भी बनिए।

बिन्दु नम्बर 137 पर आपने घोषणा की थी प्रदेश के अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को वित्तीय संबल देने के लिए हम नवीन पेंशन योजना लाएंगे और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक पाने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नवीन छात्रवृत्ति योजना लाएंगे। पेंशन योजना आ गई क्या? गत बजट की घोषणा है। पेंशन योजना का अभी तक कोई अता पता नहीं है। छात्रवृत्ति योजना के लिए आपने कहा था वह नहीं आई, उसकी जगह आपने एक नीति तो बनाई है, उसमें यह है कि एकमुश्त राशि देंगे, वह छात्रवृत्ति नहीं है। जो एकमुश्त राशि देते हैं, वह अकसर एक साथ खतम हो जाती है। बाद में छात्र को, उस खिलाड़ी को अपनी डाइट मेन्टेन करने के लिये, अपनी किट मेन्टेन करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, रैकरिंग एक्सपेंसेज के लिए, वह उसको नहीं मिल रहा है। इसलिये हमने एकमुश्त की घोषणा तो की है, वह भी अभी तक घोषणा ही है। नियम अभी कुछ महीने पहले बने हैं। उन नियमों के अंतर्गत एक भी खिलाड़ी को आपने एकमुश्त राशि दी हो तो आप मुझे बताइए।

बिंदु क्रमांक 138, गये साल का, राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिये सरकारी प्रयासों के साथ-साथ सक्रिय जुड़ाव भी आवश्यक है। इस हेतु हम एक उद्यमी एक खेल योजना लाएंगे। पिछले बजट से अब तक में कितने उद्यमियों को आपने एक-एक खेल सौंप दिया? यदि ऐसा कुछ किया हो तो खेल मंत्रीजी अपने जवाब में बताएं। मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बहुतकुछ हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ है।

139 नम्बर का जो बिंदु है उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। एशियन गेम्स, नेशनल गेम्स की तर्ज पर मैं राजस्थान में राज्य खेल

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

प्रारम्भ करने की घोषणा करता हूं। आपने किया, पिछले महीने ही किया, अच्छा किया, अच्छा आयोजन किया। हजारों की संख्या में पूरे राजस्थान से यहां खिलाड़ी आये और अपनी-अपनी योग्यता को प्रदर्शित करके गये। जालौर से भी हमारे ढाई सौ खिलाड़ी आये थे। एक मेरे जिले से ढाई सौ खिलाड़ी आये थे। यह काम जरूर आपने अच्छा किया है। उसके लिए मैं सरकार की तारीफ करता हूं।

अब इस साल के बजट पर आएं। बिंदु क्रमांक 68, हाल ही में सम्पन्न हुई राज्य खेल प्रतियोगिता में लगभग 8 हजार खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसकी तारीफ चारों तरफ हो रही है, मैं भी कर रहा हूं। पहली बार सम्पन्न हुए इन खेलों का ही नतीजा था कि असम में हुए इंडियन यूथ गेम्स 2020 में राज्य का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। खेलों के प्रति जागरूकता लाकर हम फिट राजस्थान, हिट राजस्थान के लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएंगे। जिस सरकार का मुखिया कह रहा है, फिट राजस्थान- हिट राजस्थान, उस फिट राजस्थान हिट राजस्थान की क्या दुर्गति होने वाली है, वह अभी आपने देखा, मेरे से पूर्व जो माननीय विधायक बोल रहे थे, सहाड़ा से आने वाले, उसको उलटा लटका रहे हैं। हिट राजस्थान-फिट राजस्थान, हिट करके फिट तो कारीगर करता है। पहले फिट करिए फिर हिट करिए। यह उलटा ही बोलेंगे तो परिणाम उलटे आने वाले हैं।

बिंदु क्रमांक 69, ग्राम स्तरीय खेल प्रतिभाओं की खोज कर आगे लाने के लिए राज्य खेलों की तर्ज पर हम ब्लाक स्तरीय, जिला स्तरीय खेलों का आयोजन करेंगे, जिससे वर्ष 2022 में होने वाले राज्य खेल और अधिक सफल हो सकेंगे। यहां तक बहुत अच्छा है। अंतिम लाइन पढ़िये, मंत्री महोदय, इस हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा जाएगा। यह ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। इतने बड़े राजस्थान में आप ब्लाक स्तर तक खेलकूद प्रतियोगिता करवाना चाहते हैं, पांच करोड़ रुपये में किसी कीमत पर सम्भव नहीं है। वह केवल वह रीत का रायता, जैसे मारवाड़ी में कहते हैं, आप एक फार्मेलिटी तो कर लेंगे, नाम तो कर लेंगे, पर काम नहीं होने वाला है।

आप पंचायत समिति लेवल तक स्टेडियम बनाने की बातें कर रहे हैं, मैं एस.एम.एस. स्टेडियम की बात करना चाहूंगा। वहां के क्या हाल हैं। वहां की व्यवस्थाओं में बहुत सुधार की जरूरत है। मैं जब राज्य मंत्री था तो

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

साइकिलिंग वालों के लिए साइकिल वैलोड्रम का प्रस्ताव हुआ था। साइकिलिंग एसोसिएशन मेरे पास आई थी। मैं उनको लेकर भंवरलालजी शर्मा साहब के पास गया, फिर मुख्य मंत्रीजी के पास गया। उन्होंने उस समय काम हाथ में लिया था। वह 1995-96 में जाकर पूरा हुआ। आपके पास उसको रिपेयर करने की फुर्सत नहीं है। उस पर जब साइकिल घूमती है तो जगह-जगह उसके ज्वांइट्स हैं, वे ज्वांइट्स इतने चौड़े हो गए कि धचका लग रहा है और उन साइकिलों के टायर खराब हो रहे हैं। आपको वह ठीक करने की फुर्सत नहीं है। साइकिलिंग में राजस्थान का बहुत बड़ा नाम रहा है। जिसमें बीकानेर है, बीकानेर ने हमको बहुत अच्छे साइकिलिस्ट दिये हैं। बीकानेर में साइकिलिस्ट्स के लिए क्या व्यवस्था है, कुछ नहीं, लगभग जीरो। जो थोड़ी-बहुत पुरानी बनी हुई थी, वह भी खतम हो गई। उसको भी वापस आधुनिकतम सुविधाएं हमको देनी चाहिए थीं, वे हमारे पास नहीं हैं। साइकिलें बहुत महंगी आती हैं। सस्ते से सस्ती एक लाख के आसपास आती है। अगर वर्ल्ड लेवल का खिलाड़ी पैदा करना है तो ढाई-तीन-चार-पांच लाख की साइकिलें देनी पड़ती हैं। सरकार के पास उनको देने के लिए पैसा है? आपने आज तक एक भी साइकिल बांटी है? नहीं, वह खिलाड़ियों के जिम्मे है कि आप खुद लेकर आएं।

अब वेटलिफ्टिंग में हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छा रिकार्ड कर रहे हैं। आपके एस.एम.एस. स्टेडियम की यह हालत है कि वेटलिफ्टिंग के लिए, पावर लिफ्टिंग के लिये एक बैंच लगी हुई है। उस बैंच पर लेट कर खिलाड़ी वजन उठाता है। वह वज़न स्टैण्ड पर रखा होता है। मंत्री महोदय उस बैंच पर लेट कर जब खिलाड़ी उस वज़न को उठाता है तो वह स्टैण्ड डोलता है।

श्री सभापति: आप अपनी बात दो मिनट में समाप्त करिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): जब वह वापस रखता है तब तक उस खिलाड़ी को वहम पड़ जाता है। पता नहीं, वह उस स्टैण्ड पर जाएगा कि मेरे माथे आएगा। इतनी सी देख-रेख नहीं हो रही है। यह बात भी मंत्री तक बतानी पड़ेगी क्या, विधान सभा तक बतानी पड़ेगी क्या? आपके अफसर क्या कर रहे हैं। इतने सारे अफसर स्टेडियम में लगे हुए हैं। आपकी स्पोर्ट्स कौंसिल क्या कर रही है? आपने खिलाड़ी को खेल मंत्री बहुत अच्छा दे दिया, बहुत अच्छी बात है। मेरा सुझाव है कि स्पोर्ट्स कौंसिल की चेयरमैनशिप कृष्णाजी को

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

दीजिए, फिर देखिए आपके स्टेडियम की हालत क्या सुधरती है। खिलाड़ियों को मौका दीजिए, खेल के जानने वालों को मौका दीजिए।

मंत्री महोदय, हर जिले में जो खेल अधिकारी लगाये हैं, मैं राज्य मंत्री था, तब यह लक्ष्य पूरा हुआ था। उस समय आधे से ज्यादा जिलों में खेल अधिकारी नहीं थे। माननीय भैरोंसिंहजी के प्रयास से हर जिले में खेल अधिकारी हुए। जब मैं जालौर का मुद्दा उनके ध्यान में लाया तो उनको ध्यान आया, और कितने जिले हैं, तो फिर उन्होंने सारे किये थे। खेल अधिकारियों की हालत यह है कि आज आधे से ज्यादा खेल अधिकारियों के पद खाली हैं। मेरे जालौर का स्टेडियम और खेल कार्यालय एक चपरासी के भरोसे चल रहा है। वह एक चपरासी परमानेंट है। फिर बाकी कामों के लिए डेपुटेशन पर एक पी.टी.आई. को ले रखा है, बस। एक भी कोच नहीं, एक भी अधिकारी नहीं। खिलाड़ियों के काम कैसे होंगे। खिलाड़ियों को जगह-जगह पर, हर प्रतियोगिता के समय उनको आवश्यकता पड़ती है। उनके लिये सैंक्शन निकालनी पड़ती है, उनकी अनुमतियां जारी करनी पड़ती है, आगे भेजनी पड़ती है, वह सारा करने के लिए कोई हमारे पास नहीं है। जोधपुर से अफसर आता है, जब उसका मूड होता है, तब आता है। स्टेडियम्स में सामान कुछ नहीं है। स्टेडियम्स की हालत यह है कि कहने को वे खेल स्टेडियम हैं, व्यापार मेला लगना है, स्टेडियम में लगेगा।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अभी से? जैसे आप संयम लोढाजी के लिए घड़ी बंद कर देते हैं, मेरे लिए भी थोड़ी देर बंद कर दें, प्लीज।

श्री सभापति: 15 मिनट हो गये आपको, 2.22 पर बोलना शुरू किया था, अब 2.37 हो रहे हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): स्टेडियम की हालत यह है कि वहां खेल को छोड़कर सारे काम होते हैं। चुनाव का काम होगा, स्टेडियम में होगा, मेला लगेगा स्टेडियम में लगेगा। मुश्किल से मेहनत करके उस ट्रैक को तैयार करते हैं या खेल मैदान को तैयार करते हैं और एक मेला लगता है, सारा सफाया। मेहरबानी करके स्टेडियम में ये मेले लगाने बंद करिए। मेलों के लिये अलग जगह ढूंढ कर दे दीजिए और स्टेडियम्स को माफ करिए।

मैं आखिरी दो-तीन मिनट में मेरे जालौर की बात करता हूं। जालौर ने बहुत अच्छे बाक्सर्स दिये हैं, नेशनल लेवल के बाक्सर्स दिये हैं, नेशनल लेवल

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

के रेसलर्स दिये हैं। हर साल दे रहा है। आपने उनके लिये क्या किया। क्या सरकार बाक्सर्स के लिये, रेसलर्स के लिये वहां एक अकादमी खोलेगी? जालौर की पहचान है वीर वीरमदेव, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में वह खुद एक बहुत बड़ा मल्ल था। उसी परम्परा का जालौर आज भी निर्वाह कर रहा है। बहुत अच्छे बाक्सर्स हम हर साल दे रहे हैं, लेकिन उनके लिये सुविधा जैसी कुछ चीज नहीं है।

जालौर ने अभी-अभी एक नये खेल में भी इनोवेशन किया है, कूडो, जिसको अभी तक आपने मान्यता ही नहीं दी, नेशनल स्तर पर मिल गई। स्कूल में मान्यता मिल गई।

श्री सभापति: समाप्त करिए, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, समाप्त करिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आपकी स्पोर्ट्स कौंसिल ने मान्यता जारी नहीं की है। कूडो को इसमें शामिल करिए। जालौर ने नेशनल लेवल के खिलाड़ियों को देना शुरू कर दिया है। वेटलिफ्टिंग में बहुत अच्छे, इसमें जो स्टेट लेवल के खेल हुए, उसमें जालौर का एक वेटलिफ्टर पदक लेकर गया है। जालौर में वेट लिफ्टिंग का सामान नहीं है। इस तरह की और बहुत सारी बातें हैं। जालौर में बास्केटबाल का कोर्ट नहीं है। जालौर में जो नहीं है, वह सारे राजस्थान में नहीं है। इन्डोर गेम्स के लिये कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। कोच तो नहीं है, वह तो है ही।

आप खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में जाने के लिए भत्ता देते हैं, सभापति महोदय, यह बहुत दर्दनाक बात है। वह भत्ता उनको वहीं प्रतियोगिता समाप्त होने से पहले-पहले मिल जाना चाहिए। अकसर नहीं मिलता है। फिर कहते हैं, अभी थोड़ी दिक्कत हो रही है, अभी नहीं कर पा रहे हैं। पैसा आया नहीं है, यह नहीं, वह नहीं, आपके अकाउंट में डाल देंगे। वह अकाउंट में नहीं डलता है। जो टीम का इंचार्ज लेकर गया होता है, उसके पास चला जाता है। उसमें से आधा वह रख लेता है, आधा ही मुश्किल से खिलाडियों तक पहुंचता है। आप उनको डाइट नहीं दे रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त करिए, माननीय सदस्य, समाप्त करिए। वाकई आपके बहुमूल्य सुझाव हैं, आप लिखकर भेज देना। श्रीमती कृष्णा पूनियॉ।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): यह तो बहुत गलत बात है। मैं इतनी अच्छी-अच्छी बातें कर रहा हूं, पोजिटिव बातें कर रहा हूं।

श्री सभापति: आप लिखकर भेज दें। वाकई आपके अच्छे सुझाव हैं।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या-24 पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देती हूं कि स्पोर्ट्स को इस राजस्थान जैसे बड़े स्टेट के अंदर कैसे बढ़ावा मिले, विशेषकर यह चर्चा आज रखी गयी है।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगी कि राज्य में खेल नीति बननी चाहिए क्योंकि अभी तक हमारे स्टेट में खेल नीति नहीं है और उसके लिए हमें पहले यह जरूरी है कि जो स्पोर्ट्स हैं, उसके लिए एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बनाया जाए और एक खेल नीति बनाई जाए और उस खेल नीति के अंदर अन्तरराष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं और कोचेज हैं, उनकी राय को सम्मिलित करना और उनको जरूर इसमें रखना क्योंकि यह प्रेक्टिकल उन्होंने किया है कि किस तरीके से वह इंटरनेशनल लेवल तक अपने एथलीट को लेकर गये या एथलीट में किस तरीके से अपने आपको परफार्म किया।

माननीय सभापति महोदय, यह बड़ी विडंबना है कि आज तक जब भी कोई खेल नीति बनी या बनाने की कोशिश की गयी तो किसी भी अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को जिसने कामनवेल्थ में, ओलम्पिक में या एशियन गेम्स में मैडल जीता हो या राष्ट्रीय स्तर पर जीता हो, जिसे रखा गया हो तो सामान्य खिलाड़ी का तो हम सोच ही नहीं सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं खेल मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि इस तरीके से हमारे प्रदेश में एक खेल नीति की बहुत जरूरत है और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हमारे प्रदेश में हैं, जिनको हम इस नीति के तहत ला सकते हैं और जैसा कि खेल संघ के बारे में बात की गयी थी, माननीय श्री संयम लोढ़ाजी ने भी की थी। मैं इस विषय पर यह बोलना चाहूंगी कि जिस प्रकार से किसान अपनी फसल का मूल्य तय नहीं कर सकता, ठीक उसी तरीके से खेल जगत में इस संघ में खिलाड़ी नहीं जा सकता। यह विडंबना है किसानों के लिए भी और खिलाड़ियों के लिए। इसके लिए भी मैं यह प्रावधान रखना चाहूंगी कि खिलाड़ियों का खेल संघों के जरिए क्योंकि खेल नीति बनती है या खेल आयोजन होते हैं तो वह उस संघ के अधीन होते हैं तो उसमें हमारे खिलाड़ी होने चाहिए।

(श्रीमती कृष्णा पूनियाॅ)

साथ में, खेल अनिवार्य विषय जरूर होना चाहिए। जैसा कि पिछली बार भी जब शिक्षा के ऊपर चर्चा थी, तब भी मैंने यह बोला था। आज बड़ी विडंबना है कि हमारे राज्य में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वह एक बिल्डिंग में चल रहे हैं और मैं खुद भी सरकारी स्कूल में पढ़ी हूं। छह वर्ष की आयु में जाकर एडमिशन मिलता था और हम खेलते-कूदते बचपन अपना जीते थे और फिर हमको खेल मैदान भी मिलता था, लेकिन आज एक बिल्डिंग में हमारा स्कूल चलता है, खेलने के लिए जगह नहीं है।

इसके साथ ही साथ, मैं यह कहना चाहूंगी कि टैलेंट सर्च के लिए, आप चूंकि खुद खिलाड़ी हैं और आपने देखा है, आपने पार्टिसिपेट किया है और रणजी भी आप खेले हुए हैं तो मंत्रीजी, ओलम्पिक, कामनवैल्थ गेम, एशियन गेम में मैडल जीतने की जो आयु ज्यादातर अमरीकन, यू.के., न्यूजीलैंड की या यूरोपियन कंट्रीज के खिलाड़ियों की है वह 20 वर्ष से 24, 25, 26 वर्ष की आयु में है तो हमारे खिलाड़ियों की वह आयु क्यों नहीं है? नम्बर एक, हमारे खिलाड़ी रोजगार पाने के लिए खेल में आते हैं, मैडल जीतने के लिए, वह रोजगार प्राप्त करने के बाद मैडल जीतने की कोशिश करते हैं तो खेल नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे हम टैलेंट सर्च करें, 12 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों का टैलेंट सर्च करके उन्हें स्कालरशिप दी जाए और स्कालरशिप की बात मैं इसलिए कर रही हूं कि ज्यादातर जो बच्चे खेल में आते हैं वह ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, किसान के बच्चे होंगे, मजदूर के बच्चे होंगे। फोर एग्जाम्प्ल मैं अपने खुद का बताना चाहती हूं कि जब मैं थ्रो करती थी पहली बात तो थ्रोइंग शूज इंडिया में नहीं मिलता था और जैसे-तैसे बाहर से मैंने थ्रोइंग शूज लिया तो वह थ्रोइंग शूज एक महीने के अंदर टूट गया। अब क्या किया जाए? मैं यह बताना चाहूंगी कि बारम्बार उसको रिपेयर कराकर मैंने तीन साल तक उस शूज को पहना तो आप समझ सकते हैं कि जब उसमें हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि इन बच्चों को स्कालरशिप दी जाए ताकि वह अपने खेल को सुधार सके।

साथ ही साथ, मैं जरूर यह भी कहना चाहूंगी कि हमारे जितने भी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, जिन्होंने पदक जीता है, उनके साथ भी उनका इंटरेक्शन जरूर होना चाहिए कि वह किस तरीके से अन्तरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं।

कोचिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आज जितने भी इंटरनेशनल

(श्रीमती कृष्णा पूनियॉ)

एथलीट्स हैं, वह रेलवे में रहेंगे, ओ.एन.जी.सी. में रहेंगे और अलग डिपार्टमेंट्स में रहेंगे, आज वह स्पोर्ट्स में नहीं हैं तो मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को यह कहना चाहती हूं कि उनके लिए एक ऐसा प्रावधान रहना चाहिए कि जो सैलेरी वह वहां पर पाते हैं उसी के आधार पर राज्य सरकार अगर उन्हें मौका देती है, जिससे हम उनकी जो तकनीक है या उनका जो अनुभव है, उसको हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए रख सकते हैं, उनको संजो सकते हैं और हम अपने खेलों को आगे बढ़ावा दे सकते हैं।

मैं हरियाणा की बात करना चाहूंगी कि हरियाणा में जैसे ही मैडल आये थे, मैं खुद भी हरियाणा की बेटी हूं तो मैं यह कहना चाहूंगी कि जब हरियाणा में मैडल आये तो सीधा डाइरेक्ट उनको डीवाई.एस.पी. के पद पर और आर.ए.एस. लेवल के पद उनको डाइरेक्ट दिये गये, जो कामनवैल्थ में गोल्ड मैडल थे या एशियन गेम में गोल्ड मैडल थे या ओलम्पिक में गोल्ड मैडल थे, उन खिलाड़ियों को दिये गये थे तो इसी तरीके से हमारे राजस्थान में भी एक खेल नीति में यह क्राइटेरिया जरूर होना चाहिए कि कामनवैल्थ में, एशियन गेम में और ओलम्पिक में जो खिलाड़ी मैडल जीत कर आ रहे हैं, दो परसेंट कोटा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिया है, इसका मैं स्वागत करती हूं, यह बहुत अच्छी बात है, नेशनल तक के खिलाड़ी भी उसमें आ जाते हैं, लेकिन अगर अन्तरराष्ट्रीय पदक जो खिलाड़ी हमारे जीतते हैं और वह हमारे ही प्रदेश में सेवाएं देंगे तो यह हमारे खिलाड़ियों के लिए एक प्रोत्साहन भी रहेगा और हमारे खेल को आगे बढ़ाने में भी बहुत महत्वपूर्ण कदम रहेगा।

साथ में काम्पीटिशन, आप तो खुद भी काम्पीटिशन खेलते रहते हैं। 2012 ओलम्पिक से पहले की बात है, जब मुझे ओलम्पिक में काम्पीटिशन खेलना था उससे पहले मैंने कम से कम 25 काम्पीटिशन खेले होंगे। मैं यह मान सकती हूं कि राजस्थान में इतने काम्पीटिशन नहीं हो सकते लेकिन एट-लीस्ट, कम से कम हर गेम के नेशनल, एक नेशनल तो राजस्थान में होना ही चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारे जो स्टेट लेवल के एथलीट हैं, एक तो जो बेस्ट थ्री एथलीट रहेंगे उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। बड़े एथलीट के साथ पार्टिसिपेट करेगा तो उसकी झिझक वैसे ही खुल जाएगी और दूसरा, उसको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे देश में खेल के प्रति जागरूकता कहां से आयी? 2010 में जो कामनवैल्थ गेम्स दिल्ली में हुए थे और उससे लोगों को पता चला कि खेल क्या होता है?

(श्रीमती कृष्णा पूनियॉ)

बड़ी विडंबना की बात है कि आज भी मुझसे बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि आपको राजनीति में नहीं आना चाहिए था, आप तो खिलाड़ी थे, खेलते रहते। उनको यह नहीं पता कि कितने साल तक एक खिलाड़ी की उम्र होती है, कितने साल तक वह खेल सकता है। जागरूकता जरूरी है और ऐसे में खिलाड़ियों के लिए जब काम्पीटिशन हम आर्गेनाइज करते हैं तो उनके लिए यह बहुत ही बेनिफिट वाला काम रहेगा।

साथ ही साथ, इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात मैं जरूर करना चाहूंगी कि आज जयपुर में हमारे पास इन्फ्रास्ट्रक्चर है या जोधपुर में कह सकती हूं, बीकानेर में भी नहीं है हमारे पास या एक सिंथेटिक ट्रैक है वह चूरू के अंदर है लेकिन इतने बड़े प्रदेश के अंदर, बीकानेर में साइकिलिंग अच्छी है, शेखावाटी में एथलेटिक्स अच्छी है, आप जैसे पोलो खेलते हैं, कहीं पर वालीबाल अच्छा है तो उसी तरीके से वहां पर मैं यह नहीं कह सकती कि एक बार में हम उस चीज को डवलप कर सकते हैं, लेकिन क्राइटेरिया चूज करके कि कौनसे जिले के अंदर हमारे खिलाड़ी अधिक हैं, जैसे रोइंग के किधर ज्यादा हैं या फिर एथलेटिक्स के किधर ज्यादा हैं, बाक्सिंग के किधर ज्यादा हैं तो वहां पर वह एथलेटिक्स ग्राउंड हमें डवलप करने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अगर खेल को आगे बढ़ाना है तो हमें स्पोन्सर्स भी चाहिए। प्राइवेट फंड की भी हमें जरूरत रहेगी, क्रिकेट का सब उदाहरण देते हैं और क्रिकेट में प्राइवेट फंड ज्यादा आया तो क्रिकेट आगे बढ़ा भी है। इसी तर्ज पर मैं यह कहना चाहूंगी कि हमें प्राइवेट फंड भी जुटाना होगा और पीछे मैंने एक सवाल भी लगाया था। सम्मान की बात मैंने की थी कि हमारे प्रदेश में कितने खिलाड़ी हैं? गिने चुने खिलाड़ी हैं जो अर्जुन अवार्डी हैं या द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। एक खिलाड़ी के पीछे एक कोच की इतनी अथक मेहनत होती है, लेकिन अपने प्रदेश में उसको सम्मान नहीं दिया गया। हमारे प्रदेश में खिलाड़ियों को सम्मान मिला, लेकिन उसके पीछे की मेहनत को सम्मान नहीं दिया गया तो आपने मुझे यह आश्वासन भी दिया था कि अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी हैं, कॉमनवैल्थ गोल्ड मैडलिस्ट है, उन्हीं की तर्ज पर द्रोणाचार्य अवार्डीज को भी आप सम्मान देंगे, इसको आप जरूर अपनी खेल नीति में रखें।

साथ ही साथ, अपने जो पड़ौसी राज्य हैं, माननीय सभापति महोदय,

(श्रीमती कृष्णा पूनियाँ)

वहां पर अर्जुन अवार्डी खिलाड़ियों को पेंशन दी जा रही है। यह एक आर्थिक मदद काफी मदद हो जाती है और मैं यहां पर आपसे यह मांग भी रखती हूं कि हमें कम से कम पचास हजार रुपये तक की पेंशन हमारे खिलाड़ियों के लिए जो कम से कम अर्जुन अवार्डीज हैं, उनके लिए हमें यह जरूर रखनी चाहिए। साथ ही साथ जब मैं एस.एम.एस. स्टेडियम की बात करती हूं और मैं सभी सदस्यों को भी इस तथ्य को अवगत कराना चाहूंगी।

मैं अगर आपके साथ एम.ओ.यू. करूं, एथलेटिक्स ग्राउण्ड में मैं एकेडमी चलाऊं तो बाकी हमारे इस प्रदेश के या जयपुर जिले के जो बच्चे हैं, वह प्रेक्टिस कहां करेंगे? विगत सरकार ने एम.ओ.यू. किया। हमारी सरकार के पैसे लगे। जहां पर एकेडमी चल रही है, एक तो क्रिकेट की चल रही है, दूसरी स्क्वैश की चल रही है। जहां पर हमारा बच्चा जाकर ट्रेनिंग नहीं ले सकता है, क्योंकि वहां पर उनसे फीस ली जाती है, तब उन्हें कोचिंग दी जाती है। यह सरकार ने सुविधा की थी आम बच्चों के लिए, आज वहां पर उनके साथ एम.ओ.यू. करके उन्हें वह दे दिया गया। आज वहां पर अपनी एकेडमी चला रहे हैं और बच्चों से फीस लेकर ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो अपने कोचेज हैं, फिर वह क्या करेंगे? क्योंकि उनके पास ग्राउण्ड नहीं हैं, बच्चे वहां पर ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं। आप एकेडमी को प्रोत्साहन दें, मैं मना नहीं करती, लेकिन आप रियायती दर पर उसे भूखण्ड उपलब्ध करा सकते हैं या मुफ्त में भूखण्ड दे सकते हैं। जयपुर के हार्ट में इतना बड़ा स्टेडियम है और वह हर गरीब व्यक्ति के लिए बना है और वहां पर कोई व्यक्ति अपनी एकेडमी चलाए और फीस ले तो यह मैं कहना चाहूंगी कि यह हमारे खिलाड़ियों के साथ अन्याय है। विशेष तौर पर मैंने आपको बताया कि गरीब बच्चा है, वह अपना पसीना बहाने के लिए आता है, उसके पास फीस देने के लिए पैसा नहीं है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती कृष्णा पूनियाँ (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं खेल के क्षेत्र से आती हूं, खेल की बात है तो थोड़ा-सा समय तो मैं आपसे जरूर चाहूंगी। साथ-साथ स्पोर्ट्स मेडिसन की और न्यूट्रीशन की बात आती है। स्पोर्ट्स इंजरी की बात आती है। जैसे ही स्पोर्ट्स मेडिसन की, न्यूट्रीशन की बात आती है तो सीधा-सीधा दिमाग में जाता है कि स्टेराइड की बात होती होगी। आज उतना न्यूट्रीशन डाइट में, हमारे बच्चों की डाइट में नहीं है। फूड

(श्रीमती कृष्णा पूनियॉ)

सप्लीमेंट उसको किस तरह का चाहिए, उसके लिये भी हमारे विभाग के अंदर प्रोविजन होना चाहिए। स्पोर्ट्स मेडिसिन का एक डाक्टर हमारे पास होना चाहिए। बच्चों को इंजरी भी होती है। आप तो खुद एथलीट हैं तो आपको पता है कि स्पोर्ट्स इंजरी कैसी होती हैं? वह सुविधा हमारे बच्चों के पास होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि कृष्णा हिचकिचायी। मैं कहना चाहूंगी कि बजट जुलाई में पेश हुआ था लगभग छह महीने हुए हैं और स्टेडियम को बनने में समय भी लगता है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं कि मेरी भावनाओं को समझते हुए उन्होंने सादुलपुर को स्टेडियम की सौगात दी और कहीं-न-कहीं मैं यह भी सोचती हूं कि उस क्षेत्र को बहुत ज्यादा जरूरत भी थी। खेल जगत के जितने भी आप खिलाड़ी देख सकते हैं, जो ओलम्पियन हुए हैं चाहे उसमें देवेन्द्र झाझड़िया हैं, सपना पूनियां हैं, मैं खुद हूं, मंजूबाला स्वामी हैं। इस तरीके से ज्यादातर खिलाड़ी हमारे क्षेत्र से निकले हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हमें स्टेडियम दिया, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं।

माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमने साइकिल बांटी। साइकिल और स्कूटी तो हमने भी बांटी, लेकिन हमने कलर चेंज करने का काम नहीं किया। सेवा भाव से बच्चियों को उसका लाभ मिले और आपने उसका भगवाकरण करने का काम किया। इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि इन बातों को राजनीति से परे होकर खेल को ऊपर उठाने की बात करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने खेल मंत्रालय में जोड़ने की बात कही। मैं आप पर गर्व करती हूं, आप खुद अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, समाप्त करें। माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): आप सक्षम हैं और खेल को ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे और हमारा पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। आप आगे बढ़िये ताकि हम अपने खेलों को आगे ले जा सकें। यहां पर सभी सदस्यों से

(श्रीमती कृष्णा पूनियाॅ)

मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि एक तो यह जो प्राइवेट एकेडमी अपने स्टेडियम के अंदर चल रही है, उनको बंद किया जाए, यह बहुत जरूरी है। हमारे बच्चे आशा के साथ वहां पर जाते हैं और निराश होकर वापस लौट आते हैं और जो हमारे सरकारी कोचेज हैं, वह हाथ-पर-हाथ धरे बैठे हैं। आपको एकेडमी को प्रोत्साहन देना है तो रियायती दर पर आप भूखण्ड उपलब्ध करा सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगी कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बने, जिसमें यह प्रोविजन हो कि अलग से स्पोर्ट्स के लिये फण्ड हो, ताकि स्पोर्ट्स को डवलप किया जा सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रोहित बोहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय सभापति महोदय, मैं यह टेबल कर रहा हूं।

श्री सभापति: आप व्यक्तिगत रूप से मिलकर दीजिए मंत्रीजी को। व्यक्तिगत मंत्रीजी को दीजिए। आप मंत्रीजी से चैम्बर में मिलकर उनको दीजिए वहीं पर।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। पहले मैं स्पोर्ट्स पर बोलना चाहता हूं और सबसे पहले मैं अपने जिले की डिमाण्ड रख देता हूं, जो कृष्णा पूनियाॅ जी ने बोला और बीजेपी से जो जालौर के माननीय सदस्य हैं, उन्होंने कहा, एक चीज तो खेल मंत्रीजी, आप यह कर दीजिए that stadium should be only meant for playing. It should not be meant for any other activities. Please make it a law, so that कई बार मेले का आयोजन हो जाता है, उसमें बल्लियां गाड़ देते हैं, कई बार कुछ आयोजन हो जाता है और पूरे स्टेडियम की हालत खराब हो जाती है। इसके लिए एक पालिसी डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। जो आज यहां पर डिस्कशन हो रहा है कि यदि खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स संघ बना हुआ है, उसमें रहेंगे तो तरक्की करेंगे। मैं कृष्णा पूनियाॅ की बात से इस पर बिलकुल एग्री करता हूं। राजस्थान में ऐसा एग्जाम्पल है राजस्थान शूटिंग एसोसिएशन, it is only run by shooters, professionals और यदि

(श्री रोहित बौहरा)

आज राजस्थान में गर्व से हम कह सकते हैं, कहीं पर भी मैडल्स जीते हैं सबसे ज्यादा कहीं मैडल्स जीते हैं तो राजस्थान शूटिंग एसोसिएशन के बल पर जीते हैं, क्योंकि वहां पर एक तो ब्यूरोक्रेसी का इंटरफियरेंस नहीं है, एक पालिटिकल इंटरफियरेंस नहीं है both the interferences are not there. It is run professionally by the shooters themselves. So, I feel that this is one of the best example, जो आपके फालो करने के लिए होगा कि किस तरह से उन्होंने माडल बना रखा है। आपके लिये उन्होंने ऐसे प्लेयर्स पैदा किये जिससे कि आप लोगों को यह मैडल्स मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मेरा यह कहना है कि आज आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। शिक्षा विभाग इंटर-डिस्ट्रिक्ट, इंटर-स्टेट और इंटरनेशनल, स्कूल से ही यह चालू हो जाते हैं and it goes up till the University level, यह फारमेट है क्योंकि मैं भी गेम्स खेला हुआ हूं। हमने भी बचपन में यह किया है। पर अब स्थिति ऐसी हो गयी है कि न तो शिक्षा डिपार्टमेंट इसके लिए पूरा बजट दे रहा है और उन लोगों को भी कोई-न-कोई भामाशाह ढूंढना पड़ रहा है, जो उनके बच्चों की खाने की व्यवस्था कर दे इंटर-डिस्ट्रिक्ट की। इंटर-स्टेट में कोई-न-कोई प्राइवेट स्कूल को देखना पड़ रहा है कि इस तरीके से उनके खाने की व्यवस्था की जाए। मैं यह चाहूंगा कि बजट में जब भी मुख्य मंत्रीजी अपना फाइनेंस बिल पेश करेंगे, आप एक बार जाएं, पहुंचे और यह सभी सदस्यों की भावना से उनको अवगत कराएं कि जिस तरीके से यह बजट प्रोविजन होना चाहिए। आज हम बच्चों को 'फिट राजस्थान हिट राजस्थान' की बात कर रहे हैं तो उस तरीके से बजट चाहिए। मैं यह मानता हूं कि आपका बजट कम है लेकिन आज सी.एस.आर. एक्टिविटी राजस्थान में काफी हो रही है। सी.एस.आर. एक्टिविटी के थ्रू आप जो भी पैसा, जो पब्लिक सैक्टर यूनिट्स हैं, जो प्राइवेट कम्पनीज हैं, जो पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट कम्पनीज हैं, they can give you a lot of money on CSR लेकिन यह एक पहल, क्योंकि आप खुद खिलाड़ी हैं, आप एक पहल यह करेंगे कि सी.एस.आर. एक्टिविटी में से यह पैसा कर देंगे। मैं तो यह भी कहता हूं कि राजस्थान में जो प्राइवेट लिमिटेड कम्पनीज हैं यदि आज राजस्थान सरकार चाहेगी तो सी.एस.आर. में प्राइवेट लिमिटेड कम्पनीज को भी कुछ अंशदान देने के लिये हम प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि इससे भला सिर्फ राजस्थान का नहीं, राजस्थान के बच्चों का भविष्य इन्वाल्ड है।

(श्री रोहित बौहरा)

माननीय सभापति महोदय, आज हम इस पर बहस करने में लगे हुए हैं। बीजेपी के कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि योग कराओ। We should be only focusing ourselves on games. योग करना है, नहीं करना है, यह व्यक्तिगत एक आदमी का खुद का परसेप्शन होगा। हमें उनको प्रेरित करना है। किस तरह से हम बच्चों को खेल के प्रति प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि खेल सिर्फ खेलना नहीं है, it teaches you a lot of things; it teaches you the leadership qualities, it teaches you how to mix with people और किस तरह से हम गेम्स खेलें, किस तरह से एक-दूसरे का सहयोग करें, it teaches you a lot of things.

(15.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मैं जिस पर जाना चाहूंगा वह है विज्ञान। आज विज्ञान की बात हम कर रहे हैं, आज हर क्षेत्र में विज्ञान की जरूरत है। आज राजस्थान गवर्नमेंट ने जो थैलियों का निस्तारण करने के लिये सोचा है, वह एक ही सोच सोच रखी है कि हम यह सब सीमेंट प्लांट्स की किल्न (Kiln) के अंदर जितनी प्लास्टिक की थैलियां हैं, क्योंकि वह 1200 डिग्री पर प्लास्टिक खतम हो जाएगी। सब इकट्ठी करके, we have to send it to all the cement plants. लेकिन एक सीमेंट प्लांट में इतने दूर से हमें यह प्लास्टिक का वेस्ट भेजने में जो कास्ट आ रही है, वह ट्रिमेन्डस कास्ट आ रही है। राजस्थान गवर्नमेंट को आ रही है। मेरे इसमें दो-तीन सुझाव हैं। पहला यह है कि टायर के आज pyrolysis के प्लांट पड़े हुए हैं, उसी संदर्भ में जितना प्लास्टिक वेस्ट है, हम उससे डीजल बना सकते हैं। आज वो pyrolysis plant उसी कीमत पर pyrolysis plant आते हैं जितनी थैलियां हैं और हम थैलियां बंद नहीं कर पा रहे हैं, कोई ये सोचे कि हम थैलियां बंद कर पा रहे हैं, हम थैलियां बंद नहीं कर पा रहे हैं बल्कि थैलियों को और बढ़ावा दे रहे हैं सैकंडरी पैकेजिंग करके। जो बात हम कर रहे हैं थैलियां हमें 50 माइक्रोन की यूज़ करनी पड़ रही है, मतलब पहले जो 10 माइक्रोन की थैली थी उसकी हम फाइव टाइम्स 50 माइक्रोन की थैलियां यूज़ कर रहे हैं। मेरा उसमें एक सजेशन है कि आजकल ऐसी-ऐसी थैलियां आ गयी हैं जिसमें हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं, हम 50 माइक्रोन की जगह 30 माइक्रोन यूज करेंगे तो we will save the cost and we will stop using so much of plastic that we have been using in this country और

(श्री रोहित बौहरा)

यह कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, न तो केन्द्र सरकार इसको अंडरस्टैंड कर रही है क्यों यह कान्करेंट लिस्ट में आता है, न ही हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स इसको अंडरस्टैंड कर रही है। इस पर डिस्कशन हो, विधान सभा में ये डिस्कस हो, थ्रैडबेयर डिस्कस हो कि किस तरह से हम प्लास्टिक की थैलियां बायोडिग्रेडेबल कर सकते हैं three times of the cost. We should not be using the five times of the cost, जो हम 50 माइक्रोन की थैलियां यूज़ कर रहे हैं।

दूसरा, साहब, ईस्टर्न राजस्थान में एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि न तो हम वहां स्प्रिंकलर्स यूज कर रहे हैं for our irrigation क्योंकि यह विज्ञान से सम्बन्धित है, न हम ड्रिप इर्रिगेशन यूज कर रहे हैं। मेरा एग्रीकल्चर मंत्री जी से यह निवेदन है, क्योंकि ये विज्ञान से सम्बन्धित है कि किस तरह से नई तकनीकें और जैविक खाद के ऊपर हम नई चीजें कर सकें। आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में हर पांचवां आदमी, who is suffering from cancer. Every fifth person is suffering from cancer, for which no one is taking care. आज उसमें सबसे बड़ी प्राब्लम क्या है कि डी.ए.पी. जो है, हमारे पास निचले लेवल पर जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हैं वो अवेलेबल ही नहीं हैं, न पिछली सरकार में थे न हमारी सरकार में। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर अवेलेबल नहीं होंगे तो डी.ए.पी. और जो यूरिया हम खेतों में डाल रहे हैं, उसकी मात्रा का न तो कोई सिस्टम बना हुआ है, जिसकी जितनी मर्जी आती है वो उतना डी.ए.पी. डाल देता है, यूरिया डाल देता है। साहब, मेरे यहां एक-एक गांव में पिछले 5 साल में 15-15 आदमी मर चुके हैं just because of this cancer. हमें छत्तीसगढ़ वाला माडल यूज करना पड़ेगा कि किस तरह से जैविक खाद पर छत्तीसगढ़ ने एक साल के अंदर तरक्की की है। नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स को, जितने हमारे कोआपरेटिव्ज हैं, राजफैड है, ये सब हैं, इन पर भी हमको यह नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स लाने पड़ेंगे जिससे जो हम धान या गेहूं प्रोड्यूस कर रहे हैं या सरसों प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें ये नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स हम यूज कर लें, न तो वह हमारी हैल्थ को हैजार्ड होगा न किसी को हैजार्ड होगा।

दूसरा मैं माइंस के ऊपर कहना चाहूंगा क्योंकि यह विज्ञान से सम्बन्धित है, साहब, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं। आज माइंस के अंदर हमारे पास कोई पैसा नहीं है for new explorations. माइंस डिपार्टमेंट में एक सुझाव देना चाहूंगा कि हम माइंस एक्सप्लोरेशन बोर्ड बनायें, नई

(श्री रोहित बौहरा)

तकनीक से। Today it is a mineral rich State. आज हमारे यहां नये माइंस, नये मिनरल्स की खोज ही नहीं हो पा रही है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): जो भी करता है वो एक प्राइवेट एंटरप्रिन्योर पैसा लगाता है, खोजता है और वह अपनी माइंस के लिए एप्लाई कर देता है। जब तक हम माइनिंग के ब्लाक्स नहीं बनाएंगे इसको साइंटिफिकली मैनेज नहीं करेंगे।

श्री सभापति: माइंस पर अलग है, चर्चा अलग है डिमांड पर।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): हैं, सर।

श्री सभापति: माइंस डिपार्टमेंट पर अलग से चर्चा है, उस दिन बोलिए आप। समाप्त करें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, ये विज्ञान से रिलेटेड है और माइंस पर चर्चा नहीं है। आपने विज्ञान से रिलेटेड बात की है तो इसमें इतने सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं इसलिए मैं यह चर्चा कर रहा हूं और, साहब, माइंस पर चर्चा नहीं है, खतम हो गई ये चर्चा।

मैं इसमें यह और कहना चाहूंगा कि एरियल सर्वे कराना बहुत जरूरी है, यह नई तकनीक है। हमें माइंस पर लैबोरेटरी बनाना जरूरी है जिससे कि इमिजिएटली जो भी हम नया मिनरल ढूंढ रहे हैं उसकी टैस्टिंग हो जाए, क्या क्वालिटी आफ मिनरल है। आज हमारे यहां सेमी-प्रेशियस स्टोंस की माइंस पड़ी हैं राजस्थान में, वो सेमी-प्रेशियस स्टोंस की माइंस को भी हम किस तरह से बढ़ावा दे सकें।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): साहब, दूसरा मैं यह कहना चाहूंगा कि आज आर.वी.पी.एन.एल. में लास्ट टाइम 700 करोड़ रुपये खर्च किया है नई फाइबर लाइन डालने के लिए, जितने उनके सब-स्टेशंस हैं वो सब फाइबर लाइन से जुड़े हुए हैं। हम इसको लीवरेज ही नहीं कर पा रहे। हम इसको लीवरेज करें, सरकार बात करे, कंपनियों से बात करे कि हम लीवरेज करें और इसको हम म्युनिसिपैलिटी लेवल पर और पंचायतों में, पंचायतों में फाइबर लाइन डल गई है, पंचायतों में हम ऐसा सिस्टम कर दें कि हमारे बच्चों को हम वाईफाई दे सकें, wi-fi is not only for entertainment, it is for stud-

(श्री रोहित बौहरा)

ies also. आज लाइनें डल चुकी हैं राजीव गांधी सेवा केन्द्र तक, उनको हम लीवरेज करें, उनमें बच्चों को वाईफाई स्पोर्ट्स दे दें क्योंकि आज गांवों में डेटा, साहब, आज कालिंग से महंगा हमारा डेटा हो चुका है, आज हम वहां पर डेटा को फ्रीली अवेलेबल करा देंगे तो इससे हम अपने स्टूडेंट्स को हैल्प कर सकेंगे, अपने बच्चों को हैल्प कर सकेंगे, उनका भविष्य सुंदर बना सकेंगे।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री सुमित गोदारा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आज हमने स्कूलों में कम्प्यूटर लैब्स बना दीं, कम्प्यूटर लैब्स बंद पड़ी हुई हैं। साहब, बस एक सैकिण्ड लूंगा, खतम कर रहा हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री सुमित गोदारा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): कम्प्यूटर लैब्स बनी पड़ी हैं, मैं आपसे इतना कहूंगा कि यह कम्प्यूटर लैब्स के लिए यदि आज हमारे पास टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं तो 6 से लेकर 12 तक हम कंप्यूटर एजुकेशन को बीम करें स्टूडियोज के थ्रू जिससे कि नई तकनीक से हम बच्चों की स्टडीज करा सकें जिससे वो जब 12वीं के बाद पासआउट होते हैं और जो यह कंप्यूटर कोर्स पर 15-15 हजार रुपये एक लड़के को खर्च करने पड़ते हैं, हम भले ही उनसे 30 रुपये चार्ज कर लें और उनको कम्प्यूटर शिक्षा दें जो कि नीड ऑफ-द-आवर है, इस पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह बहुत जरूरी है जो पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, कम से कम आज कांग्रेस पार्टी पावर में है, इस पर कुछ काम करें तो यह बच्चों के लिए बहुत ही सुखदायी होगा। राम राम सा।

श्री सभापति: श्री सुमित गोदारा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापति जी, आज आपने मांग संख्या 24 व 11 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आभार व्यक्त करते हुए निवेदन करना चाहता हूं। खेल के ऊपर हम आभार व्यक्त करते हैं भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जिन्होंने 'खेलो इंडिया फिट इंडिया' जैसे कार्यक्रम शुरू किये, खेलों में जागृति लेकर आये। गुवाहाटी में अभी राष्ट्रीय खेल हुए जहां 10 हजार खिलाड़ी और ऐसा खेल आयोजन आज तक भारत में नहीं हुआ जो पहली बार आयोजन किया, जिसकी पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में खिलाड़ियों में प्रशंसा हुई, उसके लिए बधाई देते हैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी को।

(श्री सुमित गोदारा)

इस सदन में गर्व भी महसूस होता है कि हमारे खेल मंत्री अशोक चांदना जी जो खुद भी खिलाड़ी हैं और हमारे बीच में बहन कृष्णा पूनियॉ जी हैं जो भी कामनवैल्थ और ओलंपिक में अपना डंका बजा चुकी हैं। उनकी बात पर ये बात कहना चाहूंगा कि 'लड़कों से ज्यादा मैडल ला रही है बेटियां, खेलों में अपने हुनर को आजमा रही हैं बेटियां उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उस क्षेत्र से बड़ी खुशी और गर्व भी होता है कि उस क्षेत्र से हमारे वहां के गारबदेसर गांव से जाये जन्मे और ओलंपिक में पहली बार सिल्वर मैडल लाने वाले कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब मेरे विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के गारबदेसर गांव के न सिर्फ ओलंपिक में पहला सिल्वर मैडल लेकर आये बल्कि साथ में भारत के खेल मंत्री बने जो कि खिलाड़ी थे, यह भी अपने आपको गौरव महसूस करते हैं इस सदन से।

माननीय सभापति जी, हम देखते हैं कि एक समय था जब यह कहावत थी कि 'पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होओगे खराब', अब आपने यह बात यहां पर कही कि 'खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब।' मैं एक दिन एक गांव में था। वहां पर यह बात बोल रहा था तो गांव का एक बच्चा बोलता है जो अच्छा खिलाड़ी था, वह बोला पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे उनके भी बाप। यह हकीकत है, वास्तव में खिलाड़ियों में आज का समय जो बदल रहा है, विश्व में परिवर्तन हो रहा है और हम देखते हैं कि हमारी सरकार, चाहे केन्द्र हो चाहे राजस्थान की सरकार हो, खेलों पर ध्यान देने का प्रयास कर रही है।

केन्द्र में हमारे युवा एवं खेल मामलात मंत्री श्री किरेन रिजीजू ने एक गोल दिया है कि वन स्पोर्ट वन डिस्ट्रिक्ट यानी एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्पोर्ट को हम आगे लेकर आयें जिससे हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ें। यह इसलिए भी जिम्मेदारी है क्योंकि हम देखते हैं कि भारत में खेल में राजस्थान आज काफी पिछड़ा है। हम देखते हैं कि जो हम से पिछड़े राज्य थे, हम उड़ीसा को देखते हैं उड़ीसा खेलों में कितना आगे बढ़ा है, वहां दिलीप टिर्की इंडिया के हाकी के कैप्टन थे। हम भी हमारे स्कूल में बीकानेर में बी.बी.एस. स्कूल जो प्रतिष्ठित स्कूल रहा उसमें हाकी खेलते थे। नेहरू गोल्ड कप में हमारे स्कूल की टीम गई और हम भी अच्छे खिलाड़ी रहे। वो खेल हाकी के प्रति था, दिलीप टिर्की जैसे प्लेयर ने वहां हाकी के लिए प्रयास किया तो आज भारत में पूरे विश्व में सबसे बढ़िया स्टेडियम कहीं बना है तो भुवनेश्वर में, वहां पर वर्ल्ड कप

(श्री सुमित गोदारा)

ऑर्गेनाइज हुआ, एफआईएच लीग वहां पर आर्गेनाइज हो रही है तो क्यों नहीं हम राजस्थान में ऐसे अन्तरराष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन करें।

हम देखते हैं नोर्थ ईस्ट से जहां के अच्छे फुटबाल के खिलाड़ी निकल रहे हैं, बाक्सिंग के खिलाड़ी निकल रहे हैं, बाइचुंग भुटिया हो चाहे सुनील छेत्री हो जो भारत की टीम के कप्तान हैं। हरियाणा देखें जहां की लड़कियां और लड़के चाहे बाक्सिंग हो, रेसलिंग हो, हर खेल में अपना नाम कर रहे हैं। कर्नाटक देखो जहां कुर्ग जैसा एक छोटा सा रीजन है, भारत के हाकी के सबसे ज्यादा खिलाड़ी कहीं से आ रहे हैं तो पर्टिकुलर रीजन से वो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। ऐसे अनेक स्थान हैं जहां से खिलाड़ी आ रहे हैं राजस्थान में हमारे पास गिने-चुने नाम हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं कि खिलाड़ी आगे रहे हैं और भारत में हमारा राज्य सबसे बड़ा है पर खेल के नाम पर आज भी हम देखें तो सबसे पिछड़े हैं।

बात करें खेल में तो पंजाब की बात करते हैं। एक समय था जब पंजाब भारत में खेल के पटल पर सबसे आगे था पर नशे की प्रवृत्ति के कारण हम देख रहे हैं कि पंजाब आज खेल में पीछे जा रहा है। यह भी एक विचारणीय बात है। जिस तरह से राज्य आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह से देश भी आगे बढ़ रहे हैं। देशों के पैरामीटर्स में अगर हम देखें कि कौनसा कंट्री डवलप्ड है, कौनसा डवलपिंग है, वह स्पोर्टस में कैसा कर रहा है, वह भी विश्व पटल पर पैरामीटर्स बना है, how's the country is failing in sports, that's also become an index on this.

खेलों में यह बात कइयों ने उठाई कि हम सुविधाएं ही नहीं दे रहे हैं। यह बात सही है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि खिलाड़ी के लिए सुविधाएं कोई बाधा नहीं है। मुझे याद है कि 1986 में मैं स्टेट स्विमिंग कंपीटिशन में अजमेर गया था। सातवीं क्लास का छात्र था। मैं 100 मीटर बैकस्ट्राक में पांचवें स्थान पर आया। मैंने आकर के मेरे पिताजी को बीकानेर में कहा कि जिस स्विमिंग पूल में मैं प्रेक्टिस करता था, वह 25 मीटर का था। अजमेर के मेयो में वह 50 मीटर का था। पिताजी ने मुझे अख़बार दिखाए कि 1986 के सियोल ओलंपिक के, उसमें सूरीनाम का 100 मीटर बटर फ्लाई में ओलंपिक में गोल्ड मैडल जीता था। उस देश में सिर्फ एक स्विमिंग पूल था।

(श्री सुमित गोदारा)

इसी तरह से हम देखते हैं कि जिम्नास्टिक में दीपा करमाकर, त्रिपुरा के साधारण गरीब परिवार से आई हुई लड़की और रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में जिम्नास्टिक में चौथे नंबर पर आई। ऐसे भी हमारे सामने अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा, अपने बल पर विश्व में अपना नाम किया।

सभापति महोदय, राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में हम देखते हैं कि हमारे खिलाड़ियों ने भी प्रयास किया। हम देखते हैं तीरंदाजी जैसे खेल में लिम्बाराम, श्यामलाल जब नेशनल टैलेंट स्पोर्टस सर्च हुआ 1985-90 में यह बात हुई थी। पर्टिकुलर रीजन में सरकारों ने उस समय शुरू किया था। उससे यह खिलाड़ी निकले। बास्केटबाल हो, शूटिंग हो, कबड्डी हो, सभी में अच्छा किया।

जिस बीकानेर से मैं आता हूं, वहां से मैंने राज्यवर्धन जी का नाम लिया। महाराजा साहब करणी सिंह जी थे जिन्होंने ओलंपिक में अपना अच्छा नाम किया। आज जयपुर की अपूर्वी चंदेला जिन्होंने भारत में और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम किया।

एथलेटिक्स की बात करते हैं तो राजस्थान के श्री राम सिंह जी शेखावत याद आते हैं। 1972 ओलंपिक म्यूनिख में 800 मीटर की रेस में वह सातवें नंबर पर आए। मैंने उनका लेख पढ़ा था। उसमें जो अफ्रीका के चैंपियन थे, उन्होंने कहा कि मैं विश्व रिकार्ड इसलिए तोड़ पाया कि श्री राम सिंह जी पहले 300, 400 मीटर तक तेज दौड़े। उसी की वजह से मैंने वर्ल्ड रिकार्ड तोड़ा। ऐसे अनेक खिलाड़ी हमारे बीच में रहे।

मैं बीकानेर जिले से आता हूं। मगन सिंह जी राजवी जो भारतीय टीम के कप्तान थे। वह अर्जुन अवार्डी रहे। कई विधायकों ने साइकिलिंग का विषय रखा। एक समय बीकानेर साइकिलिंग में बहुत आगे था। आज भी आगे है लेकिन बहुत दुख की बात है कि जो वैलोड्रम वहां पर करणी सिंह स्टेडियम में है, उसकी हालत बिलकुल ही खराब हो चुकी है। उस स्टेडियम को अगर तैयार किया जाए तो आने वाले समय में और साइकिलिस्ट वहां से निकल सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में साइकिलिंग को अभी तक विषय नहीं लिया गया है। मेरा यह भी निवेदन है कि साइकिलिंग खेल को भी पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती होती है, उसमें उसको लिया जाए ताकि उन खिलाड़ियों को भी फायदा मिले।

(श्री सुमित गोदारा)

राजस्थान एक अलग राज्य है, इसमें रेगिस्तान, पहाड़ से लेकर के सभी तरह की जलवायु एवं भौगोलिक वातावरण है। उसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स भी राजस्थान में हो सकते हैं, जिसमें माउंटेन पर ट्रेकिंग हो सकती है। डेजर्ट में होट बैलून, डेजर्ट सफारी इस तरह के खेल भी हो सकते हैं जो कि ट्यूरिज्म लाने में भी हमें मदद कर सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हम खेलों में इसलिए पिछड़े हैं कि गांवों में और शहरों में सुविधाएं नहीं हैं। शहरों की बात करें तो पार्क हमने जगह-जगह बना दिए। जहां पर भी पार्क हैं, वहां सरकार इस तरह की सुविधाएं दे कि वहां पर यदि कोई भी आदमी एकेडमी खोलना चाहे तो उस पर कामर्शियल चार्ज नहीं लगाए चाहे वह टीटी की हो, बैडमिंटन की हो, स्क्वैश की हो। स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए उन एकेडमी पर कामर्शियल चार्ज नहीं लगाएंगे तो मौहल्ले में, गलियों में स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। लोग एकेडमी खोलेंगे और बच्चे वहां पर जाएंगे। यह एक ऐसी नीति है जो राजस्थान को पूरे भारत में आगे ला सकती है। इस पर आप जरूर प्रयास करें, no commercial charges for those academies which are running in colonies.

सभापति महोदय, खेल विद्यालयों की बात यहां पर कही। मैं बीकानेर से आता हूं। मेरे खयाल से राजस्थान का एकमात्र खेल विद्यालय सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर में है, लेकिन उसकी दुर्दशा पर मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर 12 पद कोच के हैं, जिनमें से 5 पर ही कोच कार्यरत हैं। आज हम जानते हैं कि खिलाड़ियों को डाइट अलग चाहिए होती है। 100 रुपयों की डाइट है, जो पता नहीं कितने सालों से चल रही है। उसको ड्रेस भत्ता साल का एक हजार रुपया मिलता है। आजकल हजार रुपये में तो जूते भी नहीं आते। कहां से खिलाड़ी खेलेगा? वहां पर आवासीय सुविधा नहीं है। आवासीय योजना में सुधार करें। खेल मैदान भी वहां पर आधुनिक बनाए जाएं। वह काफी पुरानी स्कूल है। जब एक स्कूल बनी है और उसका भी उदाहरण सही तरह से पेश नहीं कर पा रहे हैं तो हम कहां से दूसरे की मांग रखेंगे।

सभापति महोदय, ग्रामीण अंचल में प्रतिभाओं की बात रखी। कमी कहीं नहीं है। मैं एक छोटा-सा उदाहरण दूंगा जो कि अख़बार, फेसबुक और सोशल मीडिया पर सुर्खियां बना हुआ है। दक्षिणी कर्नाटक के मुंडभीतरी गांव

(श्री सुमित गोदारा)

में श्रीनिवास गौड़ा, जो वहां पर ट्रेडिशनल रेस होती है चावल के खेतों में भैंस दौड़ की, उसमें वह उसैन बोल्ट से तेज दौड़ा कि विश्व में चर्चा रही कि यह कैसे दौड़ा। प्रतिभाओं की कमी कहीं नहीं है। प्रतिभाएं आगे लाना हमारा कर्तव्य है। अगर यह प्रयास सरकार करे तो जो गांवों में प्रतिभाएं हैं वह आगे आएं।

सभापति महोदय, गांवों की प्रतिभाओ को खेलों में आगे लाने के लिए हमने कोई काम नहीं किया। खेल मैदान गांवों में कहीं नहीं हैं। सरकार यह लक्ष्य रखे। हम तो देखते हैं कि युवा ही स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और युवा ही ग्रामीण विकास मंत्री हैं। लेकिन सवा साल बीत गया है और काम कुछ नहीं हुआ है। अगर सरकार टार्गेट लेकर खेल मैदान गांवों में बनाए तो वहां क्यों नहीं बन सकते हैं?

खेतड़ी से जो माननीय विधायक आए हैं, उन्होंने खेल मैदान के लिए बात रखी। मैं भी अपने क्षेत्र में गया तो मैंने भी अपने विधायक फंड का सबसे ज्यादा पैसा खेल मैदानों में दिया। सरकार एक माडल बनाए कि इस तरह का खेल मैदान हो, 5 लाख से 10 लाख में कोई बन सके जो कि गांवों में हम एक माडल के रूप में स्थापित कर सकें जिसमें अंदर फुटबाल और क्रिकेट का भी हो। उसके बाहर हम एक ट्रेक बनाएं जिसमें 2 फुट की दीवार हो, जिसमें बाहर बच्चे भाग सकें।

हमारे ग्रामीण अंचलों में हमने देखा कि न सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी पैरा मिलिट्री फोर्सेज और पुलिस में तैयारी के लिए अभ्यास करती हैं। उनको स्थान मिले। वह उस ट्रैक के बाहर घूमकर प्रेक्टिस करें। वह सिर्फ बच्चों के ही, युवाओं के ही काम न आए, बल्कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से गांवों में बीमारियां बढ़ रही हैं, रोगी बढ़ रहे हैं, वह बड़ों के लिए भी घूमने का स्थान बन सकता है। उसको हम अच्छा बना सकते हैं। पार्क के रूप में उसको विकसित कर सकते हैं ताकि पूरे गांव के वह काम आ सके। उसमें हम टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कबड्डी, खो-खो का स्टेडियम भी बना सकते हैं जो बच्चों के काम आ सके। सोलर लाइट आजकल जो लगती है, वह लगा दें जिससे कि लाइट का बिल भी नहीं आए, जिससे उसमें कोई खर्चा भी नहीं आए और काम भी चल सके।

मैं सरकार को इस चीज के लिए तो बधाई देना चाहूंगा कि आपने नो बैग डे रखा है। जिस तरह से आपने स्कूलों में वार्षिकोत्सव शुरू किया है उस

(श्री सुमित गोदारा)

तरह से नो बैग डे रखा है लेकिन यह जरूर विषय रहेगा कि आप इस दिन स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एसयूपीडब्ल्यू एक्टिविटी बढ़ाएं ताकि बच्चे उसका उपयोग कर सकें। हम जब भी अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे तो सबसे ज्यादा खेल के दिनों को ही याद करते हैं कि हम कैसे खेलते थे। यह एक अच्छा अवसर राजस्थान सरकार ने दिया है we shouldn't miss this. इस चीज में हम चूके नहीं कि किस तरह हम इसे कर सकें।

सभापति महोदय, मैं खेल मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि लड़कियों के लिए जहां पर बालिका स्कूल हैं, वहां पर इंडोर स्टेडियम में टेबल टेनिस की टेबल दे सकते हैं, 12 हजार, 15 हजार की टीटी टेबल आती है। वह खेल भी कोई महंगा नहीं है। लड़कियां वहां खेल सकती हैं। भारत की टीटी टीम बहुत अच्छा कर रही है। हमने देखा कि एशियाड में भी इंडियन टीम मैडल लेकर आई थी। बैडमिंटन के कोर्ट बना सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। इस तरह की व्यवस्था हम कर सकते हैं जिससे कि सुधार हो।

सभापति महोदय, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आजकल खिलाड़ियों में भी यह टैंडेंसी बढ़ रही है कि हम तो मैडल लेकर आएं और नौकरी लग जाएं या कोच बन जाएं, लेकिन अब देश बदल रहा है। अगर हम एकेडमी खोलें और दूसरों को ट्रेनिंग दें तो वह भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इससे न सिर्फ वह अवार्ड जीतें बल्कि दूसरों को भी ट्रेनिंग देकर के खिलाड़ी पैदा कर सकते हैं। यही पश्चिमी देशों में और हमारे अंदर फर्क है। वहां के लोग जीतते हैं तो दूसरों के लिए भी चाहते हैं कि और भी खिलाड़ी पैदा हों। इसी तरह का प्रयास हम सबका रहना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए बस इतना ही कहूंगा कि नीरोगी राजस्थान आप लेकर आए हो, अगर हम खेलों को बढ़ावा देंगे तो नीरोगी राजस्थान अपने आप बनेगा। एक समय था जब खेल मैदान भरे हुए रहते थे। बच्चे इतने खेलते थे कि स्थान ही नहीं मिलता था। आज हम देखते हैं कि खेल मैदान सारे खाली हैं। बच्चे ज्यादातर या तो मोबाइलों में लगे हुए हैं या घरों में बैठे हुए हैं। वह खेलों से दूर हैं। अगर यह खेल मैदानों की सुविधा हम देंगे तो वह दिन जरूर आएगा जब बच्चों का वापस खेल के प्रति रुझान बढ़ेगा। इससे न सिर्फ आउटडोर स्पोर्ट्स की तरफ बल्कि इंडोर स्पोर्ट्स की तरफ भी बढेगा।

(श्री सुमित गोदारा)

सभापति महोदय, खेल एक ऐसा विषय रहा है कि हम कहते हैं कि भारत को एक करने में जिस तरह से रेलवे, आल इंडिया रेडियो और सिनेमा ने काम किया है, उसी तरह से खेलों ने भारत को एक करने में काम किया है।

सभापति महोदय, मैं मेरी बात को समाप्त करते हुए जो सेवाएं हैं उस विषय पर बोलना चाहूंगा कि जो नो बैग डे आपने रखा है, उसमें जिस दिन खेल हो, उसी तरह से एसयूपीडब्ल्यू एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों का विकास हो सके। हमने देखा है कि आजकल स्कूलों में ये कार्य बिलकुल ही बंद कर दिए गए हैं। जब हम पढ़ते थे तो मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि हमारे 2-2, 3-3 दिन के कैंप लगते थे। हमसे सफाई का काम कराया जाता था। स्कूल में मैदान साफ कराए जाते थे। उसका असर यह पड़ा कि आज भी रास्ते में कोई चीज दिखती है तो प्रयास रहता है कि उसको उठाकर रखें। जब खुद के घर में बच्चे देखते हैं तो वह आजकल यह कार्य नहीं करते। इस तरह की गतिविधियां बंद होने से बच्चों में इस तरह के कार्यों के प्रति रुचि भी कम हुई है। इस तरह के कैंप में आप चाहे स्कूल की सफाई कराओ, चाहे आप उस दिन गांव की सफाई कराओ। बच्चे उसी गांव के हैं तो क्यों नहीं हम गांव की सफाई कराकर इस तरह की गतिविधि शुरू करें। खुद का ही गांव है तो क्यों नहीं गांव साफ हो। पौधारोपण का कार्य भी हम करा सकते हैं। नो बैग डे का आपका अच्छा प्रयास है। ऐसा नहीं हो कि यह प्रयास विफल जाए। इन चीजों को टार्गेट लेकर हम प्रयास करेंगे तो जो नीरोगी राजस्थान का आप लाये हो और आदरणीय प्रधान मंत्रीजी फिट इंडिया, खेलो इंडिया लेकर आये हैं, ये प्रयास जरूर सफल होंगे। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री वाजिब अली।

श्री वाजिब अली (नगर): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे खेल जैसी महत्वपूर्ण मांग पर विचार रखने का अवसर प्रदान किया। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां सबसे ज्यादा युवा हैं। इसके बावजूद जब इंटरनेशनल प्रतियोगिताएं या गेम्स होते हैं तो मैडल्स की सूची में हमारा नाम बहुत नीचे होता है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है क्योंकि प्रतिभाओं

(श्री वाजिब अली)

की कमी नहीं है, यदि इसमें कोई कमी रही है तो कहीं-न-कहीं सरकारों की रही है, साधनों की उपलब्धता कराने में कमी रही है।

मैं भरतपुर के नगर विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। मेरे यहां अभी विधान सभा क्षेत्र के छोटे गांव नंगला रामरतन का एक बेटा आकाश, उसने एक गांव में प्रैक्टिस करके क्रिकेट में अपने आप डवलप किया और अण्डर 19 वर्ल्ड कप खेला। निश्चित रूप से प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। खेलो इंडिया की जो प्रतियोगिताएं हो रही थीं उसमें भरतपुर की बेटियों ने फुटबाल के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया। कहीं न कहीं हमें जरूरत है कि हम कैसे अच्छे से अच्छे साधन अपने यूथ को उपलब्ध करा पाएं ताकि प्रतिभाएं सामने आएं और देश का नाम रोशन हो।

माननीय सभापति महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि हर ब्लाक स्तर पर स्टेडियम बनाये जाएं और स्पेशली फीमेल्स के लिये स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिये जाने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियां कोई एक्टिविटीज नहीं कर पातीं। स्कूल्स के अंदर खेल के मैदान जो बनाये जाएं, उनमें यह भी ध्यान रखा जाये कि फीमेल, गर्ल्स का पार्टिसिपेशन कैसे अच्छे से अच्छा हो सके। बेटियों को बढ़ावा देने के लिये पूरे देश में नारे भी चल रहे हैं, स्लोगन भी चल रहे हैं पर जहां सुविधाएं देने की बात आती है तो अक्सर सरकारों के स्तर पर कमी रहती है।

माननीय सभापति महोदय, हर पंचायत में खेल मैदान बनाये जाएं और पार्क्स भी डवलप किये जाएं। आजकल हमारे बच्चे बाहर नहीं खेल पाते और ऑनलाइन गेम्स या मोबाइल गेम्स की आदतों में ही रह जाते हैं। जहां-जहां भी नगरपालिकाएं हैं, नगर परिषदें हैं वहां पर कालोनियों में प्रोपर पार्क्स डवलप करें ताकि आउटडोर एक्टिविटीज के लिये बच्चों को प्रोत्साहन मिले।

माननीय सभापति महोदय, बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नगर में स्टेडियम की स्थापना हो और पार्क्स डवलप किये जाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री सुरेश मोदी।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): माननीय सभापति महोदय, मैं खेलकूद की मांग पर आपके माध्यम से खेल मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र के गजानन्द मोदी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नीमकाथाना में

(श्री सुरेश मोदी)

युवा व खेल विभाग द्वारा स्टेडियम निर्माण हेतु 235 लाख रुपये की राशि सन् 2018 में बीजेपी सरकार ने स्वीकृत की थी। इसके बाद निविदा जारी कर नियमानुसार वर्क आर्डर भी जारी कर दिये गये थे, जिसमें निर्माण का समय छह माह का दिया गया था, परंतु बड़े दुःख की बात है कि आज तक स्टेडियम का काम शुरू नहीं हुआ, एक रुपया भी उस पर खर्च नहीं हुआ। यह सही है कि बीजेपी का यह एक छल था, युवाओं के साथ एक धोखा था, उसे पता था कि हम दुबारा सत्ता में नहीं आ रहे, इसलिए वोट लेने का एक असत्य प्रयास उन्होंने खेल स्टेडियम की सौगात देकर किया।

माननीय सभापति महोदय, अभी एक माननीय सदस्य, पूर्व खेल मंत्री कृष्णाजी पूनियाँ से पूछ रहे थे, कांग्रेस सरकार से कि उस स्टेडियम का क्या हुआ? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि नीमकाथाना के स्टेडियम का क्या हुआ यह आप जवाब दीजिए। (व्यवधान) दो साल आप सत्ता में रहे, फरवरी, 2018 में आपने स्वीकृति जारी की थी, दिसम्बर, 2019 में आपकी विदाई हुई थी, आपने दो साल में नीमकाथाना स्टेडियम के लिए क्या किया, यह आप माननीय सभापति महोदय को बताएं। माननीय सभापति महोदय, जमीन तैयार है, क्षेत्र का युवा सरकार की ओर टकटकी लगाये बैठा है, वह देख रहा है कि कब स्टेडियम का काम शुरू हो और कब उनकी वर्षों की आस पूरी हो।

माननीय सभापति महोदय, नीमकाथाना शेखावाटी क्षेत्र का मुख्य कस्बा है। मुझे खुशी है सभापति महोदय, आप स्वयं शेखावाटी से आते हैं और आप जानते हैं अच्छे से कि सेना में, पुलिस में और अन्य सेवाओं में सबसे ज्यादा युवा भर्ती होते हैं तो शेखावाटी के होते हैं और अपनी जांबाजी के लिये भी प्रसिद्ध हैं। हम रोज सुनते हैं कि आज शेखावाटी का फलां सपूत शहीद हुआ, देश पर मर मिटा, ये जांबाज शेखावाटी से हैं।

माननीय सभापति महोदय, खेलकूद में भी प्रतिभाएं ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा हैं। देश के परिप्रेक्ष्य में हम नजर दौड़ाएं तो देश का नाम रोशन करने वाली, सारी दुनिया में नाम रोशन करने वाले अधिकतर खिलाड़ी गांवों से आते हैं। ये न बोर्नविटा पीते हैं, न हार्लिक्स पीते हैं, ये बकरी और गाय का दूध पीकर सभी के छक्के छुड़ाते हैं। यही वजह है कि आज नीमकाथाना में अर्जुन अवार्डी और पदक जीते हुए बहुत सारे खिलाड़ी हैं। अभी एक बच्ची नेपाल में ताइक्वांडो में द्वितीय रही है जो मेरे विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना की है।

(श्री सुरेश मोदी)

कुश्ती और तीरंदाजी में भी बहुत पदक जीते हैं। एक अर्जुन अवार्डी हमारे यहां कुश्ती में है। खेल मंत्रीजी अभी यहां है नहीं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले वह नीमकाथाना पधारे थे और वह स्वयं देखकर आये हैं कि उस अर्जुन अवार्डी ने अपने पैसे खर्च करके अपना समय बर्बाद करके वह एक कुश्ती का अखाड़ा चला रहे हैं। जहां के बच्चे खेलो राजस्थान में और आसाम के खेलों में बहुत सारे अवार्ड जीत कर आये हैं। इसी तरह से तीरंदाजी की कोचिंग भी एक कोच, अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी जो अवार्ड जीता हुआ है वह स्वयं के खर्चे पर चला रहा है। सेना में भर्ती के लिए नौजवान सड़कों पर दौड़ लगाते हैं, अभ्यास के लिए, रोज उनके पांवों में कंकड़ चुभते हैं, कीलें चुभती हैं और वाहनों से दुर्घटनाएं होती हैं। सबसे बड़ी बात है कि हर महीने ऐसे अभ्यास करने वाले नौजवानों की मेरे इलाके में जो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे गुजर रहा है उस पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हमारे नौजवानों को एक छोटी-सी सुविधा खेल स्टेडियम की दे दें तो इन प्रतिभाओं को तराशने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, खेल मंत्रीजी स्वयं एक खिलाड़ी हैं, युवा हैं, आज सदन में घोषणा करें और बताएं कि यह स्टेडियम कब शुरू होगा। आपने राजस्थान में इस बार खेलों में नवाचार किया है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। खेलो राजस्थान का आयोजन किया और सबसे बड़ा काम खिलाड़ियों को नौकरी में आरक्षण देने का काम किया है। उनके भत्तों में वृद्धि की, जो पुरस्कार अन्तरराष्ट्रीय मैडल जीतने पर मिलते थे, उनमें वृद्धि की। उनकी सुविधाओं में वृद्धि की। आपने सभी पुरस्कार जीते, खिलाड़ियों का सम्मान किया, यह भी एक अच्छा प्रयास है। निश्चित तौर पर आपके प्रयास रंग लाएंगे और राजस्थान में खेलों को पंख लगेंगे। मैं पुन: आपके माध्यम से खेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि नीमकाथाना क्षेत्र के युवाओं को स्टेडियम की सौगात दें। मैं मुख्य मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि 'Fit Rajasthan, Hit Rajasthan' का जो आपका सपना है, उसे पूरा करने में आपका जो पांच करोड़ का बजट है, वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, जिसे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि हर पंचायत में जैसा आपका विचार है, वह पूरा करें। हर पंचायत में एक खेल मैदान की स्थापना करें, चाहे वह नरेगा के माध्यम से हो, चाहे और किसी मद में उसका बजट मिले, परंतु

(श्री सुरेश मोदी)

ऐसी नीति बनाएं कि हर पंचायत हैडक्वार्टर पर एक खेल मैदान बने, जिससे हमारे युवाओं को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिले। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री पुखराज गर्ग।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 11 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार और धन्यवाद। सभापति महोदय, खेल की बात करते हैं तो खेल गांवों के स्कूलों में उतने ही जरूरी हैं, जितनी शिक्षा है। बच्चे जब भी स्कूल में खेलते हैं तो उनका मानसिक और शारीरिक विकास होता है। जिन बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अच्छा हो, वे हमेशा पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं और हर एक्टिविटी में आगे रहते हैं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए, खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर स्कूल में मैदान और वे सारे संसाधन जुटाये जाएं, जिनसे बच्चे अच्छी गुणवत्ता के खिलाड़ी बनें और अपने देश और प्रदेश का नाम करें। सभापति महोदय, खेल ग्रामीण क्षेत्र में इसलिए भी जरूरी हैं कि इनके माध्यम से गांवों में एक सामाजिक समरसता का माहौल भी बनता है, जिसकी आज की तारीख में राजस्थान और देश में सख्त जरूरत है।

मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि खेलों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा संसाधन जुटाएं, ज्यादा से ज्यादा बजट दें ताकि खेलों का गांवों में विकास हो और ग्रामीण क्षेत्र, दूरदराज की ढाणियों से जो अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, वे खेलों में आगे बढ़ें और उन गांवों का नाम रोशन करें। मेरे भोपालगढ़ क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे गांव हैं, जिनके बच्चे, छात्र और छात्राएं आज भी राज्य स्तर और उससे से आगे भी खेलों में भाग ले रहे हैं।

मेरे वहां एक हीरादेसर गांव है। उस गांव के बच्चे हमेशा राज्य और देश में प्रतिभागी बनते हैं, खेलते हैं, लेकिन वहां पर किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। न तो स्टेडियम है और न ही किसी प्रकार के कोई और संसाधन हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से और मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों में खेलों को ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए अधिक बजट दें

(श्री पुखराज)

और उन गांवों में, जिनके बच्चे अभी भी प्रदेश और देश में खेल रहे हैं, वहां अच्छा स्टेडियम बने और दूसरे संसाधन भी उन बच्चों को मुहैया कराये जाएं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि मेरे भोपालगढ़ क्षेत्र में सोयला, बावड़ी, भोपालगढ़, आसोप, रतकुड़िया एवं सालवा कलां, ये वे गांव हैं, जिनमें से अभी भी बच्चे प्रदेश और देश में खेल रहे हैं। इन गांवों में स्टेडियम की सख्त जरूरत है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां स्टेडियम के लिए जमीन भी अवेलेबल है, वहां स्टेडियम का विकास करें। दूसरे संसाधन भी वहां जुटाएं ताकि वे बच्चे और भी अच्छी गुणवत्ता से उस खेल की तैयारी करें और अपने गांव-देश का नाम रोशन करें।

सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो अभी नीरोगी राजस्थान के बारे में बजट पेश किया गया है, मैं समझता हूं कि नीरोगी राजस्थान का जो संकल्प है, उसे पूरा करने के लिए जरूरी नहीं है कि सभी को दवाइयां और इंजेक्शंस ही दिये जाएं। उसे नीरोगी रखने के लिए गेम्स बहुत जरूरी हैं। बच्चे जो गांव में पढ़ते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की स्कूलों में पढ़ते हैं, जब वे गेम्स में अच्छे होंगे, शारीरिक और मानसिक रूप से तंदुरुस्त होंगे, जब हमारी यह आने वाली पीढ़ी तंदुरुस्त होगी, तभी नीरोगी राजस्थान का जो विजन है, परिकल्पना है सरकार की, वह साकार होगी।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है, गांवों में ज्यादा से ज्यादा गेम्स का बजट दें और गांवों में स्टेडियम बनाएं। आजकल प्रदेश-देश में और गांवों में भी दूसरे गेम्स तो कम हो गये हैं और बच्चे क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान देने लग गये हैं। मैं समझता हूं कि उन स्कूलों में जो राज्य स्तरीय गेम्स हैं, उनमें क्रिकेट को भी शिक्षा विभाग को जोड़ना चाहिए। उसका भी अनिवार्य रूप से उन स्कूलों में कम्पीटिशन होना चाहिए। यह मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए पुन: धन्यवाद, आभार।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मांग संख्या 11 और 24 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, दुनिया की छह नम्बर की आबादी, हर छठा आदमी हिन्दुस्तानी, हर छठी समस्या भी दुनिया की हम दूर करें, ऐसी हमारी नैतिक

(श्री बलवान पूनियां)

जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए अनुसंधान और इतना जोरदार, महत्वपूर्ण विषय है आज जो सारे विश्व को इकट्ठा कर लेता है। इस अनुसंधान पर हमने खर्च के लिए बजट रखा है, जो किताब हमें दी गयी है, 2019 और 2020 में महज 1 लाख 61 हजार 120 रुपये अनुसंधान पर खर्च करेंगे हम।

सभापति महोदय, जब हमारे अनुसंधान ऐसे हैं, तब सारे के सारे विश्वविद्यालय जिनके जिम्मे अनुसंधान हैं, उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, हमारे यहां हिन्दुस्तान में 800 विश्वविद्यालय हैं, 50 हजार महाविद्यालय हैं, 3 करोड़ छात्र हैं, आईआईआईटी, आईआईएम, एनआईआईटी, आईसीएसई, सारे संस्थान जिन कमियों से जूझ रहे हैं, वे उच्च क्वालिटी के न तो शोध तैयार कर रहे हैं न अनुसंधान कर रहे हैं। जिस कृषि संकट की बात हमारे सदन में चलती है वह इसी शोध पर टिका हुआ है। हमारे यहां जो देशी क्वालिटी के बीज हमने शोध से तैयार किये थे, हमारे यहां जो बड़े-बड़े फार्मिंग इंस्टीट्यूट हिन्दुस्तान में बनाये गये थे, जो हिन्दुस्तान की मिट्टी से, आबोहवा से बीज तैयार करते थे उनकी जगह जो बीटी ने ली है उसी की वजह है कि कृषि आज संकट से जूझ रही है।

(15.40 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, जो दुनिया में लात मारकर बीटी निकाल दी गई थी, जिस अमरीका से उसको बेदखल कर दिया गया था, जिस वियतनाम में तीसरी साल बीटी को गो-बैक दिखा दिया गया था, वह आज हिन्दुस्तान के बाजार में इसलिए आ गई कि हमारे यहां रिसर्च सब खतम हो रहे हैं। रिसर्च फैलोशिप की बातें यहां नदारद हो रही हैं। मंत्री महोदय, हमारे यहां सारे के सारे विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री बांटने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। यह मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े कह रहे हैं कि हम अनुसंधान पर खर्च कहां कर रहे हैं। इसी वजह से हमारे यहां हर चीज में मिलावट और यहां तक कि उत्पादन के लिए बीज नपुंसक, नपुंसक खाना, नपुंसक पीना हो गया है और यह हिन्दुस्तान की संस्कृति पर भी हमला है।

सभापति महोदय, राजस्थान के इस हाउस में इतना जोरदार विषय डिमाण्ड के रूप में आज लेकर आए जिससे हम हिन्दुस्तान को नई दिशा दे

(श्री बलवान पूनियां)

सकते हैं। हमारे यहां नारा दिया जाता है 'बुद्धम् शरणम् गच्छामि', हम बुद्ध की शरण में चलें, हम ध्यान की शरण में चलें। बात सूर्य नमस्कार की चाहे हम कर लें, लेकिन सूर्य नमस्कार के लिए जो कंटेन्ट हमें चाहिए, वह कंटेन्ट हमें रात्रि को नहीं मिलेंगे तो सूर्य उदय होने के बाद सूर्य नमस्कार के लिए हम कैसे बैठेंगे। दो जून रोटी के लिए दौड़ पड़ेंगे।

सभापति महोदय, मैं आज सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि चाहे कृषि अनुसंधान पर, चाहे मनुष्य के अनुसंधान पर सरकार जोर दे, सरकार ने जोर दिया है नीरोगी राजस्थान पर तो मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा। मेरे से पहले जो वक्ता बोले, चाहे पिछले दिनों में डिमांड्स पर चर्चा में बोले, उन्होंने कहा कि हमारे यहां कैंसर है, हमारे यहां सिलिकोसिस है, हमारे यहां दूसरी बीमारियां फैल रही हैं। कोरोना से तो हम इतना डर गये कि हमारे नेता, प्रतिपक्ष और सदन के नेता कोरोना के उस मरीज से मिलने नहीं जा रहे हैं। यह हमारी इस कमजोरी का प्रतीक है कि हम बीमारियों से डर रहे हैं क्योंकि हम थिसिस भी नहीं कर रहे है। कैंसर से जूझ रहे हैं, बीकानेर में कैंसर ट्रेन भरकर आती है लेकिन हम इस बात का पता लगाने के लिए कतई गंभीर नहीं हैं कि कैंसर होता क्यों है और किस क्षेत्र में होता है तथा किस वजह से होता है? पानी पीने से होता है या पानी उगलने से होता है या खाना खाने से होता है? सभापति महोदय, बहुत सारे बच्चों में एक रोग है कि गेहूं खाएगा तो वह सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से हम किस चीज को खाते हैं, उसकी वजह से हमारे यहां कैंसर होता है। हमारी कोशिकाएं अनियंत्रित होकर एक रोग पैदा करती है, वह ब्लड में भी करती हैं, शरीर में करती हैं और हिन्दुस्तान में हम पता नहीं लगा पाये हैं। सभापति महोदय, यह अनुसंधान की चीज है। अमरीका में कैंसर का निदान तो नहीं ढूंढ पाये कि इसका निदान क्या है पर रोकथाम का उपचार है, लेकिन हिन्दुस्तान में यह चीज नहीं है।

सभापति महोदय, दुनिया के 100 विश्वविद्यालयों में हम कहीं नहीं हैं। हिन्दुस्तान में एक नम्बर का विश्वविद्यालय जेएनयू है जिसके पीछे हम जूते लेकर पड़े हुए हैं कि इसको फेल कैसे करें। सभापति महोदय मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा कि हमारे यहां इतनी भाषाएं हैं लेकिन आज भी हम भाषाओं की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि हमने कभी रिसर्च ही नहीं किया कि इस भाषा की जरूरत क्या है? हमने कभी इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं की कि हमें आगे बढ़ने के लिए, मनुष्यता को आगे बढ़ाने के लिए किस चीज पर शोध करना है।

(श्री बलवान पूनियां)

सभापति महोदय, यह बात साथियों की उठी कि खेल में जाएंगे तो बच्चे आत्महत्या नहीं करेंगे। यह इसलिए क्योंकि नौजवानों में आत्महत्या बढ़ रही है। 15 साल का बच्चा आत्महत्या कर लेता है। मेरे इलाके में वाकया घटा। पत्नी पर शक करके एक आदमी में एक रात अपने दो बच्चों और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और खुद जहर पी गया। ये आत्महत्याएं क्यों बढ़ रही हैं? यह तनाव कहां से आ रहा है? यह शोध का विषय है, सामाजिक विज्ञान के शोध का विषय है।

सभापति महोदय, क्या हम जानना नहीं चाहेंगे कि मनुष्य जो इतनी जोरदार चीज प्रकृति ने भेजी यह अपनी पूरी जिन्दगी कैसे बेहतर तरीके से जिये, यह हैप्पीनेस का आइडिया हिन्दुस्तान में कब आया और हिन्दुस्तान से पहले कौनसे मुल्क हैप्पीनेस की बात करने लगे हैं, यह शोध का विषय है। यह शोध का विषय है कि आदमी और ज्यादा कैसे जीये, वह 100 साल और 100 साल से ज्यादा कैसे जीये, यह शोध का विषय है और हम शोध पर क्या खर्च कर रहे हैं? मैं सरकार का ध्यान इंगित करना चाहता हूं कि हमारा बजट जो करोड़ों में होना चाहिए था वह सैकड़ों, हजारों और लाख में है। सभापति महोदय, मेरी सरकार से मांग रहेगी कि सारे तमाम विश्वविद्यालयों में शोध के लिए बजट, शोध के सब्जैक्ट बढ़ाये जाएं और खासकर कृषि के क्षेत्र में तो हमने शोध नहीं बढ़ाये तो चाहे हम पानी का कितना ही प्रबन्ध कर लें, चाहे हम कितनी ही बिजली फ्री में दे दें, लेकिन कृषि संकट और गहराएगा, और गहराएगा और इसको कोई बचा नहीं सकता।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान खेल की तरफ करना चाहूंगा। हमारे यहां बच्चों को खेलने के लिए अभी सरकार ने, केन्द्र और राज्य, दोनों सरकारों ने जैसे भागदौड़ में कोई अनाउंस करते हैं कि भागो, बीमार पड़ गये और लोग झंझट में हो गये और बहुत जोर की मानसिक प्रताड़ना समाज में आ गई इसलिए खेल की तरफ लेकर जाओ। सभापति महोदय, जिस तरीके से कैलाश जी कह रहे थे, जितेन्द्र जी भी कह रहे थे, मैंने मेरे विधायक कोटे से खेल स्टेडियम बनाने के लिए पैसा खर्च किया है और आगे भी खर्च करेंगे। मैंने खेल मंत्री जी को मेरे लैटरपैड पर लिखकर दिया है कि आप मेरे इलाके में खेल स्टेडियम बनाइये, दस लाख रुपये की मैं अभिशंसा करता हूं। मैं समझता हूं कि सदन के सारे साथी खेल को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके से आगे आएं। यह तो एक बात है, लेकिन दूसरी बात यह है कि सरकार को भी

(श्री बलवान पूनियां)

जब कर्ज लिया है राज्य चलाने के लिए तो खेल के लिए भी कोई हजार-दो हजार करोड़ और कर्ज ले लेती। अगर खेलेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। खेलेगा राजस्थान तो फिर हिट होगा, फिर फिट होगा। इसलिए इस कर्ज को एक बार बढ़ने दीजिए जनहित में। इसको रिटर्न करके लाएगा अपना नौजवान, दुनिया से गोल्ड मैडल लेकर आएगा। हमसे दो साल बाद आजाद हुआ है चाइना और जब बात ओलम्पिक खेलों की आती है तो हम एक-दो-तीन मैडल में रह जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा कांस्य और सिल्वर करके 10-15 मैडल में रह जाते हैं और वे लोग जहाज भरकर लाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वे पांच साल के बच्चे की पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी और उसके माथे की हड्डियां चैक करते हैं कि यह खेल क्या सकता है। वे ईमानदारी से उस बच्चे को आगे बढ़ाते हैं, उसके खाने-पीने के प्रबन्ध से लेकर उसकी एजुकेशन और खिलाने का प्रबन्ध का दुनिया के बहुत सारे मुल्क ऐसा काम करते हैं जो समाजवादी मुल्क रहे हैं। सभापति महोदय, जिन मुल्कों में पूंजीवाद आगे बढ़ा, वहां सारी चीज पैसे पर तौल दी गईं और सरकारों ने भी व्यवहार बनिये जैसा करना शुरू कर दिया इसलिए वे जहाज भरकर लाते हैं मैडलों के। मैं खेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं, राजस्थान के मुख्य मंत्री जी से हम सब मिलेंगे और बजट मांगेंगे कि नौजवान के साथ भेदभाव भी न किया जाए, उसको खेलने का मौका दिया जाए।

सभापति महोदय, मुझे पता नहीं, अभी एक घंटे पहले सदन में गुस्सा किसलिए आया था कि जब क्रिकेट की बात आती तो मेरे से रहा नहीं जाता, उन्होंने तो नाम नहीं लिया, मैं तो नाम ले रहा हूं कि वह +++ कहां भाग गये? पता नहीं, उन पर क्या आरोप था? मैं तो खेल ज्यादा नहीं जानता, जयपुर अभी आया हूं साहब, पहले तो जयपुर में आता ही नहीं था, एमएलए बनने के बाद आया। +++ क्या सौदा है जी? बड़ा जिक्र चलता था अखबारों में कि +++ भाग गए, +++ भाग गए, कहां भाग गए? कुछ पता करके लाये क्या खेल मंत्री जी? लन्दन क्या कर रहे हैं, उनको लाओ। क्या पता वह खेल वाला बजट उन्होंने ही रोक रखा हो, उन्होंने ही दबा रखा हो। मेरे इलाके का तो एक बच्चा क्रिकेट खेलने आया था, सातवें नम्बर पर था। उसका बांसवाड़ा था शायद कैम्प और सातवें नम्बर से वह छोरा फिसल गया और सलैक्ट नहीं हुआ। हो सकता है कि वह +++ की महामाया वहां काम कर रही होगी तो थोड़ी छंटनी करो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। कृपया समाप्त करें। अगर आप कह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, अभी तो पांच मिनट और पड़े हैं। सभापति महोदय, दो मिनट और दो। सभापति महोदय, जब सामाजिक सेवा की बात आती है तो हमारी संस्कृति में और हिन्दुस्तान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में और विभिन्न संस्थाओं में ड्रामा और थियेटर का एक रोल था जो समाज को नाटक के जरिये, संगीत के जरिये ये बातें बताते थे कि समाज आगे कैसे बढ़े, बराबरी का समाज कैसे गायब है। कैसे हमारे थियेटरों में कार्यक्रम होते थे, लोग देखते थे, जिससे संस्कृति आगे बढ़ती थी, आज थियेटर गायब हुआ। उस थियेटर को वापस हमारे रंग में लाने की जरूरत है।

सभापति महोदय, हमारे यहां स्कूलों में साइंस की लैब्स स्कूलों में स्थापित होनी चाहिए थी। आज तक आजादी के 72 साल बाद, हमारे नये शिक्षा मंत्री जी ने खूब सारे प्रयास किये, पुराने स्कूल तो वापस खोले, लेकिन लैब पर स्पेशल काम करने की ओर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि, मैं सारे साथियों को बताना चाहता हूं कि 75 हजार रुपये अगर एक एमएलए देता है स्कूल में, तो 7 लाख रुपये में लैब सरकार स्थापित करवाएगी, लेकिन सारे स्कूलों तक यह योजना जाए। जहां-जहां साइंस है, वहां लैब उच्च तकनीकी की हो, ताकि हमारे बच्चे उसमें शोध का काम कर सकें।

सभापति महोदय, एक-दो मिनट और लूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो गांव हमने खेल स्टेडियम के लिए चिन्हित किये हैं, हमने वे ही गांव चिन्हित किये हैं, प्राथमिक तौर पर जिन गांवों के युवाओं में नशे का प्रकोप दिख रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरे राजस्थान में जिस भी गांव के युवा नशे की तरफ ज्यादा दिखें वहां एक खेल स्टेडियम बना दिया जाए, ताकि बच्चे का ध्यान खेल की तरफ चला जाए और नशे के खिलाफ हमारी लड़ाई मजबूत हो सके।

सभापति महोदय, जिस गांव में बच्चे और बच्ची के भागने की ज्यादा स्थिति, 10 से ज्यादा केस हैं तो उस गांव में खेल स्टेडियम पक्का ही बनाओ, ताकि ये छोरे सारे दिन भर फोन पर यूं न लगे रहे, दो-तीन घंटे खेलने के लिए चले जाएं, दिमाग खराब नहीं हो। इसलिए मेरा सभापति महोदय, सरकार से निवेदन है कि...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): ये जरूरी चीजें हैं, इनकी तरफ सरकार ध्यान दे। मेरे विधान सभा क्षेत्र के बड़े-बड़े गांव गांधीबड़ी, छानीबड़ी, निनाण, रामगढ़ और भादरा में और भाड़ी एक गांव है बारानी क्षेत्र का, डूंगरणा गांव है, इनमें खेल स्टेडियम का निर्माण करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, शिक्षा, कला एवं संस्कृति, खेलकूद और युवा सेवाएं तथा विविध सामाजिक सेवाएं, मांग संख्या 24 और मांग संख्या 11 पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 'खेलो इंडिया' के माध्यम से गांव-गली और मोहल्ले के नौजवान छात्र-छात्राओं को खेलों में भाग लेने का मौका दिया। खेल मंत्री महोदय, आपको याद होगा कि अभी आसाम के अंदर 10 हजार युवाओं ने खेलो इंडिया के अंदर भाग लिया और प्रोत्साहन राशि के रूप में 5 लाख रुपये जीते। उन लोगों को पांच-पांच लाख रुपये भी मिले। हमारे अभी किरण जी बता रही थीं, राजसमन्द जिले के काबरा गांव की वह बेटी भावना जाट एथलेटिक्स के अंदर, ओलम्पिक के अंदर सलेक्ट हुई। माननीय प्रधान मंत्री जी का मैं इसलिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि गांवों के अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का मौका खेलो इंडिया के द्वारा माननीय प्रधान मंत्री जी ने दिया। मैं पुन: उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। उसी तर्ज के ऊपर राजस्थान सरकार ने भी यहां पर आयोजन किया। आपको भी खेल मंत्री महोदय बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे काबिल दोस्त सिरोही से आने वाले सदस्य, अभी सदन के अंदर नहीं हैं, वे चले गये हैं। उसके बाद में कई अन्य सदस्यों ने भी क्रिकेट की राजनीति के ऊपर बात करनी चाही और अभी-अभी क्रिकेट के बारे में एक भूत जो सता रहा है। आप सब लोग उस भूत को भूल नहीं पा रहे हो और आप लोगों ने गाहे-बगाहे, क्योंकि आदत है कि हमें तो विरोध करना है।

हमें खेल नीति बनाने की बात करनी चाहिए, किस तरह से हम खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए खेल नीति जल्दी से जल्दी बनाएं। लेकिन,

(श्री अभिनेश महर्षि)

हम चले जाते हैं, उसी तर्ज के ऊपर और उसके बाद में कई लोगों ने नाम लेकर बोला। आप लोग याद करिए अभी-अभी जो क्रिकेट का चुनाव हुआ। उसके अंदर किस तरह से पुलिस के इंटरवीन करने के बाद में, किस तरह से उसको अखाड़ा बना दिया गया था। आपकी ही पार्टी के दो सदस्य मैं यहां पर नाम लेना चाहूंगा +++ का, जो आपके नेता प्रतिपक्ष थे। उन्होंने किस तरह से आरोप जड़े आप लोगों के ऊपर, खेलों के अंदर आपने राजनीति की बात की। हम खेल के अंदर राजनीति नहीं करेंगे, ये बात ही बात करना चाहते हैं। माननीय सचेतक महोदय, जब सुहाती बात कहने लगे, मेरे एक माननीय सदस्य ने तो सभापति महोदय से निवेदन कर दिया कि ये अभी तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। इनको तो बोलने दो और जब अभिनेश महर्षि अभी कुछ बातें कहेगा, तब इशारा करेंगे कि जल्दी से बैठा दो इसको।

दोस्तो, मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि खेल के अंदर बजट की बात कर रहे थे आप लोग, सब लोगों ने कहा कि ऊंट के मुंह में जीरा, आप लोग खेलों के अंदर...

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, एक मिनट...

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): देखिए, सचेतक महोदय, आप विराजने का कष्ट करें। जब माननीय सदस्य बोलते हैं...

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): मेरी बात तो सुन लो।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): तो सभापति महोदय को इंटरवीन करने का...

डॉ. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): मेरी बात तो सुन लो, आपने मुझे कोट किया इसलिए बोल रहा हूं, मैंने माननीय सदस्य को...

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): कोट करें, जब आपका नम्बर आए, तब बोल देना...

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): मेरा नम्बर नहीं आता।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): आप समय बढ़ाने की बात कह रहे हैं, तो आप बोलिए। सचेतक महोदय, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है कि आप माननीय सदस्य बोलें तो बीच के अंदर बोलें। माननीय सभापति महोदय,

(श्री अभिनेश महर्षि)

मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। आप इनको कृपा करके बैठाने का कष्ट करें। सभापति महोदय, इल्तिजा करता हूं। सभापति महोदय, आपसे गुहार लगाता हूं। सभापति महोदय, ये किस तरह की बातें करते हैं, बैठ जाइये।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): मैं तो समय देने को तैयार हूं। मेरी बात तो सुनो।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): आप मेरा समय जाया कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरे समय के अंदर से इतना समय काट दीजिये। ये बीच के अंदर डिस्टर्ब कर रहे हैं। सभापति महोदय, आपका संरक्षण चाहता हूं।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): आप इनको पांच मिनट एक्स्ट्रा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये खूब समय लें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। ये किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, उन्होंने खुद ने कह दिया है पांच मिनट का समय आपको और दे देंगे। आप ज्यादा आक्रोश में नहीं आए, अपनी बात कहें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, खेलों के ऊपर जो बजट देना चाहिए था। हम नीरोगी राजस्थान की बात कर रहे हैं और खेलों के बजट को इतना कम कर दिया। पिछली बार से भी कम कर दिया तो जब खिलाड़ियों को, सब कहते हैं कि अच्छा खेलोगे, स्वस्थ रहोगे, नीरोगी काया कैसे होगी, जब तक हम खेलों के अंदर बजट नहीं देंगे, खेलों को बढ़ावा नहीं देंगे।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं खिलाड़ियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूं माननीय खेल मंत्री महोदय को प्रत्येक गांव के अंदर खेल मैदान, चाहे कोई गांव की स्कूल है तो उसके अंदर आप खेल मैदान विकसित करने के लिए और खेलों के मैदान के लिए भूमि आबंटन करने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय को निर्देश जारी करें। आपके पास में यदि बजट नहीं हो तो नरेगा के माध्यम से उन खेल के मैदानों को विकसित करने का काम करने की कृपा करें। हम लोग क्षेत्र के अंदर जाते हैं तो प्रत्येक नौजवान इस बात की मांग करता है कि हमारे खेल के मैदान के लिए आप क्या करेंगे? कहीं पर भूमि के आबंटन संबंधी समस्या आती है, कहीं पर गोचर

(श्री अभिनेश महर्षि)

भूमि का मामला आ जाता है, कहीं पर कहीं कोई जोहड़ पायतन की जमीन का मामला आ जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अंदर जो भी अड़चन आती है, उनको दूर करने की कृपा करके खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए और बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो मिलिट्री के अंदर, पैरा मिलिट्री फोर्सेज के अंदर भर्ती होना चाहते हैं। वे तैयारी करने के लिए गांव से दूर नहीं जा सकते हैं, ऐसी स्थिति के अंदर प्रत्येक गांव के अंदर खेल का मैदान विकसित करने के लिए आप प्रयास करें और बजट आबंटन करें और उनको भूमि का आबंटन करने की कृपा करें। नरेगा से उनको जोड़कर के शुरू करने की कृपा करें, मेरी पहली मांग तो यह है।

मेरे रतनगढ़ के अंदर सेठ बुद्धमल दुग्गड़ राजकीय स्टेडियम है। एक हमारे बुद्धमल जी दुग्गड़ साहब ने पैसा देकर के भामाशाह ने उस खेल स्टेडियम के निर्माण को करवाया और राज्य सरकार ने भी उसके अंदर कुछ पैसा दिया। आज उस स्टेडियम की इतनी दुर्गति हो रही है। वहां पर कभी तो कृषि उपज मण्डी की मूंगफली तौलने का काम किया जाता है, कभी अन्य किसी काम के अंदर लिया जाता है, कभी कोई सभा होती है, लेकिन खिलाड़ियों के उपयोग में किसी भी तरह से कोई काम नहीं आ रहा है।

भारत सरकार के खेल मंत्री रिजीजू साहब अभी आये थे चूरू के अंदर सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन करने के लिए, 6 करोड़ रुपये से ज्यादा सिंथेटिक ट्रैक बनाकर भारत सरकार चूरू के अंदर वह सौगात दी है। हमारे माननीय सांसद राहुल कस्वां जी के प्रयासों के द्वारा, मैंने उनसे भी मांग की थी। मैं आपसे इल्तजा करता हूं, प्रार्थना करता हूं माननीय खेल मंत्री महोदय कि हमारे रतनगढ़ के स्टेडियम के लिए कुछ खेल राशि का जो उनके डवलपमेंट के लिए राशि है, उसका आबंटन करने की कृपा करें। मेरे रतनगढ़ के अंदर टेबिल टेनिस के बहुत अच्छे खिलाड़ी, जिन्होंने स्कूल के अंदर, नेशनल लेवल के अंदर और अन्य प्रतियोगिताओं के अंदर भी नेशनल लेवल के ऊपर उन्होंने मैडल्स जीते हैं, बालिकाएं हैं, बालक हैं। वहां पर टेबिल टेनिस की एक एकेडमी बनाने की कृपा करें जिससे वहां का जो टैलेन्ट है, वह आगे बढ़कर के आपका नाम, राज्य का नाम ओर देश का नाम रोशन कर सकें। स्पोर्ट्स के अंदर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप स्वयं एक खिलाड़ी हैं और आपके दिल में खिलाड़ियों के लिए बहुत हमदर्दी है।

मैं आप लोगों से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि एससी/एसटी के जो

(श्री अभिनेश महर्षि)

भी विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी जब आप खेलों में खेलने के लिए राशि उपलब्ध करवाते हैं या जो भत्ता देते हैं तो उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाएं, जिससे उनको आगे आने वाले समय में अपने-आप को परफोर्म करने का मौका मिल सके।

(16.00 बजे)

माननीय खेल मंत्री महोदय, खेलों का आयोजन सिर्फ बड़े शहरों के अंदर होता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कोई भी एक खेल की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता वर्ष में एक बार प्रत्येक पंचायत समिति हैड क्वार्टर के ऊपर कराने की कृपा करें, जिससे आने वाले समय में ग्रामीण इलाके की जो खेल प्रतिभाएं हैं उनको ज्यादा मौका मिल सके। वहां पर बहुत सारे भामाशाह भी तैयार हो जाएंगे, आपको आर्थिक मदद भी मिल जाएगी और नेशनल लेवल के जो गेम्स, जो नेशनल लेवल की प्रतियोगिताएं हैं, उनको भी वहां पर कराने की कृपा करें। मैं आपको यह आफर देता हूं कि यदि आप किसी भी तरह की एक स्पोर्ट्स के अंदर कोई नेशनल आप वहां पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कोई एक टूर्नामेंट कराने की यदि घोषणा करें तो मैं यह कहता हूं कि रतनगढ़ के अंदर बहुत सारे भामाशाह तैयार हैं इस बात के लिए। आप एक वर्ष में कम से कम एक बार एक खेल की नेशनल प्रतियोगिता का वहां पर खेल का आयोजन, बड़ा खेल का आयोजन करने की घोषणा करें आपके अपने उद्बोधन के अंदर।

माननीय सभापति महोदय, नो बैग डे किया है, लेकिन उसके अंदर किसी तरह की कोई बाकी रूपरेखा तय नहीं की है। अब हमारे पास पीटीआई नहीं हैं और पीटीआई नहीं हैं तो वह जो नो बैग डे है उसके अंदर और कोई एक्टिविटीज को भी शामिल नहीं किया है। पीटीआई नहीं हैं हमारे पास में और हमने पीटीआईज की भर्ती करने का भी अभी कोई रोडमैप तय नहीं किया है। ऐसी स्थिति में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी पीटीआई भर्ती किए जाएं, शारीरिक शिक्षक भर्ती किए जाएं जिससे हमारा यह जो नो बैग डे वाला कंसेप्ट है, इसको हम भली प्रकार से काम में ले सकें और आने वाले समय में खिलाड़ियों को तैयार कर सकें।

अब खाद्य सामग्री में मिलावट की बात कही लोगों ने कि खाद्य सामग्रियों में मिलावट जब तक रहेगी तब तक हम अच्छे खिलाड़ी नहीं दे सकेंगे, अच्छे खिलाड़ी नहीं पैदा कर सकेंगे। बहुत पुरानी जो आदर्श विद्या

(श्री अभिनेश महर्षि)

मंदिर हुई हैं और आरएसएस जिसके नाम पर अभी आप सब एकदम से उछल जाएंगे, आरएसएस की गतिविधियों में सबसे पहले सुबह-सुबह खेलने की एक्टिविटीज होती हैं और आरएसएस की शाखाओं के अंदर खेलने की एक्टिविटीज के कारण स्वस्थ शरीर होता है और स्वस्थ मस्तिष्क होता है इसलिए आप देख लीजिए उठाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मस्तिष्क और आपके नेताओं के मस्तिष्क में बहुत बड़ा फर्क है। हम स्वस्थ मस्तिष्क को लेकर आगे आने की बात करते हैं और खिलाड़ी भी जितने पैदा हुए हैं वह आदर्श विद्या मंदिर के हुए हैं वह आप उठाकर देख लीजिए। आदर्श विद्या मंदिर की जितनी स्कूल संचालित हैं ...(व्यवधान) बैठ जाइए, बलवान भाई।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): ...(व्यवधान) यह देखो, मैं कह रहा था न पहले ही ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराज जाइए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): देखिए यह क्या बात है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठिए। माननीय सदस्य, बैठ जाइए आप। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): वैचारिक रूप से भी समृद्ध ...(व्यवधान) समृद्ध भारत, वैचारिक रूप से स्वस्थ मस्तिष्क यह आर एस एस के संस्कारों में सिखाया जाता है और उन स्कूलों के अंदर जो आप लोगों को नहीं सिखाया जाता है। मैं अभी आदर्श विद्या मंदिर के ...(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): 000

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी, विराजें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): मैं पहले ही कह रहा था कि मैं नाम लूंगा आरएसएस का और आप लोग सब खड़े हो जाएंगे। (व्यवधान) सुनिए, मैं अभी आदर्श विद्या मंदिर के एक स्कूल में गया था रतनगढ़ के अंदर ...(व्यवधान) रुक जाओ। बैठ जाओ। मैं तो आरएसएस का ही हूं यह मान लो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका समय पूरा हो रहा है आप इधर-उधर जा रहे हो, अपनी बात नहीं कह रहे हो आप।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): यह बीच में बोल रहे हैं माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: आप अपनी बात कहें न।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): हां, मैं मेरी बात कह रहा हूं, आप सुनिए तो सही।

श्री सभापति: समय खतम हो रहा है। अभी समय समाप्त हो जाएगा।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): मैं साइंस और टैक्नोलोजी की बात कर रहा हूं। मैं अनुसंधान की बात कर रहा हूं। मैं अभी आदर्श विद्या मंदिर स्कूल धानुका, रतनगढ़ में गया। वहां पर केन्द्र सरकार ने अनुदान दिया है। एक लैबोरेट्री ऐसी शानदार संचालित हो रही थी, उसका उद्घाटन करके आया हूं मैं। उसके अंदर छोटे-छोटे बच्चों ने ऐसे अनुसंधान कर रखे हैं कि वहां पर ड्रोन से, मतलब ड्रोन किस तरह से उड़ता है, वह उन्होंने वहीं पर तैयार कर दिया। अभी जो बात कह रहे थे न कि एक किसान के बेटे ने, किस तरह से ट्रैक्टर चलाया जाता हैं रिमोट से, रिमोट से अनेक एक्टिविटीज किस तरह से संचालित की जाती है यह सब दिखाया जाता है इसलिए आप अनुसंधान के ऊपर भी पैसा दो, पैसा खर्च करो, छोटे-छोटे गांव के अंदर गुदड़ी के लाल बैठे हैं जो अनुसंधान के अंदर भी अपने-आप को बहुत बढ़िया तरीके से पेश कर सकते हैं और आने वाले समय में खिलाड़ी के रूप में भी वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं।

अभी पक्ष के सदस्य भी कह रहे थे कि यह युवाओं के लिए समर्पित बजट है। संयम लोढ़ा जी ने कलई खोल दी आपकी सारी की सारी। उन्होंने बता दिया और सुरेश मोदी जी ने तो और भी ज्यादा खोल दी। उन्होंने कहा कि 2018 में घोषणा की, 2018 के अंदर निश्चित रूप से बीजेपी थी और बीजेपी ने घोषणा की और आपने अपने वक्तव्य में यह कहा कि उन्होंने सारी की सारी सब सैंक्शंस भी जारी कर दी। उसके बाद में दिसम्बर, 2018 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई, उसके बाद में 2019 आ गया और उसके बाद में 2020 भी आ गया। आपकी सरकार, आपके खेल मंत्री, अभी तक यदि आपका स्टेडियम नहीं बन पाया तो उसके लिए भी हमको दोष दे रहे हो। हमें दोष देने की बजाय मैं आप लोगों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए यह सब जो हमने सुझाव दिए हैं माननीय सभापति महोदय, अपने जवाब में इनके बारे में कुछ कहें और आने वाले समय में हम सब लोग स्वस्थ बन सकें, नीरोगी

(श्री अभिनेश महर्षि)

राजस्थान की आपकी कल्पना पूरी हो सके, इसके लिए आप प्रयास करें। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री संदीप कुमार।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 24 और 11 पर चर्चा में भाग लेने का मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं छात्र राजनीति से आया हूं और छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं और लगातार युवाओं से जुड़ा रहा हूं। पिछली सरकार में राजस्थान युवा बोर्ड में उपाध्यक्ष भी रहा हूं। मेरा निवेदन है माननीय मंत्री जी से कि जिस तरीके से राजस्थान युवा बोर्ड जो बनाया गया है, जिस उद्देश्य से राजस्थान युवा बोर्ड बनाया गया है, उस पद पर आसीन रहते हुए मुझे कई बार मन में पीड़ा हुई कि जिस सोच के साथ बोर्ड बना है उस तरीके से काम अभी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। राजस्थान युवा बोर्ड के माध्यम से राजस्थान के युवाओं को मौका मिलना चाहिए। राजस्थान के युवा का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। जिस क्षेत्र में राजस्थान का युवा आगे बढ़ना चाहता है उस क्षेत्र में राजस्थान की सरकार को उसमें सहयोग करना चाहिए और यह सारा काम राजस्थान युवा बोर्ड का होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि राजस्थान युवा बोर्ड और स्पोर्ट्स काउंसिल दोनों मिलकर सामंजस्य बनाकर उसमें काम करें। दोनों के सहयोग से काम हो। बोर्ड की मीटिंग में स्पोर्ट्स काउंसिल को बुलाया जरूर जाता है, पर स्पोर्ट्स काउंसिल और राजस्थान युवा बोर्ड का कहीं भी कोई सामंजस्य ऐसा नहीं है कि वह साथ मिलकर कोई काम कर सके। मेरा निवेदन है कि विभिन्न क्षेत्रों में, जब हमने राजस्थान युवा बोर्ड का गठन किया है कि विभिन्न क्षेत्रों में राजस्थान के युवा का सर्वांगीण विकास हो सके तो सभी फील्ड उसमें आने चाहिए और सब लोगों को, अलग-अलग शिक्षाविदों को, अलग-अलग क्षेत्र के लोगों को उसमें शामिल करना चाहिए। राजस्थान युवा बोर्ड में आप सबको ध्यान है कि स्टाफ नहीं है। मात्र 2 कमरों में राजस्थान युवा बोर्ड चल रहा है। हम युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, पर जहां राजस्थान युवा बोर्ड की बात करते हैं तो एसएमएस स्टेडियम में मात्र 2 कमरे हैं। एक में पूरा स्टाफ बैठता है और एक चेयरमैन के लिए कमरा बनाया हुआ है। मुझे राजस्थान युवा बोर्ड में उपाध्यक्ष बनाया, 2 साल तक मुझे वहां कोई आफिस नहीं मिला। वहां पर दो ही कमरे थे। वहीं एडजस्ट करके कहीं न कहीं कुर्सी डालकर के बैठना पड़ा। एक सदस्य सचिव जो वहां

(श्री संदीप कुमार)

लगाया हुआ है वह भी डेपुटेशन पर है। स्टाफ जो लगाया हुआ है वह भी अधिकतर संविदा पर है। मेरा निवेदन है कि जितने भी जो बोर्ड और आयोग बनाए हुए हैं उनमें प्रोपर सभी जगह पर स्टाफ लगाया जाए और वह अच्छे से काम कर सके, इसके लिए राज्य स्तर पर ही नहीं, जिला स्तर पर और ब्लाक स्तर पर भी व्यवस्था होनी चाहिए और वहां पर मेंबर और बोर्ड का गठन ब्लाक स्तर पर होना चाहिए ताकि 1-1 युवा तक राजस्थान सरकार की सुविधाएं पहुंच सके।

दूसरा मेरा निवेदन है कि राजस्थान युवा बोर्ड के माध्यम से कार्यक्रम कराये जाते हैं और उस कार्यक्रम में लगातार एक परम्परा चल रही थी कि राजस्थान युवा बोर्ड के कार्यक्रमों में एनजीओ को आमंत्रित कर लिया जाता था। जिला स्तर पर एक कार्यक्रम कराया, उसमें एनजीओ के लोग आ गये। जो पहले से ही एनजीओ बनी हुई है, जो कलाकार हैं, जिन्होंने अपनी टीम बनाई हुई है, ऐसे लोगों को बुलाकर उस कार्यक्रम में इनको इन्वाइट किया जाता था और उन्हीं लोगों में से स्टेट लेवल पर भेज दिया जाता था। पिछली बार इसमें एक सुधार हुआ, कालेज और स्कूल स्तर पर युवाओं को आमंत्रित किया गया और ब्लाक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर संभाग स्तर पर और फिर स्टेट लेवल पर प्रतिभागियों को मौका मिला और फिर राष्ट्रीय युवा महोत्सव में उन लोगों को जाने का मौका मिला। स्कूल, कालेज के जिन बच्चों का उस फील्ड में इंटरेस्ट था, उनको वहां जाने का मौका मिला। इस तरह से हम ब्लाक स्तर पर बोर्ड का गठन करके और ब्लाक स्तर की प्रतिभाओं को स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक ले जाने का प्रयास करें और उसके लिये बोर्ड का गठन बहुत जरूरी है। ब्लाक स्तर तक हमारा बोर्ड बनना चाहिये।

दूसरा, एक नशा मुक्ति का कार्यक्रम हमने चलाया था। माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि आज हरियाणा, पंजाब से लगते हुए जो जिले हैं, उनमें युवाओं में नशे का प्रभाव बहुत बढ़ता जा रहा है। उन युवाओं को नशे की लत से दूर करने के लिए एक अभियान हम चलाएं और उन युवाओं को नशे से दूर करने के लिये हम उनको प्रोत्साहित करें। वहां पर सर्वे करवाकर किस-किस नशे में और कितने युवा उस नशे में हैं, उनको हम दवाई भी उपलब्ध कराएं और उनको अन्य किसी कार्य में भी लगाएं।

मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं राजस्थान के माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री जी का कि उन्होंने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय

(श्री संदीप कुमार)

प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिये दैनिक भत्ते को बढ़ाकर दोगुना कर दिया, इसके लिये माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद है। इसके अलावा ग्रामीण स्तर के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिये राज्य स्तर पर, जिला और ब्लाक स्तर पर भी खेलों का आयोजन कराया जाएगा, इस तरह की हमारी सरकार की मंशा है। नीरोगी राजस्थान, हिट राजस्थान और फिट राजस्थान का भी हमने संकल्प लिया है। इसके अलावा अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी हैं, उनको जो अनुदान सहायता राशि दी जाती है, उसको भी बढ़ाया गया है। मेरा निवेदन है 'खेलो राजस्थान' के माध्यम से एक नवाचार हमारे मंत्री जी ने, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कराया, जिसमें 8 हजार खिलाड़ियों ने भाग लिया, इसके लिये भी धन्यवाद है। पंचायत स्तर पर हम खेल के मैदान डवलप करने जा रहे हैं, यह सोच हमारी सरकार ने रखी है, इसके लिये भी सरकार का धन्यवाद है।

मेरा निवेदन है कि जो-जो बातें हमने बजट में रखी हैं, जो-जो सोच हमने रखी हैं, वास्तव में पंचायत स्तर पर खेल के मैदान डवलप होने चाहिये। चाहे वह स्कूली शिक्षा के माध्यम से स्कूल के मैदानों को हम डवलप करें या फिर बाकी जगह कोई जमीनें हैं, उनको हम डवलप करें। मेरा निवेदन है कि हर पंचायत स्तर पर और कोशिश यह हो कि हर रेवेन्यू गांव में एक खेल का मैदान होना चाहिये। जब हम खेल की बात कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है, तो खेल के लिये सुविधा देना भी जरूरी है। इसके लिये मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि प्रत्येक रेवेन्यू गांव में कोई न कोई एक खेल का मैदान बने, इसके लिये हम सब लोग मिलकर प्रयास करें। इसमें शिक्षा विभाग को भी शामिल कर सकते हैं। मैंने महसूस किया कि स्कूली शिक्षा को स्पोर्ट काउंसिल या स्पोर्ट डिपार्टमेंट से बिलकुल अलग रखा है। मेरा निवेदन है कि उनका भी आपस में को-ओर्डिनेशन होना चाहिये। स्कूलों में जो प्रतियोगिता होती है, स्कूलों से निकलने वाले खिलाड़ियों को स्पोर्ट काउंसिल के माध्यम से या हमारे खेल विभाग के माध्यम से उनको सम्मानित करना चाहिये और उन खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करने के लिये हमको कार्यक्रम रखने चाहिये।

श्री सभापति: अब कृपया समाप्त करें।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मेरा निवेदन है राजस्थान युवा बोर्ड के

(श्री संदीप कुमार)

माध्यम से एक कैरियर गाइडेंस के लिये भी अच्छे कैम्प आयोजित करने चाहिये, सेमिनार आयोजित करनी चाहिये ताकि युवाओं को स्कूली शिक्षा के दौरान यह पता चले कि स्कूल से बाहर निकलने के बाद हमको किस दिशा में जाना है। इस तरह के कैरियर गाइडेंस के कोर्सेज हों।

दूसरा मेरा निवेदन है कि इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स भी हमारे राजस्थान युवा बोर्ड के माध्यम से हम लगा सकते हैं। राजस्थान के हमारे युवाओं की इंग्लिश बहुत वीक होती है। जब बगल के स्टेट के छात्र आते हैं तो हमारे लोगों को बड़ा शर्मिंदा-सा होना पड़ता है, उनको गिल्टी फील होती है। मेरा निवेदन है कि इस तरह के कार्यक्रम भी हम उसमें चला सकते हैं।

माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि तीन लाख की आबादी का हमारा शहर है भिवाड़ी। भिवाड़ी-तिजारा हरियाणा से टच है। हमारे यहां सुविधा नहीं होने के कारण बहुत सारे हमारे खिलाड़ी हरियाणा में खेलने जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है 1991 में यूआईटी ने 35 बीघा जमीन एक्वायर करके रखी हुई है। किसानों को मुआवजा दे दिया है, जमीन पड़ी हुई है। वहां पर एक अच्छा स्टेडियम बने ताकि हमारे तीन लाख की आबादी के उस शहर में, जिनकी जमीनें औद्योगिक क्षेत्र में चली गई हैं, उनको खेलने का मौका मिले, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ओम प्रकाश हुड़ला (अनुपस्थित)। श्रीमती रमीला खड़िया।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 24 और 11 खेलकूद पर बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जिस क्षेत्र से मैं आती हूं वह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। दक्षिण राजस्थान से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। मध्यप्रदेश और गुजरात की सीमा से लगता हुआ एरिया है। सभापति महोदय, यहां खेल मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं इनका ध्यान आकर्षित करवाना चाहती हूं कि मेरा कुशलगढ़ क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है। बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हमारे बांसवाड़ा जिले में लिम्बाराम जी एक बहुत बड़े खिलाड़ी हुए। धनेश्वर जी मीणा बांसवाड़ा में कोच हैं। हमारा कुशलगढ़ क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे युवाओं को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से खेल में सम्मिलित किया जाए। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करती हूं कि हमारे कुशलगढ़ में एक छोटा-सा कस्बा

(श्रीमती रमीला खड़िया)

है, उसमें एकमात्र स्टेडियम है। उस स्टेडियम में पानी गिरता है। अभी 15 अगस्त के दिन जब स्टेडियम में छोटे-छोटे बालक-बालिकाएं आये तो वहां इतना पानी गिर रहा था कि वहां बैठना तो दूर, खड़े रहने तक की व्यवस्था नहीं थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि उस स्टेडियम के लिये हमें बजट दिया जाए, उसको अच्छे ढंग से किया जाए जो पोटल्या पंचायत में पड़ता है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि मेरे कुशलगढ व सज्जनगढ, दो ऐसे ब्लाक हैं, वहां सभी स्कूलों में खेल मैदान बनाये जाएं, मैं इसकी मांग रखती हूं। इसी तरह से एक हमारे आवासीय विद्यालय सुडादा में है, उसमें पर्याप्त जमीन है। मैं कहना चाहती हूं कि वहां खेल मैदान की अच्छी जगह है, इसलिए उनको बजट दिया जाए। इसी तरह से हमारे सज्जनगढ़ पंचायत समिति और डूंगरा और कूण्डा के बीच में एक ऐसी जमीन है, जब दीपावली का समय रहता है, उस समय वहां के खिलाड़ी क्रिकेट खेलने के लिये खेतों में इधर-उधर सफाई करवाते हैं और जेसीबी चलाकर वह खेलते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि मेरे सज्जनगढ़ क्षेत्र में और कुशलगढ़ क्षेत्र में हर स्कूल में आपके माध्यम से खेल स्टेडियम बनाये जाएं। इसी तरह से मैं शिक्षा में भी आग्रह करूंगी। बड़े दु:ख के साथ आपको कहना पड़ रहा है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में डूंगरीपाड़ा में जो स्कूल है, उसमें हैंडपम्प व शौचालय नहीं हैं। बच्चे पानी पीने के लिए इधर-उधर भटकते रहते हैं और इसी तरह से हमारे यहां छोटी सारवां में एक स्कूल है, जो पिछली सरकार के समय से गिरी हुई पड़ी है। उस स्कूल में मात्र दो ही कमरे हैं और करीब 300 बच्चे उसमें पढ़ते हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी और इसी तरह से कुशलगढ़ के लिए मांग रखती हूं। शिक्षा के मामले में और खेल के मामले में हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। किसान और हमारे लड़के किस तरह से आगे बढ़ें जब स्टेडियम मिलेगा तो हमारे लड़के कुशलगढ़ से खेलकर बांसवाड़ा जिले में जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ऐसी मैं मांग रखती हूं। जय हिन्द, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह जी रावत (अनुपस्थित)। श्री जब्बर सिंह सांखला।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 24 व 11 पर चर्चा करने करने का जो मौका दिया है, उसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, आज यहां शिक्षा और खेल की बातें हो रही हैं।

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

आदरणीय मंत्री महोदय, यहां विराजे हैं। चले गये? कोई बात नहीं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में वर्षों पहले वालीबाल का एक कोचिंग सेंटर हुआ करता था। आसीन्द के बाद उस कोचिंग सेन्टर को बीकानेर ले जाया गया है। आसीन्द से ऐसे कई सैकड़ों प्लेयर हैं, जो नेशनल लेवल पर खेल चुके हैं और जिन्होंने हिन्दुस्तान का नाम भी रोशन किया है। अभी आज सवेरे बात चल रही थी। आदरणीय डाक्टर साहब ने जाखड़ साहब का नाम लिया था। जाखड़ साहब ने आसीन्द कोचिंग सेंटर से ही कोचिंग की थी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बात भी कहना चाहता हूं कि कबड्डी, खो-खो, जबलिंग कुछ ऐसे खेल हैं, जो गांवों से निकलते हैं। इनकी प्रतिभाएं गांवों से निकलती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि गांवों में जो खेल के मैदान हैं, जो स्कूलों में हैं। ऐसा नहीं है कि मैदान नहीं हैं, खेल के मैदान बहुत जगह पर हैं। स्कूलों के माध्यम से हैं। मैदानों पर या तो बाहुबलियों के, पूंजीपतियों के या राजनेताओं के नाजायज कब्जे हैं। ये समस्याएं हैं, जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। बहुत सारी जगहों पर कंटीले झाड़ बबूल हैं, मैदान साफ-सफाई के अभाव में यूं के यूं ही पड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि खेल मैदानों पर जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं, उनके कब्जे हटाए जाएं। जिनमें कटीले बबूल उगे हुए हैं या जिनमें साफ-सफाई नहीं है, उनके लिए अलग से एक फंड रिलीज किया जाए, जिससे उस फंड से उनकी साफ-सफाई कराकर उन खेल मैदानों को विकसित किया जाए।

दूसरा, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक खेल मैदान हो, एक खेल मैदान विकसित हो जिससे वहां के जो छात्र-छात्राएं हैं, जो स्कूलों के माध्यम से जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं। सभापति महोदय, जो छोटी-छोटी प्रतिभाएं गांवों में ज्यादा हैं और गांवों से ही निकलती हैं। इतिहास गवाह है कि हिन्दुस्तान में जितनी भी प्रतिभाएं आयी हैं, वे छोटे-छोटे गांवों से ही आयी हैं। मैं यह चाहता हूं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक खेल मैदान विकसित हो, जिसके लिए सरकार अलग से फंड दे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान का एक अच्छा स्टेडियम विकसित हो।

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की बातें करते हैं। मेरा यह निवेदन है कि जो बड़े-बड़े शहर हैं, जैसे मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो आसीन्द, बदनोर, गुलाबपुरा, हुड्ड़ा, ये बड़े शहर हैं और जो सबसे बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें बरसनी, ब्राह्मणों की सरेड़ी, खारी का लांबा और शंभुगढ़ जैसी बड़ी-बड़ी ग्राम पंचायतें हैं। उनमें बालिकाओं के लिए खेल स्टेडियम अलग से हो। इससे प्रत्येक पंचायत हैड क्वार्टर की कोई भी बालिका जो खेल में रुचि रखती है, उनको अपने खेल को विकसित करने का और अपनी प्रतिभा को उभारने का मौका मिलेगा। आगे जाकर वह अपने गांव, अपने शहर और अपने देश का नाम रोशन करेगी। बालिकाओं के लिए बड़ी-बड़ी ग्राम पंचायतों व शहरी क्षेत्रों में अलग से खेल मैदान हो, यह भी मैं आपसे मांग करता हूं।

सभापति महोदय, कुछ शिक्षा की बातें हैं। हालांकि, आपने इस पर सुबह फरमाया था, लेकिन फिर भी मैं मेरी तरफ से दो-चार बातें कहना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र का बदनोर उपखंड पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके में जो छात्राएं हैं, वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं और हम खेल की बातें कर रहे हैं। जहां आठवीं तक के विद्यालय हैं, आठवीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद पर्याप्त साधन नहीं होने से, बसों का साधन नहीं होने या 10-15 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल होने से वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं, जिनमें दो-तीन गांवों के नाम हैं जैसे बड़ाच, सापोड़ा आदि। जहां की बालिकाएं आठवीं से आगे की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं। वह जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि ये जो विद्यालय हैं, इनको उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाने की घोषणा आप इसी बजट में करवा देंगे तो बालिकाओं के लिए एक अच्छी सुविधा हो जाएगी और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का जो हम सभी दावा करते हैं, हम सभी बातें करते हैं, इससे वे शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगी।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में वालीबाल का एक ग्राउंड है, जिसका नाम विजय क्लब है। एक छोटा-सा ग्राउंड है। उस ग्राउंड को विकसित करने के लिए मैंने पिछले दिनों भी मांग की थी। आदरणीय मंत्री जी के भी ध्यान में है। मैंने उनसे भी निवेदन किया था। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि आसीन्द शहर में विजय क्लब नाम का जो वालीबाल ग्राउंड है, उसके लिए आप अलग से 50 लाख रुपये का फंड

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

घोषित करें। मैंने पहले भी निवेदन किया है कि आसीन्द शहर से वालीबाल के प्लेयर नेशनल लेवल तक खेल चुके हैं और आसीन्द में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं। वहां बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। हमारे वहां से सैकड़ों खिलाड़ी निकले हुए हैं, जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है। उस विजय क्लब के लिए मैं चाहता हूं कि 50 लाख रुपये का फंड आप अलग से रिलीज करें और उस विजय क्लब को विकसित कराएं। वहां पर लाइट लगी हुई है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक छोटे-छोटे बच्चे वहां वालीबाल खेलते हैं ओर बड़े-बड़े भी वहां खेलने के लिए आते हैं। कभी-कभी तो हमारे आसीन्द में पूरा का पूरा गांव वालीबाल का मैच देखने आता है। वहां के लोगों की, वहां के लड़कों की और वहां के खिलाड़ियों की वालीबाल में रूचि है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसी बजट में आसीन्द शहर में विजय क्लब के लिए 50 लाख रुपये का अलग से फंड घोषित करें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। वंदे मातरम।

श्री सभापति: श्री हाकम अली जी।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे अनुदान की मांग संख्या 24 व 11 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। महोदय, मैं शेखावाटी क्षेत्र से आता हूं, जहां की धरती ने इस देश की सेना को सबसे ज्यादा सैनिक दिये हैं। यहां के युवाओं में सेना में जाकर देश सेवा करने का बहुत जज्बा रहता है। अधिकतर युवा सेना भर्ती की तैयारी में हर समय लगे रहते हैं। इसके साथ ही यहां के युवाओं में खेलों के प्रति बहुत रुचि है। इस क्षेत्र के युवाओं ने खेलों में भी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पदक प्राप्त किये हैं तथा वे खेलों की तैयारी करते रहते हैं। परंतु इस क्षेत्र के युवाओं को तैयारी करने के लिए स्टेडियम का अभाव है। सुबह-सुबह देखेंगे तो आपको युवा सड़कों पर दौड़कर तैयारी करते हुए हर तरफ नजर आएंगे, इसलिए गांव में दौड़ने के लिए ट्रैक बनाया जाए, चाहे नरेगा से बनाया जाए या अन्य कोई मद से बनाया जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में भी एक बड़ा स्टेडियम निर्माण कराया जाए। गांव के खेलों हेतु खेल स्टेडियम, खेल मैदान तैयार

(श्री हाकम अली खां)

करवाया जाए ताकि क्षेत्र में युवा खेल में और अच्छा प्रदर्शन कर सकें। आपके माध्यम से हमारे मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने पिछली सरकार में झुंझुनूं में एक खेल विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी जिसको पिछली भाजपा सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। कभी ध्यान भी नहीं दिया। वहां अधिकारी भी नियुक्त कर दिया, जो अधिकारी आज भी वहां अपना टाइम व्यतीत कर रहा है, स्टेडियम में बैठकर, स्टेडियम में बच्चों को खिलाकर। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर ध्यान देकर झुंझुनूं में खेल विश्वविद्यालय खोला जाए।

सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान शेखावाटी की तरफ दिलाना चाहूंगा कि शेखावाटी में बहुचर्चित खेल कबड्डी जो लुप्त होता जा रहा था, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे फिल्म स्टार अभिषेक बच्चन जी को, उन्होंने कबड्डी के खेल को बहुत ही बहुचर्चित कर दिया और लुप्त होते हुए खेल को वापस जिंदा किया और कबड्डी जैसे खेल को इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति दिलाई है। इसके बाद शेखावाटी में फिर से गांव के लड़कों में कबड्डी खेलने का चार्म हुआ है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में मेरे गांव का एक आसिफ नाम का लड़का टेबल टेनिस का बहुत अच्छा खिलाड़ी है, जो राज्य स्तर पर, नेशनल स्तर पर और इंटरनेशनल स्तर पर खेल चुका है तथा अब तक लगभग 20 मैडल प्राप्त कर चुका है। महोदय, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस खिलाड़ी को न तो राज्य सरकार के द्वारा, न ही भारत सरकार के द्वारा कोई सहायता या सहयोग किया गया है। इसके पिता ने कर्जा लेकर के इस बच्चे को खिलाया। इस बच्चे को देखकर इसकी बहनों ने भी, इसकी तीन बहनें हैं, उन्होंने भी टेबल टेनिस में राज्य स्तर पर और नेशनल स्तर पर खेला है। ये गरीब परिवार से आता है, इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी नियमानुसार राज्य सरकार से सहायता मिलती है, उस लड़के को सहायता दिलाई जाए ताकि ऐसे युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से उस बच्चे ने इंटरनेशनल खेलना बंद कर दिया क्योंकि अपने स्तर पर वह कितने दिन खेल सकता था। इंटरनेशनल खेलने के लिए गरीब परिवार का

(श्री हाकम अली खां)

बच्चा जाता है तो उसको फ्लाइट में जाना पड़ता है, वहां होटलों में रुकना पड़ता है तो फ्लाइट का टिकट और होटल का खर्चा उसका बाप वहन नहीं कर सका और उसने उसको कहा कि नौकरी की तलाश कर। मैं एक बार फिर मंत्री जी से आपके माध्यम से नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे युवाओं को अगर सरकार सहयोग देगी तो राजस्थान का ही नहीं देश का भी नाम रोशन करेंगे।

मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों में खेल की प्रतिभाएं बहुत हैं, लेकिन साधन का अभाव है। हमारे एक साथी महेन्द्र जी अभी बता रहे थे कि मैंने मेरे एमएलए कोटे से मेरे विधान सभा क्षेत्र के खिलाड़ी के लिए अभिशंसा की थी धनुष खरीदने के लिए, उसका मेरे पास जवाब आया कि इसका कोई टैक्नीकल अधिकारी नहीं है इसलिए हम इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं कर सकते। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि या तो टैक्नीकल अधिकारी रखा जाए या ऐसे जो जवाब देते हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जाए कि आप क्या कर रहे हैं?

महोदय, शेखावाटी में फुटबाल, वालीबाल, खो-खो, कबड्डी, ये ऐसे खेल हैं कि गांव के अनपढ़ लोग भी ये खेल खेल सकते हैं और अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं, अगर उनको कोई स्टेज या स्टेडियम मिले। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, चाहे नरेगा के माध्यम से या और कोई मद से, हर गांव में, गांव का चाहे स्कूल का मैदान हो या गांव का और कोई मैदान हो, वहां पर खेलों के लिए एक ट्रैक बनाया जाए, खेल का साधन उपलब्ध कराया जाए।

मेरे से पहले के वक्ताओं ने बताया कि 'नीरोगी राजस्थान' बनाना है। 'नीरोगी राजस्थान' तभी बनेगा जब युवाओं का ध्यान खेल की तरफ जाएगा। युवा सुबह-शाम खेलेंगे तो तंदुरुस्त भी रहेंगे और 'नीरोगी राजस्थान' का सपना साकार होते हुए भी नजर आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जी जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): सभापति महोदय, मांग संख्या 24 एवं 11 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार। हमारे जीवन में भोजन की जितनी आवश्यकता है, जीवन चलाने के लिए, जैसे शिक्षा व ज्ञान मनुष्य के लिए आवश्यक है, वैसे ही ये बड़ी ताकत है खेल। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 'शरीर रक्षतु खलु धर्मसाधनम्' मनुष्य का पहला धर्म है कि शरीर की रक्षा करे। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो मन स्वस्थ रहता है

(श्री धर्मनारायण जोशी)

और मन स्वस्थ रहता है तो संसार के सारे काम हम कर सकते हैं। इसीलिए शिक्षा जितनी आवश्यक है, उसी प्रकार खेल भी आरोग्यता के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवन में कौशल के लिए हमारे लिए जरूरी है।

माननीय सभापति जी, कई वक्ताओं ने कहा कि खेल बजट बहुत कम रखा है। मुझे लगता है कि अगर 100 करोड़ भी बजट रख देते तो भी कम था क्योंकि आज जिस प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है, उसमें आप और हम दोषी नहीं हैं। 100 करोड़ बजट अधिकारी मीटिंग कर-कर के उसको खतम कर देते हैं। खिलाड़ी तक नहीं पहुंचता है। मेरी माननीय खेल मंत्रीजी से आपके माध्यम से प्रार्थना है कि जनसहयोग लेकर, क्योंकि जनसहयोग से, माननीय जितेन्द्र सिंह जी ने कहा था कि जनसहयोग से जो काम हो सकता है, वह सरकार से नहीं हो सकता है। मेरी प्रार्थना है कि आदर्श खेल गांव डवलप करें, आदर्श विद्यालय डवलप करें और जैसी माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी बजट में घोषणा की थी कि शनिवार को बैग नहीं आएगा, वैसे ही अगर घर, परिवार गांव, स्कूल तय कर लें कि 5 से 6, 4 से 5 नो मोबाइल, नो इंटरनेट, नो टीवी तो मैं सोचता हूं कि इसको हम ठीक कर सकते हैं।

हमारा देश संसार का सबसे युवा भारत है। 65 परसेंट संसार के युवा भारत में रहते हैं, इसीलिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने आते ही केन्द्र में, हम सबके लिए गौरव की बात है, उन्होंने 21 जून को योग दिवस संसार को स्वीकार करवाया। उन्होंने मन की बात में अपने पैंतीसवें एपिसोड में यह कहा कि 'पढ़ोगे-लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब' इसकी बजाय उन्होंने कहा कि 'पढ़ोगे-लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब', यह प्रधान मंत्री जी ने पैंतीसवें एपिसोड में कहा।

आज का दौर कम्प्यूटर का है, सोशल मीडिया का है। सारे बच्चे चौबीस घंटे इसी में उलझे रहते हैं। आप जहां भी देखिए, अभी एक मैंने उदाहरण देखा था कि घर के, परिवार के गांव से दादी को लेकर आए, पांच-सात दिन अपने पास रहने। सोशल मीडिया पर देखा था मैंने, दादी आ गई, परिवार के सब लोग बैठे हैं और सबने अपना-अपना मोबाइल चालू कर रखा है और दादी एक कोने में बैठी हुई है। यह जो समाज की स्थिति बनी है, सारी नई पीढ़ी स्क्रीन पर खेल रही है। मैदान में नहीं खेल रही है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस पर ध्यान दिया जाए। हम सामूहिक रूप से इसको तय करें।

(श्री धर्मनारायण जोशी)

यह पर्टिकुलर किसी पार्टी का मामला नहीं है। हमारे भारत के प्रधान मंत्री ने 16 मार्च, 2018 को मणिपुर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की, खेल यूनिवर्सिटी की और उसके बाद जून, 2018 में भारत के माननीय राष्ट्रपति जी वो अध्यादेश लाए और उस अध्यादेश को मंजूरी दी और हमारे देश का पहला खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में बना। तमिलनाडु में खेल यूनिवर्सिटी है, गुजरात में खेल यूनिवर्सिटी है, मध्यप्रदेश में खेल यूनिवर्सिटी है, पंजाब खेलों का गढ़ कहा जाता है, महाराष्ट्र खेलों का गढ़ कहा जाता है, हमारा दुर्भाग्य है कि हम राजस्थान में यह नहीं कर पाए। अभी-अभी दिल्ली की सरकार ने भी, वहां खेल विश्वविद्यालय स्थापना की घोषणा की है। आपको ध्यान हो तो, पिछले दिनों यहां जयपुर में खेलों का आयोजन किया। मुझे लगता है कि वह नाम तो लेते नहीं हैं, परंतु यह प्रेरणा भारत के प्रधान मंत्री की है। उन्होंने गुवाहाटी में 10 हजार खिलाड़ियों को बुलाकर, बहुत बड़ा खेलो इंडिया का आयोजन किया। 2019 के बजट में केन्द्र की वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड की घोषणा की, यह भी हमारे लिए एक उपलब्धि है। आप गाँवों में जाइये, खेल मैदानों पर अतिक्रमण है।

श्री सभापति: कृपया ऊपर से जो आवाज आ रही है इसको बंद करो। वहां से यहां नीचे तक आवाज नहीं आनी चाहिए।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): प्रभावशाली लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। माननीय सभापति महोदय, उदयपुर में खेल गांव है, वह किसने दिया, इस सरकार ने दिया या उस सरकार ने दिया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, परन्तु वहां नीरजा मोदी स्कूल चल रहा है। स्कूल को दे दिया। आपको आश्चर्य होगा वहां दो साल पहले एक-एक लाख रुपये के मेम्बर बनाए, ढाई सौ मेम्बर बनाए। ढाई सौ मेम्बर की दो साल में एक बार भी मीटिंग नहीं हुई, वह एक-एक लाख रुपये कहां गए, क्या किया, पता नहीं, वह खेल गांव वाले जाने। मैं चाहता हूं कि इसका भी मंत्री महोदय उत्तर दें।

माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय स्तर पर फिजिकल फाउण्डेशन आफ इंडिया एक संस्था है, उसकी रिपोर्ट है, हमारे सारे स्कूलों में 70 प्रतिशत फिजिकल टीचर नहीं हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है। आपके वागड़ क्षेत्र के सरताज जिन्होंने संसार में नाम प्रसिद्ध किया राजसिंह जी डूंगरपुर, मेरी उनसे बहुत अच्छी मित्रता थी। ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं जिनका नाम चलता है, उन्होंने

(श्री धर्मनारायण जोशी)

मुझे कहा था कि चंडीगढ़ में एक मैदान पर कोचिंग चल रही थी, मैं खिलाड़ियों को कोचिंग दे रहा था, वहां पर कपिल देव फुटबाल खेल रहे थे। फुटबाल खेलते-खेलते मेरे पास छाया में आकर बैठ गए, मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या नाम है, उसने बताया कि कपिल देव। मैंने पूछा क्या खेलते हो, तो कहा कि फुटबाल खेलता हूं। राजसिंह जी ने बताया कि मैंने कपिल देव को कहा कि कल से तुम क्रिकेट खेलने आओ। आज कपिल देव का संसार में कितना बड़ा नाम है। ऐसे लोग सलेक्शन करें। राजसिंह ने बताया कि सचिन तेंदुलकर 16 वर्ष की उम्र में, पूरा देश चाहता था कि अंतरराष्ट्रीय टीम में शामिल नहीं हो, मैंने सचिन तेंदुलकर को शामिल किया और सचिन तेंदुलकर ने संसार में नाम ऊंचा किया। हमारे जनजाति छात्रावास हैं, 42 छात्रावासों में कोच हैं, 35 कोच के पद खाली हैं। कहां से प्रशिक्षण देंगे। उदयपुर में कबड्डी का नेशनल खिलाड़ी है, शाम को शिकंजी का ठेला लगाता है, माननीय सभापति महोदय, हमारा यह दुर्भाग्य है।

इस विषय में मेरे कुछ सुझाव हैं। माननीय मंत्री महोदय, इसको स्वीकार कराएं। उदयपुर में जिला खेल अधिकारी एक दिन कार से कहीं जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी पानी-पेशाब के लिए रोकी होगी, देखा कि एक 12-13 साल का बालक गुलेल से पत्थर मार रहा है और बकरियां चरा रहा है। उन्होंने उसको बुलाकर पूछा कि निशाना लगाते हो। बच्चे ने कहा हां, निशाना लगाता हूं। उन्होंने कहा कि सटीक निशाना लगा, बच्चे ने निशाना लगा दिया। दूसरे दिन वह उसके घर गए, परिवार को तैयार किया, उस बालक को उदयपुर लेकर आए, अंगूठा छाप लिम्बाराम, उस बालक को तैयार किया। वह एशियाड में गया, ओलम्पिक में गया। जनजाति क्षेत्र में ऐसी प्रतिभाएं हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी प्रतिभाओं को निखारकर आगे लाएं। समय-समय पर ग्राम स्तर, खण्ड स्तर पर कम्पीटिशन करवाए जाएं। कबड्डी जिसका अभी अमिताभ बच्चन का बेटा या कोई और, आयोजन कर रहे हैं, ऐसे लोग आयोजन करते हैं, उसको प्रोत्साहन मिलता है। सरकार ने अभी दो-चार दिन पहले ही, यहां एक नाइट हुई थी, हाउसिंग बोर्ड ने की थी, अच्छी बात है, ऐसे बड़े कलाकार को बुलाकर, उनके साथ ऐसे खेल का आयोजन किया जाए, प्रोत्साहन मिलेगा। खिलाड़ियों को रैगुलर कोचिंग दी जाए। उनको प्रोत्साहन राशि दी जाए। यह सब सरकार के भरोसे नहीं होगा। अगर सरकार के भरोसे

(श्री धर्मनारायण जोशी)

रहे तो कुछ होना जाना नहीं है। प्रोत्साहन देकर हमारे भारतीय खेलों को आगे बढ़ाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अनेक सदस्यों ने अनेक बातें बताई हैं। मेरे सुझावों पर गौर करके सरकार खेलों में राजस्थान का नाम ऊंचा करे, मदद करे। धन्यवाद, जय भारत।

श्री सभापति: श्री लाखन सिंह।

श्री लाखन सिंह (करौली): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 24 व 11 पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ग्रामीण क्षेत्र के सीनियर सैकण्डरी विद्यालय में गेम्स का सामान जैसे फुटबाल, नेट, बास्केटबाल, वालीबाल, हाकी का सामान उपलब्ध होना चाहिए। यह सामान पहले भी स्कूलों में उपलब्ध होता था। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि स्कूलों में अगर सामान नहीं होगा तो बच्चे किससे खेलेंगे। व्यवस्था के अनुसार सामान उपलब्ध कराना चाहिए। प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर स्टेडियम होने से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को फायदा मिलेगा। अगर प्रत्येक उपखण्ड पर स्टेडियम होगा तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे उपखण्ड पर जाकर खेलने का लाभ ले सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े शहरों में नहीं जा सकते, स्टेडियम में भी नहीं खेल सकते इसलिए उनको उपखण्ड स्तर पर लाभ मिल सके। जो बच्चे दूसरी जगह, बड़े शहरों में नहीं जा सकते उन्हें फिटनेस मिलेगी। जो बच्चे बाहर नहीं जा सकते उनको वहीं फिटनेस सेंटर मिल जाएगा।

सीबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में कई बार धांधली हुई। राजस्थान व सीबीएसई बोर्ड दोनों अलग-अलग बोर्ड हैं। राजस्थान बोर्ड के बच्चे राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान बोर्ड के बच्चों की अलग टीम होती है और सीबीएसई की अलग टीम होती है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सीबीएसई के बच्चे जो राजस्थान बोर्ड की तरफ से खेलते हैं वह दोहरा लाभ लेते हैं। राजस्थान के बोर्ड के बच्चों के खेलने की अलग व्यवस्था की जाए, सीबीएसई के लिए अलग की जाए क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर सीबीएसई की अलग टीम होती है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए।

(श्री लाखन सिंह)

कई बार खेलों में धांधली होती है। योग्य बच्चे नहीं जा पाते। पिछली सरकार के समय 14 वर्षीय बास्केटबाल का खेल कोटा में था, उसमें काफी धांधली हुई थी, अखबारों में भी आया था, इस तरह की धांधली होती है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। धांधली होने से योग्य बच्चे रह जाते हैं।

(16.49 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

छात्राओं की टीम जब भी कहीं खेलने जाए तो विश्वसनीय महिला पीटीआई अध्यापिका जाए, जिससे छात्राएं अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सकें। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि छात्राओं की टीम कहीं जाए तो विश्वसनीय पीटीआई को भेजा जाए ताकि बच्चियां अपने आपको सुरक्षित महसूस करें।

आज भी स्कूलों में पी.टी.आई. अध्यापकों के पद रिक्त हैं। मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि पी.टी.आई. के जो भी पद हैं, उनको भरने का प्रयास करें।

जिला स्तर पर जो बच्चे खेलते हैं, खेलने के बाद वे जीतते हैं, तो मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि उनके लिये प्रोत्साहन राशि दी जाए, जिससे उनका मनोबल आगे बढ़े और वे आगे खेलने के लिये उत्साहित हों।

क्रिकेट के कोच, हमारे भारत देश के ग्रेट खिलाड़ी जैसे कपिल देव, गांगुली, सचिन आदि अनेक ऐसे खिलाड़ी हैं, उन्हें कोच बनाया जाए, बाहर वालों को क्यों? क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ेबड़े खिलाड़ी हैं। हमारे देश में कोच बनकर जो बाहर के आते हैं, उनको क्यों बनाया जाए? हमारे ही देश के जो खिलाड़ी हैं उनको ही कोच बनाया जाए। यह मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है।

अधिकतर स्कूलों में, गांवों में खेलने के लिये मैदान नहीं हैं। मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कई जगह स्कूलों में खेल के लिए, स्टेडियम्स के लिए जमीनें अलाट करवा रखी हैं तो वे जमीन अलाट हो रखी हैं, लेकिन स्टेडियम में डवलप करने के लिए एक विशेष पैकेज दिया जाए, क्योंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र करौली सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, ऊबड़-खाबड़ है। बच्चों को पढ़ने के लिये दूर-दराज से जाना पड़ता है इसलिये कई जगह ब्लाक लेवल पर या बड़े-बड़े गांवों में स्टेडियम डवलप किये जाएं जिससे बच्चे खेलने में अपनी रुचि ले सकें।

(श्री लाखन सिंह)

एक मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्रीजी ने एक बहुत अच्छा काम किया है, जो शनिवार के दिन बैग नहीं ले जाना है, नो-बैग-डे, यह बहुत अच्छा कार्य है। इससे बच्चों को पूरा दिन खेलने का या कला का या संस्कृति का या बाल सभाओं का एक फ्री दिमाग से अपना पूरा दिन मिलेगा। इसलिये यह एक बहुत अच्छा कार्य है और बच्चों को इस चीज में रुचि मिलेगी। अधिकतर बच्चे, जिस तरह से मोबाइल में लगे रहते हैं, तो जब बच्चों की खेल में रुचि बनेगी तो उस मोबाइल से भी उनका कुछ मोह भंग होगा और अगर खेलने में वे रुचि रखेंगे तो दिमाग भी, मस्तिष्क भी उनका अच्छा रहेगा, आगे पढ़ने में भी उनकी रुचि रहेगी।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि करौली में एक हमारा स्टेडियम है। जब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी, उसमें कुछ पैसा दिया। पिछले पांच सालों में कुछ भी पैसा नहीं दिया। उस स्टेडियम के लिए जगह है। उसमें कुछ काम हुआ है। अभी वहां बैठने की व्यवस्था नहीं है, बाउंड्री नहीं है। इसलिये, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंत्रीजी, उसके लिए कुछ बजट दिया जाए।

मैं कला पर भी बोलना चाहता हूं। हमारे करौली जिले की ऐतिहासिक धरोहर तिमनगढ़ किला है, मासलपुर तहसील से 9 किलोमीटर दूर है। यहां शिल्प कला की बेजोड़ प्राकृतिक शिल्प कृतियां तिमनगढ़ किले में दफन हैं। मूर्ति तस्करों ने कई दशकों से शिल्प कृतियों को तलाशने में किले की प्राचीरों को हिला दिया है। तिमनगढ़ किले से निकलने वाली शिल्प कृतियों की अन्तरराष्ट्रीय बाजार में लाखों से ज्यादा कीमत है। ऐसे में तिमनगढ़ किला पुरातत्व विभाग की धरोहर भी है, दूसरी ओर मासलपुर की ऐतिहासिक धरोहर तिमनगढ़ किले के सौन्दर्यीकरण के लिए पिछली सरकार द्वारा तकरीबन ढाई करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। इस राशि से सरोवर सागर से सड़क बनने के साथ, तिमनगढ़ किले के मुख्य द्वार पर शौचालय, स्वागत कक्ष एवं अन्य सुविधाएं विकसित करने की योजनाएं बनाई गई थीं। सरकार ने राशि स्वीकृत कर दी। सड़क का निर्माण हुआ, जबकि तिमनगढ़ जिले के मुख्य द्वार के आसपास जो सौंदर्य का प्रयास किया जाना था, वह अभी तक नहीं हुआ है। तिमनगढ़ किले में पर्यटकों की आवाजाही बनी रहती है। किले के अन्दर छत्री रानी का तालाब, अन्य धरोहरें ऐसी हैं, जिन्हें जीर्णोद्धार कर पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाया जा सकता है। इसके मुख्य द्वार एवं

(श्री लाखन सिंह)

आसपास की चारदीवारी का जीर्णोद्धार करवाया जाना जरूरी है। इसके लिए सरकार बजट स्वीकृत करे तो करौली जिले में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ सकती है। इससे क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही सियासती धरोहर की सुरक्षा भी सम्भव हो पायेगी एवं सरकार को राजस्व का भी फायदा होगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आठ बजे तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय आठ बजे तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आठ बजे तक बढ़ाया गया।

श्रीमती शोभारानी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24 व 11 पर विचार

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 24 के अंतर्गत शिक्षा, कला एवं संस्कृति, खेलकूद पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, आज हमारे सरकारी स्कूलों में इतने क्वालिफाइड टीचर्स होने के बावजूद भी सक्षम लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि सरकारी स्कूलों का रिजल्ट अच्छा नहीं है। यह बहुत गम्भीर विषय है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ऐसी क्या वजह है, जिसकी वजह से लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजना चाहते हैं। उस वजह का पता लगायें और ऐसी व्यवस्था करें जिससे सरकार के बजट का एक मोटा भाग सरकारी स्कूलों पर खर्च किया जाता है, वह व्यर्थ न जाए। वह तभी हो पायेगा, जब आप सभी ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे हर कोई व्यक्ति, चाहे अमीर हो या गरीब हो, खुशी-खुशी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना शुरू करे।

(श्रीमती शोभारानी कुशवाह)

सभापति महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहती हूं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों के स्किल डवलपमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मैंने महसूस किया है कि व्यापारिक ज्ञान न होने की वजह से पढ़े-लिखे बच्चे भी बेरोजगार घूम रहे हैं क्योंकि हमारी शिक्षा का जो पैटर्न है, वह केवल लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए पढ़ने हेतु मजबूर करता है। हम सब जानते हैं कि सरकारी नौकरी सबको तो मिल नहीं सकती। ऐसी स्थिति में अगर हम बच्चों को व्यापारिक शिक्षा में सक्षम बना देते हैं तो पढ़ाई के साथ-साथ निश्चित तौर पर कोई भी बच्चा सरकारी नौकरी न मिलने की स्थिति में बेरोजगार नहीं रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को आयोजित करने के लिए कोई भी स्थायी मंच नहीं है। इसलिए सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में कहीं भी एक सरकारी भूमि आबंटित कर एक सांस्कृतिक एवं कला केन्द्र की स्थापना की जाए जिससे समय-समय पर होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जा सकें जिससे मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव एवं शहर में छिपी हुई प्रतिभाएं निकलकर सामने आ सकें तथा जिससे हमारे विधान सभा क्षेत्र धौलपुर का ही नहीं, हमारे प्रदेश एवं देश का नाम रोशन हो सके।

मेरे विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के पी.जी. कालेज में इनडोर स्टेडियम नहीं है जिससे युवा खिलाड़ी एवं खेल प्रेमियों को काफी परेशानी होती है। अत: माननीय सभापति महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के पी.जी. कालेज में एक इनडोर स्टेडियम का निर्माण करवाया जाए जिससे उभरती हुई खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिल सके।

मेरे विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेल के मैदान नहीं हैं और उनमें खेल के उपकरण भी नहीं हैं जिससे बचपन से ही उभरने वाली खेल प्रतिभाएं बच्चों के अंदर छिपी रह जाती हैं। अत: माननीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेल के मैदान एवं उपकरण उपलब्ध कराये जाएं।

(17.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मेरा यह विनम्र निवेदन है कि हर गांव और ढाणी में कहीं न कहीं सरकारी सिवायचक एवं चरागाह भूमि उपलब्ध होती

(श्रीमती शोभारानी कुशवाह)

है तो उसमें से कुछ जमीन विद्यालयों को खेल के मैदान के लिए आबंटित कर दी जाए जिससे सरकारी विद्यालयों के लिए, खेल के मैदान के लिए भी समस्या का हल हो सके।

अन्त में, माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि शहर में भी नहीं गांवों में भी बच्चों के साथ बच्चियों को भी खेल के लिए जाग्रत किया जाए, उनका खेल के प्रति अध्यापकों एवं कोच द्वारा उत्साहवर्धन किया जाए जिससे वह अपनी प्रतिभाओं को खेलों द्वारा दिखा सकें।

माननीय सभापति महोदय, खेल एक ऐसी प्रक्रिया है, जिससे बच्चे, बूढ़े और जवान सभी खेलना पसंद करते हैं क्योंकि खेल एक ऐसा मनोरंजन है जो खेल-खेल में ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है। जब हम लोग पढ़ते थे तो खेल का एक पीरियड होता था और उसमें हम सब हर तरह के खेल खेला करते थे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री से यह विनम्र निवेदन करना चाहती हूं कि हर सरकारी विद्यालय में खेल का एक पीरियड जरूर हो। आज के आधुनिक समय में बच्चों का खेलों के प्रति रुझान कम होता जा रहा है। सभी लोग मोबाइलों पर गेम खेलकर अपना समय काटते हैं जिससे युवा और बच्चों का स्वास्थ्य तथा मस्तिष्क कुप्रभावित हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, युगों-युगों से हमारे देश में देवी-देवता ही नहीं, अपितु हमारे पूर्वज भी खेलों के माध्यम से खाली समय में खेल खेला करते थे और अपना मनोरंजन किया करते थे जिससे वह स्वस्थ और शक्तिशाली हुआ करते थे। अतः खेल के महत्व को देखते हुए खेलों को बढ़ावा दिया जाए क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री आलोक बेनीवाल।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24 और 11 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। काफी लंबे समय से खेलकूद और शिक्षा पर सम्माननीय सदस्यों ने अपनी चिंताएं और महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं।

(श्री आलोक बेनीवाल)

माननीय सभापति महोदय, जो हमारा ग्रामीण परिवेश है और उसमें खास तौर से खेलकूद के लिए जो मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, वह है खेल मैदान और आज की तारीख में सबसे बड़ी चिंता है कि उन खेल मैदानों को तैयार करने में और स्टेडियम तैयार करने में जो वित्तीय असुविधा है, उसके बारे में मैं राज्य सरकार को यह कहना चाहूंगा कि हम इस विभाग को जो खेलकूद विभाग है युवाओं का, इसमें जो बजट का अलोकेशन किया जाता है, इसमें जो आने वाला समय है क्योंकि शिक्षा का और युवाओं के साथ में खेलकूद का चोली-दामन का साथ है। आप शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत बड़ा बजट लाते हैं लेकिन खेलकूद के क्षेत्र में हम बजट में कंजूसी कर जाते हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत समय से खेल स्टेडियम बना हुआ है। आज उसकी स्थिति, बीच-बीच में उसमें कई मदों से पैसा लगा, आज उस स्टेडियम में जो सुविधा उपलब्ध है लेकिन उस स्टेडियम की सार-संभाल करने वाला और वहां पर जो बिजली का कनेक्शन है वह लगभग विगत साल भर से कटा हुआ है। आज यह पता नहीं है उस स्टेडियम के बिजली के बिल का कि उसका पेमेंट करके उसको जमा कौन कराएगा और उसको चालू कौन कराएगा? वहां पर उस स्टेडियम को संभालने वाला कोई नहीं है। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद करता हूं, मैंने अभी उनसे यह कहा था कि पूर्व में उसमें एक कोच पदाधिकारी लगे हुए थे, मैंने कहा कि साहब, वापस इनको वहां पर लगाओ जिससे वह इस स्टेडियम की सार-संभाल तो कर सके और इसके अंदर कोई untoward activity जो होती है, वह नहीं हो पाए और हमारा जो स्टेडियम है, उसकी साफ सफाई रहे, उसमें लाइटिंग व्यवस्था हो सके।

हमारा युवा है और जो ग्रामीण परिवेश में आज, मैं बहुत सारी प्रतियोगिताओं में गया हूं, माननीय सभापति महोदय, जो कि इंडिविजुअल कैपेसिटी पर हमारे ग्रामीण परिवेश के जो भामाशाह लोग हैं जो खिलाड़ियों में इंट्रेस्ट रखते हैं, वह आयोजित करते हैं। चाहे वह कबड्डी की प्रतियोगिताएं हों, चाहे वालीबाल की हों, चाहे क्रिकेट की हों, चाहे अन्य जो हमारे स्पोर्ट्स हैं, उसका जो खेल है, वह हमारे वहां पर लोकल स्तर पर ही जो हमारे भामाशाह हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो नौजवान हमारे इसमें इंट्रेस्टेड हैं वह वहां पर अयोजित करते हैं, उसमें सरकार का कहीं सहयोग अपेक्षित वहां पर नहीं रहता है तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं और खास तौर से हमारी सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूलों के जो ग्राउंड्स हैं उनमें कइयों में आज भी,

(श्री आलोक बेनीवाल)

सबसे पहले तो तुरंत उनकी चारदीवारी का काम होना चाहिए तब जाकर उसके ग्राउंड्स सुरक्षित रह पाएंगे। ग्राउंड्स पर जो अतिक्रमण हो गया है वह हटे, साफ सफाई हो, ट्रैक बनें, उसमें खेलने की सुविधा हो तब जाकर हमारा जो नौजवान है, जो ग्रामीण परिवेश में खेलने के प्रति अपनी रुचि रखता है, उसको यथास्थिति के हिसाब से अच्छा चयन करने के लिए जगह मिल पाए, तब जाकर हम कहीं थोड़ा बहुत उनको जो हमारे खेलने वाले युवा साथी हैं, उनकी मदद कर पाएंगे।

आज सरकार के पास में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह आपके गांव स्तर तक पहुंचने के लायक नहीं है। मैं माननीय मंत्रीजी से भी यह कहना चाहूंगा कि आप इस तरह का एक पूरा स्ट्रक्चर बनाइये जो ग्रामीण स्तर से लेकर, गांव के स्तर से लेकर स्टेट लेवल तक आपको इसमें जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको तराशने में मदद मिल सके, तब जाकर हम राजस्थान में एक नए युग की शुरुआत इस खेल के संबंध में कर पाएंगे।

आज ग्रामीण स्तर पर, मैं जब विधायक बना तो बहुत सारे युवाओं ने कहा कि साहब, हमें सर्विसेज में जाने के लिए सड़क पर दौड़ना पड़ता है। मैंने खुद अपने एम.एल.ए. कोटे से लगभग तीन-चार जगह ट्रैक के लिए पैसे दिये हैं। आने वाले समय में भी जो हमारे सीनियर सैकण्डरी विद्यालय हैं, उनके अंदर दीवार का निर्माण कार्य भी पूरा नहीं है, उसमें भी मैंने पैसे दिये हैं तो हम तो हमारे युवाओं को हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब तक बजट नहीं होगा, जब तक विजन नहीं होगा कि हम नीचे के स्तर से लेकर, जब बच्चा छोटा होता है वहां से उसको तराशने का काम नहीं करेंगे, तब तक हम जो उपलब्धि चाहते हैं खेल के अंदर, वह हमारे को प्राप्त नहीं हो पाएगी।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र की बहुत बड़ी विडंबना है कि आज हम स्पोर्ट्स के बारे में या खेल के बारे में यहां पर चर्चा तो करते हैं लेकिन उसको कैसे डवलप करना है, नीचे के लेवल से, जहां प्राथमिक स्तर से लेकर और कालेज स्तर तक जब आप इसको तराशेंगे तभी जाकर आप इन खिलाड़ियों को मौका दे पाएंगे और जब तक आपके पास संसाधन नहीं होंगे इनको तराशने के लिए, तब तक आप और हम इस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बात तो हम सब कर लेते हैं कि यह होना चाहिए, वह होना

(श्री आलोक बेनीवाल)

चाहिए, स्टेडियम भी होना चाहिए, लेकिन स्टेडियम के साथ उस स्टेडियम को मेंटेन करने के लिये कैसे उसकी व्यवस्था की जाए कि उसका जो स्वरूप है, वह 12 महीने उसी स्वरूप में रहे। कहीं टूट-फूट होती है तो उसके निर्माण कार्य के लिए पैसा कहां से आएगा? वहां व्यक्ति कौन होगा, वहां पर कोच का अपाइंटमेंट होगा या नहीं होगा? वह किस तरह का कोच होगा? वह क्रिकेट का कोच होगा, हाकी का कोच होगा, किस खेल से संबंधित कोच होगा? बहुत बड़ा काम इस क्षेत्र में करने की आवश्यकता है। जब तक हम इसमें आमूल-चूल परिवर्तन नहीं करेंगे, निश्चित तौर से जो हम उम्मीद लेकर चल रहे हैं, उस उम्मीद को पूरा करना हमारे लिए संभव नहीं होगा और युवाओं का आज की तारीख में स्पोर्ट्स की तरफ बहुत रूझान है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में।

माननीय सभापति महोदय, शायद आप भी अपने विधान सभा क्षेत्र में गये होंगे। अपने स्तर पर गांव के लोग वह प्रतियोगिताएं करा रहे हैं, जो कि हर सरकार को करानी चाहिए। वहां पर बाहर से टीमें आती हैं हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से। मैंने खुद ने देखा है। आज वह लोग जब इस पैशन में लग गये हैं तो सरकार को भी यह कहीं सोचना चाहिए कि हमारे को इसमें आगे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा बजट का इसमें एलोकेशन करें और ऊपर से लेकर नीचे तक डिपार्टमेंट का एक इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएं जिससे कि वह नीचे के स्तर तक पहुंचकर उन युवाओं को तराशने का काम करें। जिस भी खेल के क्षेत्र में वह आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें उनको मौका मिल पाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं पुन: माननीय मुख्य मंत्रीजी का और खेल मंत्रीजी का तो धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी इस प्रदेश से मैडल जीतकर आते हैं उनकी पुरस्कार राशि को बढ़ाया। उनके रोजाना के जो खर्चे हैं उनको भी बढ़ाया, लेकिन जो बात मैंने कही, वह बात बहुत इम्पोर्टेंट है।

माननीय सभापति महोदय, आज विदेशों के लिये हम बात कर रहे थे कि चाइना खेलों में इतना आगे क्यों बढ़ गया, आस्ट्रेलिया इतना आगे क्यों बढ़ गया, यू.एस.ए. इतना आगे क्यों बढ़ गया? हम और चीजों के अंदर जब किसी को तराशते हैं या हम अपनी टैक्नोलोजी को अपडेट करने के लिये जापान जाते हैं, चाइना जाते हैं, यू.एस.ए. जाते हैं तो हम स्पोर्ट्स के अंदर यह क्यों नहीं करते हैं कि हमारे यहां से स्पोर्ट्स पर्सन या जो भी इसमें इंट्रेस्टेड हैं, या जो भी इसके लिये जिम्मेदार हैं, वह विदेशों में जाकर देखें कि वह अपने

(श्री आलोक बेनीवाल)

खिलाड़ियों को कैसे वहां पर तैयार करते हैं और उनको क्या सुविधा दी जाती है, तब जाकर वह खिलाड़ी उनके देश के लिये मैडल जीतकर लाते हैं। इसलिए मैं पुन: राज्य सरकार से मांग करूंगा कि इसमें अधिक से अधिक बजट का एलोकेशन करें और ग्रामीण स्तर पर जो गांव है, वहां तक इस सुविधा को पहुंचाएंगे तब जाकर हमारे युवाओं को इसका पूरा लाभ मिल पाएगा। आपने बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती जाहिदा।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां): माननीय सभापति महोदय, आपने जो मुझे मांग संख्या 24 और 11 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूं। आज मेन विषय खेलकूद और युवा सेवाओं पर जो अनुमति आपने मुझे दी, इसके लिए मैं सरकार का शुक्रिया अदा करती हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वर्तमान बजट में हर वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया है और विशेष तौर पर युवा व खेल को जो बजट दिया है, वह बहुत ही सराहनीय कदम है।

इसके साथ ही 'नो बैग डे' एक बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि हमारे स्कूल के बच्चों पर इतना ज्यादा वज़न हम लोगों ने स्कूल के बैग्स का डाल दिया है कि वे उसके बोझ तले ही दब गये हैं। आजकल के बच्चे बाहर जाकर खेलते ही नहीं हैं। हमारी जो पीढ़ी थी, हम लोगों का ज्यादातर समय स्कूल से आने के बाद शाम के टाइम पर हम सब भाई-बहन मिलकर खेलते थे। आज के परिवेश में, जहां परिवार भी छोटे हो गये हैं और न्यूक्लियर फैमिली हो गयी है, न तो लोग साथ ही रहते हैं, न ही वह लोग खेलते हैं। वह कम्प्यूटर पर या लैपटाप पर या मोबाइल पर लगे रहते हैं। खेल का जो महत्व है, उसको हमारे बच्चे और हम लोग भी भूलते जा रहे हैं, क्योंकि खेल से आपका शरीर भी अच्छा विकसित होता है, दिमाग भी विकसित होता है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि हमारे टाइम पर हम लोग स्कूल में पीटी. करते थे, उससे अपने आप में ही सारी एक्सरसाइज हो जाती थी तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगी कि जहां पर भी पी.टी. टीचर्स की जगह नहीं है, वहां पर यह पोस्ट क्रिएट की जाए और जहां पर रिक्त चल रहे हैं, उनको वहां पर लगाने की व्यवस्था की जाए।

(श्रीमती जाहिदा खान)

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले हमें खेलों को गांव से शुरू करना होगा। पहले तो हर गांव के स्कूल के अंदर ही खेल प्रतियोगिता हों। उसके बाद उनको इंटर स्कूल प्रतियोगिता करना होगा, फिर ब्लाक लेवल प्रतियोगिता पर करना होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और फिर स्टेट लेवल पर, तब जाकर कहीं इंटरनेशनल लेवल पर नंबर आता है। इसके लिए बहुत जरूरी है सही कोचिंग होना और सही गाइडेंस देना। शरीर के लिए जिस तरह आत्मा जरूरी है, उसी तरह से खेलों के लिए सही कोच होना बहुत जरूरी है। हमें बच्चों को हैल्दी काम्पीटिशन के लिए तैयार करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर हालत में तुझे फर्स्ट आना है। इस तरीके पर जोर नहीं देना चाहिए क्योंकि जब तक हैल्दी काम्पीटिशन नहीं होगा तो वह हार को अच्छी तरह से नहीं स्वीकारेंगे और इससे वह लोग आगे नहीं बढ़ सकते। जिस तरीके का हम उनमें डवलपमेंट चाहते हैं वह उस तरह से नहीं हो सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगी कि कालेज के लिये सीएम. साहब ने पिछले बजट में घोषणा की थी। उसी के साथ अगर हमारे यहां बड़ा इनडोर स्टेडियम और आउटडोर स्टेडियम बना दिया जाए तो एक ब्लाक स्तर पर बच्चों के खेलने के लिए अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। स्टेडियम नहीं होने की वजह से बच्चे खेलों में रुचि नहीं लेते और ना ही वह लोग खेल पाते हैं, जैसे कबड्डी, क्रिकेट, रस्साकशी, रेसलिंग, बाक्सिंग, फुटबाल आदि।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कामां के उपखण्ड पहाड़ी और कामां में स्टेडियम का निर्माण करवाया जाए, जिससे कि सी.एम. साहब की और हमारी सरकार की जो भावना है कि बच्चे आगे खेलें, उन्होंने इसी को प्रोत्साहन देने के लिए जो राशि है, उसको भी बढ़ाया है। यह तभी हो पाएगा जब बच्चे खेलेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र कामां में शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचे था। उसी को ध्यान में रखते हुए जब माननीय मुख्य मंत्रीजी पहली बार मुख्य मंत्री बने थे और माननीय सी.पी. जोशी साहब मंत्री थे, तब मरहूम चौधरी तैय्यब हुसैन साहब ने राजीव गांधी पाठशालाएं खुलवायी थीं और मुझे बहुत खुशी है और सदन के माध्यम से मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगी माननीय मुख्य मंत्रीजी का और सीपी. जोशी साहब का, कि जितनी भी हमारी ढाणियां थीं, उस टाइम सबसे ज्यादा स्कूल कामां में खुले थे और यह

(श्रीमती जाहिदा खान)

उसी टाइम की नींव रखी गयी थी जब पढ़ाई की तरफ हमारा इलाका चला। इनके इन प्रयासों से क्षेत्र में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी और लोगों ने अपने बच्चों को भेजना शुरू किया। 2008 में जब मैं एमएलए बनी तो आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने मुझे दो कालेजों की सौगात दी। उसके अलावा प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सैकण्डरी स्कूल हमारे यहां अपग्रेड हुए। मेरी मांग पर नये स्कूल भी खोले गये, लेकिन बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि जब भाजपा सरकार आयी तो सबसे पहले उन्होंने मेरे इलाकों के दोनों कालेज बंद किये और जो टीचर्स थे उनको वहां से हटाया और बहुत ही कम वहां पर उनमें टीचर्स रहे, जिनको हम आज तक भी पूरा नहीं करा पाये हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को एक सुझाव देना चाहूंगी कि यह डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैड क्वार्टर पर मैक्सिमम टीचर्स या और भी अधिकारी-कर्मचारी रहते हैं, एक तरीके से इनको वहां पर बुलाया जाए ताकि हर जगह कामन हो पाये, जब तक यह ट्रांसफर्स नहीं खुलते।

माननीय सभापति महोदय, यह बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी सरकार ने आते ही जो भी स्कूल बीजेपी सरकार ने बंद किये थे, उनको उन्होंने दुबारा से खोला और मैं इसके लिए उनकी बहुत शुक्रगुजार हूं। मेरे यहां पर जो दो कालेज खुले हैं, उनके लैक्चरर्स के पद भी बहुत रिक्त हैं और हमारे यहां सिर्फ आर्ट्स फैकल्टी खोली गयी है। मैं यह कहना चाहूंगी कि साइंस और कामर्स फैकल्टी भी खोली जाए, क्योंकि बच्चों को अगर साइंस और कामर्स लेनी होती है तो उनको 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है या फिर वह पढ़ाई को छोड़कर घर पर बैठ जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि साइंस और कामर्स फैकल्टी भी खोली जाए और जिन स्कूलों में उर्दू विषय नहीं है, उनमें उर्दू विषय भी खोले जाएं क्योंकि यह माइनोरिटी एरिया है और यहां पर उर्दू बच्चे पढ़ना चाहते हैं। सीनियर सैकंडरी स्कूलों में भी मेरे यहां पर साइंस और कामर्स नहीं है इसलिए ग्राम कैथवाड़ा, सबलाना, गढ़ाजान, घाटमिका, जोतरूहुल्ला, सहसन, भवनवाड़ी स्थित सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में साइंस और कामर्स की फैकल्टी खोली जाए।

मेरा इलाका बालिका शिक्षा में भी बहुत ही पिछड़ा हुआ है इसी को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले साल मुझे पहाड़ी में एक माइनोरिटी गर्ल्स रेजिडेंशियल होस्टल दिया था, इस बजट में मुझे कामां में

(श्रीमती जाहिदा खान)

बायज और गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल दिया है, मैं इसके लिए उनकी बहुत शुक्रगुजार हूं कि वे पढ़ाई पर हमारे इलाके पर विशेष ध्यान दे रहे हैं क्योंकि मैं बार-बार यही बात कहती हूं और यही हमने सुना है कि कोई भी समाज, कोई भी इलाका जब तरक्की कर सकता है जब आपके बच्चे पढ़े-लिखे हों और खास तौर से बालिकाएं क्योंकि लड़का तो एक कुल उजालता है और लड़की दो कुल उजालती है तो इसलिए लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है।

जैसे गांव परहेल, जुरहरा, सतवाड़ी, सहसन बडोली ढेहर को वर्तमान स्तर से उच्च स्तर पर अपग्रेड करने की मेहरबानी करें। कैथवाड़ा, सहसन, जोतरूहुल्ला, नौगांवा, ओलंदा, नंदेरा, लाडमका, भवनवाड़ी, छपरा, घोसिंगा, सामलेव व गढ़ाजान में नये माध्यमिक स्तर के बालिका स्कूल खोले जाएं जिससे कि लड़कियां पढ़ सकें क्योंकि, सभापति जी, आप भी समझते हैं कि लड़कियों को घर से दूर भेजने में इस जमाने में बहुत दिक्कत आती है। अगर घर के पास स्कूल होंगे तो इस जनरेशन में लड़कियां पढ़ने लगेंगी और समाज का असली विकास ही जब ही हो पायेगा जब लड़कियां पढ़कर निकलेंगी।

माननीय सभापति जी, मेवात विकास क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के भविष्य को देखते हुए मैं आपसे दोबारा रिक्वैस्ट करूंगी कि मेरी बतायी हुई मांगों को सरकार पूरा करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ललित कुमार ओस्तवाल।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): सम्माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24 शिक्षा कला एवं संस्कृति खेलकूद तथा युवा सेवाएं एवं मांग संख्या 11 विविध सामाजिक सेवाएं पर मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका एवं मेरी पार्टी के नेताओं का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

एक स्वस्थ समाज की कल्पना करते ही हमारे मन में सबसे पहले शिक्षा का ध्यान आता है क्योंकि शिक्षा के बिना सब बेकार है। शिक्षा ही वह कुंजी है जो किसी भी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए और सफलता प्राप्त करने का रास्ता प्रदान करती है। शिक्षा का व्यक्तित्व निर्माण के साथ ही देश के निर्माण और विकास में भी सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। माननीय सभापति महोदय, आज के बच्चे, आज के युवा ही कल के भविष्य हैं और ये

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

भविष्य तभी बेहतर होगा जब इन्हें बचपन से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और बचपन से ही, प्राथमिक विद्यालय के स्तर से ही इनको खेलकूद का अच्छा अवसर मिले, ये बच्चे खूब खेलें, अच्छा पढ़ें और खूब खेलें।

प्राथमिक विद्यालय स्तर पर भी प्रतियोगिताएं होती हैं, टूर्नामेंट होते हैं उसमें भी बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन टूर्नामेंट का समय लगभग वर्षा काल में आता है, हमेशा जुलाई, अगस्त सितम्बर में लगभग जब बारिश होती है उसी समय ये खेलों का समय आता है। कई बार बच्चे ठीक से खेल नहीं पाते हैं, बारिश चलती रहती है और महज औपचारिकताएं करके उन टूर्नामेंट को पूरा किया जाता है। मेरा इस मामले में यह भी निवेदन है कि टूर्नामेंट के अलावा भी स्कूल के बच्चों को कभी पास के स्कूलों में आपस में दोनों स्कूलों को खेलने का कुछ प्रयास करना चाहिए एवं इसके साथ ही समय-समय पर कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी विद्यालयों में होना चाहिए।

प्रत्येक विद्यार्थी में छिपी हुई प्रतिभा को शिक्षक, पी.टी.आई. पहचानें और उसकी प्रतिभा को विकसित करके अपने देश का एवं क्षेत्र का नाम ऊंचा करने में सहयोग करें। यह काम शिक्षक महोदय और पी.टी.आई. महोदय ही कर सकते हैं। विद्यालय में सभी खेलकूद सामग्रियों का प्रभावी उपयोग हो, सभी खेलों को बढ़ावा मिले।

शहर हो या गांव, लगभग सभी विद्यालयों के नाम पर जमीन आबंटित है, लगभग 90 प्रतिशत विद्यालयों के नाम पर जमीन आबंटित है लेकिन उसमें अपन देखें तो 50 प्रतिशत खेल मैदानों पर किसी न किसी का अतिक्रमण है चाहे वह पास में खेत वाला होगा, कुए वाला होगा या कोई प्रभावशाली व्यक्ति होगा। पूरी जमीन पर नहीं होगा तो कुछ थोड़ी-बहुत जमीन पर जरूर होगा। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि एक अभियान चलाकर सर्वे किया जाए और जिस खेल के मैदान पर, विद्यालय का हो या किसी का भी हो, खेल के मैदान पर अगर किसी का अतिक्रमण है तो अभियान चला करके उनका अतिक्रमण हटाया जाए और सरकार की किसी भी योजना से, भले ही नरेगा से करायें या भले ही सरकार पैसा दे, सरकार बजट दे और वहां पर उस खेल के मैदान पर

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

चारदीवारी का निर्माण हो ताकि भविष्य में कोई भी अतिक्रमी अतिक्रमण नहीं कर पाये।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं कुछ मामलों में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहली से पांचवीं कक्षा के लिए एक एस.आई.क्यू.ई., स्टेट इनिशिएटिव फोर क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल, जिसकी डायरी विद्यालयों में जुलाई में पहुंच जानी चाहिए लेकिन वह अभी जनवरी, फरवरी में पहुंची है। परीक्षाएं आ गई, अब कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे?

अभी 29 फरवरी से पहले-पहले सभी विद्यालयों में वार्षिकोत्सव करने थे, लगभग विद्यालयों में किये भी हैं और उसका बजट सरकार ने 10 हजार रुपये तय किया, लेकिन मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि जो राशि भेजी है वह यहां से अभी तक तीन-तीन हजार रुपये ही भेजे हैं, बाकी का अध्यापक अभी कहीं से भी चुकाओ और उसके बाद में उनके पास आएगा।

राज्य सरकार हर स्कूल को, हर विद्यालय को छात्र संख्या के हिसाब से ग्रांट देती है, 25 हजार, 50 हजार, 75 हजार, एक लाख, आवश्यक खर्चों के लिए लाइट बिल भरो या भवन का कोई छोटा-मोटा रखरखाव है, रंगाई-पुताई है इसके लिए लेकिन अभी भी जो 2017 का नामांकन है उसके आधार पर दिया जाता है। अभी 2020 चल रहा है, छात्र नामांकन काफी बढ़ा है, लेकिन 2017 के नामांकन से ही दिया जा रहा है और उसमें भी 25 परसेंट राशि ही मिली।

बच्चे खूब खेलें, अच्छा खेलें, उसके लिए बच्चों का स्वस्थ और मजबूत होना भी बहुत जरूरी है और उसके लिए हमारी पिछली सरकार ने, माननीय वसुन्धरा जी की सरकार ने बच्चों को दूध की व्यवस्था की थी कि उनको स्कूलों में, विद्यालयों में दूध पिलाया जाये। मुझे खुशी है कि ये योजना अभी भी चालू है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि अकेले मेरे चित्तौड़गढ़ जिले में पिछले 6 माह से दूध का पैसा नहीं दिया है। इसमें लगभग 8 करोड रुपया जिले में अभी भी बाकी चल रहा है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी लगभग सवा करोड़ से ऊपर बकाया है। सभापति महोदय, इससे नुकसान क्या हो रहा है कि जो दूध वाला है उसको पैसा समय पर नहीं मिल रहा है तो वह दूध खराब भी देता है, कभी पानी ज्यादा डाल करके भी देता है तो विद्यालय वाले बंद नहीं कर सकते, अगर बंद करें तो वह कहता है कि मेरे को पहले का पैसा दो, मेरा

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

भुगतान करो, उसके बाद किसी दूसरे से दूध ले सकते हैं। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि उसको समय कर भेजा जाए।

एक निवेदन और भी है कि जो पहले विद्यार्थी मित्र काम करते थे और जिनका चयन किसी वजह से पंचायत सहायक में नहीं हो पाया, कुछ लोग, कुछ बच्चे प्रदेश में ऐसे भी घूम रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि उनको भी पंचायत सहायक पर चयन करके लगाया जाये।

सरकार को मेरा एक निवेदन और है कि हर गांव में और हर गांव में संभव न हो तो कम से कम हर पंचायत मुख्यालय पर सामूहिक खेल मैदान स्कूल के अलावा भी, विद्यालय में तो हो ही लेकिन सामूहिक खेल मैदान के लिए भी जमीन आबंटित कराएं। वहां पर सरकार द्वारा स्टेडियम का निर्माण हर पंचायत मुख्यालय पर हो ताकि विद्यार्थियों के अलावा भी कई खिलाड़ी गांव में है, वे वहां अभ्यास कर सकें और अपना भविष्य सुधार सकें। हमारे इधर गांव में तो कई जगह ग्रामीण टूर्नामेंट भी होते हैं, कहीं समाज के होते हैं, कहीं गांव वाले मिलकर करते हैं और उसमें सरकार पैसा नहीं देती है फिर भी वे लोग जैसे भी हो, चंदा इकट्ठा कर-करके देते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसी प्रतियोगिता में भी, ऐसे टूर्नामेंट जो ग्रामीण कराते हैं उसमें भी सरकार की तरफ से कोई न कोई सहयोग देना चाहिए ताकि दूसरों को भी बढ़ावा मिलेगा। खेलों को खूब बढ़ावा मिले इसके लिए जहां पर भी पी.टी.आई. का पद रिक्त है, किसी भी विद्यालय में हो, उसको सरकार मेहरबानी करके तुरंत भरे।

हम अगर संस्कृति की बात करें तो हमारे देश पर कई विपदाएं आईं, कई विदेशी आक्रमणकारी आए। उस समय भी हमारे पूर्वजों ने संस्कृति को संभाल करके रखा। आज की तारीख में तो हमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। थोड़े बहुत में भी हमारा काम चल सकता है। मेरा सदन से निवेदन है कि संस्कृति को बचाने के लिए भी हम लगे रहें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान, जय चित्तौड़।

श्री सभापति: श्री मदन प्रजापत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, आज खेल और युवा मामले, मांग संख्या 24 और 11 के संबंध में काफी माननीय सदस्यों ने अपनी भावना प्रकट की।

(श्री मदन प्रजापत)

सभापति महोदय, खेल सदियों से समाज और इंसान से जुड़ा हुआ है। सभी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खेल मैदान हों। प्रतिभाएं आगे आएं। हर राज्य की जनता और सरकार की भावना होती है कि ज्यादा से ज्यादा मैडल मिले। इसमें कोई शक नहीं कि कोई व्यक्ति यह नहीं चाहता है कि खेलों को बढ़ावा नहीं मिले, युवा आगे नहीं बढ़ें। यह भी सभी जानते हैं कि जहां खेल मैदान अधिक होंगे, वहां अस्पतालों की संख्या कम होगी।

सभापति महोदय, सिर्फ भाषण से काम चलने वाला नहीं है। सरकारें चाहे कोई भी रही हों, लेकिन बजट और सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, उतनी नहीं मिल पाती हैं। इसके कारण कई समस्याएं आती हैं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार इस बात के लिए करता हूं कि अब खेलों में जो खिलाड़ी मैडल जीतकर आएंगे, उनको 75 लाख से 3 करोड़ और 50 लाख से 2 करोड़ की राशि मिलेगी। इतनी शानदार राशि बढ़ाकर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया है। इसका संदेश पूरे प्रदेश और देश में गया है।

सभापति महोदय, इस विभाग को बजट ज्यादा मिले। आप जानते हैं कि गांवों में खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं। मैं उन भामाशाहों को धन्यवाद देता हूं जो दिल खोलकर अपनी खरी कमाई में से इनकी मदद करते हैं। एक मेले जैसा माहौल बन जाता है। कोई भोजन की व्यवस्था करता है, कोई टैंट की व्यवस्था करता है। मैं तो यह बात भी हर जगह बोलता हूं कि अगर यह भामाशाहों का सहयोग नहीं होता तो खाली सरकार के भरोसे तो इन खिलाड़ियों की रौनक फीकी रह जाती। वह हमेशा मदद करते हैं।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह जो 500 नए कोच लेने तथा भत्ता बढ़ाने का काम किया है, यह अच्छा है। इसके अलावा सभी माननीय सदस्यों के सुझाव कटमोशन में आए हैं कि हर पंचायत को खेल मैदान मिले, उनकी सुविधाएं बढ़ें, लेकिन बिना बजट के यह संभव नहीं है। चाहे शहर हो, चाहे गांव हों, खिलाड़ियों का खेल के प्रति रुझान शुरू से रहा है, सदियों से रहा है। जो अपने त्योहार होते हैं, उनके साथ में भी खेलों को जोड़ा गया है।

सभापति महोदय, पहले कई तरह के खेल होते थे। आज जरूर परिवर्तन आया है। बाकी खेलों की तुलना में क्रिकेट के प्रति लोगों का जुनून

(श्री मदन प्रजापत)

बढ़ा है। चाहे छोटी सी ढाणी, गांव में जाएं तो बच्चे खेलते नजर आएंगे। उसके प्रति रुझान बढ़ा है। क्रिकेट के साथ में जो मूल दूसरे खेल हैं, इनको बढ़ावा देना भी बहुत जरूरी है। खेल मैदान के अलावा, चाहे वाकिंग ट्रैक हो, चाहे दौड़ने के लिए ट्रैक हो, कालेज हो, स्कूल हो, उनमें ज्यादा से ज्यादा सुविधा होगी तो यह युवाओं के लिए अच्छा होगा।

सभापति महोदय, आज युवा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि युवाओं में जो मानसिक तनाव है और शारीरिक विकास जो रुक रहा है, उसके कई कारण हैं। उन पर शिक्षा का बहुत बड़ा बोझ है। उसके अलावा यह मोबाइल आने के बाद, दादाजी से पोता मोबाइल लेता है, 2 साल, 5 साल की उम्र में जिस तरीके से मोबाइल में खेल खेलने लग जाते हैं तो उससे वास्तविक खेलों में कमी आती है। धरातल पर अगर युवा नहीं खेलेंगे और नहीं दौड़ेंगे तो आने वाले समय में शारीरिक विकास रुक सकता है। अगर शारीरिक विकास अवरुद्ध हो गया तो मानसिक तनाव बढ़ेगा। सभापति महोदय, आप आए दिन मानसिक तनाव के बारे में सुनते हैं। चाहे कोटा हो, चाहे कोई भी कोचिंग हब हो, वहां आए दिन बच्चे आत्महत्याएं करते हैं। यह मोबाइल का और कम्प्यूटर का युग है। 15-20 साल पहले ये मोबाइल आए थे। अब इंसानों में चाहे आंखों पर हो, चाहे कानों पर हो, इनका प्रभाव नजर आ रहा है। आज 2, 4 साल का बच्चा 4-4 घंटे तक मोबाइल देखेगा तो क्या होगा? आने वाले 5-10 साल में देखने को मिलेगा कि जो कद, काठी, शारीरिक वज़न और विकास पहले था, आज वह बच्चों में देखने को नहीं मिलता है। यही हालात रहे और शारीरिक विकास रुक गया तो युवा कहां जाएंगे। धरातल पर खेल बहुत जरूरी हैं।

सभापति महोदय, शनिवार को जो नो बैग डे घोषित किया है, यह भी युवाओं के शारीरिक विकास में मददगार साबित होगा। अगर कोई गुरुकुल या स्कूल में रहे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज शिक्षा एक व्यापार हो गया है। वह टैक्सियां जो बच्चों को ले जाती हैं, 10-15 किलोमीटर तक शहरों में उनको घुमाकर के ले जाती हैं। यह भी शारीरिक विकास में बाधक बनता है।

सभापति महोदय, यह खेल मैदान की जो बात की, नींव की मजबूती जरूरी है। आज चाहे यह पोषाहार हो, चाहे बच्चों का दूध हो, चाहे आंगनबाड़ी केन्द्रों पर हो, वह बच्चों के विकास के लिए आधार है। दूध के मामले में आए

(श्री मदन प्रजापत)

दिन पानी मिलाने के बारे में, आजकल तो यूरिया और पता नहीं क्या मिलाते हैं, सुनते रहते हैं। महिला, बाल विकास और पोषाहार के मामले में सख्त हिदायत दी जाए। अगर कोई भी मिलावट करेगा तो सख्त कार्यवाही हो। यह युवाओं के जीवन के साथ में खिलवाड़ है। इसके लिए आप क्रांतिकारी फैसला लें। दूध हो, बच्चों के पोषाहार हो, आंगनबाड़ी केन्द्रों में किसी ने भी गड़बड़ की तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। नींव इसी से मजबूत होगी।

सभापति महोदय, खेल मैदान और स्टेडियमों के लिए अगर बजट को बढ़ाया जाता है तो आने वाले समय में काफी मदद मिलेगी। आज युवा को किताबों के साथ ही यह भी मानसिक तनाव है कि मुझे कौनसा रोजगार मिलेगा। बेरोजगारी की समस्या के कारण आए दिन आत्महत्याएं करते हैं। वह टेंशन के कारण खेल के प्रति भी रुचि नहीं दिखा सकता है।

आज कृष्णा पूनियॉ जी जैसी कई प्रतिभाएं हैं, जिन्होंने नाम रोशन किया है। मंत्री जी खुद पोलो खेलते हैं। कई साधन सम्पन्न हैं। कई ने बिना सुविधाओं के भी अपने देश का नाम रोशन किया है। आज ही नहीं, महाभारत काल से लेकर आज तक सुविधाएं नहीं मिलने के बावजूद भी जिन प्रतिभाओं में जज्बा, हौसला, जोश और लगन है, उन्होंने देश का नाम रोशन किया है।

माननीय सभापति महोदय, अन्य खेलों को भी बढ़ावा दिया जाये। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कौशल विकास केन्द्र के माध्यम से रोजगार शिक्षा का भी प्रबन्ध किया है क्योंकि शिक्षा और खेल ये आपस में जुड़े हुए हैं। किताबी ज्ञान के अलावा रोजगार का ज्ञान भी अति आवश्यक है। आज बेरोजगारों की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। रोजगार शिक्षा के साथ इनके प्रति ध्यान देना आवश्यक है वह चाहे कौशल विकास के माध्यम से हो क्योंकि शिक्षा, खेल, संस्कार और रोजगार, ये सभी बातें युवाओं में होगी तभी यह कारगर साबित होगा।

माननीय सभापति महोदय, खेल मैदान के साथ में कोच की जो बात हुई, शारीरिक शिक्षक के जो रिक्त पद हैं ये भी भरे जाने चाहिये क्योंकि शुरुआत बच्चे की स्कूल से होती है और बाद में वह कालेज में जाता है। ऐसे कई सैकड़ों, हजारों स्कूल हैं जहां पर खेल को खिलाने वाले नहीं हैं। नींव अगर कमजोर रह गयी तो उस पर मजबूत मंजिल नहीं बन सकती और मजबूत मंजिल तभी बनेगी जब नींव का आधार मजबूत होगा और नींव मजबूत करने के लिये शारीरिक शिक्षा और हर गांव में खेल मैदान होगे तो युवाओं के लिए अच्छा होगा।

(श्री मदन प्रजापत)

माननीय सभापति महोदय, युवाओं के विकास के लिये यूथ होस्टल भी जरूरी हैं। पहले नेहरू युवा केन्द्र और ललित कला नाटक अकादमी हुआ करते थे। मैं चाहता हूं कि हर जिले में यूथ हास्टल हो ताकि आपस में मिलना-जुलना भी होता रहे, आपस में आदान-प्रदान भी होता रहे। ज्ञान के साथ खेल भी हो क्योंकि व्यक्ति जन्म से बड़ा नहीं होता। आज अपन यहां बैठे हैं, अपन भी अपने समय में युवा रहे हैं। हर युवा चाहता है कि मेरी पहचान बने, अलग-अलग क्षेत्र में, चाहे कोई सर्विस सैक्टर में, खेल क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र हैं, उनमें हो। युवाओं के मन में यह जुनून होता है कि मैं भी नाम कमाऊं और देश का नाम रोशन करूं। अगर उनको सही ट्रैक और प्लेटफार्म नहीं मिलता है तो कई युवा लायक होने के बावजूद भी मुकाम हासिल नहीं कर पाते तो यह इनके लिये हर गांव में खेल मैदान हो, हर कालेज में खेल मैदान हो और डिविजन स्तर पर खेल महाविद्यालय की स्थापना और जिले में यूथ हास्टल, तो इस तरह की बातें की जाए।

मैं मोबाइल का विरोध नहीं कर रहा हूं पर चार साल का बच्चा अगर मोबाइल गेम खेलने लगा और धरातल पर खेल नहीं खेला तो उसका शारीरिक विकास रुक सकता है। आज से दो पीढ़ी पहले की शारीरिक कद काठी और आज के दस-पन्द्रह साल के बच्चे की कद काठी अगर हम देखते हैं, चाहे वह वज़न के मामले में हो, चाहे हाइट के मामले में हो, कमतर ही है। अगर यह नस्ल धीरे-धीरे कमजोर हो गयी तो कौन खेल खेलेगा, यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है। यदि कोई बच्चा बीस-पच्चीस साल तक यह मोबाइल पर आंखें डालकर बैठे रहेगा और घर से बाहर नहीं निकलेगा तो यह उसके शारीरिक विकास के लिए बहुत बड़ा नुकसान सिद्ध हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, इनके अलावा कई सुझाव भी हैं। काफी समय हुआ, आपने मुझे समय दिया। मेरा पुन: एक बात पर निवेदन है कि खेल मैदान हो, रिक्त पद भरे जाएं और ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं बढ़ायी जाएं तो धरातल पर खेल के मामले में प्रतिभाएं तैयार होंगी और प्रतिभाएं तैयार होंगी तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो सौगात दी है, ये मामूली बात नहीं है, चार गुना इनका हौसला बढ़ाने के लिये युवा को हिम्मत चाहिये, लाइये मैडल और 75 लाख नहीं 3 करोड़ रुपये मिलेंगे, यह हिम्मत और फैसला कोई मामूली नहीं है। पुन: आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल (बोलने के लिये खड़े नहीं हुए), श्री नारायण बेनीवाल। श्री बाबुलाल।

श्री बाबुलाल (झाड़ोल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 24 शिक्षा, कला, संस्कृति, खेल, युवा के विषय पर विचार व्यक्त करने के लिये समय दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा नीति किसी देश का भविष्य तय करती है। हमारे खेल के विषय में काफी लोगों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज हमारे देश में जिस प्रकार का वातावरण बना है, जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं उनके पीछे अगर मूल कोई कारण है तो हमारे देश में जो पौराणिक शिक्षा पद्धति थी, आश्रम व्यवस्था थी, गुरु आश्रम हुआ करते थे, वो शिक्षा पद्धति थी जिसके कारण से हिन्दुस्तान दुनिया में विश्व गुरु कहलाया। दुनिया के सारे के सारे लोग हिन्दुस्तान में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया करते थे। हमारे यहां तक्षशिला और नालन्दा जैसे विश्वविद्यालय थे जहां पर दुनिया के लोग आकर ज्ञान प्राप्त करते थे।

माननीय सभापति महोदय, आज हम लोग देखेंगे तो पाश्चात्य संस्कृति का जिस प्रकार से हमारे देश पर आक्रमण हो रहा है और आक्रमण हुआ है, आज हमारे उन ऋषि मुनियों की बात कहें तो अनुभव के आधार पर यह उन्होंने हमको बताया कि दुनिया का चक्र, जन्म-मरण-पुनर्जन्म, इंसान मरने के बाद अपने कर्म के आधार पर 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। अगर अच्छे कर्म करेगा तो वह मोक्ष को प्राप्त होगा और अगर वह पाप करेगा तो उसका परिणाम भी उसी को भुगतना है। इस डर के कारण हमारे देश में पाप बहुत कम हुआ करते थे। मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा इसलिए मैं पुण्य पाने के लिए अच्छे कर्म करूं। आज इस भोगवादी संस्कृति के कारण, भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे मनुष्य भागता जा रहा है। मेरा बंगला होना चाहिये, मेरे पास गाडियां होनी चाहिये, मेरे पास इतनी सारी वैभव और सम्पत्ति होनी चाहिये, उसी के कारण हमारे में स्वार्थ पैदा हुआ।

पहले के जमाने का एक उदाहरण आता है। एक पति-पत्नी जा रहे थे, रास्ते में पति ने देख लिया कि एक सिक्का पड़ा है। पति ने देखा कि पत्नी के मन में कहीं लालच नहीं आ जाये इसलिये पांव से धीरे से उस पर मिट्टी डाल दी। पत्नी यह सारा दृश्य देख रही थी। उसने कहा कि पतिदेव आपने यहां पर मिट्टी क्यों डाली? पत्नी ने क्या कहा, पति से बढ़कर उसके विचार थे, ज्यादा

(श्री बाबुलाल)

जिद की तो उसने कहा कि यहां पर एक सिक्का पड़ा था, आपके मन में कहीं स्वार्थ न आ जाये, आप इस सिक्के को देख न लो, उठा न लो, इस कारण से मैंने इस पर मिट्टी डाल दी। पत्नी ने क्या कहा माननीय सभापति महोदय? पत्नी ने कहा कि पराया धन मिट्टी के बराबर है, यह भाव था। आज क्या भाव है? दुनिया चाहे कुछ भी करे, कहीं भी जाये, मेरे पास में सारी सुख सुविधाएं हों, यह सारा का सारा कारण हुआ है, ये सारी परिस्थितियां पैदा हुई हैं तो हमारी शिक्षा नीति के कारण पैदा हुई हैं।

पहले हमारे समाज में आश्रमों में बच्चे पढ़ते थे, जीवन का सारा समर्पण करके पढ़ते थे। पच्चीस साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते थे। आज हम समाज में क्या देखते हैं? सुबह उठकर जब अख़बार पढ़ते हैं तो देखते हैं, यहां पर बलात्कार हुआ, नाबालिग बच्चियों के साथ हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ। उस समय पच्चीस साल तक उस युवा के मन में यह भाव नहीं आता था कि यह बलात्कार क्या चीज है, सम्भोग क्या चीज है। यह उस समय की शिक्षा नीति के कारण हुआ करता था। आज सोशल मीडिया की बात मैं करूं, हमारे देश के प्रधान मंत्री का आज ही अख़बार में छपा है। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया से मेरा मोह भंग हुआ है, मैं सोशल मीडिया से हटना चाहता हूं। इसके पीछे क्या कारण हैं? क्यों हटना चाहते हैं? आज जब हम सुबह व्हाट्सएप खोलते हैं, यू-ट्यूब खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, उनमें दृश्य क्या होते हैं, हम सब उससे वाकिफ हैं। उन सारी चीजों को देखकर के समाज किस दिशा में जाएगा, क्या करेगा, यह हमें समझ में नहीं आता। हम सब लोगों को मिलकर के, पक्ष-विपक्ष का भाव छोड़कर के कम से कम शिक्षा जगत को, शिक्षा नीति को ठीक दिशा में ले जाना चाहिए। ले जाना है तो यही रास्ता है कि हमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पढ़ाना चाहिए। पढ़ाना पड़ेगा। आज नहीं पढ़ाएंगे तो कल आने वाली पीढ़ी पढ़ाएगी। नहीं पढ़ाएंगे तो आने वाला समय और भी खराब आएगा। मैंने पिछली बार कुछ बातें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए कही थीं। मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहूंगा। हमारे महापुरुषों, ऋषि-मुनियों के दिये हुए ज्ञान को हमें पढ़ाना पड़ेगा। फिर चाहे कोई हमें साम्प्रदायिक कहे तो कहे, लेकिन इस शिक्षा नीति को, इस वातावरण को ठीक करने के लिए हमें उन महापुरुषों, उनके आदर्शों को पढ़ाना पड़ेगा। उससे ही देश आगे बढ़ेगा और हम दुनिया में वापस पर उस परम पद पर पहुंच सकते हैं।

(श्री बाबुलाल)

सभापति महोदय जी, आपने बहुत सारी बातें कही हैं 'खेलो इण्डिया' की। हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने 'खेलो इण्डिया' के नाम से हिन्दुस्तान के युवाओं को खेल जगत में आगे लाने की दृष्टि से 'खेलो इण्डिया' को आगे बढ़ाने का काम किया। सभापति जी, मैं गांव से आता हूं और गांव की बात कहता हूं। आज हमारे यहां जो माननीय सदस्य बैठे हैं, उनमें से कई माननीय सदस्यों को शुगर होगी, बीपी होगी। हमारे गांव में शुगर और बीपी समझते नहीं हैं। उसके पीछे कारण हैं। खेल भले ही नहीं खेलता होगा वह। सुबह उठकर अपने खेत पर जाता है, पानी पिलाता है, खोदता है। कुछ न कुछ काम करता है, पसीने से लथपथ होता है और इसी के कारण शरीर में बीमारियों से लड़ने के लिए ताकत पैदा होती है। आज हमें बच्चों को खेल मैदान में भेजना पड़ेगा। हमारे कई योगी हैं, जिन्होंने योग केन्द्र खोल रखे हैं। हमारी एक भी आवश्यकता नहीं है। हम हल चलाते हैं। उससे वहां का व्यक्ति आज भी तंदुरुस्त है और इन बीमारियों से दूर है। जिस दिन वह भी यह सोच लेगा कि मुझे आराम की जिंदगी जीनी है तो इन बीमारियों को अपनी ओर बुलाएगा। आपने खेल जगत की बहुत बड़ी बात कही। हम खेल केन्द्र खोलेंगे। पिछली बार हमारे मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में कहा था कि मैं घोषणा करता हूं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर खेल केन्द्रों का निर्माण किया जाएगा। क्या हुआ उस घोषणा का? जवाब दें न। केवल हर बजट में आकर के हम घोषणा करके लोगों से यह कहेंगे कि हम आपके लिए यह करेंगे। कम से कम पिछला हिसाब तो बताएं कि इतना तो हमने किया, जो रह गया, वह अब करेंगे।

आपने शिक्षा जगत में जो पैसा रखा था नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण करने के लिए, नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक की शुरुआत किसने की थी? सबसे पहले शुरुआत हुई थी आठवीं तक के बच्चों के लिए भैरोंसिंह जी शेखावत के समय में। आठवीं से लेकर बारहवीं तक की हमारी पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे सिंधिया के समय में नवीं से लेकर बारहवीं तक मुफ्त किताब देने का काम किया गया था। सभापति महोदय जी, 2019-20 में आपका पुस्तक वितरण करने का बजट था केवल 73 करोड़ रुपये। अब आपने खर्च कितना किया? 45.66 करोड़ रुपये। पुस्तक लेने वाले बच्चे नहीं थे या आपने केवल बजट देकर पैसा रख दिया और बता दिया कि पुस्तकें नहीं बांटेंगे, ऐसा तय कर दिया था क्या? कम से कम यह तो बताने का आप काम करें।

(श्री बाबुलाल)

सभापति महोदय जी, महाविद्यालयों की मैं बात करूं तो आज जो गांवों में महाविद्यालय हैं, उनकी स्थिति क्या है? मेरे झाड़ोल विधान सभा क्षेत्र की ही मैं बात करूं तो दो महाविद्यालय हैं और दोनों में पढ़ाने वाले व्याख्याता नहीं हैं। अब हम क्या पढ़ाएंगे? कौन पढ़ाएगा? बच्चों ने एडमिशन ले लिया। उसकी गुणवत्ता क्या होगी, यह कौन तय करेगा? विद्यालयों की हालत मैं पहले ही बता चुका हूं।

मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमें महाविद्यालय और स्कूल्स भी खोलने चाहिए। जहां आवश्यकता है, वहां खोलने चाहिए, लेकिन आज शहरों में स्थिति क्या है? शहर के आसपास आप देखेंगे तो वहां पर सरप्लस संख्या में मिलेंगे। उसके लिए आप ही दोषी नहीं हैं, हम भी दोषी हो सकते हैं। हम सत्ता में आएंगे, हमारे जो रिश्तेदार हैं, मिलने वाले हैं, उन्हें हम सुविधाजनक जगह भेजेंगे, उन्हें असुविधा नहीं होनी चाहिए। आप आएंगे, आपके जितने रिश्तेदार हैं, नजदीकी लोग हैं, उन सबको आप सुविधाजनक जगह पहुंचाएंगे। उन गांव और गरीब का क्या होगा? हमारी सरकार में यह तय हुआ था कि हम गांवों में पहले भेजेंगे। भेजने की व्यवस्था भी की थी। आप यह नीति क्यों नहीं अपनाते कि सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों की जो खाली जगह हैं, उन्हें भरेंगे। उसके बाद शहरों में जो भी जगह होंगी, वहां पर हम लगाएंगे। शहर में रहने वाला तो पढ़ने वाला है। गांव का नहीं पढ़ना चाहता? वह भी तो पढ़ना चाहता है न। सभापति महोदय जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इन सारे विषयों पर गम्भीरता से चिंता करके आने वाले इस बजट पर जब आपका जवाब आये, उस समय हमें बताने का प्रयास करेंगे।

आज के खेल जगत में आप जिस खेल का ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन कर रहे हैं, वह क्रिकेट है। अब क्रिकेट हमारे देश का गेम नहीं है। हमारे परम्परागत गेम, हमारे हिन्दुस्तान के जो गेम्स थे, उनमें कबड्डी थी, तैराकी थी, खो-खो थी, ऐसे कई गेम्स हैं, जिन्हें हम प्रोत्साहित करते ही नहीं हैं। हमारे गांवों में फुटबाल, जो कि एक बहुत ही रुचिकर गेम है और कोटड़ा में तो इतना रुचिकर गेम है कि मकर संक्रांति पर टूर्नामेंट हर साल होता है। 25-30 टीमें भाग लेती हैं। मैं आपको न्यौता देता हूं, कभी वहां आकर आप उन खिलाड़ियों को देखिएगा, उन्हें किसी तरह का प्रशिक्षण नहीं दिया हुआ है, गांव के हैं, उनके पास कोई ग्राउण्ड नहीं हैं, खेल मैदान नहीं हैं, छोटी-सी जगह मिलती है, वहां पर खेलकर तैयार होते हैं। उनके खेलने का तरीका, उनका जो

(श्री बाबुलाल)

स्टेमिना है, वह देखेंगे तो कहेंगे कि इन खिलाड़ियों को यदि प्रशिक्षण मिल जाए तो हिन्दुस्तान क्या, पूरी दुनिया में हिन्दुस्तान का नाम रोशन कर दें, ऐसे खिलाड़ी हैं। उन लोगों को जगह नहीं मिलती है, प्रशिक्षण नहीं मिलता है और इस कारण वे गांव में खेलकर धीरे-धीरे उम्रदराज हो जाते हैं और वहीं खतम हो जाते हैं। आगे बढ़ नहीं पाते हैं। मैं चाहूंगा कि आप झाड़ोल और कोटड़ा में खेल केन्द्र तो खोलें ही, लेकिन जो युवा प्रतिभाएं हैं, उन्हें निखारने के लिए कोई कैम्प लगाकर, उनको देखकर, उनमें से जो अच्छे लोग हैं, उनका चयन करके आगे भेजेंगे तो प्रदेश ही नहीं, देश का नाम रोशन करेंगे। ऐसी प्रतिभाएं हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था। हमारे झाड़ोल में लिम्बाराम ने देश-दुनिया में हिन्दुस्तान का नाम रोशन किया। उनको जगह मिलनी चाहिए, उनको अवसर मिलना चाहिए, पर उनको अवसर देने वाला कोई नहीं है। इसलिए, सभापति महोदय, बहुत ज्यादा न कहकर जितने भी अध्यापकों के रिक्त पद हैं, महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं, उन्हें भरें।

(18.00 बजे)

एक मेरी मांग है जो वहां के स्थानीय लोगों की मांग है, वहां के युवाओं की मांग है, पढ़े-लिखे लोगों की मांग है कि फलासिया एक बैल्ट है जो बहुत दूर का है, ग्रामीण क्षेत्र भी है। झाड़ोल में तो महाविद्यालय है, कोटड़ा में भी है, अगर वहां फलासिया में एक महाविद्यालय की घोषणा हो जाए, महाविद्यालय खोलेंगे तो आपका गुणगान करेंगे, आपको धन्यवाद भी देंगे। इतनी बात कहकर मेरी बात को खतम करता हूं। जय भारत, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमर सिंह।

श्री अमर सिंह (बयाना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 24 और 11, खेलकूद तथा युवा सेवाएं पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

सभापति महोदय, खेलकूद, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी का एक मेल है और सबको मिला दिया जाए तो एक बहुत बड़ी जान है। जान है तो जहान है, जान नहीं तो खुला कब्रिस्तान है। सभापति महोदय, शिक्षा एक दुधारू तलवार है और आज गांव से लेकर शहर, प्रदेश नहीं, पूरे देश के लिए जरूरत है क्योंकि

(श्री अमर सिंह)

जो इंसान पूर्ण शिक्षित हो जाता है वह खुद पर अत्याचार नहीं होने देता है और न ही दूसरों पर अत्याचार होना सहन कर सकता है। सभापति महोदय, अगर पूरा देश ही शिक्षित हो जाएगा तो हमारे देश का एक नया निर्माण बनकर रहेगा।

सभापति महोदय, आपका ध्यान ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को विकसित करने हेतु तहसील स्तर पर एक खेल स्टेडियम का निर्माण कराने की ओर दिलाना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री साहब का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना के उप खण्ड रूपवास के गांवों में अनेक प्रतिभावान ग्रामीण युवा एवं युवतियां क्रिकेट, कबड्डी, रस्साकशी, कुश्ती, मुक्केबाजी, फुटबाल तथा स्थानीय खेलों में अपनी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, पर उन्हें सिर्फ अवसरों का अभाव है। यदि इस क्षेत्र की मांग को देखते हुए रूपवास तथा सूपा गांव में स्टेडियम बना दिया जाए तो यहां अच्छे खिलाड़ी तैयार किये जा सकते हैं। सभापति महोदय, आपसे करबद्ध निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना के उपखण्ड रूपवास तथा बयाना के गांव सूपा में स्टेडियम के निर्माण हेतु इसी बजट में घोषणा करने का कष्ट करें। मुझे इसी बजट में घोषणा की पूर्ण आशा और उम्मीद है। मुझे बजट घोषणा का पूर्ण भरोसा है।

मैं आपका उचित ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि बयाना विधान सभा डांग क्षेत्र है और डांग क्षेत्र होने के नाते आज इस मंदिर में, पहली बार इस सदन में आया हूं जब खड़े होकर बोल रहा हूं। बंशी पहाड़पुर का भी इस सदन में सैण्ड स्टोन लगा हुआ है। लम्बे समय से वहां पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन कुछ समस्याओं को देखते हुए मुझे वोट दिया और मैंने अपने क्षेत्र में तमाम तरीके की मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए घोषणा की थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री को जिन्होंने वर्तमान बजट में हर वर्ग को संतुष्ट रखने का प्रयास किया है।

सभापति महोदय, लम्बे समय से, प्राचीन काल से उपखण्ड रूपवास में 32 ग्राम पंचायतों और करीबन ढाई लाख की आबादी को देखते हुए राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या इन गांवों के बीच में जितने भी विद्यालय हैं वहां के छात्र एवं छात्राएं पढ़ते हैं। वहां एक बहुत बड़ा मैदान है और हर वर्ष की भांति वहां एक मेला लगता है और उस मेले को देखते हुए, उस पहाड़ी क्षेत्र

(श्री अमर सिंह)

को देखते हुए, ढाई लाख की आबादी को देखते हुए, क्योंकि वह क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, राणा सांगा का जो खानवा युद्ध हुआ था, उसकी स्मृति को देखते हुए रूपवास की जो उप तहसील है दाऊजी का मंदिर, कुकंद नदी से बंध बारेठा उषा मंदिर, बाणासुर की नगरी को देखते हुए, अपनी देश-दुनिया को देखते हुए वहां तमाम तरीके के खेल या प्रतियोगिताएं होती हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पुन: माननीय मंत्री साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि जो नो बैग डे की स्कीम सरकार ने चलाई है, वह बहुत ही अच्छी चलाई है। पूर्व में जो हमारे बुजुर्ग थे, ऐसी सुविधाएं भी नहीं थीं, लेकिन वे जानते थे कि खेलकूद से, कबड्डी से, रस्साकशी से स्वास्थ्य को लाभ मिलता है और उसके साथ शिक्षा और स्वास्थ्य का तालमेल भी है। सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत, राम-राम साहब।

श्री सभापति: श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, खेल, शिक्षा, विज्ञान विषय पर मुझे बोलने का जो अवसर दिया है, मैं आपका आभार ज्ञापित करता हूं। सबसे पहले विज्ञान विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। निश्चित रूप से आजादी के बाद हमारे देश ने विज्ञान में बहुत तरक्की की है। प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, चाहे हवाई जहाज का क्षेत्र हो, चाहे खेती का क्षेत्र हो, चाहे वह मानव जीवन की आवश्यक आवश्यकताएं हों, उनके लिए विज्ञान ने बहुत खोज की है, लेकिन मेरी इस बारे में यह सोच है कि ये सृष्टि, ये प्रकृति यह मानव शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। इन पंच महाभूतों में पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश, इन पांच के बिना मानव सभ्यता, मानव जीवन संभव नहीं है। वैज्ञानिक प्रगति के इन सौ सालों में महाभूतों के पंच तत्वों का शरण हुआ और जो हालात बने हैं मानव जीवन पर जो खतरा पैदा हुआ, उसके बारे में भी हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। आज जो मानव के लिए आवश्यक चीज है खेती, जिससे हमको अन्न मिलता है, हम उस खेती के बारे में, उस जमीन के बारे में विचार करें। इस विज्ञान ने उसकी क्या दशा की है। यूरिया और डीएपी के प्रयोग से सारे खेत एक तरह से, जिस तरह से व्यक्ति के अफीम की लत पड़ती है, उस तरह अफीम की लत हमारी जमीन की पड़ चुकी है। अगर हम यूरिया और डीएपी

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

नहीं दें तो निश्चित रूप से आज हमारे खेत अन्न पैदा करना बंद कर देंगे। ये एक तरह का दुष्प्रभाव है विज्ञान का, इसके बारे में हमको चिंतन करने की आवश्यकता है।

आज दिल्ली में वायु प्रदूषण की जो स्थिति है और पूरे देश में जो प्रदूषण की स्थिति है, वह विज्ञान की देन है। जितनी नई-नई खोज हुई चाहे वाहनों के क्षेत्र में हुई हो, चाहे परमाणु और अणु बम हमने बना लिये हों, लेकिन उन्होंने मानव जीवन को भी खतरे में डाला है, इसमें कोई दोराय नहीं है। अगर मानव को, इस प्रकृति को बचाने के लिए विज्ञान की खोज होती है तो अच्छी बात है। मानव जीवन और सभ्यता ही खतरे में पड़ जाएगी तो इस विज्ञान को लेकर हम क्या करेंगे। यह हमारे लिए चिंता का विषय है और अब सही और सटीक समय इस बारे में जो भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वे वैज्ञानिक हों, चाहे राजनेता हों, जो नीतियां बनाते हों, उनको यह सोचना पड़ेगा कि जो हालात आज हमारी जमीन के है, जिस तरह के रोग फैल रहे हैं, कैंसर जैसी घातक बीमारियां फैल रही हैं, नये-नये रोग फैल रहे हैं, ये सब विज्ञान की देन है। पेस्टीसाइड से, यूरिया से, डीएपी से इस तरह के रोग फैल रहे हैं।

आज एक अणु बम से करोड़ों लोग खतम हो सकते हैं। पहले जो युद्ध होते थे वे मानव आधारित युद्ध होते थे। एक तलवार के वार से एक ही व्यक्ति की मृत्यु हो सकती थी। आज एक अणु बम से करोड़ों लोग एक साथ खतम हो सकते हैं। इतने परमाणु बमों का जखीरा इस विश्व में है, अगर उन सबका उपयोग एक बार हो जाए तो यह सृष्टि लाखों वर्षों तक वापस सही तरीके से नहीं आ सकती। जिस तरीके से हमारे पुरखे हमको विरासत में दे गये थे, वह विरासत हम नष्ट कर रहे हैं। इस ओर हमको ध्यान देना आवश्यक है।

आज विज्ञान के क्षेत्र में इतनी तरक्की हुई है, लेकिन मेरे भीलवाड़ा शहर में, उप नगर है पुर, उस पुर में चार हजार से अधिक मकानों में दरारें आ गईं। सरकार को, प्रशासन को हमने बार-बार लिखा कि कारण क्या है, कारण ढूंढिए, हमने जिंदल को उसका कारण बताया था कि जिंदल के कारण से ये दरारें आ रही हैं। सरकार मानने को तैयार नहीं है। विज्ञान मानने को तैयार नहीं कि यह उसके कारण से आ रही तो विज्ञान आज तक यह खोज नहीं कर सका। हमारे उस पुर में चार हजार से ज्यादा मकानों में दरारें किस कारण से आई हैं।

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

अब हम मानव हित में विज्ञान का उपयोग करें, तो सही है। अगर इस प्रकृति को नष्ट करने के लिए ही इस विज्ञान का उपयोग हो तो उस पर हमको गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। ये मेरा निवेदन है इन पंच महाभूतों को अगर हमने शुद्ध रख लिया तो करोड़ों वर्षों से यह प्रकृति बनी हुई है। हमारे ऋषि, मुनि जो प्राचीन वैज्ञानिक माने जाते थे, उन्होंने हमको कहा था ''जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके'', विष्णु के रूप में हमारे जल को माना गया। विष्णु के रूप में हमारे ज्वाला मतलब सूर्य को माना गया, विष्णु के रूप में हमारी पृथ्वी माता को माना गया, विष्णु के रूप में पहाड़ों को माना गया और इस तरह से इस अध्यात्म के साथ जोड़कर हमारी प्रकृति का संतुलन बैठाने का जो सुंदर प्रयास किया था। आज हम आधुनिक युग में उस संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। अगर संतुलन के साथ विकास होगा तो यह हमारी मानवता अक्षुण्ण रहेगी, अन्यथा आज मानवता पर गंभीर खतरा इस विज्ञान के कारण से पैदा हुआ। इस पर मैं एक बार पुनः कहता हूं हमको अब चिंतन की आवश्यकता है।

दूसरा जो विषय है आज की मांग का खेलकूद, मैं उसमें यह निवेदन करना चाहता हूं कि खेलकूद में जब हम स्कूल में पढ़ते थे, उस वक्त 1965-70 के बीच में, जब टूर्नामेंट में जाते थे, प्राइमरी स्कूल में तो हमारा गेहूं, आटा हमको ले जाना पड़ता था और टूर्नामेंट में जाते थे तो रोटी बनाने की व्यवस्था भी हमको करनी पड़ती थी। इन 50-60 सालों में आज भी जहां ग्रामीण टूर्नामेंट होते हैं, पूरी व्यवस्थाएं ग्रामीणों को करनी पड़ती हैं। अब हम कहते हैं कि 3 करोड़ रुपया आपको ओलम्पिक पद जीतने पर देंगे, दो करोड़ रुपये सिल्वर मैडल पर देंगे, एक करोड़ रुपया हम कांस्य पदक पर देंगे, लेकिन पदक लेकर आएंगे तब देंगे, बाकी तो ये घोषणा है केवल, आज जो आपने बजट में घोषणा की है नो-बैग डे की, उसमें बजट का कुछ नहीं लगा। इस तरह का ज्ञान लगाकर इस तरह की व्यवस्था भी अगर हम करें तो खेलों का भला हो सकता है।

आज मेरा यह निवेदन है कि खेल जैसा क्षेत्र जिसमें विश्व में देश का नाम होता। हमारा देश केवल और केवल क्रिकेट के इर्द-गिर्द घूम रहा है। इस क्रिकेट के कारण से दूसरे सारे खेलों की बर्बादी हो रही है। आज पदकों की तालिका में हमारा नाम आना चाहिए। आज अगर कुश्ती की तरफ ध्यान दें तो हमको कम से कम कुश्ती में तीस पदक इंटरनेशनल लेवल पर एक खेल में

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

मिल सकते हैं। अगर तैराकी में ध्यान दें तो तैराकी में तीस पदक हमको मिल सकते हैं। कांस्य पदक, गोल्ड, सिल्वर मिलाकर 30 पदक का एक-एक खेल होता है। हम क्रिकेट के पीछे पड़े हैं, जब कि न तो क्रिकेट ओलम्पिक में शामिल है और न एशियाड में शामिल है। हम पूरे इस क्रिकेट के दीवाने होकर, कोई तो आरसीए का अध्यक्ष बनने में लगा हुआ, कोई किसी में बनने में लगा है। मैं आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन आज माननीय सिरोही से आने वाले सदस्य ने जो बात कही थी...

श्री सभापति: आप बिलकुल भी चर्चा नहीं करेंगे इस पर। माननीय सदस्य, विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): 000

श्री सभापति: कोई चर्चा नहीं करेंगे उस पर। मैंने विलोपित कर दिया उसको।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): विलोपित कर दिया तो कोई बात नहीं।

श्री सभापति: सब ठीक है, अब आप तो निर्देश देंगे।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं आज गांवों में...

श्री सभापति: अब पंचभूतों से बाहर निकलो आप।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): जो खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं वे प्रतिभा खोज के लिए होती हैं और उन प्रतिभाओं के लिए सरकार का कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन जनता का बहुत पैसा लगता है। हर गांव में जब टूर्नामेंट होता है तो 8 से 10 लाख रुपये प्रत्येक गांववासी का खर्च होता है। प्रत्येक गांववासी भामाशाह के माध्यम से उन टूर्नामेंटों का आयोजन करते हैं। खाने-पीने से लेकर ठहरने तक व्यवस्था सब गांव वाले करते हैं। सरकार एक पूरा मंत्रालय खोलकर बैठी है और उस मंत्रालय के माध्यम से यदि हम व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो यह सरकार के लिए गंभीर चिंतन का विषय है। आज शिक्षा के क्षेत्र, शिक्षा और खेल आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम बीस हजार, तीस हजार करोड़ का बजट शिक्षा के लिए देते हैं तो उसमें एक हजार करोड़ का बजट खेल के लिए भी निश्चित रूप होना चाहिए, ये मेरा सदन में निवेदन है।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि हम 200 विधायक हैं, एक विधायक को सवा दो करोड़ रुपये प्रतिवर्ष मिलते हैं। 25 लाख रुपये प्रत्येक विधायक को

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

केवल खेल के क्षेत्र में प्रति वर्ष देना चाहिए, यह मेरा निवेदन है सदन के प्रत्येक सदस्य से, जिससे हमारे देश का वास्तविक जो खेल है उसका विकास होगा। आज 5 करोड़ का खेल बजट है उससे कुछ भी नहीं होगा, न हींग लगेगी न फिटकरी, लेकिन अगर 50 करोड़ रुपये हम विधायक कोष के माध्यम से देंगे तो जिस तरह से हमको अभी मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि पुलिस का स्वागत कक्ष विधायक कोष से बनाया जाएगा तो स्वागत कक्ष विधायक कोष से बनने की बजाय वह पैसा हमको खेल में प्रतिवर्ष देने का अगर नियम बना दिया जाए तो इससे खेल जगत का बहुत-बहुत भला होगा। यह मेरा आप सबसे निवेदन है।

दूसरा, मेरे भीलवाड़ा में डीएमएफटी का बजट है, अभी 700 करोड़ रुपये पड़ा हुआ है भीलवाड़ा जिले का केवल और एक वर्ष से उसकी न कोई मीटिंग हो रही है, न कुछ हो रहा है। डीएमएफटी के माध्यम से अगर भीलवाड़ा शहर में एक इंटरनेशनल लेवल का रेसिंग ट्रैक और एक स्विमिंग पूल, हमारे शाहपुरा में स्विमिंग की बहुत प्रतिभाएं हैं, भीलवाड़ा में जूडो-कराटे, कुश्ती और हाकी जैसी बहुत खेलों की प्रतिभाएं हैं। बास्केटबाल, वालीबाल की बहुत प्रतिभाएं हैं। अगर दस करोड़ रुपये की लागत से इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बन जाए, जमीन हमारे पास उपलब्ध है तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि डीएमएफटी के फंड को जल्दी से जल्दी मीटिंग करके रिलीज करवाया जाए और उसमें कलेक्टर के माध्यम से 10 करोड़ रुपये का इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम अगर बन जाता है तो निश्चित रूप से भीलवाड़ा जिले को ही नहीं, पूरे राजस्थान को खेल के क्षेत्र में फायदा मिलेगा।

आज की तारीख में भीलवाड़ा में जितनी भी हमारे जिले में पंचायत लेवल पर सीनियर सैकंडरी स्कूल्स हैं, अब सरकार कहती हैं कि विज्ञान को बढ़ावा देना है लेकिन विज्ञान विषय ही नहीं है और अगर कहीं विषय है प्रत्येक पंचायत में सीनियर सैकंडरी स्कूल खुल चुकी है, तो अगर विज्ञान विषय है कहीं पर तो न लैबोरेट्री है और न वहां प्रयोग की कोई व्यवस्था है तो निश्चित रूप से सरकार को शिक्षा बजट में यह व्यवस्था करनी चाहिए जिससे हमारे बच्चे विज्ञान की ओर आकर्षित हों।

शिक्षा के लिए मैं अंत में, शास्त्र का एक श्लोक बोलता हूं और उसका अर्थ भी आपके सामने रखूंगा। हमारे जो आज के पैरेंट्स हैं वह कैरियर बनाने के लिए शिक्षा दिलाते हैं कि यह शिक्षा लेकर के कलेक्टर बनेगा, कोई एसपी

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

बनेगा। जब बच्चे को पहली कक्षा में भर्ती कराते हैं तो आईएएस, आईपीएस से नीचे की भावना नहीं होती है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कहा है,

'न चौरहार्यं न च राज्यहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी।

व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्या धनं सर्वधनप्रधानम् ||'

अगर विद्या धन को हमने प्राप्त कर लिया तो कैरियर तो अपने आप बनेगा, लेकिन इंसान को बनाना बहुत आवश्यक है और विद्या का असली उद्देश्य, विद्या न चोरी हो सकती, न चोरहार्यं, न चोरी हो सकती है, न च राज्यहार्यं, कितना भी विद्वान होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लग सकता, राज भी हरण नहीं कर सकता उसका। न भ्रातृभाज्यं, न भाइयों में उसका बंटवारा हो सकता है, न च भारकारी, सोने चांदी का वजन लगता है, जेब में पैसा होता है तो जेब भारी हो जाती है, लेकिन जितना अगर विद्या का भंडार आपके पास होगा तो वजन नहीं लगेगा, वह विनम्र बनेगा। व्यये कृते वर्धत एव नित्यं, जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। इसलिए शास्त्र कहता है, हमारे विद्वान कह कर गए हैं कि विद्या धनं सर्वधनप्रधानम् और विद्या का असली उद्देश्य 'विद्या ददाति विनयम् विनयाद याति पात्रताम्, पात्रताम श्रद्धा माप्नोति, श्रद्धया सत्य मापयते।' विद्या का उद्देश्य होता है, विद्या से विनय मिलता है, विनय से पात्रता मिलती है, पात्रता से श्रद्धा उत्पन्न होती है और श्रद्धा होती है, तभी सत्य की प्राप्ति होती है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, अच्छा बोले, लेकिन मैं एक बात और एड करना चाहता हूं,

'विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परपीड़नाय।

खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय।।'

श्री सभापति: यह तो पंडितों का शास्त्रार्थ हो गया।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): इसका अर्थ यह है कि विद्या किसी के पास हो तो दूसरों को सिखाएं। किसी के पास धन हो तो परोपकार के कार्य में खर्च करें और किसी के पास शक्ति हो तो पीड़ित मानव की रक्षा करें, ऐसा व्यक्ति सज्जन व्यक्ति कहलाता है और जिसके पास धन हो और अहंकार करे कि मैं अरबपति हूं, करोड़पति हूं, लखपति हूं और जिसके पास शक्ति हो और दूसरों को परेशान करे और जिसके पास विद्या हो और कुतर्क करे तो वह व्यक्ति दुर्जन कहलाता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए। यह पंडितों का शास्त्रार्थ है, आप कहां कूद पड़े बीच में? विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री बिहारीलाल (नोखा): 000

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री सभापति: माननीय पारख साहब, 2 पंडितों का शास्त्रार्थ चल रहा है आप कहां कूद पड़े बीच में? विराजिए। अंकित नहीं होगा किसी का भी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): 000

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, विराजिए। श्री राजकुमार रोत।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 24 पर चर्चा हो रही है, जो खेल का विषय है। सबसे पहले तो मैं सभापति महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज तक सभी विषयों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन यह जो खेल का विषय है इसको उन्होंने प्रायोरिटी दी। आज हम नीरोगी काया राजस्थान की बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और यह खेल एक ऐसा है जो हर बच्चा बचपन से अपने विद्यालय में हर जगह खेलता है। इससे दो फायदे हैं, एक तो है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और दूसरा अपने विद्यालय से खेलता है तो विद्यालय का नाम रोशन करेगा और राज्य से खेलता है तो राज्य का नाम रोशन करेगा और देश से खेलता है तो देश का नाम रोशन करेगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, यह देखिए, यह आसन और वक्ता के बीच में से जा रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, ध्यान रखेंगे आगे से आप। माननीय सदस्य, आपसे मुखातिब हूं मैं। ध्यान रखेंगे आगे से आप। सुबह ही बताई थी आपको यह सारी बातें। श्री राजकुमार रोत।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को और मंत्री महोदय को विशेषकर मेरे जिले की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। वहां पर जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला है, मैं इस सदन में आज उस शख्स की बात करना चाहता हूं श्री लिंबाराम निनामा जो अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर खेला है, पद्मश्री मिला है, उनको अर्जुन पुरस्कार मिला है।

श्री सभापति: कृपया शांति से सुनें उनको।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): तीरंदाजी में उन्होंने किसी भी संस्था में किसी भी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। उन्होंने जंगलों में अपने घर में जो देशी तीर धनुष होता है उसके माध्यम से सीखा था और उनकी इस प्रतिभा को कई लोग आगे ले गए और वे कामनवैल्थ के राष्ट्रीय कोच रहे थे। उनको पद्मश्री भी मिला था, लेकिन कुछ दिन पहले एक खबर छपी थी कि वह आदमी अपनी दवाई के लिए दर-दर भटक रहा है। वह इतना साधारण आदमी था कि वे कामनवैल्थ के कोच रहे थे, उनको कई देशों ने बुलाया था कि उनके देश में यह ट्रेनिंग दो, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरे देश को दूंगा और जब देश की बात आती है तो कई राज्यों ने उनको आमंत्रण दिया था कि आप हमारे यहां आओ और ट्रेनिंग दो, लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरे राज्य को दूंगा और वह इतना साधारण आदमी था कि उन्होंने आज तक जीवन में फोर व्हीलर तक नहीं ली थी और आज वह आदमी दर-दर भटक रहा है। उनका पूरा परिवार कह रहा है कि हमें पद्मश्री मिला, अर्जुन पुरस्कार मिला, लेकिन वह किसी काम नहीं आया। आज वे अपील करते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मेरे साथ जो हुआ है लेकिन कोई भी ओलंपिक गेम खेलता है तो उसका स्वास्थ्य कार्ड बनना चाहिए तो कहीं न कहीं वह अपने बुढ़ापे में अपनी दवाई तो करा सके। यह जो तीरंदाजी है यह जो हमारा समूह है, मैं एक आदिवासी कम्युनिटी से आता हूं और जो भील समुदाय है इस भील समुदाय का इतिहास पढ़ें, भील शब्द का अर्थ ही होता है, तीर धनुष चलाने में दक्ष लोगों को भील कहा जाता है। आज उस इलाके में सुविधा का अभाव है जो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है। अगर पर्याप्त मात्रा में हमको साधन मिल जाए तो आज पूरे राज्य का और पूरे देश का नाम रोशन करेंगे वह लोग और आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं आशा करूंगा कि तीरंदाजी के क्षेत्र में अगर राजस्थान में सौ परसेंट सामान खरीदते हो तो उसका 50 प्रतिशत डूंगरपुर और बांसवाड़ा को उपलब्ध कराएं क्योंकि वहां पर ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं। आज इस देश में कई प्रकार के खेल हैं, लेकिन उस इलाके में कई लोगों को पता ही नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं है कितने प्रकार के खेल हैं। हम टेनिस की बात करते हैं, पोलो की बात करते हैं, कराटे की बात करते हैं, लेकिन उस इलाके के बच्चों को इन खेलों के बारे में नहीं पता, नाम भी नहीं सुन रखा है। हम मंत्री महोदय से आशा करेंगे कि वहां पर एक खेल विद्यालय खोला जाए। एक

(श्री राजकुमार रोत)

स्टेडियम खोला जाए, विशेषकर मेरी चौरासी विधान सभा में। वहां पर्याप्त मात्रा में जमीन मिल जाएगी।

आज युवा कौशल की बात हो रही है। उस इलाके में जैसे गोफन बनाते हैं, तीर धनुष बनाते हैं, तो उनको भी पेटेंट कराएं और युवा कौशल के माध्यम से वहां के जो युवा बेरोजगार हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाए तो एक रोजगार भी मिलेगा और उन लोगों को आगे आने का भी मौका मिलेगा। आज हमारे राज्य से कई लोग खेल में गये, हमारे इस सदन में भी बैठे हुए हैं। हम घोषणा तो कर देते हैं लेकिन धरातल पर नहीं होता। आज मैं बात करूं मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीरंदाजी की, एक लड़की है, उसके लिए मैंने एमएलए कोटे से रिकमंड किया है, 7 महीने हो गये हैं, लेकिन आज तक उसकी स्वीकृति नहीं निकल पाई है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं, उनको आगे लाएं।

डूंगरपुर-बांसवाड़ा में कई बार विद्यालयों से टूर्नामेंट के लिए जाते हैं तो बच्चों को खेल की सामग्री नहीं मिलती है। स्टाफ द्वारा कहा जाता है कि अभिभावकों से पैसा लाकर आप लेकर जाओ। उनको जाने के लिए सुविधा नहीं मिल पाती है। इतने अभाव में भी कई ऐसी प्रतिभाएं आगे आई हैं। हम अगर नीरोगी काया की बात करते हैं तो खेल पर विशेष योगदान देना चाहिए। मैं इस सदन में मांग करता हूं विशेषकर हमारे चौरासी विधान सभा क्षेत्र में जो आदर्श विद्यालय हैं, उनमें खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाए, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रफीक खान।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, मांग संख्या 24 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं उसके लिये आपका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। पिछले कई दिनों से कई अलग-अलग मांगों पर चर्चाएं इस सदन में हो रही हैं और आज भी काफी डिटेल में चर्चा सदन में हुई और सभी लोगों ने स्पोर्ट से रिलेटेड और युवा मामलों से रिलेटेड काफी सारी बातें सदन में रखीं। युवाओं में जो बेरोजगारी फैल रही है, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बेरोजगारी का संकट क्यों आ रहा है, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारे राजस्थान में जो हमारे खेल मंत्री हैं, वह काफी युवा, एनर्जेटिक हैं। मैं यह कह सकता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान के सारे खेल मंत्रियों से अगर कम्पेयर करोगे तो हमारे खेल मंत्री सबसे फिट और सबसे युवा हैं। जिस तरीके

(श्री रफीक खान)

से इन्होंने पिछले दिनों एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट पूरे प्रदेश में आर्गनाइज किया, मैं इसके लिये इनको धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। एक शेर इनकी नजर करता हूं। ''गिरते हैं शहसवार ही मैदान-ए-जंग में, वह तिफ्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले।''

युवाओं में बेरोजगारी की बात पर प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया शांति रखें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): धरातल पर अगर देखा जाये तो 5 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाये और हर साल जितने भी स्टूडेंट पढ़ाई करके आगे बढ़ रहे हैं, वह बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके रोजगार के प्रति केन्द्र सरकार का रवैया बिलकुल खराब है और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मुख्य मंत्री जी को जिन्होंने 55 हजार नौकरियां इस साल यहां एनाउंस कीं और यह कहा कि हम 55 हजार नये युवाओं को रोजगार देंगे।

बहुत सारी बातें लोगों ने कीं, किसी ने स्टेडियम की डिमांड की, किसी ने क्रिकेट एकेडमी की बात की, किसी ने शारीरिक विकास की बात की, शारीरिक शिक्षकों की बात की। बहुत सारी डिफरेंट-डिफरेंट बातों पर सदन में चर्चा हुई। मैं भी अपनी विधान सभा की कुछ बात आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूं। मंत्री जी, हमारे यहां बहुत सारे स्टेडियम, बहुत सारी फैसेलिटीज डिफरेंट-डिफरेंट खेलों के लिए हैं। जयपुर शहर में तो यह अवेलेबल है। मेरी विधान सभा में जामडोली एक बहुत बड़ा एरिया है और वहां खेल की कोई फैसेलिटी नहीं है। वहां आप सिर्फ हमें एक जमीन और एक स्टेडियम उपलब्ध करा दें, बाकी संसाधन हम अपने आप डवलप कर लेंगे। मैं विधायकों से भी यह गुजारिश करूंगा कि सब लोग अपने-अपने विधायक कोष से एटलीस्ट सर्टेन परसेंटेज 2 से 5 परसेंट के बीच का कोई भी अमाउंट अगर स्पोर्ट्स पर या स्पोर्ट्स एकेडमी पर और खेलों पर अगर खर्च करेंगे तो पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ी खेल की प्रतिभाओं का विकास होगा। जैसा मुझे बताया गया अभी हमारे बजट में मुख्य मंत्री जी ने जो एनाउंसमेंट किया है, ओलम्पिक में गोल्ड मैडल लाने वालों को पहले जो 75 लाख रुपये मिलते थे, उसे बढ़ाकर 3 करोड़ की राशि की घोषणा की, सिल्वर में 50 लाख से 2 करोड़ रुपये किये, ब्रांज में 30 लाख से एक करोड़ रुपये किये। एशियन गेम्स में

(श्री रफीक खान)

जिनको 30 लाख मिलते थे, उनको एक करोड़ की घोषणा की, सिल्वर मैडल वालों को 20 लाख से 60 लाख और ब्रांज को 10 लाख से 30 लाख की घोषणा की। इसके लिए मैं खेल मंत्री और मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं।

बहुत-से साथियों ने अभी उदाहरण दिये कि बजट में खेलों के प्रति बहुत कम राशि दी गई, कम पैसे की घोषणा की गई। मैं इस बारे में थोड़ी-सी बात आप लोगों की नालेज में लाना चाहता हूं। कल सदन में पानी पर चर्चा हो रही थी। 15 अगस्त, 2019 को लाल किले से नरेन्द्र मोदी जी ने बहुत बड़ी घोषणा की और पानी पर उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में हम साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये की योजना बनाएंगे और जल जीवन मिशन में साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये देकर 70 साल से जहां पानी के कनेक्शन नहीं दिये गये हैं, उन सबको पानी के कनेक्शन देंगे और पूरे हिन्दुस्तान को पानी से लाभान्वित करेंगे। जब बजट इन्होंने दिया तो मात्र साढ़े ग्यारह हजार करोड़ रुपये। इस 1 फरवरी, 2020 को साढ़े तीन लाख की घोषणा करने वालों ने बजट दिया साढ़े ग्यारह हजार करोड़ रुपये का। हमारी सरकार तो वह काम करती है जो घोषणा करती है, वही देती है, ऐसे फालतू घोषणा नहीं करती। मैं इसके लिए हमारे खेल मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छे से डिपार्टमेंट को आर्गेनाइज किया।

खेल का हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा महत्व है। खेल सिर्फ एक खेल ही नहीं है, वह आदमी को एक शेप देता है, एक लक्ष्य देता है, उसको अपनी पूरी लाइफ स्टाइल को ढालने का तरीका बताता है। sportsman spirit डवलप करता है, टीम की भावना डवलप करता है। मुझे पूरी खुशी है और बड़े फख्र से मैं कह सकता हूं कि मंत्री जी के मार्गदर्शन में हम बहुत अच्छा काम, खेलों में कर पाएंगे। आपने मुझे मांग संख्या 24 पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री सभापति: श्री गणेश घोघरा।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 24 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी और हमारे मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि खेलों के लिए अच्छा बजट दिया है, खिलाड़ियों के लिए भी इन्होंने अच्छी घोषणा की है, उसके लिए इनको बहुत-बहुत धन्यवाद

(श्री गणेश घोघरा)

देना चाहता हूं। नीरोगी काया खेलों से ही रहती है और मंत्री जी हर खेल खेलना जानते हैं और इनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता है और यह मेरे राजनीतिक गुरु भी रह चुके हैं, इसलिए मैं जो चाहूं वह मांग सकता हूं। मंत्री जी कम से कम मेरी एक डिमांड तो पूरी करेंगे।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि हर पंचायत स्तर पर एक खेल मैदान होना चाहिये क्योंकि गांवों में खेल मैदान नहीं होने से कई प्रतिभाएं आगे नहीं बढ़ती हैं, निखरती नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि नरेगा के माध्यम से सैंक्शन निकाली जाये, मैदान समतलीकरण कराया जाये, उसकी बाउंड्री कराई जाये तो खिलाड़ियों के लिये अच्छा रहेगा।

साथ ही मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र टीएसपी एरिया डूंगरपुर की बात करना चाहूंगा। वह आदिवासी जनजाति बहुल क्षेत्र है। यहां तीरंदाजी हर बच्चे में निखरती है। हमारे यहां पर कई कोचेज तैयार हुए हैं। कई ओलम्पिक भी खेले हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में खेले हैं और पदक भी लाये हैं, लेकिन उनके पास आधुनिक संसाधन नहीं होने की वजह से वे कहीं न कहीं पीछे रह गये हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हमारे वहां पर डूंगरपुर में स्पोर्ट्स काम्पलेक्स में तीरंदाजी एकेडमी खोली जाए। वहां का आदिवासी आगे बढ़ सके और देश के लिए कुछ पदक ला सके। जिस तरह से महाभारत में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था, उसने पेट में ही धनुर्विद्या सीख ली थी, उसी तरह से आदिवासी भी जब पैदा होता है और वह छोटा होता है तब से ही उसको तीर धनुष चलाने का शौक होता है। तीर धनुष उसका हथियार है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में तीनों जगह पर एक-एक एकेडमी खोली जाए, जिससे हमारी प्रतिभा आगे बढ़ सके और बच्चों की हौसला अफजाई हो। कई बच्चे अच्छे निशानेबाज हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे कम्पाउंड वाला धनुष नहीं ले सकते हैं, वे आगे नहीं खेल सकते हैं, इसलिए वे आगे क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं। मंत्री जी से निवेदन है कि आप हमें अच्छा बजट दें तो हमारे वागड़ क्षेत्र का भला हो सकेगा।

महाराणा प्रताप का सेनापति पूंजा भील था। उस समय अकबर से छापामारी युद्ध करते थे। उस समय अकबर की सेना के सामने राणा पूंजा के सैनिक लड़े थे। छापामारी युद्ध किया था। उस समय तीर धनुष से मुगलों की

(श्री गणेश घोघरा)

सेना भगायी थी। हम उन आदिवासी भील वंशज के टीएसपी क्षेत्र से आते हैं। मंत्री जी से निवेदन है कि विशेषकर स्पोर्ट्स काम्प्लैक्स का बजट दिया जाए, क्योंकि वहां पर न तो ट्रैक है, न ही फुटबाल का मैदान है। पूरे जिला मुख्यालय पर कोई भी खेल मैदान नहीं है। आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर मुख्यालय पर अधिक से अधिक बजट दें और खेलों को आगे बढ़ाएं। मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, आज महत्वपूर्ण मांग 24 व 11 पर मैं बोलना चाहता हूं। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। खेल अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम किस तरह से अपने शरीर को नीरोग रख सकें, नीरोगी राजस्थान तभी होगा, जब खेल प्रत्येक नौजवान खेलेगा और उसके लिए उसे सारी सुविधाएं मिलें। हमारी सरकार ने इस बजट के अंदर भी, आपने देखा होगा कि सात दिन के अंदर एक दिन पढ़ाई नहीं होगी, बच्चों को खेल खिलाया जाएगा। बच्चों का किस तरह से विकास हो, बच्चों के लिए अन्य तरीके की गतिविधियां जैसे भाषण आदि उन्हें सिखाया जाए ताकि शरीर व मानसिक विकास हो सके।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर शरीर स्वस्थ है तो सब ठीक है और अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो सब कुछ ही ठीक नहीं है। जिसके लिए खेल बहुत जरूरी है। मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने बात बतायी कि खेल के लिए सरकार किस तरह से प्रोत्साहन दे रही है। किस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी ने राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय, स्टेट लेवल और जो खेल में भाग ले रहे हैं, जीत रहे हैं, उनके लिए इनाम की घोषणा भी की है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हमें इन खेलों के लिए जो भी सुविधाएं हो, वे करनी चाहिए। चाहे प्रत्येक पंचायत पर खेल का स्टेडियम हो, चाहे नरेगा से हो या अन्य एमएलए फंड हो, डीएफएमटी का फंड हो, अगर हर पंचायत में बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम हो तो बच्चे नित्य खेलेंगे। खेल में सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, जो पुराने खेल हैं, कबड्डी है, खो-खो है, कुश्ती है, इस तरह के खेल खेलें ताकि उससे शरीर मजबूत होगा और आज जिस तरह से ये बीमारियां फैल रही हैं, हमारा खान-पान शुद्ध नहीं है। इन खेलों के माध्यम से इस शरीर को हष्टपुष्ट किया जा सकता है।

(श्री मेवाराम जैन)

इन्हीं खेलों के माध्यम से आज आप नौकरियों में देखिए, आज जितनी भी भर्तियां हैं, उनमें शारीरिक जांच की जाती है, दौड़ भी होती है। ये सारी बातें खेल के माध्यम से युवाओं को मिलती हैं। सरकार चाहती है कि युवाओं को किस तरह से आगे बढ़ाएं, उसके लिए चाहे बजट की जहां भी आवश्यकता पड़े, बजट बढ़े और सरकार ने उसके लिए 55 हजार नौकरियां दी हैं। इसमें घोषणा की है कि युवा कैसे आगे बढ़ें, उनके लिए हर तरह से सरकार प्रयासरत है।

सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि युवाओं के लिए हम जितना कर सकें, उतना कम है। देश में आने वाले समय में अगर युवा तरक्की करेंगे, युवा आगे बढ़ेंगे। युवा आज आगे बढ़ने चाहिए। युवा जिस तरह से बेरोजगार हो रहे हैं, उनको हम किस तरह से आगे बढ़ाएं। आज युवा नशे की लत में जा रहे हैं, उनको हम किस तरह से छुड़ाएं। चाहे शराब हो, अफीम हो, चाहे गांजा हो, आजकल नये-नये नशे हैं। उनसे हम कैसे उनको अलग रखें, इसलिए इन सबके लिए खेल का होना बहुत जरूरी है। यही हमारे मंत्री जी और हमारे मुख्य मंत्री जी चाहते हैं।

हमारे राजस्थान में पहली बार इस तरह खेलों का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान लेवल पर हो रहा है, जिले के लेवल पर हो रहा है। खेलों के माध्यम से हम कैसे बच्चों का मानसिक तनाव कम कर सकें, युवाओं को कैसे आगे बढ़ा सकें, यह बहुत ही अच्छी शुरूआत है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम युवाओं के लिए प्रयास करें।

सभापति महोदय, आज युवा देश का भविष्य है। आज आवश्यकता है कि हम युवाओं के लिए चाहे आज विद्यालयों की बात करें, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने प्रत्येक सरकारी विद्यालय में वार्षिक उत्सव रखा है, उसके माध्यम से वहां अभिभावक आते हैं, वहां अभिभावकों व गांव वालों के आने से स्कूल में लाखों रुपये दान दिये जाते हैं ताकि बच्चों के खेल के लिए, बच्चों के लिए फर्नीचर आदि हो, बच्चे किसी तरह से पढ़ाई में, खेल-कूद में विकास कर सकें। मुझे इस बात की खुशी है कि वहां अध्यापक अपनी तनख्वाह से उसमें अपने पैसे दे रहे हैं कि इन बच्चों के लिए। मैं कई ऐसे आयोजनों में गया हूं, जहां 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपये भामाशाहों ने आगे बढ़कर दिये हैं कि कैसे हम इन बच्चों को आगे ले जाएं। हम किस तरह से उनकी शिक्षा में विकास कर सकें। किस तरह से हम उनका स्वास्थ्य ठीक कर सकें और उनको सारी

(श्री मेवाराम जैन)

सुविधाएं दे सकें। सभापति महोदय, बहुत ही अच्छी शुरुआत है और मैं चाहूंगा कि खेल के माध्यम से बच्चों को रोजगार मिले और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और उनकी सुविधाओं के लिए हम हर तरह से मदद कर सकें।

विज्ञान की बात करें। आज विज्ञान का युग है। प्रत्येक व्यक्ति आज इस विज्ञान के युग में प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। हम कहां तक बढ़ गये हैं? देश में सुई तक नहीं बन रही थी। आज हम चन्द्रमा तक पहुंच गये हैं। कम्प्यूटर के युग में हम कहां तक पहुंच गये हैं और विज्ञान किस तरह से तरक्की कर रहा है। आज खेती की बात करें, किस तरह से पहले खेती होती थी और आज विज्ञान कितनी तरक्की कर गया कि पहले हमारे यहां अमरीका से ज्वार आती थी और उससे हम काम चला रहे थे, लेकिन आज हम विदेशों में निर्यात करने की स्थिति में हैं और निर्यात कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें भी हमें आवश्यकता है कि गांवों में प्रयोगशालाएं खुलें और वहां लोगों को सिखाया जाए कि किस तरह की खेती हो। आज जिस तरह से खेती में यूरिया वगैरह जो काम में लिया जा रहा है, इसको बंद करें। जिस तरह से दूषित पानी है, दूषित खान-पान है, इनको कैसे रोकें? किस तरह से शरीर को हम स्वस्थ रख सकें, इसके लिए गांवों में इस तरह के आयोजन हों, प्रतियोगिताएं हों, लोगों को सिखाया जाए कि विज्ञान किस तरह से आगे बढ़ चुका है। हम विज्ञान को नौजवानों तक कैसे आगे बढ़ाएं ताकि वे आगे बढ़ सकें। प्रत्येक विद्यालय के अंदर प्रयोगशाला हो और प्रयोगशाला के अंदर इन बच्चों को सिखाया जाए कि नये-नये आविष्कार कैसे हों? इन बच्चों को सिखाएंगे तभी तो ये आगे बढ़ पाएंगे। इसके लिए बजट हो और प्रयोगशालाएं हों। अंत में ज्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं यही कहूंगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझने की आवश्यकता है कि हम खेल को और विज्ञान को समझें और इसको कैसे आगे बढ़ाएं? इसके लिए सरकार और हम सबको मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे इसमें तरक्की करें? किस तरह से हम इसको आगे ले जाएं? धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय सभापति जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे मांग संख्या 11 और

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

24 पर बोलने का मौका दिया। विशेषकर मैं धन्यवाद माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय खेल मंत्री जी का इस बात के लिए करना चाहता हूं कि सरकार ने राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाले दैनिक भत्तों में क्रमश: 500 से 1000 और 300 से 600 लगभग दुगुनी बढ़ोतरी की है, जो स्वागत योग्य है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने संविदा पर विभिन्न खेलों के 500 कोच लगाने की घोषणा की है, जिस पर 10 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। इसके लिए भी मैं सरकार को और खेल मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। ग्राम स्तरीय खेल प्रतिभाओं को खोजकर आगे लाने के लिए राज्य खेलों की तर्ज पर ब्लाक स्तरीय एवं जिला स्तरीय खेलों का आयोजन जल्दी शुरू किया जाएगा जिससे वर्ष 2022 में होने वाले राज्य खेल और अधिक सफल होंगे।

प्रदेश में खेलों को अधिक बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाओं के तहत कार्य किये जा रहे हैं। मेरा विधान सभा क्षेत्र नदबई एवं उच्चैन जो तहसील है, उसमें खेलों को अभी तक बढ़ावा देने के लिए कोई खेल स्टेडियम नहीं है। माननीय खेल मंत्री जी हमारे बीच बैठे हुए हैं। उनसे मैं मांग करना चाहता हूं कि जो उच्चैन तहसील है और नदबई मेरा हैडक्वार्टर है विधान सभा क्षेत्र का, उस पर कम से कम एक-एक खेल स्टेडियम की स्थापना जरूर की जाए जिससे युवाओं को उसमें खेलकूद का मौका मिले और आगे बढ़ सकें।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि खेलकूद का मैदान इसलिए भी आवश्यक है कि पिछले दिनों 11 जुलाई की एक घटना मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें मुझसे लगा हुआ जो डीग्कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र है, एक ही परिवार के 6 लोग सुबह की सैर करने 5 बजे सड़क पर निकले थे और उनकी उसी समय एक गाड़ी से दुर्घटना हो गयी। 6 के 6 लोगों की वही मौत हो गई इसलिए खेलकूद के साथ-साथ सुबह टहलने के लिए, जो हमारे वृद्ध लोग हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके लिए भी खेलकूद के मैदान की अति-आवश्यकता नदबई और उच्चैन में है। चूंकि समय कम है, अत: मैं पुन: एक बार यही मांग करते हुए माननीय खेल मंत्री चांदना साहब यहां बैठे हुए हैं उनसे उम्मीद करूंगा कि जिस तरह पूरे प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए तरह-तरह की कई योजनाएं, जिनकी घोषणा पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा की गई, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी उच्चैन और नदबई दोनों में एक खेल स्टेडियम की जरूर स्थापना हो। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बुलाकी दास कल्ला।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 11 और 24 के बारे में माननीय 32 सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के संबंध में, वैसे तो बहुत कम कटौती प्रस्ताव आए हैं, लेकिन मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो भी सुझाव दिए हैं और जो कटौती प्रस्ताव दिए हैं, मैं यथासमय उन तक प्रत्युत्तर भिजवाने का प्रयत्न करूंगा।

सभापति महोदय, आज का युग वैज्ञानिक युग है। मनचाहे तो आकाश में उड़ें, मनचाहे तो समुद्र के साथ हंसो-खेलो, मनचाहे तो आप यहां बैठे-बैठे अपने परिवारजन या मित्र जो अमेरिका, जापान, जर्मनी या विश्व के किसी भी कोने में हैं, बैठे-बैठे बात करो। व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से दुनिया एक ग्लोबल विलेज के रूप में सिमट गई है। साइंस और टैक्नोलोजी के विकास के कारण आज हम इंटरनेट के माध्यम से कोई भी सूचना, गूगल के माध्यम से और अन्य साधनों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इस वैज्ञानिक क्रांति को आमजन तक पहुंचाने के लिए, गांव तक पहुंचाने के लिए 1983 में इस विभाग की स्थापना की गई। स्थापना के बाद यह विभाग निरंतर साइंटिफिक टैम्पर विकसित करने के लिए गांवों का, शहरों का सामाजिक और आर्थिक विकास करने के लिए साइंस और टैक्नोलोजी का उपयोग करते हुए उनको साइंटिफिक टैम्पर में लाने का प्रयास करता है। इसके लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम हमने हाथ में लिए हैं।

खास तौर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी स्कूल हैं उन स्कूलों में जहां पर फिजिक्स, कैमिस्ट्री, साइंस बायोलोजी, मैथेमेटिक्स, एग्रीकल्चर अथवा साइंस से संबंधित जो भी विषय पढ़ाया जाता है, उन विद्यार्थियों के लिए खास तौर से रिसर्च एंड डवपलमेंट का कार्यक्रम शुरू किया गया है और जो व्यक्ति इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, उनको विभाग की तरफ से 25 हजार से 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। साइंस के विभिन्न विषयों पर कांफ्रेंसेज आयोजित करने के लिए राज्य स्तर पर यदि कोई कांफ्रेंस आयोजित की जाती है तो उसके लिए 25 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। यदि केन्द्रीय स्तर की कोई वर्कशाप या कांफ्रेंस आयोजित की जाती है तो उसके लिए 50 हजार रुपये की सहायता दी जाती है और यदि अन्तरराष्ट्रीय स्तर की कांफ्रेंस आयोजित की जाती है तो उसके लिए

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

एक लाख रुपये की सहायता दी जाती है। इस वर्ष इस प्रकार की 20 कांफ्रेंस और वर्कशाप्स हुए हैं, जिसके लिए 15 लाख रुपये की सहायता दी गई है। इसके अलावा किन-किन लोगों को वर्कशाप में, किन यूनिवर्सिटीज को, किन कालेजों को चयनित किया जाए, इसके लिए वक्तन-वक्तन विभाग द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है। उस विज्ञापन के जरिये कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, चाहे वह सरकार से ग्रांट-इन-एड ले रहा हो अथवा यूजीसी से मान्यता प्राप्त कोई निजी विश्वविद्यालय, कालेज इसमें एप्लाई कर सकता है और एक्सपर्ट की एक कमेटी इसमें किन-किन वर्कशाप को और किन-किन सेमिनार को एड देनी है, वह तय करती है।

सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों द्वारा जो रिसर्च की जाती है, उसके लिए भी एक विज्ञापन जारी किया जाता है। उस विज्ञापन के जरिये जो विद्यार्थी उसमें एप्लाई करते हैं, उनके दसवीं, बारहवीं के जो मार्क्स हैं, उनके आधार पर और खासतौर पर उन्होंने जो प्रोजेक्ट भेजा है, उस प्रोजेक्ट को एक्सपर्ट कमेटी जज करती है। जज करने के बाद सिलेक्ट करती है और उनको भी सहायता देती है। चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का आयोजन दिसम्बर में किया गया। इसमें 5 लाख तो राज्य सरकार की तरफ से अनुदान मिला। 20 लाख रुपया केन्द्र की तरफ से अनुदान मिला। ये इस बार 8 व 9 दिसम्बर को उदयपुर में आयोजित हुआ। इसमें करीब 1200 बच्चों ने भाग लिया। 30 बच्चों को हमने गोल्ड मैडल दिया। उनके माडल्स को देखकर एक्सपर्ट कमेटी ने जो तय किया था, उसके आधार पर। इंस्पायर स्कालरशिप भी हम लोग देते हैं। इसमें 5 हजार रुपया पर-मंथ इंस्पायर स्कालरशिप दी जाती है, जो बच्चे साइंस में दसवीं में, बारहवीं में और बी.एससी. और बी.टैक में मार्क्स प्राप्त करते हैं, उनको और उसके बाद जो प्रोजेक्ट उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसको एक्सपर्ट कमेटी देखकर उसके बाद निर्णय करती है। उनका चयन करके ऐसे 100 बच्चों को आठ सप्ताह हेतु देश के जाने-माने करीब-करीब 200 इंस्टीट्यूट जो नेशनल लेवल के हैं, उनमें और देश के जाने-माने आईटीआई में आठ सप्ताह की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे इनको अच्छे साइंटिस्ट बनने का, अच्छे इंजीनियर बनने का, अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे रिसर्च स्कोलर बनने की प्रेरणा मिलती है।

(19.00 बजे)

इसके अलावा हमारे यहां पेटेंट सूचना केन्द्र महाविद्यालयों में पांच जगह इसके सेंटर खुल चुके हैं। आईटी पालिसी में रिसर्च को पेटेंट कराना कैसे

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

होता है, पेटेंट आईटीआर की गाइड लाइन विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में बताई जाती है। अभी हाल ही में उप मुख्य मंत्री जी ने साइंस टैक्नोलोजी रिसर्च इनोवेशन डिजाइन एंटरप्रिन्योरशिप, इसके लिए पांच लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इसके अंतर्गत दो कार्यक्रम किए गए हैं। एक तो, पोकरण में 11 मई को जो विस्फोट हुआ है, उस दिन नेशनल टैक्नोलोजी डे मनाया गया। हाल ही 28 फरवरी नेशनल साइंस डे, इसके लिए पांच लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

अभी कुछ माननीय सदस्यों ने, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि प्रयोगशालाएं बननी चाहिए, विकसित होनी चाहिए। मैं उनको बताना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग के 134 स्कूलों को माडल स्कूल बनाया गया है, उनको हम सहयोग करते हैं। 5 हजार स्कूलों में साइंस क्लब बनाए गए हैं। उन साइंस क्लब को हम 10-10 हजार रुपये की सहायता देते हैं। इन साइंस क्लब के माध्यम से साइंटिफिक टैम्पर बच्चों में डवलप हो, इस प्रकार का हमारा प्रयास रहता है।

इसके अलावा विज्ञान पार्क जयपुर, झालरापाटन, डबल गेट, झुन्झुनूं, कोटा, उदयपुर में बन रहा है। अजमेर पश्चिम से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही, अजमेर और बीकानेर पार्क को भी स्वीकृत कर दिया गया है। आगामी 27 महीनों में आपका पार्क बन जाएगा।

विभाग के नये कार्यक्रम हैं, उनके बारे में कुछ बताने से पूर्व, माननीय सदस्यों ने सवाल यहां उठाए हैं, उनके बारे में कुछ बात कहना चाहूंगा। जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हर व्यक्ति के खून में वैज्ञानिक है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं उनको कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति बचपन से ही, जब पैदा होता है या तो वह आशु वैज्ञानिक होता है या आशु कलाकार होता है या आशु लेखक होता है, अच्छा एकेडेमिशियन होता है, नैसर्गिक क्षमता हर व्यक्ति में है, लेकिन उन नैसर्गिक क्षमताओं को तलाशने की जरूरत है। उन व्यक्तियों को यदि साइंटिफिक माहौल दे दिया जाए तो वह साइंटिस्ट बन जाएगा। उनको यदि अच्छा कलाकार मिल जाएगा तो उससे प्रेरणा मिल जाएगी तो वह कलाकार बन जाएगा। साहित्यकार से प्रेरणा मिल जाएगी तो साहित्यकार बन जाएगा। डाक्टर से प्रेरणा मिलेगी तो डाक्टर बन जाएगा। इंजीनियर से प्रेरणा लेगा तो इंजीनियर बन जाएगा। हर व्यक्ति

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

जीवन में कुछ बनना चाहता है, लेकिन बनने का माध्यम तालीम ही है। बिना तालीम, बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आदमी कुछ नहीं बन सकता।

इसी प्रकार भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि कैंसर ट्रेन आती है। यह बात सही है कि बीकानेर में हरियाणा, पंजाब से कैंसर ट्रेन आती है। सरकार ने उनके लिए लीनियर एक्सीलरेटर, गामा कैमरा, कोबाल्ट थैरेपी, ऐसी सब प्रकार की व्यवस्था, जो रोगी वहां आते हैं, उनके निराकरण के लिए कर रखी है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कैंसर पैदा कैसे होता है। अब तक हमने जो पढ़ा है कि कार्बन के सेवन से, धूम्रपान से, दूषित पर्यावरण से, ज्यादा से ज्यादा केमिकल रिएक्शन होने से कैंसर होने की बात कही गई है। मैं समझता हूं कि इन चीजों से बचना चाहिए। यह भी हमें साइंस सिखाता है। किन-किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए, किन-किन चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हमें विज्ञान सिखाता हे।

इन्होंने एक बात और कही कि सौ साल से ज्यादा कैसे जीएं। इसके लिए हमारे आयुर्वेद के, वह भी वैज्ञानिक ही थे। चाहे आप उनको वेद कह दो। उन्होंने कहा था हरड बहेड़ा आंवला और चौथी नीम गिलोय, इन चारों का सेवन करे तो रोग कहां से होय। इनका सेवन करो, सौ साल तक जीओगे। जो आदमी प्राणायाम करता है वह सौ वर्षों तक जीता है। जो व्यक्ति खेचरी करता है, क्रिया योग करता है, आप गूगल में देख लीजिए महावतार बाबा 1800 साल से ऊपर है वह जी रहे हैं, बिना भोजन किए, 1800 साल के हैं। क्रिया योग भी एक साइंस है,...(व्यवधान) 1800 साल से ऊपर है, आप बाहर गूगल में जाकर देख लेना। खेचरी और क्रिया योग करने वाला व्यक्ति वह जितने वर्ष चाहे उतने वर्ष जी सकता है। सांप खाने से मर सकता है, करंट से मर सकता है, डूबने से मर सकता है, एक्सीडेंट में मर सकता है लेकिन प्राकृतिक रूप से जितने साल वह जीना चाहे जी सकता है।

इसी प्रकार, ग्रामीण स्कूलों में साइंस लैब खुलें, यह बात अजमेर पश्चिम से आने वाले माननीय सदस्य ने कही। हम निश्चित रूप से...

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): पश्चिम नहीं, उत्तर है।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सोरी उत्तर है, मैं माफी चाहता हूं। उत्तर और पश्चिम पासपास है इसलिए। (व्यवधान) अजमेर उत्तर से

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

आने वाले माननीय सदस्य ने कहा साइंस लैब ग्रामीण स्कूलों में खुले। जहां-जहां साइंस खुली हुई है वहां हम लैब खोलने का भी प्रयास करते हैं, हमारा विभाग भी इसमें पूरा सहयोग करेगा। जहां तक बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही, जिसका मैं बता ही चुका हूं।

अब मैं कुछ महत्वपूर्ण निर्णय विभाग के हैं जो आपको बताना चाहता हूं।

बजट घोषणा 2020-21 भरतपुर संभाग, माननीय पर्यटन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भरतपुर संभाग में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जाएगा जिससे पूर्वी राजस्थान की आम जनता, विशेषकर युवाओं को लाभ मिलेगा। अब तक सभी संभागीय मुख्यालयों पर हमारे कार्यालय हैं। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर मुख्यालय है, बीकानेर में भी है, लेकिन भरतपुर नया संभाग मुख्यालय बना था, यहां पर प्रौद्योगिकी विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं था। विशेषकर इससे युवाओं को लाभ मिलेगा।

राज्य में कमजोर, पिछड़े एवं दलित वर्ग को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए अनुसूचित जाति सैल स्थापित किया जाएगा।

राज्य में युवा वैज्ञानिकों, युवा शोधकर्ताओं, वैज्ञानिक पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए स्ट्राइड पुरस्कार प्रारम्भ किए जाएंगे।

राज्य में विज्ञान प्रौद्योगिकी की ज़िलेवार आवश्यकताओं की मैपिंग करने के लिए रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

कार्या प्रोग्राम के तहत राज्य के विज्ञान संकाय के 27 छात्र-छात्राओं को देश के परमाणु ऊर्जा विभाग, आईआईटी, बायोटैक्नोलोजी विभाग, सीएसआईआर, आरसीएमआर की प्रतिष्ठित लैब में लघु शोध परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2020-21 में 100 छात्र-छात्राओं को अवसर प्रदान किया जाएगा।

राजस्थान में जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए जैव विविधता बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में राज्य जैव विविधता फैलोशिप कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए ट्रैड मार्क पेटेंट, डिजाइन के आवेदन दाखिल करने के लिए तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराना, राज्य की बौद्धिक

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

सम्पदा अधिकार नीति 2019 के नीतिगत फायदे राज्य के नवप्रवर्तकों को मिलेंगे।

राज्य में निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में भी बौद्धिक संपदा अधिकार प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे।

पांच हजार से अधिक युवाओं को बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में 40 वर्कशाप के माध्यम से ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी।

राज्य से जियोग्राफिकल इंडिकेशन की संख्या 17 करने के लिए राज्य सरकार वित्तीय एवं तकनीकी सहायता मुहैया कराएगी। राज्य सरकार के प्रयासों से सोजत मेहंदी को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने की संभावना है।

राज्य में उद्योगों एवं अकादमिक सहयोग कार्यक्रम के अधीन विभिन्न विश्वविद्यालयों में उद्योग जगत के विशेषज्ञों को निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा।

उदयपुर में 05 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला उप क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र दिसम्बर 2020 तक प्रारम्भ हो जाएगा।

जोधपुर में इनोवेशन हब माह सितम्बर, 2020 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

राज्य में नवीन विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए स्मार्ट सिटी, नगर विकास न्यास एवं अन्य संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा।

जोधपुर में उप क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र को साइंस सिटी में अपग्रेड करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भिजवाया जाएगा।

अजमेर में विज्ञान केन्द्र का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा और 27 माह में यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

भरतपुर संभाग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का जो क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जाएगा, उस पर लगभग 47.5 लाख का खर्चा आएगा।

नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने, यह तो स्टेडियम से सम्बन्धित है, उधर, सभापति महोदय, मेरे खयाल में माननीय सदस्यों ने साइंस एण्ड टैक्नोलोजी के बारे में जो प्रश्न उठाये थे, मैंने उनका प्रत्युत्तर दे दिया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आ गये, आ गये, सबके उत्तर आ गये।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): कट-मोशंस के प्रत्युत्तर भिजवा दूंगा। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मांग संख्या 11 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: श्री अशोक।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 24 शिक्षा, कला, संस्कृति एवं खेल के ऊपर एक सार्थक चर्चा हुई। बड़ी खुशी की बात है कि 81 कटमोशंस खेलों के ऊपर लगे, 31 माननीय सदस्यों ने इसके ऊपर अपनी बात रखी। मुझे लगता है कि आज, क्योंकि हम जब तैयारी कर रहे थे, तब 81 कटमोशंस लगे, यह हमारे विभाग के लिए बड़ी नई बात थी क्योंकि अक्सर 2-3-4 कटमोशंस लगते थे और खेल विभाग एक अनदेखा विभाग रह जाता था।

यह हमारे लिए खुशी की बात तो है ही, साथ ही साथ मैं समझता हूं कि इस एक साल में सदन के नेता और हमारे मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोतजी ने खेलों के प्रति जो प्रयास किये, उन प्रयासों की वजह से राजस्थान में खेलों में जो वातावरण बना, यह उस वातावरण बनने का एक प्रमाण है। यह हमारे विभाग के लिये बड़ी खुशी और गर्व की बात है।

माननीय सभापतिजी, खेल एक ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे लगता है कि सदन में जितने सदस्य हैं, इस सदन में जितने अधिकारी हैं, सभी लोग बचपन से लेकर बड़े हुए, कुछ न कुछ खेल जरूर खेले होंगे। मुझे यह बताते हुए बड़ा दुःख होता है कि हमारे प्रदेश में और देश में एक बात बड़ी प्रचलित थी। कुछ सदस्यों ने भी उसको बोला। मैं उसको फिर से कहूंगा ताकि हम देखें और सोचें कि खेलों के प्रति अब हमारे नजरिये को बदलने का समय है।

मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटा था और खेल के मैदान पर हम लोग जाना चाहते थे तो हमें कहा जाता था कि पढ़ो-लिखो, कुछ सरकारी नौकरी लग जाएगी, कुछ बन जाओगे, खेल से तो कुछ भी बनने वाले नहीं। एक कहावत थी कि पढ़ोगे-लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे-कूदोगे तो हो जाओगे खराब।

श्री सभापति: आपकी तो इतनी उम्र ही नहीं है।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): ऐसी कहावत सभी लोगों ने सुनी होगी।

(श्री अशोक)

माननीय सभापति महोदय, खेल खेलना रुचि की बात है। कोई मैदान पर खेलता है, कोई दिमाग का खेलता है। भिन्न-भिन्न प्रकार के खेल अपनी-अपनी रुचि के हिसाब से हर व्यक्ति खेलता है।

मैं एक साइंटिफिक बात भी आप लोगों को बताना चाहता हूं, सदन को अवगत कराना चाहता हूं। हालांकि काफी लोग जानते होंगे। खेल-खेलते वक्त, रनिंग करते वक्त, एक्सरसाइज करते वक्त, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि 14-14 साल के बच्चे, 15-15 साल के बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। कई लोग प्रेशर में आकर सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन खिलाड़ी कभी सुसाइड नहीं करता। यह किसी ने सुना नहीं होगा। उसका मुख्य कारण है कि जब एक खिलाड़ी खेल खेलता है तो उसके शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन सीक्रेट होता है। यह हार्मोन स्ट्रैस बर्स्ट करता है, पेन रिलीफ करता है। इसको आम भाषा के अन्दर हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। जो व्यक्ति रोज खेलेगा उसके अन्दर यह हार्मोन सीक्रेट होगा और वह खुश रहेगा। आप और हम किसी भी राजनीतिक ऊंचाई को पा जाएं, किसी भी बड़े पद को पा जाएं, कितना भी पैसा, कितनी भी जमीन पा जाएं, पर अगर हमें खुशी नहीं मिले तो मुझे लगता है कि कुछ भी पाने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। खेलों से यह साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि एंडोर्फिन हमारी बाडी सीक्रेट करती है, जो स्ट्रैस बर्स्ट, पेन रिलीफ और हमें खुशी देने का काम करती है।

इतने इम्पोर्टेण्ट मुद्दे के ऊपर आज हमारे कई साथियों ने बात रखी। कृष्णा पूनियॉ जी ने खेल नीति के बारे में बात की। मैं समझता हूं कि उन्होंने जो सुझाव दिये, वे बड़े महत्वपूर्ण सुझाव थे। खेल नीति तकरीबन कमप्लीट है। उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है। वह काम पूरा करके नई खेल नीति बहुत जल्दी आप सब लोगों के सामने आयेगी, मैं सदन को आश्वस्त कराना चाहता हूं। तकरीबन जो पाइंट्स बड़ी बहन कृष्णाजी ने उठाये, एक खिलाड़ी होने के नाते उनका बड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। उन्होंने बड़े अच्छे पाइंट्स बताये। 90 प्रतिशत उसमें हैं, बाकी मैं निश्चित रूप से आपके बड़े एक्सपीरियंस का और आपसे पर्सनली मिलकर उसका लाभ उठाऊंगा।

एक बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया कि जो स्टार प्लेयर्स हैं, जो अचीवमेंट करने वाले खिलाड़ी हैं, उनके साथ में नये अपकमिंग खिलाड़ियों का इंटरेक्शन का प्रोग्राम होना चाहिए। वह उनके लिए मोटिवेशनल भी होगा और

(श्री अशोक)

वह उनको आगे आने वाले समय में खेलों में उनके सामने क्या चैलेंजेज आने वाले हैं, उनके लिए भी उनको मदद करेगा। इस सुझाव के लिये आपका धन्यवाद। मैं इसको आर्गनाइज करूंगा, बहुत जल्दी हम लोग विभाग की तरफ से इन इंटरेक्शन प्रोग्राम्स को चालू करेंगे।

आपने स्पोर्ट्स इंजरीज और मेडिसिंस के बारे में बात कही। हमारा डिपार्टमेंट इसको लेकर बड़ा चिंतित भी है। हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है भविष्य में, क्योंकि इसमें काम बाकी है। यह एक बड़ा सब्जैक्ट है। अभी हमारे डिपार्टमेंट के पास में साइंस और टैक्नोलोजी का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जो इसको डवलप करने में, इसके ऊपर होमवर्क करने में हमको थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुत जल्दी इस आइडिया को कमप्लीट करके रिहैबिलिटेशन सेन्टर का, जो हमारे अमूल्य खिलाड़ी हैं वे हमारे प्रदेश की धरोहर हैं। वे केवल एक खिलाड़ी नहीं हैं, वे हमारे गर्व का सब्जेक्ट हैं, वे हमारे मान-सम्मान का सब्जेक्ट हैं। एक खिलाड़ी जो हजारों घंटे ट्रेनिंग करके खिलाड़ी बनता है, उसके परिवार के लिए, उसके खुद के लिए तो वह एक गर्व की बात है, लेकिन हमारे प्रदेश का वह एक असेट है। असैट की तरह अगर हम उसको ट्रीट करेंगे, उसको रिहैबिलिटेशन का मौका मिलेगा, उसकी इंजरी को रिकवर करने का मौका मिलेगा, उसको फिजियोथैरेपिस्ट की मदद मिलेगी तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में, जैसे असैट्स की मेंटिनेंस होती है, रिपेयर होती है उसी प्रकार से, खिलाड़ी का मेंटिनेंस, रिपेयर सही समय से हो जाएगा तो आने वाले समय में हमारे प्रदेश के खिलाड़ी कई अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में और ज्यादा मैडल लाकर हमें गौरवान्वित कराएंगे।

कैलाश त्रिवेदीजी, जो खुद वालीबाल के एक राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने भी बड़े अच्छे सुझाव दिये। कोचेज ब्लाक लेवल पर होने चाहिए। निश्चित रूप से हम इसके ऊपर काम कर रहे थे और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 60 से 70 प्रतिशत नये कोच, जो हम संविदा पर लगायेंगे, वे ब्लाक लेवल पर भी अपनी सुविधाएं देंगे। ऐसी हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं। यह नहीं कि केवल जिले पर जाकर बैठ गये। ब्लाक लेवल पर भी उनके हुनर का फायदा ग्रामीण बच्चों को मिले, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले बच्चों को मिले, ऐसी व्यवस्था करेंगे।

(श्री अशोक)

ग्रामीण खेलों के बारे में बताया, यह एक अमूल्य सुझाव था। अभी कुछ विचाराधीन नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि भविष्य में हम इसके ऊपर निश्चित रूप से कोई नीति बनाकर, कोई अच्छा स्ट्रक्चर बनाकर फूलप्रूफ ताकि हमारे जो ग्रामीण खेल हैं, वे हमारी धरोहर हैं। जैसे हमारी ग्रामीण बिल्डिंग्स हैं, ग्रामीण कल्चर है, यह सब हमारी धरोहर है तो ग्रामीण खेल भी हमारी धरोहर है, इस धरोहर को बचाने के लिए, कहीं हम भूल नहीं जायें। आज बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि सभी ज्यादातर खेल, जिनके अन्दर बड़े आर्गनाइजेशंस हमारे देश में होते हैं, वे सब हमने विदेशों से अपनाये हैं। केवल कबड्डी हमारा एक मात्र ऐसा खेल है, जो 31 देश खेलते हैं। कबड्डी हमारा एक मात्र ऐसा खेल है, जो विदेशों में अपनी पहचान बना सका है तो हमारे ग्रामीण खेलों को भी अगर हम बढ़ावा देंगे तो आने वाले समय में उसको अपने इम्पोर्टेंट नोट्स में रखेंगे।

एक बहुत अच्छा सुझाव उन्होंने यह दिया कि ग्रामीण विकास, खेल विभाग और शिक्षा का खेल, शिक्षा का जो खेल विभाग संभालते हैं इनकी एक जोइंट कमेटी बनाकर एक जोइंट प्रोग्राम चलाया जाए, यह बड़ा अच्छा सुझाव है, इसके ऊपर निश्चित रूप से हम लोग काम करेंगे।

मावली से आने वाले माननीय सदस्य आदरणीय श्री धर्मनारायणजी जोशी ने एक बात उठाई कि खेल गांव के अंदर एक स्कूल चल रही है। वह स्कूल खेल गांव की जमीन के ऊपर एक प्राइवेट स्कूल चलाने वाले को किसने दी? इसका खुलासा खेल मंत्री करें, ऐसा उन्होंने कहा। माननीय सभापति महोदय, मैं किसी सरकार के ऊपर छींटाकशी नहीं करना चाहता था लेकिन माननीय सदस्य ने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया कि इस जवाब को देना मेरी मजबूरी हो गयी। इस स्कूल को खेल गांव के अंदर जमीन वर्ष 2004-05 में दी गयी और तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्रीजी के करकमलों से वह काम हुआ तो आपको और हमको सबको यह पता है कि 2004-05 में ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह जो स्कूल चल रहा है, यह अभी 2019 में शुरू हुआ है।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): कोई बात नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह अभी 2019 में शुरू हुआ है। वह केवल आपका कामप्लैक्स ऐसा बना जिसमें देश-विदेश की जितनी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भी कांफ्रेंस हों, उसके लिए बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आपकी इस सरकार के आने के बाद यह मिर्जा नाम का जो विद्यालय है, उसको दे दिया, केवल किराये के लालच में। (व्यवधान)

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): यह 2004-05 में दिया गया है। यू.आई.टी. के द्वारा दिया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): चलो, आपकी बात मान लेते हैं कि 2004-05 में दिया गया तो आप रद्द कर दो, कैंसिल कर दो इसको। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं तो जवाब तो आप पूरा सुनें।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): यह आपका कोई तरीका नहीं है। माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, आपको सुनना पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कैंसिल कर दो न इसको।

श्री सभापति: विराजिये विराजिये।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): मैं आपको जवाब दे रहा हूं। अगर आप कोई सवाल करते हो तो फिर जवाब सुनने का भी माद्दा रखो।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) अगर यह 2004 में दिया है तो यह सदन जो दंड दे, वह मैं स्वयं लेने को तैयार हूं। तय कर लीजिए आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 2004 में दिया है, यह तय कर लीजिए और नहीं तो आपने जो सदन को गलत तथ्य पेश किये हैं, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे या मैं 2004 में वहां का विधायक था, अगर उसमें दिया हो इस स्कूल को तो मैं जिम्मेदार और आप कह रहे हों तो गलत तथ्य, जिसने भी आपको यह कागज पकड़वाया है न, उसको फिर सावधान कर देना, यह बात 2019 की है।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, आप आगे जारी रखिये।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): मैं यह तथ्य भी आपके पास भेज दूंगा ताकि आपकी संतुष्टि हो जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति: आगे बोलिये न आप।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): और आपको किसी प्रकार की सज़ा देना या इस प्रकार का, आप बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, हम सब तो आपके बच्चे बराबर हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं। यह कांग्रेस पार्टी की रीति-नीति का हिस्सा नहीं है कि किसी कारण बात में उलझकर किसी वरिष्ठ माननीय सदस्य का हम ऐसा करें।

श्री सभापति: आप आगे जारी करिये इसको।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): साथ ही उन्होंने एक मुद्दा उठाया, माननीय सभापति महोदय, कि ढाई करोड़ रुपया, मैम्बर बनाकर, ढाई सौ मैम्बर बनाये गये। यह बात बिलकुल सही है कि सवा सौ मैम्बर 2016-17 में बने, 75 हजार रुपये उनसे मैम्बरशिप की फीस ली गयी। महाराणा प्रताप खेल सोसाइटी के नाम पर रजिस्ट्री करवाकर और 2017 के अंदर सवा सौ सदस्य सवा लाख रुपये फीस लेकर बनाये गये। इस प्रकार से यह ढाई करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ और 2016-17 में और 2017-18 में किनकी सरकार थी? अगर इसका भी आप विरोध करते हैं, आप इसका भी चैलेंज करते हैं? कोई बात नहीं लेकिन अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, इसको ज्यादा किसी प्रकार का कोई ...(व्यवधान)

श्री सभापति: वह बात अलग है, यह बात अलग है।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय सभापति महोदय, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि कोई सीनियर खिलाड़ियों का सम्मान नहीं करता। अभी हम लोगों ने स्टेट गेम्स करवाये और इन स्टेट गेम्स के अंदर आजादी के बाद जितने भी खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, उन्हें ओपनिंग के दिन मान-सम्मान दिया गया। कुछ सीनियर लोगों की आंखों में आंसू आ गये और वह बोले कि हमने अपनी सारी जिंदगी खेलों में लगा दी, पहली बार हमारा किसी ने बुलाकर मान सम्मान किया है तो वरिष्ठ खिलाड़ियों का मान-सम्मान करने का काम भी माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोकजी गहलोत के समय में हुआ है यह मैं अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं।

(श्री अशोक)

श्री गणेश घोघराजी और श्री राजकुमारजी रोत ने तीरंदाजी की बात कही, आपने यह बात बिलकुल सही कही। बांसवाड़ा जिले, डूंगरपुर जिले में तीरंदाजी का एक नैचुरल टैलेंट है और निश्चित रूप से आपके जिले में अभी नये उपकरण बहुत जल्दी एक महीने के अंदर खरीदे जाएंगे और उसमें से तीरंदाजी का सामान आप छांट-छांटकर ले जाना, आपको कोई रोकने वाला नहीं है ताकि हमारे ट्राइबल बैल्ट के बच्चे, उनमें 75 परसेंट टैलेंट नैचुरल है, केवल 25 से 30 परसेंट उनकी ट्रेनिंग हो जाए और अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएं, जिनकी एक्यूरेसी अच्छी हो, जिसका रिजल्ट अच्छा हो तो वह बच्चे जैसे लिम्बारामजी ने हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारे ट्राइबल बैल्ट के वह बच्चे भी हमारा नाम रोशन करने का काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, श्री बलवान पूनियांजी ने एक बात कही कि मेरे यहां का एक बच्चा क्रिकेट खेलता है और मैं बलवान पूनियांजी को एक विश्वास और दिलाना चाहता हूं कि मुझे तो यह लगता है कि उनके यहां पर कमेंट्री का बहुत अच्छा टैलेंट है और मुझे यह लगता है कि इस सदन के काफी लोग जिन्होंने अगर उनकी कमेंट्री सुनी है तो वह जरूर मेज बजाएंगे और यह मानेंगे कि उनकी कमेंट्री का टैलेंट बहुत खास है तो निश्चित रूप से अगर कमेंट्री के टैलेंट वाले कोई बच्चे हों तो आप हमारे पास भेजिये, हम उनको ट्रेनिंग करवाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, कुछ बातें आयीं जिनके ऊपर भी मैं जवाब देना चाहता हूं। नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वह स्टेडियम सैंक्शन हो गया। पूर्ववर्ती सरकार ने स्टेडियम सैंक्शन तो कर दिया लेकिन पैसे देकर नहीं गये। हमने अभी इस वर्ष के अंदर आपकी पहली किश्त निकाल दी है और कल मैं आपको लैटर दे दूंगा, पूर्व में जो निकाल दी है।

चूरू जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आर.एस.एस. के ट्रेनिंग कैम्प के अंदर एक्सरसाइज करवायी जाती है। हां, जिला तो चूरू ही है। ट्रेनिंग कैम्प, मैं तो उनसे इतना-सा पूछना चाहता हूं कि क्या कभी आपने वह ट्रेनिंग कैम्प खुद ने अटेंड किया है?

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): हां, किया है।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): किया है?

श्री सभापति: विराजिये विराजिये। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): एक सैकण्ड।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, आप अपनी बात समाप्त करें। ऐसे नहीं। अंकित नहीं होगा, बैठिये आप।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है, मैंने छोटा-सा सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया। ओ.के. थैंक यू। (व्यवधान)

श्री सभापति: क्यों उत्तेजना पैदा करते हो?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): इसमें इतना उत्तेजित होने की क्या बात है?

श्री सभापति: आप अपनी बात को समाप्त करें।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): लेकिन मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि उन कैम्प्स के अंदर छोटे-छोटे बच्चों के हाथ में लाठियां दी जाती हैं। लाठी का प्रयोग या तो भविष्य में मारने के भी काम आ जाती है और या कोई मार रहा है तो उसे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप खेल से संबंधित अपनी बात कहें, आप क्यों उत्तेजना पैदा करते हो?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): यह मेरे कटमोशन में है। यह मेरे कटमोशन में बोला है, साहब।

श्री सभापति: विराजिये विराजिये।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): कोई बात नहीं। उसको ज्यादा नहीं खींचेंगे। मैं खेल पर ही कहना चाहता हूं। भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बोलते-बोलते कुछ बातें अच्छी भी बोलीं और कुछ बातें ऐसी बोलीं कि उनका जवाब भी मुझे देना पड़ रहा है कि ओलम्पिक मैडल की तीन करोड़, दो करोड़, एक करोड़ की राशि कर दी, इससे क्या होता है? यह तो सब बातें हैं। यह बातें नहीं हैं, यह विचार है और यह रोड मैप है।

माननीय सभापति महोदय, यह रोड मैप है, यह टार्गेट है जो उन छोटे-छोटे बच्चों को दिया गया है और मुझे यह विश्वास है कि हमारे राजस्थान में खिलाड़ियों में वह टैलेंट है कि भविष्य में बहुत सारे ओलम्पिक में गोल्ड मैडल भी लेंगे, सिल्वर मैडल भी लेंगे और यह रोड मैप जो आज तीन करोड़, दो

(श्री अशोक)

करोड़ और एक करोड़ है, इसको प्राप्त करके आगे खेलों का वातावरण बनेगा। उन्होंने यह भी कहा कि खेल विभाग तो केवल क्रिकेट को ही सपोर्ट करता रहता है। मैं उनकी जानकारी के लिये बता दूं कि क्रिकेट एक आटोनोमस बाडी है, वह खेल विभाग से किसी प्रकार का पैसा नहीं लेती है। उलटा, माननीय सभापति महोदय, सालाना 50 लाख रुपये खेल विभाग को दूसरे खेलों को चलाने के लिये देती है। यह मैं उनकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं और हमारे राजस्थान में बहुत सारे खेल विभाग के स्टेडियम हैं उनके साथ एम.ओ.यू. कोई आज नया नहीं हुआ है, सरकार किसी की भी आयी, 17-18 साल से उनके साथ एम.ओ.यू. होता आ रहा है, लेकिन जिनके बारे में कुछ चर्चाएं चलीं और जब सब खड़े हो गये तब बात को ठंडा करना पड़ा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा।

श्री सभापति: हां, मत जाइए आप उसमें।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): लेकिन उनके जमाने में जब पूर्ववर्ती सरकारों का राज था, तब उस खेल स्टेडियम के बदले में, एम.ओ.यू. के बदले में एक फूटी कौड़ी खेल विभाग को नहीं दी। मैं बड़े गर्व के साथ बता देना चाहता हूं कि इस एक साल के अंदर एक करोड़ 90 लाख रुपये वही क्रिकेट वाले, जिनको यह कोस रहे थे, वह हमको दे चुके हैं और सालाना तकरीबन दो से तीन करोड़ रुपये हम उनसे लेंगे और आने वाले समय में उस पैसे को दूसरे खेलों के उद्धार के लिए लगाएंगे ताकि क्रिकेट का जो पूरी दुनिया के अंदर नाम है, उसका फायदा और खेलों को मिल सके। इसके ऊपर मैं दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा-

'नजर को बदलो नजारे बदल जाते हैं
सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं
कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है
दिशा को बदलो, किनारे खुद बदल जाते हैं।।'

किसी ने यह कहा है, पर मुझे पता नहीं किसने कहा, लेकिन अच्छा कहा है इसलिए मैंने यहां पर बता दिया।

माननीय सभापति महोदय, अभी तक तो माननीय सदस्यों ने जो बातें उठायीं ..(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, विराजिए आप। समाप्त करने दीजिए आप उनको। बीच में इंटरवीन मत कीजिए। हां, माननीय मंत्री महोदय, समाप्त करें।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय सभापति महोदय, अभी तो 7.30 बजे हैं, कोई बात नहीं, आपके आदेश की पालना करूंगा और जल्दी ही अपनी बात को समाप्त करूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: क्या वह बोल नहीं सकते क्या? आप बार-बार उनको सलाह दे रहे हैं, क्या वह बोल नहीं सकते? बोल सकते हैं तो बोलने दीजिए उनको। क्यों आप बार-बार में सलाह दे रहे हो? वह अच्छा बोल रहे हैं।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): मैं सदन के सामने बताना चाहता हूं कि इस एक साल में खेल विभाग ने क्या किया? यह जो वातावरण बना है, उसके नीचे नींव के पत्थर क्या हैं, वह स्तम्भ क्या हैं? पहला स्तम्भ है 2 प्रतिशत सरकारी नौकरियों के कानून में अमैंडमेंट। आदरणीय सभापति महोदय, आज से पहले केवल इंडिया लिखी हुई जर्सी वाले बच्चों को तो नौकरी मिलती थी और मैडल लेने वाले बच्चों को नौकरी मिलती थी, लेकिन जिस जर्सी के ऊपर राजस्थान लिखा रहता था, उसके लिए कोई नौकरी का प्रावधान नहीं था। यह पहली सरकार है, अशोक गहलोतजी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है कि जिसने जर्सी के पीछे राजस्थान लिखा होगा, उन बच्चों को भी इसके अंदर क्वालिफाई कराया है। साथ ही साथ, पैरा के हमारे खिलाड़ी, जिनके साथ कुदरत ने कोई नाइंसाफी कर दी हो, लेकिन मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और उनके संघर्ष के जज्बे को सलाम करता हूं कि वह दुनिया में बड़ेबड़े मैडल लेकर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। उन खिलाड़ियों को भी हमने इसमें सम्मिलित किया है।

माननीय सभापति महोदय, पूर्व में 52 विभागों के अंदर यह 2 प्रतिशत नौकरी मिलती थी, हमने इसको बढ़ाकर 56 विभाग कर दिये हैं। माननीय सभापति महोदय, स्कूल नेशनल के और यूनिवर्सिटी नेशनल के बच्चे, जो मैडल जीतते हैं, उन्हें भविष्य में प्रदेश की असैट्स मानते हुए स्कूल नेशनल और यूनिवर्सिटी नेशनल के बच्चों को भी इन दो प्रतिशत नौकरी के अंदर हम लोगों ने इनक्लूड किया है ताकि वह 18 साल के होते ही उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी हो जाए तो 10-12 साल वह अपने गेम को और

(श्री अशोक)

परस्यू करे और सेफ रहकर इस गेम को परस्यू करेंगे तो आने वाले समय में राजस्थान का मान-सम्मान अद्वितीय रूप से बढ़ा देंगे पूरी दुनिया के अंदर और पूरे देश के अंदर।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का धन्यवाद देना चाहता हूं कि कई माननीय सदस्यों ने स्टेट गेम्स के लिये हमें बधाई दी और यही सही तरीका है कि जब कोई अच्छा काम हो तो उसकी बड़ाई होनी भी चाहिए। 02 से 06 जनवरी को हमने 18 खेलों के स्टेट गेम्स कराये। माननीय सभापति महोदय, मुझे यह बताते हुए गर्व है कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हमारे सभी साथियों की उसमें मेहनत है, मैं अकेला कुछ नहीं हूं। मुझे यह बताते हुए गर्व है कि राजस्थान भारत में पहला प्रदेश बना है जो स्टेट गेम्स करा पाया है। इसके अंदर 3,500 बालिकाएं और 4,500 बालक और एक हजार से ऊपर आफिसर्स ने भाग लिया और इसका रिजल्ट क्या रहा कि इसके पांच दिन बाद ही खेलो इंडिया का आयोजन हुआ तो उस आयोजन के अंदर पूर्व में राजस्थान को 44 पदक मिले थे, वह संख्या बढ़कर 51 पदक हो गयी और संख्या तो बढ़ी ही बढ़ी, माननीय सभापति महोदय, गोल्ड और सिल्वर मैडल की संख्या डेढ़ गुणा बढ़ी। इसका मतलब कि क्वालिटी के साथ इम्प्रूवमेंट। जो पहले रजत लाये थे वह गोल्ड लेकर आये। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ज्यादा हुआ इन स्टेट गेम्स की वजह से।

माननीय सभापति महोदय, इस साल खेलों को बढ़ावा देने के लिए आपने देखा कि ऐतिहासिक घोषणा हुई। हर व्यक्ति हमसे कहता था। मैं एक साल से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं कि हरियाणा में ऐसा होता है मध्य प्रदेश में ऐसा होता है, उड़ीसा में ऐसा होता है, महाराष्ट्र में वैसा होता है, उनकी तर्ज पर कोई काम क्यों नहीं करते? पहली बार, माननीय सभापति महोदय, ओलम्पिक के स्वर्ण पदक जीतने पर, जो पूर्व में हमारे यहां राशि 75 लाख होती थी, उसको बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये किया गया, रजत पदक की राशि, जो 50 लाख होती थी, उसको बढ़ाकर 2 करोड़ किया गया और कांस्य पदक की राशि 30 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ कर दी गयी और राजस्थान को इस राशि के अंदर हरियाणा की टक्कर में खड़ा कर दिया। इससे ज्यादा राशि पूरे देश में किसी भी राज्य में नहीं है। यह हमारे प्रदेश के लिए बड़े मान-सम्मान की बात है, गौरव की बात है।

(श्री अशोक)

माननीय सभापति महोदय, एशियाड के अंदर और कामनवैल्थ गेम्स के अंदर स्वर्ण पदक की 30 लाख की राशि को बढ़ाकर एक करोड़ किया गया, रजत पदक की 20 लाख की राशि को बढ़ाकर 60 लाख किया गया और कांस्य पदक की राशि 10 लाख को बढ़ाकर 30 लाख किया गया।

माननीय सभापति महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने बच्चों के ट्रेवलिंग, रहने और खाने की सुविधा के ऊपर भी खेद जताया। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि 'साल एक फैसले अनेक' वाली यह जो हमारी सरकार है, इन्हें एक-एक तिनके का पता है, बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। माननीय सभापति महोदय, पूरे राजस्थान से आठ हजार बच्चे आये, 90 प्रतिशत बच्चे ग्रामीण परिवेश के थे। हमें बड़ी टेंशन थी, हमको यह चिंता खाये जा रही थी कि 3,500 बच्चियां हैं, 4,500 बच्चे हैं, सब यूथ हैं, अंडर 23 हैं। कहीं कोई ऐसी बात नहीं हो जाए, अच्छा कार्यक्रम कराते-कराते कोई बात नहीं हो जाए। हमारे खेल विभाग ने इतना अच्छा आयोजन किया, सभी अधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक छोटी-सी घटना, चाहे वह सेफ्टी सिक्योरिटी से लेकर हो, चाहे वह रहने-खाने से लेकर हो, चाहे किसी प्रकार के रिजल्ट या आयोजन में किसी प्रकार का विवाद हो, एक प्रतिशत भी उसके अंदर सिंगल शिकायत नहीं आयी। साथ ही साथ जो खेल संघ हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसी को देखते हुए हमारे मुख्य मंत्रीजी ने बजट में राष्ट्रीय स्तर की 500 रुपये की प्रतिदिन की राशि को बढ़ाकर एक हजार किया और राज्य स्तर की 300 रुपये की राशि को बढ़ाकर 600 किया गया। इस राशि को दुगुना कर दिया गया ताकि आने वाले समय में बच्चों को टी.ए., डी.ए., रहने और खाने की कोई समस्या नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, गुरु बिना कुछ भी संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति खिलाड़ी बनता है, एक छोटा बच्चा तो कच्ची मिट्टी के बराबर है। उस गीली मिट्टी को कोई घड़ा बना सकता है, कोई खिलौना बना सकता है, कोई उससे ईंट बना सकता है, तो उसको बनाना क्या है, यह गुरु के हाथ में होता है और गुरु बिना शिष्य का कोई मोल नहीं होता है।

सभापति महोदय, बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण मिले, उसके लिए पिछले बजट में जो कि 6 महीने पहले ही आया था, कई बार कहते हैं कि बजट की

(श्री अशोक)

घोषणा थी आपका काम नहीं हुआ, 6 महीने पहले आया था, एक साल का भी समय नहीं मिला, मगर ठीक है, आंकड़ों से खेलना हो, जादूगरी की बात करनी हो तो भी कोई बात नहीं। उससे पूर्व में कोचेज लगाने का साल के तीन करोड़ रुपये का बजट था, पिछले बजट में तीन से पांच किया और इस बजट में सीधा पांच से दस कर दिया ताकि राजस्थान के खिलाड़ियों को, बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण मिल सके, ज्यादा से ज्यादा गुरु उपलब्ध हों और उन बच्चों का, खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके, इसके तहत 500 खेल प्रशिक्षक आने वाले साल में लगेंगे।

इसके अलावा आपने देखा कि मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की शनिवार को नो बैग डे की, छोटे-छोटे बच्चों के चेहरों पर आप मुस्कान देखो, अब शनिवार को जाते हैं तो खुश होकर जाते हैं, उस मुस्कान का कोई मोल नहीं है। सभापति जी, दुआएं लगेंगी और आने वाले समय में इसका रिजल्ट भी देखेंगे। (व्यवधान) उनकी भी बात करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक ऐतिहासिक फैसला है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसी बजट में घोषणा की है, स्टेडियम, खेल मैदान, क्रीड़ा संकुल के लिए यदि कोई निजी संस्था उनको बढ़ावा देगी तो उसके लिए भू उपयोग परिवर्तन शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया गया है ताकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आएं और खेलों के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, हमारे प्रदेश के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खेलने की अपॉर्चुनिटी मिले और हमारे यहां पर खिलाड़ी तैयार हों। यह ऐतिहासिक फैसला होगा, माननीय सभापति महोदय, कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को यह भू-परिवर्तन, कहने को तो परिवर्तन लगता है लेकिन बुखार आ जाता है परिवर्तन के नाम से।

कुछ माननीय सदस्य बड़े जोर-शोर से कह रहे थे कि खेलो इंडिया से यह हो गया, खेलो इंडिया से वह हो गया, निश्चित रूप से खेलो इंडिया से, जो खेलो इंडिया का आयोजन है, टूर्नामेंट तो बहुत शानदार है, माननीय सभापति महोदय, और मैं उसकी बिलकुल बड़ाई करने में कमी नहीं रखूंगा, बहुत अच्छा आयोजन है लेकिन मानसिकता देखिये कि 2017-18 में विकास कार्य हेतु 51 करोड़ 90 लाख रुपये केन्द्र सरकार ने जारी किये और 2018-19 में प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार आई तो जीरो स्वीकृति आई और 2019-20 में मात्र 7 करोड़ 98 लाख रुपये की स्वीकृति आई, यह 2 साल में जीरो और 7.98 करोड़ जहां कि उससे जस्ट पहले वाले साल में 51 करोड़ 90 लाख थी।

(श्री अशोक)

कुछ हमारे साथियों ने कहा कि खेलों को तो राजनीति से दूर रखना चाहिए तो मैं यह मानता हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन विपक्ष में बैठे हमारे जो सदस्य हैं, जिनकी केन्द्र में सरकार है, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप सच्चे खेल प्रेमी हैं और यदि आज सदन में आपने जो कुछ कहा, वह दर्द खिलाड़ियों के लिए आपके दिल में है तो इस राशि को जीरो से और सात-आठ करोड़ से बढ़ाकर केन्द्र सरकार से, आपके नेताओं से आप बात करें, मुझे चलना होगा तो मैं खुद चलूंगा, प्रपोजल्स हमारे पास में तैयार हैं, इसको वापस बढ़ाकर कम से कम पूर्व के बराबर 52 करोड़ तो किया जाए। यह मैं आशा करता हूं कि आप इसमें हमारा सहयोग करेंगे और प्रदेश के भले के लिए यदि यह काम करना पड़े तो मुझे लगता है कि आपको किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी।

श्री सभापति: समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): बस हो गया, साहब, ज्यादा नहीं बचा।

माननीय सभापति महोदय, यूथ होस्टल की बात भी आई, निश्चित रूप से यूथ होस्टल का फायदा हमारे प्रदेश के यूथ को मिलता है। राजस्थान में 4 जिलों में यूथ होस्टल संचालित हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर। यूथ होस्टल की जमीन तो प्रदेश सरकार आबंटित करती है लेकिन आज तक जो भी यूथ होस्टल बने हैं, उनका पैसा केन्द्र सरकार ने ही दिया है, ऐसी प्रथा चलती आ रही है। 2012-13 में हमारी सरकार ने 9 जिलों में यूथ होस्टल के लिए जमीन आबंटन की उसके बाद हमारी केंद्र से सरकार चली गई। माननीय सभापति महोदय, इन 6 सालों में इन नौ में से एक भी यूथ होस्टल का पैसा केन्द्र से हमारे पास में नहीं आया। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे मुझे आगे मदद नहीं मिले, मैं तो विपक्ष के जो हमारे साथी और वरिष्ठ नेता हैं, उनसे एक बच्चे के रूप में आग्रह करूंगा कि मैं आपके साथ चलूंगा, आप मेरे साथ चलें और ये यूथ हास्टल भी केन्द्र सरकार से हमें दिलाएं ताकि आने वाले समय में राजस्थान के युवाओं का भविष्य उज्ज्वल हो।

सभापति महोदय, मैं एक विशेष बात करना चाहता हूं। बहुत साथियों ने यह कहा कि पूर्व में 70 लाख का बजट था अब 50 लाख है, यह 70 लाख से 50 लाख से क्या होगा? यह बिल्कुल सही बात है, अगर ऐसे सुनें तो 70

(श्री अशोक)

लाख, 50 लाख से कुछ भी नहीं होगा, प्रदेश बहुत बड़ा है, करोड़ों में जनसंख्या है, लेकिन मुझे यह बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव उत्तर प्रदेश, लखनऊ में अभी 12 से 16 जनवरी में हुआ, 88 सदस्य दल हमारे राजस्थान से गया, 18 सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं हुईं जिसमें पूरे देश से बच्चे आये थे, युवा आये थे, 18 में से 9 प्रतियोगिताओं में राजस्थान के युवाओं ने पदक हासिल किया। माननीय सभापति महोदय, यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। बिना साधन के भी हमारा डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के कर्मचारी साथी किस प्रकार से लगे हुए हैं, यह उसका एक जीता जागता उदाहरण है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात को खतम करता हूं। सभापति महोदय, क्योंकि जब हम इस साल के बजट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं लेकिन अगर हम भविष्य का एक रोड मैप अभी से तैयार नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि बजट किसके लिए मांगेंगे। जब हमारे पास में प्रोजेक्ट्स तैयार होंगे, नीतियां तैयार होंगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान के खेलों का ये जो बजट में पीछे रहा है, आगे बढ़ जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, खेल नीति की बात मैंने पूर्व में बतायी कि बहुत जल्दी खेल नीति में जो संशोधन करने हैं, बहुत छोटे संशोधन हैं उन्हें करके, हालांकि अच्छा संशोधन करने के लिए विरोध भी हो सकता है लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं। खिलाड़ियों का भला होना चाहिए, ऐसा संशोधन करके हम लाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में मैंने माननीय सदस्य का जवाब देते हुए बताया कि हमारा इसके ऊपर होमवर्क चल रहा है, यह एक साइंस का सब्जैक्ट है और यह बड़ा इम्पोर्टेंट और क्रूशियल सब्जैक्ट है, इस पर ज्यादा जल्दबाजी करने से हम एक अपंग सैटअप तैयार नहीं करना चाहते, हम भविष्य में एक अच्छा रिहैबिलिटेशन सेंटर तैयार करना चाहते हैं, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं।

आज के जो मुझे सुझाव मिले उन सुझावों से जो सहाड़ा, रायपुर से आने वाले आदरणीय माननीय सदस्य, जिन्होंने खुद राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। आने वाले समय में राजस्थान के खिलाड़ियों की टैक्निक को सुधारने के लिए जूनियर कैम्प्स आयोजित करेंगे ताकि बचपन

(श्री अशोक)

में जब बच्चा खेलना सीखता है तभी अगर उसकी टैक्निक फुलप्रूफ हो जाएगी, चाहे खेल कोई-सा भी होगा तो भविष्य में जाकर उस खिलाड़ी को कभी समस्या नहीं आएगी, उसको इंजरी नहीं होगी और उसका फुल आउटकम निकलेगा, उसकी मेहनत का पूरा नतीजा निकलेगा, ऐसे कैम्प्स भविष्य में आयोजित करवाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, हम स्पेशल बैचेज बनाएंगे। एशियाड, कामनवैल्थ, ओलंपिक के जो टूर्नामेंट आने वाले हैं उसमें वे कौन से बच्चे हैं कि जिनके ऊपर थोड़ा-सा भविष्य में फिनिशिंग का काम किया जाएं, स्ट्रेंथनिंग का काम किया जाए, टैक्निक इम्प्रूवमेंट का काम किया जाए या मोटिवेशन का काम किया जाए कि वो उस मैडल के आसपास पहुंच जाएं या मैडल लेकर आ जाएं, उनके लिए हम स्पेशल बैचेज बनाएंगे उनका विशेष ध्यान रखकर ताकि आने वाले समय में उस बैच के बच्चे उन प्रतियोगिता के अन्दर मैडल जीतें और ये इनाम राशि लेकर हमें गौरवान्वित महसूस कराएं।

माननीय सभापति महोदय, स्पोर्ट स्कूल के ऊपर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। इस साल हम इसका काम पूरा करके बहुत जल्दी स्पोर्ट स्कूल, सभापति महोदय, क्योंकि खिलाड़ी कोई भी खेल खेले, उस खेल की पर्टिकूलर मसल्स होती हैं। यदि वह मसल्स उसकी स्ट्रांग हैं तो वह खिलाड़ी उस खेल में अच्छा परफार्म करेगा। हर खेल की सपोर्टिंग मसल्स भी होती हैं। यदि सपोर्टिंग मसल्स उसकी स्ट्रांग हैं तो उस खेल में उसका आप्टिमम रिजल्ट आएगा। लेकिन मसल्स मेकिंग का काम कब होता है? यह 9 साल से लेकर के 17 साल तक होता है। हम ध्यान कब देते हैं? हम 18-20 साल के बाद ध्यान देते हैं। 20-22 साल में तो 90 प्रतिशत खेलों में खिलाड़ी पीक कर जाते हैं। 24, 25 और 26 की उम्र के बाद में ढलान पर आ जाते हैं।

सभापति महोदय, जब बोन्स स्ट्रक्चर बन रहा है, मसल्स स्ट्रक्चर बन रहा है, मसल्स क्वालिटी डवलप हो रही है, स्किन क्वालिटी डवलप हो रही है, वह उम्र 8 से 18 है। भविष्य में हमारे प्रदेश में स्पोर्ट्स स्कूल हों ताकि 8-9 साल की उम्र में बच्चा स्पेश्लाइज्ड स्कूल के अंदर आ जाए। उसका करिकुलम भी स्पोर्ट्स सपोर्टिव होना चाहिए। यदि एक बच्चे को 7 घंटे पढ़ाएंगे, 3 घंटे ट्यूशन पढ़ाएंगे तो 10 घंटे वह एजुकेशन लेगा। वह एकेडमिक में तो अच्छा कर सकता है, लेकिन खेलों में अच्छा नहीं कर सकता। खेलों के हिसाब से उसका करिकुलम बने। ऐसी व्यवस्था हम लोग भविष्य में लेकर आएंगे।

(श्री अशोक)

सभापति महोदय, बहुत जल्दी ही एक नीति हम लाने वाले हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा और भोले शंकर की कृपा रही तो इस सदन के चलते-चलते उस पर प्रेस कांफ्रेंस कर देंगे।

राजगढ़ विधान सभा से आने वाली माननीय सदस्य ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हरियाणा में तो खिलाड़ी मैडल जीतते ही डीवाईएसपी बन जाता है, बड़े-बड़े पदों पर बैठ जाता है। यह बिलकुल सही बात है। इसके ऊपर इस 6-8 महीनों में हमारे डिपार्टमेंट के सब लोगों ने, अधिकारियों ने बात की। दूसरे डिपार्टमेंट से भी हमें सपोर्ट मिला। बड़ी चर्चा हुई। पालिसी तैयार हुई। उसके सारे बिन्दु तो अभी नहीं बता सकता। वह तो पालिसी बन जाए उसके बाद की बात है, लेकिन वह बहुत जल्दी ही आपके सामने आएगी कि हमारे खिलाड़ी जो अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एशियाड में, कामनवैल्थ में, ओलंपिक्स में मैडल जीतते हैं, उनको सीधी नौकरी देने का प्रावधान किया जाए। यह नीति वैसे तो आउट आफ टर्म के नाम से 2016 में आ गई थी। लेकिन एक ऐसी नीति पूर्ववर्ती सरकार ने बना दी कि 2016 से अभी तक एक सिंगल खिलाड़ी को उसके अंदर नौकरी नहीं मिली है। ऐसा कागज का पुलिंदा क्यों बनाना कि जिसमें खिलाड़ी को कोई फायदा नहीं हो। मैं तो पूछना चाहता हूं कि क्यों ऐसी फाइल तैयार की? हमने उसमें अमेंडमेंट्स किए हैं। मैं इस सदन में दावा कर रहा हूं कि अमेंडमेंट होकर 10 से 15 दिन के अंदर, जिस दिन वह रिलीज होगी, उस दिन मैं 10-12 खिलाड़ी खड़े कर दूंगा, जो कि सीधा नौकरी हासिल करने के लायक होंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार केवल सपने नहीं दिखाती है, उन्हें पूरा करने का माद्दा रखती है।

सभापति महोदय, एक और विशेष प्रावधान हमने उसमें किया है कि राजस्थान के खिलाड़ी को पहले तो हम अन्तरराष्ट्रीय मैडल जीतने पर सिर पर चढ़ा देते हैं, उसका इतना मान-सम्मान करते हैं, लेकिन फिर वह नौकरी के लिए किसी दफ्तर में भागा-भागा फिरता है। अब उसको बिना वैकेंसी के, वह जो डिजर्विंग पोस्ट होगी, वह उसको मिलेगी। जब वैकेंसी आएगी तो उसको प्री कंज्यूम्ड मान लिया जाएगा। ऐसी पालिसी राजस्थान सरकार बना रही है। यह देश में पहली पालिसी होगी। दूसरे प्रदेश इस पालिसी को लेकर जाएंगे, यह मैं आपको बताना चाहता हूं।

(श्री अशोक)

सभापति महोदय, यूथ बोर्ड के अंदर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के मुकाबले पैसा कम है लेकिन पैसों से ही सारा काम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जिनके पास सुविधाएं हैं, वही सब कुछ करते हैं। बिना सुविधाएं वाले भी दुनिया में आगे निकलते हैं। इसके ऊपर केवल दो लाइन कहकर अपनी बात को समाप्त करुंगा।

'मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है

पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है'।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि मांग संख्या 24 पारित की जाए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की अनुदान की मांगें पारित होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय अनुदान की मांगें पारित होने तक बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय अनुदान की मांगें पारित होने तक बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग का पारण

मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24- शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,30,98,13,71,000/- (तीन सौ तीस अरब अठानवे करोड़ तेरह लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 11 विविध सामाजिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11- विविध सामाजिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 62,48,85,000/- (बासठ करोड़ अड़तालीस लाख पिचासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 04 मार्च 2020 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 19.56 बजे बुधवार, दिनांक 04 मार्च 2020 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बस्सी की ग्राम पंचायतों में स्वीकृत कार्य

277. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में विगत पांच वर्ष में किस-किस ग्राम पंचायत में किस-किस योजना के अन्तर्गत कितनी राशि के क्या-क्या कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण करवा लिये गये हैं? यदि नहीं, तो कौन-कौन से कार्य किस-किस कारण से अपूर्ण हैं तथा उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में विगत पांच वर्षों में (वर्ष 2015-16 से 2019-20) तक कराये गये कार्यों का ग्राम पंचायतवार, योजनावार एवं स्वीकृत राशि तथा व्यय का विवरण परिशिष्ट-1 (पंचायत समिति बस्सी की ग्राम पंचायतों का) व परिशिष्ट-2 (पंचायत समिति चाकसू की ग्राम पंचायतों का) पर संलग्न है।

(2) सभी स्वीकृत कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। कुल स्वीकृत 4723 कार्यों में से 3179 कार्य पूर्ण हुए हैं, 1285 कार्य प्रगतिरत, 258 कार्य अप्रारम्भ व 1 कार्य निरस्त किया गया है।

स्वीकृत कार्यों में से अपूर्ण/अप्रारम्भ कार्यों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट-1 व 2 में अंकित है।

कार्यों के अपूर्ण रहने के मुख्य कारण स्थानीय विवाद, महात्मा गांधी नरेगा व अन्य योजनाओं में राशि प्राप्ति में विलम्ब होना, संवेदक (ठेकेदार) द्वारा निर्माण सामग्री की आपूर्ति में विलम्ब करना, ग्राम पंचायत द्वारा कार्य पूर्ण करने में विलम्ब करना एवं व्यक्तिगत लाभ के कार्यों में लाभार्थी द्वारा अपनी सुविधा अनुसार कार्य करना आदि है।

उक्त अपूर्ण कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराने हेतु विभाग द्वारा निर्देश दे दिये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

केन्द्रीय योजना आयोग से राज्य को स्वीकृत राशि

285. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2013 से 31 जनवरी, 2020 तक केन्द्रीय योजना आयोग से राज्य को किस-किस योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? वर्षवार एवं योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई उक्त राशि में से राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि किस-किस योजना में व्यय की गई? वर्षवार, योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 में 60.00 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2014-15 में 73.00 करोड़ रुपये राज्य को एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता राशि के रूप में स्वीकृत किये गये, जिसका वर्षवार एवं योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

वर्ष 2014-15 के पश्चात् केन्द्रीय योजना आयोग से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

(2) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 में योजना आयोग द्वारा स्वीकृत राशि में से 37.31 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2014-15 में स्वीकृत राशि में से 73.00 करोड़ रुपये का व्यय किया गया, जिसका वर्षवार व योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर, जोधपुर व अजमेर कमिश्नरेट में महिलाओं के साथ लूटपाट की घटनाएं

304. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जयपुर, जोधपुर व अजमेर कमिश्नरेट के अधीन क्षेत्रों में जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2020 तक महिलाओं की चेन स्नेचिंग, लूटपाट, बच्चों व बालिकाओं के अपहरण की कितनी घटनाएं घटित हुई तथा कितनों को मौके पर गिरफ्तार किया गया व न्यायालय में कितने प्रकरणों में चालान पेश किया गया? प्रकरणवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जयपुर जोधपुर व अजमेर जिला के अधीन क्षेत्रों में जनवरी 2019 से 31 जनवरी, 2020 तक महिलाओं की चेन स्नेचिंग के 278, लूटपाट के 317, बच्चों/बालिकाओं के अपहरण के 1123 कुल 1718 प्रकरण दर्ज हुए। उक्त प्रकरणों में कुल 825 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से मौके पर 108 को गिरफ्तार किया गया है। 432 प्रकरणों में संबंधित न्यायालयों में चालान पेश किया गया। मदवार प्रकरणों की सूचना 'अ' 'ब' एवं 'स' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शासन सचिवालय व अधीनस्थ कार्यालयों में शीघ्रलिपिकों के रिक्त पद

305. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में शासन सचिवालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में वर्तमान में शीघ्रलिपिकों के कितने-कितने पद कहां-कहां पर कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2018 में सरकार द्वारा शीघ्रलिपिक के पदों हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी? यदि हां, तो कितने पदों की और कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्मल कुमावत)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है अथवा भर्ती स्थगित कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार शीघ्रलिपिक के पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शीघ्रलिपिक भर्ती परीक्षा वर्ष 2011 के पश्चात् शासन सचिवालय में 77 पद, राजस्थान लोक सेवा आयोग में 05 पद वर्तमान में शीघ्रलिपिकों के रिक्त हैं तथा प्रशासनिक सुधार (ग्रुप 3) विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर अधीनस्थ कार्यालयों में शीघ्रलिपिकों के रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा विज्ञापन संख्या 13/2018 दिनांक 04-07-2018 द्वारा शीघ्रलिपिकों के कुल 1085 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी है।

(3) जी नहीं।

(4) शासन सचिवालय एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा शीघ्रलिपिकों की भर्ती हेतु प्रेषित अर्थना बोर्ड स्तर पर प्रक्रियाधीन है तथा अधीनस्थ कार्यालयों में शीघ्रलिपिकों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा बोर्ड को प्रेषित की जाने वाली अर्थना प्रक्रियाधीन है, जिस पर प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा कार्यवाही की जानी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कर्मचारियों को केन्द्र के समान वेतनमान देने की कार्ययोजना

306. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में राज्य कर्मचारियों को केन्द्र के समान वेतनमान देने का प्रावधान है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या केन्द्र के सातवें वेतन आयोग में ग्रेड पे 2400 के लिये पे मेट्रिक्स 25500–81100 तथा ग्रेड पे 2800 के लिये पे मेट्रिक्स 29200–

(श्री शंकर सिंह रावत)

92300 निर्धारित की गई है? यदि हां, तो प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिये ग्रेड पे 2400 व 2800 को क्रमश: L-5, L-6, L-7 व L-8, L-9 में क्यों विभाजित कर दिया गया है? यहां तक कि ग्रेड पे 2400 के लिये अधिकतम पे मेट्रिक्स L-7 (22400–71200) तथा ग्रेड पे 2800 के लिये अधिकतम पे मेट्रिक्स L-9 (28700–91300) केन्द्र की पे मेट्रिक्स से कम रखी गयी है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ग्रेड पे 2400 व 2800 के कर्मचारियों के लिये केन्द्र के समान वेतनमान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जी हां। केन्द्र में ग्रेड-पे 2400 के लिये पे-मेट्रिक्स 25500-81110 तथा ग्रेड-पे 2800 के लिए पे-मेट्रिक्स 29200-92300 निर्धारित है।

प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिए राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 (छठा वेतन आयोग) में दिनांक 01-01-2006 से निर्धारित ग्रेड-पे 1900, 2000, 2100, ग्रेड-पे 2400 एवं 2800 को दिनांक 01-07-2013 से बढ़ाकर क्रमश: ग्रेड-पे 2400 (ग्रेड-पे संख्या 9), ग्रेड-पे 2400 (ग्रेड-पे संख्या 9 ए), ग्रेड-पे 2400 (ग्रेड-पे संख्या 9 बी), ग्रेड-पे 2800 (ग्रेड-पे संख्या 10) एवं ग्रेड-पे 2800 (ग्रेड-पे संख्या 10 ए) निर्धारित की गई है।

उक्त ग्रेड-पे के आधार पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 (सातवां वेतन आयोग) में ग्रेड-पे के पारस्परिक लेवल क्रमशः एल-5, एल-6, एल-7, एल-8 एवं एल-9 निर्धारित किये गये हैं।

राज्य में ग्रेड-पे 2400 के लिए अधिकतम पे-मेट्रिक्स एल-7 22400-71200 तथा ग्रेड-पे 2800 के लिए अधिकतम पे-मेट्रिक्स एल-9 28700-91300 निर्धारित है क्योंकि राज्य एवं केन्द्र के विभागों एवं पदों में समानता नहीं होने के कारण वेतनमान भी भिन्न हैं।

राज्य में विभिन्न लेवल हेतु निर्धारित पे-मेट्रिक्स, केन्द्रीय सातवें वेतन आयोग द्वारा छठे वेतन आयोग में विभिन्न ग्रेड-पे हेतु निर्धारित एन्ट्री-पे को आधार मानकर पे-मेट्रिक्स तैयार करने हेतु निर्धारित किये गये मापदण्डों के अनुसार तैयार की गई है।

(3) जी नहीं। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झोटवाड़ा ग्राम (जयपुर) में दर्ज प्रकरणों की पुन: जांच

307. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जयपुर के थाना झोटवाड़ा में दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 16/13, 306/17, 196/18, 632/19, 640/19, 641/19 व 716/2019 में किस-किस अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया? जांच अधिकारी का नाम व पदनाम सहित जांच रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अधिकारियों का थाना झोटवाड़ा में पदस्थापन कब से कब रहा तथा पदस्थापन काल में खण्ड (1) में अंकित एफ.आई.आर. के अतिरिक्त उन्हें किन-किन प्रकरणों में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार खण्ड (1) में अंकित एफ.आई.आर. में जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्टों की जांच अन्य उच्च अधिकारी से कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर आयुक्तालय के थाना झोटवाड़ा जयपुर (पश्चिम) में दर्ज एफ.आई.आर. 16/13, 306/17, 196/18, 632/19, 640/19, 641/19 व 716/2019 में नियुक्त जांच अधिकारियों का नाम एवं पदनाम सहित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त अधिकारियों का थाना झोटवाड़ा जयपुर (पश्चिम) में पदस्थापन का विवरण एवं खण्ड (1) में अंकित एफ.आई.आर. के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में जांच अधिकारी नियुक्ति का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। खण्ड (1) में अंकित एफ.आई.आर. में जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्टों की जांच अन्य उच्च अधिकारी से कराये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

खण्ड (1) में अंकित एफ.आई.आर. की जांच अन्य उच्चाधिकारी से नहीं करवाये जाने के संबंध में विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नदबई के सड़क से वंचित गांव

308. श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र नदबई में ऐसे कितने राजस्व गांव हैं जो सड़क से जुड़ने से वंचित हैं? क्या सरकार उक्त वंचित गांवों को सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र नदबई में 18 राजस्व गांव डामर सड़क से वंचित हैं। बजट घोषणा 2019-20 के अनुसार जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर 500 या 500 से अधिक आबादी के गांवों को आगामी चार वर्षों में चरणबद्ध तरीके से सड़क से जोडा जायेगा।

500 से कम आबादी के गांवों को डामर स़ड़क से जोड़ना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भोपालगढ़ ग्राम पंचायत में पानी निकासी की व्यवस्था हेतु कार्ययोजना

309. श्री पुखराज (भोपालगढ़): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बड़े कस्बों तथा गांवों में पानी की उचित निकासी तथा व्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम बनाने हेतु सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला जोधपुर की भोपालगढ़ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था करने के संबंध में कोई विशेष कार्ययोजना बनाकर बजट जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान राशि उपलब्ध करायी जा रही है। इस राशि से पानी

(पंचायती राज मंत्री)

की उचित निकासी व व्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम के कार्य भी अनुमत हैं। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी) में उक्त कार्यों को प्राथमिकता अनुसार ग्राम पंचायत को प्राप्त अनुदान से करवाया जाता हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में भी ग्राम पंचायत के ठोस एवं तरल संसाधन प्रबंधन (Solid and Liquid Resource Management) के प्लान तैयार किए जा रहे हैं।

(3) भोपालगढ़ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था करने के संबंध में कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

ग्राम पंचायत भोपालगढ़ द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में ठोस एवं तरल संसाधन प्रबंधन (Solid and Liquid Resource Management) प्लान तैयार किया गया है जिसमें नाला/नाली निर्माण, सीवरेज (गन्दे पानी की निकासी हेतु) आदि कार्य प्रस्तावित हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चूरू पंचायत समिति में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवास

310. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति चूरू में प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत आवासों में से कुल कितने आवासों का निर्माण पूर्ण हुआ एवं अपूर्ण आवासों को कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत समिति के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत आवासों की दूसरी व तीसरी किश्त बकाया है? यदि हां, तो कितने आवासों की व क्यों?

(3) उक्त पंचायत समिति के अन्तर्गत कुल कितने पात्रताधारी परिवार थे जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास स्वीकृत होने थे तथा वर्तमान में कितने आवेदन लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत वर्ष 2016-17 से

(ग्रामीण विकास मंत्री)

2019-20 तक पंचायत समिति चूरू में 1619 आवास स्वीकृत किए गए, जिनमें से 22 स्वीकृत आवासों के लाभार्थियों द्वारा राशि लौटा दिए जाने के कारण निरस्त किए गए, जिसके उपरांत शेष 1597 स्वीकृत आवासों में से 1497 आवास पूर्ण हो चुके हैं व एवं शेष रहे 100 अपूर्ण आवास माह मार्च 2020 तक पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक पंचायत समिति चूरू में स्वीकृत आवासों में से 75 आवासों की दूसरी किश्त एवं 93 आवासों की तीसरी किश्त बकाया है।

योजनान्तर्गत आवास निर्माण स्वयं लाभार्थी द्वारा किया जाता है एवं किश्तों का भुगतान आवास निर्माण स्तर के आधार पर किये जाने का प्रावधान है। लाभार्थियों द्वारा आवास का निर्माण निर्धारित स्तर तक पूर्ण कराए जाने के उपरांत बकाया किश्तों का भुगतान कर दिया जाएगा। विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

(3) पंचायत समिति चूरू में प्रधानमंत्री आवास योजना में SECC सूची 2011 में 2467 पात्र परिवार थे जिसमें से 1619 को लाभान्वित कर दिया गया है। योजनान्तर्गत निर्धारित मापदंडों के आधार पर 806 परिवार अपात्र पाए गए, जिनको रिमांड मोड्यूल के माध्यम से वरीयता सूची से हटा दिया गया है। वरीयता सूची में 34 लाभार्थी भूमिहीन हैं जिनको भूमि उपलब्धता पश्चात् एवं शेष 8 पात्र लाभार्थियों की आवास स्वीकृति हेतु वर्ष 2019-20 में अतिरिक्त लक्ष्य आबंटित कर दिए गए हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बसेड़ी में पार्वती बांध से पेयजल आपूर्ति

311. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में पार्वती बांध से पेयजल आपूर्ति की योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त योजना कब तक क्रियान्वित होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में 82 गांव पेयजल योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत चंद्रावली के लगभग 100 परिवारों को पाइप लाइन की गहराई अधिक होने से पेयजल नहीं मिल पा रहा है? यदि हां, तो क्या

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

सरकार उक्त परिवारों को पेयजल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्राम हरजपुरा में जनता जल योजनान्तर्गत डाली गयी क्षतिग्रस्त पाइप लाइन को ठीक करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के ग्रामों हेतु सतही जल स्रोत पार्वती बांध आधारित किसी भी योजना के प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

उक्त जल योजना हेतु पूर्व में बनाये गये प्रस्तावों के अंतर्गत ग्रामों हेतु आवश्यक जल मांग के अनुरूप पार्वती बांध में जल आरक्षण सुनिश्चित नहीं होने के कारण इन की स्वीकृति तत्समय जारी नहीं की गई।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी की पंचायत समिति सरमथुरा का ग्राम चन्द्रावली, पार्वती बांध आधारित क्षेत्रीय जल योजना आंगई-सरमथुरा से लाभान्वित है। स्वीकृत योजना के प्रावधान के अनुरूप ग्राम कोटा में निर्मित उच्च जलाशय से पाइप लाइन द्वारा 8 सार्वजनिक नलों के माध्यम से ग्राम चन्द्रावली में पर्याप्त मात्रा में पेयजल आपूर्ति लगभग एक से डेढ़ घण्टा प्रतिदिन की जा रही है।

उक्त ग्राम पहाड़ी पर स्थित होने तथा नई बस्तियों के ऊंचाई पर अवस्थित होने के कारण इस आबादी को लगभग 200 से 250 मीटर की दूरी पर स्थापित सार्वजनिक नलों से पेयजल उपलब्ध हो पाता है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी की पंचायत समिति बसेड़ी के पम्प एवं टैंक जल योजना से लाभान्वित ग्राम हरजपुरा में निर्मित नलकूप से भू-तल जलाशय तक जाने वाली राइजिंग पाइप लाइन, ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम में पुलिया एवं नाले के निर्माण के दौरान अलग-अलग स्थानों पर क्षतिग्रस्त किये जाने एवं ट्रांसफॉर्मर जल जाने के कारण योजना से पेयजल आपूर्ति बाधित रही थी। इस अवधि में ग्राम में स्थापित एवं क्रियाशील 32 हैण्डपम्पों से पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु रखी गई।

योजना को पुन: चालू करने हेतु अन्य ट्रांसफॉर्मर स्थापित करवाया

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

जाकर तथा विभाग द्वारा एक स्थान पर क्षतिग्रस्त पाइप लाइन को ठीक किया जाकर दिनांक 22.02.2020 से ग्राम में 2 भू-तल जलाशयों से पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गई है तथा 2 अन्य भू-तल जलाशयों से पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करने हेतु क्षतिग्रस्त पाइप लाइन सुधारने का कार्य किया जा रहा है।

पीलीबंगा के पेयजल सुविधा से वंचित गांव/ढाणियां

312. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में पेयजल सुविधा से वंचित गांव व ढाणियों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसे कितने गांव व ढाणियां हैं, जिनमें शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार कुल सम्मिलित 563 ग्रामों में से 13 ग्राम आपणी योजना से तथा 535 ग्राम भू-जल/नहर आधारित विभिन्न जल योजनाओं से वर्तमान में जुड़े हुए हैं। जल योजनाओं से इस प्रकार जुड़े हुए 548 ग्रामों में से 547 ग्रामों में वर्तमान में पेयजल आपूर्ति की जा रही है तथा रावतसर तहसील के आपणी योजना से जुड़े ग्राम रामपुरा मटोरिया में ग्राम स्तरीय जल एवं स्वास्थ्य समिति द्वारा बकाया जल राजस्व (माह सितम्बर, 2019 से नवम्बर, 2019 तक की राशि रुपये 63,378/-) विभाग में जमा नहीं कराये जाने के कारण दिनांक 01 दिसम्बर, 2019 से जल सम्बन्ध विच्छेद कर पेयजल आपूर्ति नहीं की जा रही है।

भारत सरकार के समेकित प्रबन्धन सूचना तंत्र के अनुसार विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की चिन्हित समस्त 20 ढाणियां पेयजल योजनाओं से लाभान्वित हैं। पेयजल योजना से लाभान्वित ग्राम एवं ढाणियों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

उक्त विधान सभा क्षेत्र के शेष 15 ग्राम विभागीय पेयजल योजनाओं से वर्तमान में जुड़े हुए नहीं हैं तथा स्थानीय ग्रामवासी निजी जल स्रोतों से

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

पेयजल प्राप्त करते हैं। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के नवीन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों हेतु तय प्राथमिकता अनुसार योजनाओं के प्रस्ताव बनाये जाकर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार चरणबद्ध रूप से इनकी स्वीकृति जारी की जायेगी। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(2) भारत सरकार के समेकित सूचना प्रबन्धन तंत्र (आई.एम.आई.एस.) की दिनांक 01.01.2019 की स्थिति के अनुसार विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में फ्लोराइड एवं अन्य अशुद्धियों से कोई ग्राम एवं ढाणी प्रभावित नहीं है।

विभिन्न पेयजल योजनाओं से क्षेत्र के उक्तानुसार लाभान्वित ग्राम एवं ढाणियों में पेयजल गुणवत्ता के निर्धारित मानकों के अनुरूप पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुनिश्चित की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नोगांवा ग्राम (अलवर) में घरों के ऊपर से गुजर रही 11 के.वी. लाइन को शिफ्ट करने की योजना

313. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जिला अलवर की तहसील रामगढ़ के ग्राम नोगांवा में घरों के ऊपर से 11 केवी की लाइन जा रही है? क्या सरकार घरों के ऊपर से जा रही 11 केवी लाइन को शिफ्ट करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

अलवर जिले की तहसील रामगढ़ के नोगावां में विद्युत लाइनें नियमानुसार ही खींची गई हैं। तत्पश्चात् विकासकर्ता अथवा संस्था द्वारा स्थापित लाइन के नीचे आवासीय कालोनियां काट दी जाती हैं अथवा निवासियों के द्वारा लाइनों के नीचे बिना स्वीकृति के मकान बना लिये जाते हैं। ऐसी विद्युत लाइन को दूसरी जगह शिफ्ट करने हेतु किसी विकासकर्ता/ संस्था/आवेदक द्वारा आवेदन करने पर तकमीना की 50 प्रतिशत राशि जमा करने के उपरांत निगम द्वारा नियमानुसार विद्युत लाइन को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। शेष 50 प्रतिशत राशि निगम द्वारा वहन की जाती है।

डेगाना में नहरी प्रोजेक्ट के तहत जल कनेक्शन

314. श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना व मेड़ता में नहरी प्रोजेक्ट के तहत घर-घर जल कनेक्शन दिये गये हैं? यदि हां, तो उक्त योजना के तहत कौन-कौन से गांवों व ढाणियों को जोड़ा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजना के तहत शेष गांवों व ढाणियों को कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में कस्बा डेगाना एवं वर्ष 2001 की जनगणनानुसार कुल 190 ग्राम सम्मिलित हैं। नागौर लिफ्ट पेयजल परियोजना के स्वीकृत प्रथम चरण में इस क्षेत्र के 78 ग्रामों में से 2 ग्राम क्रमश: बुटाटी एवं चम्पाखेड़ी में घर-घर जल संबंध द्वारा स्वच्छ नहरी पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है। भू-जल आधारित पाइप्ड जल योजनाओं से घर-घर जल संबंधों से पूर्व से लाभान्वित 8 ग्रामों को स्वच्छ नहरी पेयजल से लाभान्वित करने का कार्य प्रगति पर है।

विधान सभा क्षेत्र डेगाना के 45 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए इनमें घर-घर जल संबंधों द्वारा स्वच्छ नहरी पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय एस.एल.एस.एस.सी. की 19वीं बैठक दिनांक 26.12.2019 द्वारा राशि रुपये 75.48 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है। इस क्षेत्र के शेष रहे 23 ग्रामों में सार्वजनिक नलों द्वारा स्वच्छ नहरी पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है। ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उक्त परियोजना के स्वीकृत द्वितीय चरण के पैकेज सप्तम् (सी.डी.एस.-04) में उक्त क्षेत्र के 112 ग्राम एवं कस्बा डेगाना सम्मिलित हैं। इस पैकेज का कार्य माह अगस्त, 2020 तक पूर्ण किया जाकर विधान सभा क्षेत्र डेगाना के 112 ग्रामों को घर-घर जल संबंध द्वारा स्वच्छ नहरी पेयजल से लाभान्वित करना प्रस्तावित है। ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में कस्बा मेड़ता एवं वर्ष 2001 की जनगणनानुसार कुल 174 ग्राम सम्मिलित हैं। नागौर लिफ्ट पेयजल

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

परियोजना के स्वीकृत प्रथम चरण में इस क्षेत्र के समस्त 174 ग्रामों में से 7 ग्राम क्रमशः मोकलपुर, सोगावास, डांगावास, लाम्पोलाई, बग्गड़, रैण एवं थल्ला की ढाणी में घर-घर जल संबंध द्वारा स्वच्छ नहरी पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है तथा भू-जल आधारित पाइप्ड जल योजनाओं से घर-घर जल संबंधों से पूर्व से लाभान्वित 22 ग्रामों को स्वच्छ नहरी पेयजल से लाभान्वित करने का कार्य प्रगति पर है।

विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के 102 ग्रामों में घर-घर जल संबंधों द्वारा स्वच्छ नहरी पेयजल उपलब्ध कराया जाने हेतु विभागीय एस.एल.एस.एस.सी. की 19वीं बैठक दिनांक 26.12.2019 द्वारा राशि रुपये 75.48 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है। इस क्षेत्र के शेष रहे 43 ग्रामों में सार्वजनिक नलों द्वारा स्वच्छ नहरी पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है। ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

नागौर लिफ्ट पेयजल परियोजना के उक्त वर्णित प्रथम एवं द्वितीय चरण में नागौर जिले के किसी भी विधान सभा क्षेत्र की ढाणियों को घर-घर जल संबंधों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान स्वीकृत नहीं था।

(2) विभागीय एस.एल.एस.एस.सी. की 19वीं बैठक दिनांक 26.12.2019 द्वारा विधान सभा क्षेत्र डेगाना के 45 ग्राम एवं 84 ढाणियां तथा विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के 102 ग्राम एवं 50 ढाणियां सम्मिलित करते हुए इनमें घर-घर जल संबंधों द्वारा स्वच्छ नहरी पेयजल उपलब्ध कराये जाने की उक्तानुसार स्वीकृति जारी की गई है। योजना की तकनीकी स्वीकृति एवं कार्यादेश उपरांत इसका क्रियान्वयन प्रारम्भ करना प्रस्तावित है। ढाणियों का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र डेगाना एवं मेड़ता के उक्तानुसार शेष रहे 23 एवं 43 ग्रामों में सार्वजनिक नलों द्वारा स्वच्छ नहरी पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है। इन ग्रामों एवं शेष रही ढाणियों में घर-घर जल संबंध द्वारा पेयजल उपलब्ध कराये जाने की योजनाओं पर तय प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार चरणबद्ध रूप से स्वीकृति जारी करना संभव होगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बूंदी शहर में सीवरेज निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण

315. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बून्दी शहर में सीवरेज का कितना कार्य होना था और वर्तमान में कितना कार्य हो चुका है?

(2) क्या सरकार सीवरेज कार्यों से खराब हुई सड़कों को पूर्ण रूप से दुबारा बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार बून्दी शहर में सीवरेज के कार्य को कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बून्दी शहर में 150 कि.मी. सीवरेज लाइन एवं 0.5 एमएलडी के दो एस.टी.पी. का कार्य किया जाना था। अब तक 65 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त कार्य हेतु 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गई थी जिसके विरुद्ध 61.55 करोड़ रुपये के कार्य हो चुके है।

(2) जी हां। सीवरेज कार्य में जो भी सड़कें तोड़ी जाती है, उन्हें साथ के साथ ही दुरुस्त किया जाता है।

(3) बून्दी शहर में अब तक सीवरेज का लगभग 65 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य दिसम्बर 2020 तक पूर्ण कर दिया जायेगा।

शिवराम कालोनी, जगतपुरा (जयपुर) में सुविधा क्षेत्र पर अतिक्रमण

316. श्रीमती गंगा देवी (बगरू): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि शिवराम कालोनी, जगतपुरा, जयपुर में मार्च, 2002 में जेडीए द्वारा कैम्प लगाकर सुविधा क्षेत्र छोड़ा गया था? यदि हां, तो कितना? क्या सरकार उक्त सुविधा क्षेत्र पर हुए अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में उक्त अतिक्रमण भूमि पर सामुदायिक भवन बनाने का विचार रखती है? नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती गंगा देवी)

(3) क्या यह सही है कि जगतपुरा रेलवे फाटक के पास दादू कालोनी में श्मशान बना हुआ है? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या सुविधाएं हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त श्मशान में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त श्मशान के विकास के लिए जन-प्रतिनिधियों द्वारा पत्र दिया गया है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जगतपुरा स्थित लक्ष्मी नगर गृ.नि.स.स. की योजना शिवराम कालोनी, स्कीम नं. 9 का दिनांक 08.03.2002 को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कैम्प लगाकर नियमित किया गया था। अनुमोदित मानचित्र के अनुसार 3465.65 वर्गगज सुविधा क्षेत्र छोडा गया था।

गृ.नि.स.स. द्वारा उक्त सुविधा क्षेत्र में भूखण्ड सृजित करने के कारण भूखण्ड्धारियों द्वारा नियमन किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये थे, जिसके संबंध में जोन द्वारा जोनल स्तरीय समिति की बैठक में एजेण्डा तैयार कर बी.पी.सी.एल.पी. की 116वीं बैठक दिनांक 23.04.08 में निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 104, 105, 111, 112, 113, 114, 143 एवं 144 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त कर राज्य सरकार को नियमन हेतु पत्र भिजवाया जाये। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा पत्र क्रमांक: प.3()नविवि/3/2007 जयपुर दिनांक 20.06.08 द्वारा उक्त भूखण्डों को सुविधा क्षेत्र से मुक्त कर नियमन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी पालना में वर्ष 2008 में उक्त भूखण्डों के पट्टे जारी किये जा चुके हैं। जोनल लेवल समिति के एजेण्डा नोट की प्रति परिशिष्ट "अ" एवं राज्य सरकार को प्रेषित पत्र की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

सुविधा क्षेत्र की शेष बची भूमि 672.92 वर्गगज पर वर्तमान में पार्क निर्मित है। पार्क की भूमि के चारों तरफ चारदीवारी निर्मित है तथा पार्क में झूले लगे हुए हैं एवं किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।

(2) जी नहीं। उक्त कालोनी के मानचित्र में सामुदायिक भवन हेतु भूमि नामित नहीं है।

(3) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा हथरोई गढ़ी गृह निर्माण सहकारी समिति की अनुमोदित योजना दादू कालोनी में कोई श्मशान नहीं है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(4) जी हां। जन प्रतिनिधियों से दो पत्र प्राप्त हुए हैं एवं दादू कालोनी में श्मशान नहीं होने के कारण कोई भी विकास कार्य की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति की सम्राट नगर, जगतपुरा (जयपुर) के भू-खण्ड

317. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जगतपुरा रोड, सांगानेर, जयपुर में श्री छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा आवासीय योजना सम्राट नगर किन-किन खसरा नं. पर सृजित की गई थी एवं इसमें कुल आवासीय भूखण्ड किस-किस साइज के थे? योजना का लेआउट प्लान, वर्तमान नामान्तरण की प्रति, भूखण्डों की साइज, आबंटियों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कालोनी में कितने भूखण्डों पर मकानों, दुकानों का निर्माण किया जा चुका है व कितने भूखण्ड रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त योजना में कई भूखण्ड विवादित हैं और विभिन्न न्यायालयों (राजस्व एवं सिविल) में वाद विचाराधीन व लम्बित हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त योजना जविप्रा द्वारा अनुमोदित है और उक्त को नगर निगम को हस्तान्तरित किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्री छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की योजना सम्राट नगर ग्राम खोखावास तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 432 लगायत 442, 445 से 447, 458 से 463, 466, 467, 470, 478 से 482, 593, 594, 608, 634, 635, 599, 600, 613/729, 600/731, 598, 611, 632, 603 से 606 कुल किता 44 रकबा 8.39 हैक्टे. पर सृजित है। योजना में विभिन्न क्षेत्रफल के कुल 178 भूखण्ड सृजित हैं जिनमें से 30 भूखण्ड एयरपोर्ट से प्रभावित हैं। योजना का ले-आउट प्लान परिशिष्ट "अ" पर तथा वर्तमान स्वामित्व संबंधी ऑनलाइन प्राप्त जमाबंदी की प्रति परिशिष्ट "ब" पर एवं आबंटियों की सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) उक्त योजना में लगभग 118 भूखण्डों पर निर्माण किया जा चुका है एवं लगभग 30 भूखण्ड रिक्त हैं। योजना में कोई दुकान नहीं है।

(3) जी हां। योजना में भूखण्ड एयरपोर्ट विस्तार क्षेत्र से एवं 200 फीट एयरपोर्ट रोड से प्रभावित होने के कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में निम्न याचिकाएं लम्बित हैं:-

क्र.सं.	याचिका संख्या	उनवान
1.	5601/2009	श्रीमती अनिता बनाम जविप्रा
2.	5602/2009	श्रीमती विजय श्रीमाली बनाम जविप्रा
3.	5603/2009	श्री अशोक कुमार शर्मा बनाम जविप्रा

(4) जी नहीं। श्री छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की आवासीय योजना सम्राट नगर गैर अनुमोदित योजना है। वर्तमान में उक्त योजना को नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परबतसर नगरपालिका में सीवर लाइन डालने की योजना

318. श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि परबतसर नगरपालिका क्षेत्र में सीवर लाइन डालने की योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नगरपालिका क्षेत्र में सीवर लाइन डालने का कार्य अब तक प्रारम्भ नहीं हुआ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अब कब तक प्रारम्भ हो जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में परबतसर शहर में सीवरेज लाइन डालने का किसी भी योजना में चयन नहीं होने के कारण कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 01 के उत्तर में निहित है।

झालावाड़ में बूंद-बूंद सिंचाई योजना के तहत देय अनुदान

319. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जिला झालावाड़ में बूंद-बूंद सिंचाई योजना के अन्तर्गत उपकरण आदि खरीदने के लिए अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में कितने किसानों को कितनी अनुदान राशि का भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार को उक्त योजना में किसानों को दिये जाने वाले अनुदान में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। झालावाड़ जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को बूंद-बूंद सिंचाई संयंत्र खरीदने पर अनुदान दिया जाता है। पिछले पांच वर्षों में 11041 किसानों को लाभान्वित कर रुपये 3164.44 लाख की अनुदान राशि का भुगतान किया गया। विवरण सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त योजना में किसानों को दिये जाने वाले अनुदान के सम्बन्ध में झालावाड़ जिले से अनियमितता की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रायसिंहनगर के पशु चिकित्सालयों में उपलब्ध दवाइयां

320. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में कितने पशु चिकित्सालय व उप केन्द्र हैं? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालयों को वार्षिक कितनी राशि की दवाइयां उपलब्ध करवायी जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चिकित्सालयों व उप केन्द्रों पर कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं तथा कब तक उक्त रिक्त पदों को भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में पंचायत समितिवार पशु चिकित्सा संस्थाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के पशु चिकित्सालयों में वर्ष 2019-20 में उपलब्ध करवायी गयी औषधियों की राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

पशु चिकित्सा संस्थाओं की मांग एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुरूप औषधियां दी जाती हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में पशु चिकित्सा संस्थाओं में रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जायल में संचालित पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

321. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल में पशुचिकित्सा केन्द्र एवं उप केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नये पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त चिकित्सालयों व उप केन्द्रों में कितने पद रिक्त हैं और कितने पद भरे हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल में संचालित पशु चिकित्सा संस्थाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार खोली जाती हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र जायल में संचालित पशु चिकित्सा संस्थाओं में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शेरगढ़ में बूंद-बूंद सिंचाई योजना के तहत लाभान्वित किसान

322. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बूंद-बूंद सिंचाई योजना लागू की गई है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में बूंद-बूंद सिंचाई योजनान्तर्गत विगत तीन वर्षों में कितने किसानों द्वारा आवेदन किया गया तथा कितने किसानों को लाभान्वित किया गया एवं कितने शेष हैं? पंचायत समितिवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में बूंद-बूंद सिंचाई योजना में शेष सभी किसानों को लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में बूंद-बूंद सिंचाई हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष 2015-16 से संचालित है। इससे पूर्व आन फार्म वाटर मैनेजमेन्ट, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन तथा सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत भी बूंद-बूंद सिंचाई संयंत्रों हेतु अनुदान देय था। उक्त योजना का पूर्ण विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जोधपुर जिले की विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समितिवार वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 व 2019-20 के दौरान बूंद-बूंद सिंचाई के तहत कुल आवेदन, लाभान्वित, निरस्त व बकाया कृषकों का विवरण परिशिष्ट-2 में संलग्न कर दिया गया है।

(3) शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बूंद-बूंद सिंचाई का किसी भी कृषक का आवेदन बकाया नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कामां में राशन की दुकानों का आवंटन

323. श्रीमती जाहिदा खान (कामां): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र कामां में कितनी राशन की दुकानें संचालित हैं व कितनी आबंटित की जानी शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती जाहिदा खान)

(2) क्या सरकार उक्त अनावंटित दुकानों को आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कामां विधान सभा क्षेत्र में कुल 150 राशन की दुकानें संचालित हैं एवं 20 दुकानें आबंटन से शेष हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। आबंटन सलाहकार समिति के गठन के बाद शीघ्र विज्ञापन जारी कर उक्त उचित मूल्य दुकानों का आबंटन कर दिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झुंझुनूं में भामाशाह कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने हेतु प्राप्त आवेदन

324. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं के उप खण्ड कार्यालय में भामाशाह कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने हेतु कितने-कितने आवेदन-पत्र जनवरी, 2018 से जून, 2019 तक प्राप्त हुए? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवेदन पत्रों में से कितने भामाशाह कार्ड कब-कब लिंक किये जा चुके हैं तथा कितने लम्बित हैं? लम्बित होने के कारण सहित विवरण सदन की मेज मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं के उपखण्ड कार्यालय में जनवरी, 2018 से जून, 2019 तक भामाशाह कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना से लिंक कराने के कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) भामाशाह कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना से लिंक कराने के कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

मुण्डावर में उज्ज्वला योजना के तहत जारी गैस कनेक्शन

325. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर जिला अलवर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में दिसम्बर, 2018 से 31 दिसम्बर, 2019 तक कितने गैस कनेक्शन जारी किये व कितने शेष हैं? ग्रामवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शेष पात्रताधारियों को शीघ्र गैस कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना में गैस कनेक्शन जारी करने के कोई मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर जिला अलवर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में दिसम्बर, 2018 से 31 दिसम्बर, 2019 तक 2677 एल.पी.जी. गैस कनेक्शन जारी किये गये हैं एवं शेष गैस कनेक्शनों की संख्या 32 है, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राज्य स्तरीय तेल समन्वयक के अनुसार उज्ज्वला योजना में लक्ष्य पूर्ति होने के कारण शेष कनेक्शनों को स्थगित कर दिया गया है।

(3) जी हां। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दौसा में संचालित दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां

326. श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला दौसा में कितनी दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां जयपुर डेयरी के अन्तर्गत संचालित हैं एवं कौन-कौनसी बंद हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त बंद पड़ी समितियों को सरकार द्वारा पुन: चालू किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. के अधीनस्थ दौसा जिले में कुल 724 समितियां हैं। उक्त समितियों में 456 चालू हैं एवं 268 समितियां बन्द हैं।

(गोपालन मंत्री)

चालू समितियों की सूची प्रदर्श-अ एवं बन्द समितियों की सूची प्रदर्श-ब पर संलग्न है।

(2) जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. जयपुर के कार्यक्षेत्र में जो दुग्ध समितियां अपमिश्रित दूध सप्लाई करने के कारण बन्द हैं, उन्हें वर्तमान में पुन: चालू करना प्रस्तावित नहीं है।

जो समितियां अन्य कारण से बन्द हैं, उन्हें पुन: प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में जयपुर दुग्ध संघ के संचालक मण्डल की दिनांक 27 जून, 2019 को आयोजित 173वीं बैठक के एजेण्डा प्रस्ताव संख्या 173 (17) पर लिये गये निर्णय के अनुसार उपरोक्त श्रेणी की दुग्ध समितियों को जोन प्रभारी की सिफारिश/विवेक के आधार पर सक्षमता को देखते हुए पुन: प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी। उक्त दुग्ध समितियों को केस-टू-केस आधार पर जोन प्रभारी के द्वारा पुन: प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आहोर में खनिज उद्योगों को प्रोत्साहन देने की कार्ययोजना

327. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र आहोर में कितना राजस्व प्राप्त होता है? क्या सरकार आहोर में खनिज उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र आहोर से खान विभाग को वित्तीय वर्ष 2018-19 में 3.58 करोड़ तथा वर्ष 2019-20 में दिनांक 31.01.2020 तक रुपये 4.44 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।

आहोर में खनिज उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर कोई योजना/प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, अपितु राज्य में खनिज उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 17.12.2019 से प्रभावी की गई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 में मिनरल सैक्टर को विनिर्माण क्षेत्र के थ्रस्ट सैक्टर्स

(खान मंत्री)

की सूची में सम्मिलित करते हुए पात्र विनिर्माण उद्यमों को सामान्य परिलाभ के साथ-साथ अतिरिक्त परिलाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 में खनिजों की सूची अंकित करते हुए, सूची में अंकित खनिजों का प्रयोग करने वाले पात्र उद्यमों द्वारा न्यूनतम 2 करोड़ रुपये का निवेश किये जाने पर निम्नानुसार अतिरिक्त परिलाभ (थ्रस्ट सैक्टर के अन्तर्गत) दिये जाने के प्रावधान किये गये:-

प्लान्ट एण्ड मशीनरी क्रय करने हेतु रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों से लिए गए टर्म लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान (5 वर्षों के लिए तथा अधिकतम 25 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक) अथवा प्लान्ट एण्ड मशीनरी पर किए गए निवेश का 25 प्रतिशत पूंजी अनुदान (अधिकतम 25 लाख रुपये तक)।

श्रीडूंगरगढ़ में शहीदों के स्मारक का निर्माण

328. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के कितने जवान देश की सीमाओं पर शहीद हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त शहीदों के स्मारक बनाने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार राजकीय कालेज श्रीडूंगरगढ़ का नाम शहीद कैप्टन चन्द्र चौधरी के नाम पर रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के 3 जवान देश की सीमाओं पर शहीद हुए हैं। विवरण परिशिष्टक पर संलग्न है।

(2) शहीद स्मारक का निर्माण राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 01.10.2009 के अनुसार किया जाता है। प्रति परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। शहीद कैप्टन चन्द्र चौधरी के नाम से बिग्गावास रामसरा में स्थापित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का नामकरण किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सागवाड़ा में बन्द बस सेवाओं का पुनर्संचालन

329. श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में कई मार्गों पर संचालित निगम बस सेवाएं बंद कर दी गई हैं? यदि हां, तो किस-किस मार्ग पर कब से? उक्त सेवाओं को किस कारण बंद किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्र की उक्त सेवाओं को बंद कर देने के कारण आमजन को आवागमन हेतु परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है?

(3) क्या सरकार उक्त सेवाओं को पुन: संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीमित संसाधनों एवं संचालन लागत से कम आय आने के कारण सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र की बन्द किये गये वाहनों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी हां। सरकार की घोषणा "ग्रामीण परिवहन बस सेवा का विस्तार करते हुए दूर-दराज के गांवों/ढाणियों को बस सेवा से जोड़ना" के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण मार्गों का सर्वे कर संचालन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी नहीं। निगम के सीमित संसाधनों के कारण खण्ड "1" में वर्णित बन्द की गई सेवाओं को पुन: संचालित करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विद्यालयों में कम्प्यूटर विषय के पद का सृजन

330. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकारी विद्यालयों में कम्प्यूटर विषय अनिवार्य कर दिया गया है किन्तु प्रदेश के विद्यालयों में कम्प्यूटर विषय का पद सृजित नहीं किया गया है? उक्त स्थिति में क्या कम्प्यूटर शिक्षण प्रभावित हो रहा है? इस हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है?

(श्री कान्ति प्रसाद)

(2) क्या सरकार भविष्य में सरकारी विद्यालयों में कम्प्यूटर विषय का पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा संख्या 99 द्वारा राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के लिए "कम्प्यूटर शिक्षक का कैडर" सृजन करने की घोषणा की है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) प्रश्न के भाग संख्या 01 के अनुसार।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रयोगशाला सहायक भर्ती को पूर्ण करने की कार्ययोजना

331. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा मई, 2018 में प्रयोगशाला सहायक भर्ती हेतु आवेदन प्राप्त कर दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण की गई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा काफी समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अब तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर प्रोविजनल वरीयता सूची जारी नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। विभाग द्वारा प्रयोगशाला सहायक तृतीय श्रेणी के 1200 रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को दिनांक 14.03.2018 को अर्थना भिजवाई गई थी। बोर्ड द्वारा दिनांक 09.05.2018 को विज्ञापन जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये तथा दिनांक 03.02.2019 को परीक्षा आयोजित करवाई गयी थी, परन्तु प्रक्रियाधीन भर्तियों में अधिसूचना दिनांक 13.02.2019 एवं दिनांक 19.02.2019 का प्रभाव दिये

(शिक्षा राज्य मंत्री)

जाने हेतु कार्मिक विभाग के पत्रांक प.7(1)कार्मिक/क-2/2017 दिनांक 23.06.2019 के क्रम में अति पिछड़ा वर्ग को 01 प्रतिशत के स्थान पर 04 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षरण दिये जाने एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने हेतु 31 अतिरिक्त पदों के सृजन की वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर दिनांक 16.07.2019 को 1231 पदों की संशोधित अर्थना बोर्ड को भिजवाई गई थी।

बोर्ड द्वारा दिनांक 22.07.2019 को 1.5 गुणा अभ्यर्थियों का पूर्णतया अस्थाई परिणाम घोषित किया गया। इसके पश्चात् कार्मिक विभाग की अ.शा. टीप दिनांक 18.9.2019 द्वारा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के लागू होने की दिनांक 24.01.2019 के समय प्रक्रियाधीन समस्त भर्तियों में विशेष योग्यजनों को पूर्व में देय आरक्षण 3 प्रतिशत के स्थान पर इन नियमों के तहत देय 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिये जाने हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को पुन: संशोधित अर्थना दिनांक 15.10.2019 को भिजवाई गई।

बोर्ड द्वारा दिनांक 05.08.2019 से 16.08.2019 तक दस्तावेज सत्यापन करवाया गया जिसमें अनुपस्थित अभ्यर्थियों के दिनांक 13.11.2019 से 14.11.2019 तक दस्तावेज सत्यापन उपरान्त अन्तिम परीक्षा परिणाम दिनांक 20.12.2019 को जारी कर 1231 पदों के विरुद्ध 1041 चयनित आशार्थियों की अभिस्तावना नियुक्ति हेतु विभाग को प्राप्त हो चुकी है, किन्तु रिट संख्या 19836/2019 पूजा गोदारा बनाम राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित चयन प्रक्रिया पर रोक आदेश होने के कारण नियुक्ति दिया जाना संभव नहीं हो रहा है।

(3) जी हां। माननीय न्यायालय का स्थगन हटने एवं कर्मचारी चयन बोर्ड से शेष 190 चयनित आशार्थियों की अभिस्तावना प्राप्त के पश्चात् पूर्ण नियुक्ति दिया जाना संभव हो सकेगा।

आसीन्द (भीलवाड़ा) के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेल मैदान को विकसित करने की योजना

332. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आसीन्द के खेल मैदान को विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के समस्त राजकीय विद्यालयों के अविकसित खेल मैदानों को विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसीन्द में वर्तमान में खो-खो व वालीबाल के मैदान विकसित हैं।

अन्य खेलों के लिए मैदान विकसित किए जाने हेतु विद्यालय विकास समिति द्वारा प्रस्ताव स्थानीय निकाय नगरपालिका आसीन्द को प्रेषित किया गया है। स्थानीय स्तर पर संसाधनों की व्यवस्था होने पर ही खेल मैदान विकसित किया जाना सम्भव है।

(2) जी हां। विद्यालयों के खेल मैदानों को विकसित किए जाने हेतु मनरेगा योजना, स्थानीय विकास योजनाओं एवं अन्य स्रोतों से आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। इस सम्बन्ध में जारी परिपत्र/आदेशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आमेर के विद्यालयों में रिक्त पद

333. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र आमेर में वर्तमान में कितने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आमेर में वर्तमान में प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत

(शिक्षा राज्य मंत्री)

कुल 228 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं एवं माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत कुल 63 राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनका विवरण क्रमश: परिशिष्ट क-1 व क-2 पर सलंग्न है।

(2) उक्त विद्यालयों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का श्रेणी वार विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	**पदनाम**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
1	प्रथम श्रेणी	120	113	07
2	द्वितीय श्रेणी	297	279	18
3	तृतीय श्रेणी	865	719	146

(3) जी हां। माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में व्याख्याता सीधी भर्ती के 5000 पदों की भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई जा चुकी है, परिणाम आना शेष है।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत तृतीय श्रेणी अध्यापक के 31000 पदों पर भर्ती माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2020 इसी वर्ष अगस्त माह में आयोजित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उक्तानुसार सीधी भर्ती परीक्षा एवं पदोन्नति अभ्यांश के पद विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर विद्यालयों में रिक्तियों को भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-01

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

सिवाना गढ़ के भीमगोड़ा तीर्थ का संरक्षण

पांडवों के अज्ञातवास की याद दिलाता है सिवाना गढ़ का भीमगोड़ा तीर्थ। साल के 365 दिन अमृतरूपी बहता है पानी। राजस्थान की छप्पन पर्वतमालाओं में स्थित गढ़ सिवाना का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली रहा है। यहा पर स्थित ऐतिहासिक दुर्ग जहां एक ओर जौहर और शाकों से तपी इस भूमि के गौरवमयी अतीत की याद दिलाता है तो दूसरी ओर यहां पर महाभारत काल में पांडवों को दिये गये अज्ञातवास के साक्ष्य भी दृष्टिगोचर होते हैं। उनमें से एक है यहां का अभयधाम भीमगोड़ा तीर्थस्थल, जहां के बारे में ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय यहां पर व्यतीत किया था।

मान्यता के अनुसार अज्ञातवास के दौरान जब पांडव माता कुन्ती के साथ इन पहाड़ियों से होकर गुजर रहे थे, उस दौरान माता कुन्ती को प्यास लग गई। जब इन बीहड़ों में कहीं पर भी पानी का स्रोत नजर नहीं आया तो दस हजार हाथियों के समान बल रखने वाले पांडव भीम ने अपना घुटना पर्वत पर दे मारा जिससे जल की धारा बहने लगी। इस स्थान पर आज भी यह स्वच्छ जल की धारा पूर्व की भांति निर्बाध रूप से बह रही है। अकाल के दौरान भी यहां अनवरत पानी बहता है, जो कुण्ड में इकट्ठा होता रहता है, जहां आमजन इसे पीते हैं।

अभयधाम भीमगोडा तीर्थस्थल ऐतिहासिक होने के साथ ही क्षेत्रवासियों की आस्था से जुड़ा स्थान है। अतः राज्य सरकार को पुरातत्व विभाग/पर्यटन विभाग को जिम्मा देकर यहां के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु प्रयास करने चाहिये।

वैसे यह स्थान मारवाड़ के लोगों के श्रद्धा के माने जाने वाले श्री रामानंदी विष्णु वैरागी बिंदु गादी गढ़ सिवाणा के अमर गुरु मंछाराम जी महाराज की तपोस्थली रहा है। यहां पहाड़ी पर एक गुफा है जिसमें अमर गुरु मंछाराम जी महाराज ने तपसाधना की थी। इस पवित्र स्थान पर बहुत सी गोशालाएं स्थित हैं जहा गायों की सेवा की जा रही है। साथ ही अमर गुरु अभयरामजी महाराज द्वारा स्थापित अनेक ऐसे मंदिर हैं जिनमें स्थापित मूर्तियां अपने आप में विशिष्ट एवं अनुपम हैं। इस स्थान पर हर वर्ष गणगौर

तीज पर प्रसिद्ध मेला भरता है जिसमें हजारों लोग आते हैं। मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ऐसे ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक सौंदर्य के भंडार और लाखों लोगों के आस्था के केन्द्र इस पावन स्थान को विशेष श्रेणी में लेकर संरक्षण एवं संवर्द्धन का कार्य करे।

सधन्यवाद।

हमीर सिंह भायल

(सिवाना)

कनिष्ठ सहायकों को ग्राम विकास अधिकारी का चार्ज

मेरे विधान सभा क्षेत्र आसपुर जिला डूंगरपुर में तीन पंचायत समिति कार्यालय हैं जिसमें दोवड़ा में कुल 34 पंचायत हैं जिसमें ग्राम विकास अधिकारी 15 कार्यरत हैं तथा 19 रिक्त हैं। आसपुर पंचायत समिति में कुल 31 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें 17 पद रिक्त हैं तथा 14 ग्राम विकास अधिकारी कार्यरत हैं। पंचायत समिति साबला में 31 ग्राम पंचायतें हैं, उसमें भी 15 ग्राम विकास अधिकारी कार्यरत हैं, वहां पर भी 14 पद रिक्त हैं। यह समस्या मेरे विधान सभा आसपुर व पूरे राजस्थान की है। हर ग्राम विकास अधिकारी के पास 4-4 ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी दे रखी है। इससे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आम जन को समस्या हो रही है।

अतः ग्राम पंचायतों में कार्यरत अनुभवी कनिष्ठ सहायकों को रिक्त ग्राम पंचायतों में पूर्व की भांति वापस चार्ज दिया जाये। पूर्व में सरकार का आदेश भी हुआ था। अत कनिष्ठ सहायकों को चार्ज दिया जाये ताकि समय-समय पर ग्राम पंचायत में जनकल्याणकारी व अन्य कार्य किया जा सके।

गोपीचंद मीणा

(आसपुर)

छबड़ा-कुम्भराज सड़क मार्ग का अपूर्ण कार्य

अध्यक्ष महोदय, छबड़ा-कुम्भराज सड़क मार्ग की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 19 जून, 2017 को जारी की गई। इस कार्य के लिए राशि रुपये 40.0 करोड़ स्वीकृत किए गए। उक्त सड़क 1300 मीटर भाग को छोड़कर बाकी सम्पूर्ण कार्य तकमीने के अनुरूप पूर्ण किया जा चुका है। बाकी रहे सड़क के इस भाग का निर्माण कार्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सीपेज में होने के कारण डामर से निर्माण किया जाना न्यायोचित नहीं था। वर्तमान में छबड़ा- कुम्भराज सड़क मार्ग पर शेष रही 1300 मीटर सड़क नहीं बनने की वजह से साधन मध्यप्रदेश नहीं जा पा रहे हैं, जिससे आमजन को काफी

नुकसान उठाना पड़ रहा है। दिनांक 07.08.2018 को अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा.नि.वि. संभाग कोटा दवारा साइट की विजिट की गई तथा उक्त भाग में सी. सी. सड़क निर्माण प्रस्तावित कर संशोधित तकमीना प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। संशोधित तकमीना अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृत कर उक्त कार्य की बचत राशि की निविदाएं आमंत्रित कर दी गईं, किन्तु मुख्य अभियंता कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त न होने तथा आचार संहिता लग जाने से कार्यादेश जारी नहीं हो सके। 1300 मीटर सड़क बनाने के लिए बजट की भी समस्या नहीं है। सड़क बनाने में 2.73 करोड़ रुपये व्यय होंगे, जबकि स्वीकृत राशि में से 5.5 करोड़ रुपये बचे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि छबड़ा-कुम्भराज सड़क मार्ग पर शेष रही 1300 मीटर सीसी सड़क निर्माण हेतु बचत राशि 5.50 करोड़ में से 2.73 करोड़ राशि स्वीकृत हो जाती है तो उक्त शेष कार्य किया जाना संभव हो सकेगा।

अतः इस महत्वपूर्ण समस्या के निराकरण की ओर मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं।

प्रताप सिंह

(छबड़ा)

बाली की सड़कों की चौड़ाई बढ़ाना व मरम्मत

महोदय,

बाली विधान सभा क्षेत्र की अति महत्वपूर्ण सड़क स्टेट हाईवे 16 साण्डेराव से देसूरी वाया बाली, फालना, सादड़ी नगरपालिका क्षेत्र से गुजरती हुई देसूरी से गोमती को नेशनल हाईवे नं. 8 को मिलती है। दूसरी सड़क सादड़ी से नाडोल, एमडीआर 40 जो सिंदरली, ढालोप और कोटड़ी पंचायत मुख्यालय से गुजरती है। पीपीपी मोड के तहत साण्डेराव से मुण्डारा तक इसकी मरम्मत व चौड़ाई भी हुई है, परंतु मुण्डारा से लेकर देसूरी तक अभी भी सड़क मात्र 5 मीटर चौड़ी है और क्षतिग्रस्त है। यह सड़क जोधपुर और उदयपुर की मुख्य सड़क है, जहां हजारों की संख्या में रोज पर्यटक इस सड़क से गुजरते हैं और नेशनल हाईवे 14 और नेशनल हाईवे 8 को सड़क जोड़ती है। सादडी से नाडोल एमडीआर 40 की यह देसूरी उपखंड की सबसे महत्वपूर्ण सड़क है, इसकी लंबाई 22 किमी. है। 7 किमी. सड़क की चौड़ाई व मरम्मत हो चुकी है, पर अभी भी 16 किमी. का काम शेष है।

अतः सरकार से निवेदन है कि इन सड़कों की चौड़ाई बढ़वाने व

मरम्मत करवाने के लिए सरकार प्रस्ताव मंगवाकर इन सड़कों के निर्माण कार्यों को स्वीकृत करने की कृपा करे।

पुष्पेन्द्र सिंह

(बाली)

डग में गागरीन पेयजल परियोजनाओं से वंचित गांव

मेरे विधान सभा क्षेत्र में डग गागरीन पेयजल परियोजना के अंतर्गत कई गांव व ढाणी अभी तक इस परियोजना से नहीं जुड़ पाए। कई स्कूलों में पीने के पानी के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। उनको पीएसपी से जोड़ा जाये। गागरीन पेयजल परियोजना में जो कार्य किया जा रहा है, वह कार्य गुणवत्ता पूर्ण नहीं है और कई जगह पाइप टूट गए हैं। जो पानी की टंकियां बनायी गयी हैं वे भी मापदण्ड के अनुसार नहीं बनाई है। आज भी ग्रामीण लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। कई छोटे गांव खेड़ा व ढाणी इस योजना से छूट गये हैं। जो छूट गये हैं उन्हें इस परियोजना से जोड़ा जाये।

इसी प्रकार माधवी सिंचाई परियोजना का पानी भी सभी गांवों तक नहीं पहुंच पा रहा है। कई छोटे गांव ढाणी व स्कूल इस परियोजना से वंचित रह गये हैं। इनको जोड़ा जाये। पूर्व में चम्बल परियोजना में करीब 42 गांव इस परियोजना से जुड़े थे जिसकी जगह राजगढ़ परियोजना द्वारा इन गांवों को जोड़ा गया मगर पाइप लाइन नहीं बदली गयी।

पुरानी लाइन होने से ग्रामीणों को पानी आखिरी मकान तक नहीं मिल पा रहा है। रेवा परियोजना के तहत आने वाली ढाणियों की स्कूलों को पानी नहीं मिल रहा है। इसे भी सुचारु रूप से पानी दिलवाया जाये। नगरपालिका भवानी मण्डी व पचपहाड़ में पूर्ववर्ती सरकार में सीवरेज व लाईन का कार्य स्वीकृत हुआ था जिसकी डीपीआर भी बन गयी थी, मगर अभी तक कार्य चालू नहीं हुआ जिससे पानी की आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं हो पा रही है। मेरा मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि सीवरेज का कार्य चालू करवाया जाये। इसी आशा व विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

कालूराम

(डग)

मावली में सरकारी विद्यालयों के भवनों की मरम्मत

मेरे विधान सभा क्षेत्र मावली में अधिकांश सरकारी स्कूलों के भवन पुराने व जीर्ण स्थिति में हैं। कई भवनों की वर्षों से मरम्मत तक नहीं हो पायी

है। कुछ समय पहले मावली के समीप साकरोदा में स्कूल भवन के पुराने कमरे ढह गये। उस दिन अवकाश होने से जनहानि नहीं हुई, लेकिन विभाग व प्रशासन में इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कोई हलचल तक नही हुई। मावली तहसील के पुरावतों का खेड़ा स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में करीब 100 छात्र-छात्राएं एक ही कक्षा-कक्ष में पढ रहे हैं। वह भी जर्जर व सीलन से भरा है। विद्यालय समिति, ग्राम सभा में चर्चा हो चुकी है। पी.ई.ई.ओ. को सूचित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। इसी तरह उच्च माध्यमिक विद्यालय जावड, बालिका विद्यालय मावली गांव, बालिका विद्यालय, फतहनगर व उच्च माध्यमिक विद्यालय, बांसलिया सहित कई विद्यालयों के भवन मरम्मत की राह देख रहे हैं, पर लगता है विभाग व सरकार किसी हादसे का इन्तजार कर रही है। स्कूल के कमरों मे वर्षा का पानी गिरना आम बात है। इसके लिए पूरी तहसील के स्कूलों की छतों की मरम्मत का अभियान चलाया जाये और सरकार प्रदेश के नौनिहालों की स्कूल भवन में जीवन रक्षा सुनिश्चित करे। यही निवेदन है।

धर्मनारायण जोशी

(मावली)

भर्ती परीक्षाओं के परीक्षा केन्द्रों का शिडयूल्ड एरिया में निर्धारण

प्रदेश में आरपीएससी व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विभिन्न प्रकार की परीक्षा के लिए छात्रों को परीक्षा केन्द्र दूर-दूर के जिलों में दिये जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि नकल जैसी करतूतों को रोकना है, जो हमारे शिड्यूल्ड एरिये में नही होता है, लेकिन उसका विपरीत प्रभाव हमारे शिड्यूल्ड एरिया के गरीब बच्चों पर पड़ रहा है। जब परीक्षा केन्द्र अन्य सम्भाग में दिया जाता है तब बसों व होटलों मे लूट मच जाती है। किराया दो से तीन गुना बढ़ जाता है। कई महिलाओं को परिवार के एक सदस्य को साथ लेकर जाना पड़ता है। इस तरह हमारे शिड्यूल्ड एरिया के गरीब बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और कई बार तो पेपर लीक होने से दुबारा एग्जाम होता है तो फिर वह फिर लूटा जाता है। इस तरह एक छात्र को कम से कम 4000 से 5000 तक का चूना लग रहा है। इस कारण शिड्यूल्ड एरिया के 25 से 30 प्रतिशत छात्रों ने परीक्षा ही नहीं दी है और लड़कियों की सुरक्षा की दृष्टि से भी यह खतरा है। इस प्रकार हमारे शिड्यूल्ड एरिया के गरीब छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता हूं।

अतः सरकार से अनुरोध है कि सभी प्रकार की परीक्षाओं में शिड्यूल्ड

एरिया के छात्रों की गरीबी का ध्यान रखते हुए शिड्यूल्ड एरिया के छात्रों को शिड्यूल्ड एरिया में ही परीक्षा केन्द्र दें और महिलाओं को उनके गृह जिले में ही परीक्षा केन्द्र देने का कष्ट करें।

राजकुमार रोत
(चौरासी)

साधुवाली में गाजर मण्डी की स्थापना

मान्यवर,

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर का गांव साधुवाली उत्तर भारत का सबसे बड़ा गाजर का उत्पादक और बाजार है और सम्पूर्ण उत्तर भारत की गाजर की कुल पैदावार का 80 प्रतिशत उत्पादन यहीं होता है। गांव साधुवाली में गंगनहर के किनारे किसान गाजर की धुलाई व बिक्री करते हैं और यहीं से देश के विभिन्न हिस्सों से आये व्यापारी गाजर की खरीद कर देश के अलग-अलग हिस्सों में बेचते हैं। लिहाजा किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए साधुवाली में गाजर धुलाई छंटाई और पैकिंग की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित गाजर मण्डी की स्थापना की जाये। पूर्व में भी प्रस्ताव जिला कलेक्टर के पास भिजवाया गया था, लेकिन उस प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। गाजर मण्डी की स्थापना से जहां एक ओर व्यापारियों को सुविधा हो जायेगी, वहीं साथ ही क्षेत्र में रोजगार की भी संभावनाएं बढ़ जायेंगी और गंगनहर के किनारे गाजर धोने के कारण कमजोर होकर नहर की पटरी टूटने की आशंका भी नहीं रहेगी।

जगदीश चन्द्र
(सादुलशहर)

सामोद की पहाड़ियों में एनीकट का निर्माण

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सामोद में एक प्राकृतिक बांध बना हुआ है जिसको लोग राजोला बांध कहते हैं लेकिन सन् 1995-96 में तेज बारिश होने के कारण यह बांध टूट गया जिससे आज आस-पास के गांव सुल्तानपुरा, फतेहपुरा, कुशलपुरा, सामोद, विजयसिंहपुरा, झीड़ा, महार आदि गांवों में जल का स्तर ऊपर रहता था, लेकिन जब से यह बांध टूटा है तब से जल का स्तर काफी नीचे चला गया तथा अब तो कई ट्यूबवैल भी सूखने लगे हैं। अतः भविष्य में जल का स्तर बढ़ाने व पीने के पानी की समस्या का समाधान करना है तो अविलम्ब इस बांध का पुनः निर्माण कराना अति आवश्यक है।

आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि इस बांध के पास ही गायत्री परिवार के सदस्यों द्वारा पहाड़ी पर 1000 पेड़ लगाये गये हैं। सामोद की पहाड़ी में बरसात के दिनों में पानी की झरने बहते हैं। यदि इन सामोद की पहाड़ियों में वन विभाग पंचायत एवं सिंचाई विभाग में से किसी विभाग के द्वारा छोटे-छोटे एनीकट बना दिये जायें तो पानी का जलस्तर भी बढ़ेगा और इन पेड़ों को भी पानी मिलने से इनको भी बचाया जा सकेगा।

इसी आशा व विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

रामलाल शर्मा

(चौमूं)

केलवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय का पीजी में क्रमोन्नयन

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 विशेष उल्लेख के तहत सदन का ध्यान आकर्षित कर ये निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के केलवाड़ा कस्बे में स्थित राजकीय महाविद्यालय में स्नातक की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को 45 किमी. दूर बारां जाना पड़ता है। ऐसे में कई विद्यार्थी आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। सहरिया बहुल क्षेत्र में अधिकांश लोगों के आर्थिक हालात ठीक नहीं हैं, जिसके चलते विद्यार्थी आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं। निर्धन और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को विशेषकर बालिकाओं को पढाई बीच में ही छोड़नी पड़ रही है। स्थानीय लोग इस मांग को लेकर लम्बे समय से आंदोलन भी कर रहे हैं। विद्यार्थियों की यह मांग है कि राजकीय महाविद्यालय केलवाड़ा को पीजी में क्रमोन्नत किया जाए। यहां कला वर्ग के अलावा कोई अन्य विषय संचालित नहीं है, जिससे अन्य विषय की पढ़ाई को लेकर भी विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में इस कालेज में विज्ञान और वाणिज्य संकाय आरम्भ करना बेहद आवश्यक है। राज्य सरकार बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। हमारे मुख्य मंत्री जी भी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि विद्यार्थियों के हित में विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के राजकीय महाविद्यालय, केलवाड़ा को पी.जी. में क्रमोन्नत किया जाये तथा इस महाविद्यालय में विज्ञान और वाणिज्य संकाय शीघ्र आरम्भ करवाया जाये।

निर्मला सहरिया

(किशनगंज)

नागौर में प्रधानमंत्री सड़क योजना से वंचित गांव

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा कि 250 से अधिक आबादी वाली सभी ढाणियों को प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क से जोड़ा जाना था, परन्तु नागौर जिले में ऐसी 36 सड़कें शेष रह गयी हैं, जिसमें से 22 सडक मेरे विधान सभा क्षेत्र की वंचित रह गयी हैं।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र का अधिकांश भूभाग मरुस्थलीय क्षेत्र है व अधिकांश आबादी ढाणियों में रहती है। रेगिस्तानी क्षेत्र होने के कारण यहां पर आवागमन के साधन रेतीले रास्तों में फंस जाते हैं। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की 250 से अधिक आबादी वाली इन ढाणियों की 22 सड़कें अतिशीघ्र बनवाकर क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करने का श्रम करें।

मोहन राम चौधरी
(नागौर)

लघु एवं मध्यम श्रेणी के गैर सरकारी विद्यालयों को प्रोत्साहन

राजस्थान सरकार ने अपने जन-घोषणा पत्र में लघु एवं मध्यम दर्जे के गैर सरकारी विद्यालयों के प्रोत्साहन, संरक्षण एवं संवर्धन तथा समस्या समाधान का वादा किया था, परन्तु कुछ बिन्दुओं पर ध्यान दिलाना चाहता हूं:-

1. टाइम फ्रेम:- आरटीई में प्रवेश से पुनर्भरण तक के दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं। प्रवेश व भौतिक सत्यापन टाइम फ्रेम के अनुसार किये जाते हैं, परन्तु पुनर्भरण सत्र 2018-19 का अभी तक बकाया है। बकाया भुगतान समय सीमा के अन्दर किया जाना चाहिए।
2. यूनिट कास्ट:- सरकार द्वारा यूनिट कॉस्ट का निर्धारण किया जाता है। सत्र 2015-16 में यूनिट कास्ट 17582 रुपये तक किया गया। सत्र 2019-20 में घटते घटते 10579 रुपये हो गया। एक तरफ महंगाई दर में वृद्धि हो रही है दूसरी तरफ यूनिट कास्ट कम हो रही है। इसको समय के अनुसार बढाया जाना चाहिए।
3. विद्यार्थी सरकारी या प्राईवेट नहीं:- राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूटी, लैपटाप आदि की योजनाएं हैं। प्राइवेट स्कूलों के छात्रों को यही लाभ नहीं मिल रहा। अतः सभी छात्रों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
4. मैरिट घोषणा बन्द करना:- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर

द्वारा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक परीक्षा की मैरिट गत दो वर्षों से बंद कर दी गयी है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए मैरिट घोषित की जानी चाहिए। सीबीएसई बोर्ड मैरिट घोषित करता है। अतः आरबीएसई को भी मैरिट घोषित करनी चाहिए।

5. परीक्षा शुल्क:- कक्षा 8 की वार्षिक बोर्ड परीक्षा में डाइट द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाता, परन्तु कक्षा 5 की वार्षिक बोर्ड परीक्षा में प्राइवेट स्कूलों से प्रति छात्र 40 रूपये परीक्षा शुल्क लिया जाता है। कक्षा 5 का परीक्षा शुल्क समाप्त किया जाना चाहिए।

6. इन सब बातों को लेकर निजी शिक्षण संस्थानों के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा, भीलवाड़ा 2 मार्च को जिले के शिक्षा अधिकारी से मिलकर अपनी बात कहते हैं तो बदतमीजी, मारपीट की जाती है, मुकदमा दर्ज करवाया जाता है जो कि निंदनीय है। ऐसे शिक्षा अधिकारी के खिलाफ जांच होनी चाहिए और तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त सभी मांगों को छात्र हित में समाधान करने की कृपा करें। विधान सभा में विशेष उल्लेख पर चर्चा हेतु अनुमति चाहता हूं।

बिहारीलाल

(नोखा)

चम्बल नदी की दायीं मुख्य नहर की दीवारों की ऊंचाई में वृद्धि

निवेदन है कि चम्बल नदी से सिंचाई के लिए दो मुख्य नहर कोटा में हैं। चम्बल की दायीं मुख्य नहर मेरे विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में कोटड़ी, थेकड़ा, रायपुरा, धाकड़खेड़ी, उम्मेदगंज से होकर गुजरती है।

यह नहर की दीवार की ऊंचाई या तो बहुत छोटी है या दीवार है ही नहीं और कई जगह पर टूटी हुई है। इसके कारण कई हादसे हो चुके हैं और आये दिन कई लोगों को जान गंवानी पड़ती है। अभी हाल ही में 2.1.2020 को सूरसागर के थेकड़ा पुलिया पर बाइक सवार दीपक अग्रवाल नहर की दीवार से टकराकर दुर्घटनावश चम्बल दायीं नहर में गिर गया। उसको बचाने नहर में शाहनवाज उर्फ शानू कूदा। परन्तु दुःख की बात है कि दोनों ही नहीं बच पाये और दीपक अग्रवाल का शव आज दिन तक नहीं मिला। ऐसे और भी दुर्घटनाएं हुई हैं तथा कई अन्य व्यक्तियों की इसी नहर में डूबने से मृत्यु हो चुकी है।

घनी आबादी का क्षेत्र होने के कारण और सुरक्षा के नजरिये से इन सम्पूर्ण नहर की दीवारों को ऊंचा करवाना अति आवश्यक है तथा जहां दीवार नहीं है वहां दीवार का निर्माण करवाना चाहिए। साथ ही थेकड़ा पुलिया पर तथा नहर के किनारे बसे हुए आबादी क्षेत्र पर रोड लाइट लगवाना अति आवश्यक है।

अतः माननीय मंत्री जी से इस समस्या के समाधान की आशा व विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

कल्पना देवी

(लाडपुरा)

सुमेरपुर के गांवों में पेयजल संकट का समाधान

सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में 80 प्रतिशत गांव व शहर जवाई बांध के पानी पर निर्भर हैं व 20 प्रतिशत गांव हैंडपंप पर आधारित हैं। जवाई बांध में पिछले वर्ष 2019-20 में डेड स्टोरेज का पानी पम्पिंग कर इन गांवों में पहुंचाने का कार्य जलदाय विभाग द्वारा किया गया। गत वर्ष जवाई बांध के कैचमेंट एरिया में बरसात कम होने से पानी की आवक कम हुई जिससे क्षेत्र के गुड़ाएंटला, एन्दलावास, भांवरी, गोदावास, पादरली तुरकान, निम्बाड़ा पुरोहितान, सापुनी, टेवाली, ठाकुरला, गुड़ा बिच्छु, तोगावास, हाथलाई, गिरवर, खुशी, जबडीया, केरला, बल्दो की ढाणी, गिरादडा, डेन्डा, बाला, डींगाई, जेतपुरा, गुडा सोनीगरा, कुरना, पादरला, मादरी, सोनाइ माझी, आइचिया, बुधवाडा, गुडा नारकान, प्रतापगढ़, दयालपुरा, रूपावास, चांगवा, मुलियावास, खोड, मनिहारी, कानदरा, गुरडाई, हेमावास, रामसिया, डरी, कानेलाव, करवा, गुन्दोज, गुडा दुर्गादास, सोडावास, गुड़ा प्रतापसिंह, पेनावा, सादडा, सुन्देलाव, दुजाना, रामनगर, सिन्दरु बाबागांव, खिन्दारा गांव, धनापुरा, सोनपुरा, जाखोडा, नेतरा, रोजडा, गलथनी, जवाई बांध, पराखिया, पावा, वेनपुरा, देवतरा, बांकली, कोलीवाडा, अनगोर, बलवना, खट्टकड़ा, माडल, सेदरिया, हिरनखुरी, ढोला, चाणोद, कोसेलाव, पोड़ना और सुमेरपुर व तखतगढ़ क्षेत्र में पेयजल की भयंकर समस्या उत्पन्न हो गयी थी। इन गांवों में अपर्याप्त मात्रा में चार- चार दिन से पानी की सप्लाई दी गयी थी। वर्तमान में भी जवाई बांध में पानी कम है अगर समय पर बरसात नहीं आती है तो उपरोक्त गांवों में पानी की भयंकर समस्या होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान

आकर्षित करना चाहता हूं कि उपरोक्त गांवों में जवाई बांध से पेयजल सप्लाई के अलावा आवश्यकतानुसार हैंडपम्प, ट्यूबवैल, ओपनवैल, पाइपलाइन या अन्य व्यवस्था भी यथासमय स्वीकृत करायें जिससे आने वाले समय में पेयजल संकट से निपटा जा सके।

जोराराम कुमावत

(सुमेरपुर)

मनोहरथाना में क्षतिग्रस्त पुलियाओं की मरम्मत

निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में अधिक बारिश के कारण अत्यधिक पुलिया पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसके कारण आने जाने वाले राहगीरों को भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा PMGSY से बनी रपटों पर भी बरसात के दिनों में पानी आ जाने के कारण कई घण्टों तक जाम लग जाता है। इनकी ऊंचाई नहीं बढ़ाई गयी तो बरसात के समय आने जाने वाले राहगीरों का रास्ता अवरुद्ध हो जायेगा जिसके कारण क्षेत्र की समस्त जनता का शहरों तक आना-जाना बाधित हो जायेगा। इससे बहुत सारी जगह पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा जिससे उनकी पढ़ाई भी बाधित हो जायेगी और पुलिया के अभाव में बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने में भी समस्या उत्पन्न होगी। इस परिस्थिति में उसकी मृत्यु भी हो सकती है।

महोदय, मरम्मत होने वाली पुलियाओं की सूची इस प्रकार है:-

1. इस्लामपुरा से बोरबन्द रोड के मध्य।
2. देवलीबड से बोरबन्द रोड के मध्य।
3. गुराडी चौराहे से बामलाबेह रोड के मध्य।
4. मानपुरा से जोगमण्डी रोड के मध्य।
5. उमरिया से रकडा रोड के मध्य।
6. हताईखेडा से जूनापानी रोड के मध्य।
7. ल्हास से लसुडियाशाह रोड के मध्य।

ऊंचाई वाली पुलियाएं निम्न प्रकार से हैं:-

1. खाताखेडी से मनोहरथाना के बीच हाईलेवल ब्रिज।
2. घाटोली से खेलखोयरा रोड के मध्य।
3. NH 52 से गेहूं खेडी रोड़ के मध्य।

4. चित्तोड़ा से म.प्र. बार्डर रोड के मध्य।

5. सरडा से मानपुरा रोड के मध्य।

6. असनावर से रातादेवी रोड के मध्य।

7. टांडी सोहनपुरा से साल की डूंगरी रोड के मध्य।

8. डूंगरगांव से कंवरपुरा रोड के मध्य।

9. मनोहरथाना से टोडरी जगन्नाथ रोड के मध्य।

10. चुरेलिया से घाटोली रोड के मध्य।

अतः महोदय, आपसे निवेदन है कि इस ओर विशेष ध्यान देकर क्षतिग्रस्त पुलियाओं की मरम्मत एवं ऊंचाई बढ़ायी जाये जिससे बरसात के समय में मार्ग अवरुद्ध न हो और आमजन को राहत मिल सके।

गोविन्द प्रसाद

(मनोहरथाना)

परिशिष्ट 2

मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति (2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं) पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति (2204 - खेलकूद तथा युवा सेवाएं) के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री अमीन खां (शिव):

1. बाड़मेर जिले की माडल स्कूल देतानी में खेलों को बढ़ावा देने हेतु खेल मैदान बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

2. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में बन रहे स्टेडियम के अधूरे काम को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

3. हनुमानगढ़-गंगानगर जिले के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. जिला हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर के ग्रामीण विद्यालयों में खेल मैदान का निर्माण करने, खिलाड़ियों को खेल संबंधी सामग्री उपलब्ध कराने एवं शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

5. अलवर शहर में इन्दिरा गांधी स्टेडियम में सिन्थेटिक ट्रेक बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

6. राजसमंद जिले के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के स्वीकृत पदों के रिक्त रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
7. राजसमंद जिले के विद्यालयों के Sports Ground पर बाउन्ड्री वाल नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

8. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में खेल मैदान बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

9. डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर खेल महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

10. तहसील चूरू में सभी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदान बनवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

11. जिला मुख्यालय पर यूथ हास्टल स्थापित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

12. ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदानों पर हुए अतिक्रमणों को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

13. ग्राम पंचायत स्तर पर ट्रेक व खेल मैदान का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

14. प्रदेश में खेल प्रतिभाओं से संबद्ध एवं संरक्षण हेतु स्पोटर्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना):

15. नागौर जिले में खेलकूद एवं युवा सेवाओं का विस्तार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी):

16. जिला बून्दी के विद्यालयों में इनडोर स्टेडियम के लिए हाल निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. जिला बून्दी के विद्यालयों में तरण ताल का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

18. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में खेल मैदान बनाने के लिए प्रत्येक स्कूल में जमीन आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

19. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के राजकीय विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

20. विधान सभा क्षेत्र दूदू के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लाखन सिंह (करौली):

21. करौली जिले के स्कूलों में खेल मैदान का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

22. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सभी विद्यालयों में खेलकूल मैदान बनाने तथा युवाओं को खेल हेतु प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना):

23. नीमकाथाना के गजानन्द मोदी उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेल स्टेडियम के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

24. सांगोद में महाराज भीम सिंह स्टेडियम में तरण ताल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

25. विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा ऐच्छिक विषय के रूप में लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

26. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के रघुनाथपुरा एवं बुहाना में स्टेडियम नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

27. प्रदेश में सभी खेलों के खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर दिये जाने वाले भत्ते को बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा):

28. ग्रामीण क्षेत्र में खेल प्रतिभा हेतु कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

29. विद्यालयों में खेल मैदानों पर तम्बाकू उत्पाद रखने पर पाबन्दी लगाकर दण्डित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. विद्यालयों में सूर्य नमस्कार, व्यायाम प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

31. जिला मुख्यालय कोटा पंचायत समिति मुख्यालय इटावा में आउटडोर एवं इनडोर खेल मैदान निर्माण में बरती जा रही उपेक्षा के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

32. खेल विद्यालयों में रिक्त पदों पर पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबुलाल (झाडोल) :

33. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के विद्यालय में खेल मैदान के निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में खेल छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू):

35. पिण्डवाड़ा तहसील में खेल मैदान नहीं होने एवं उनको जमीन आबंटित नहीं करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संदीप कुमार (तिजारा):

36. तिजारा और भिवाड़ी में खेल स्टेडियम खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री वाजिब अली (नगर):

37. विधान सभा क्षेत्र नगर में खेल स्टेडियम खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा):

38. प्रत्येक पंचायत पर खेल मैदान बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश हुड़ला (महुवा):

39. विधान सभा क्षेत्र महुवा में खेल स्टेडियम का निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगसी राम (रेवदर):

40. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के उप खण्ड मुख्यालय पर खेलकूद हेतु स्टेडियम का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

41. प्रतापगढ़ टीएसपी क्षेत्रों में आदिवासी प्रतिभाओं को विकसित करने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर खेलकूद केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी):

42. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में खेल स्टेडियम का निर्माण, खेल मैदानों के लिये भूमि आबंटन, खेल मैदानों के चारों तरफ चार दीवारी तथा अतिक्रमण हटाने तथा युवाओं के लिए जिम एवं ट्रेक की सुविधा के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

43. जिला चित्तौड़गढ़ में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर खेल मैदान (स्टेडियम) बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. चित्तौड़गढ़ शहर में इनडोर खेल स्टेडियम के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

45. प्रदेश व जिला युवा बोर्डों का गठन कर उन्हें साधन-सुविधाएं दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. पंचायत स्तर पर खेल प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकेश (गंगापुर):

47. गंगापुर शहर में खेल स्टेडियम निर्माण व युवाओं को खेल से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

48. राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रयोजनार्थ खेलकूद उपकरण मुहैया कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. जहाजपुर उप खण्ड एवं कोटड़ी उप खण्ड मुख्यालय पर खेल स्टेडियम का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़-जंक्शन):

50. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़-जंक्शन में खेलों को प्रोत्साहन हेतु रा.उ.प्रा.वि. नाडी जोजावर के खेल मैदान में स्टेडियम व रोशनी की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

51. जैतारण उप खण्ड मुख्यालय पर रा.उ.मा.वि. जैतारण के पीछे की विद्यालय जमीन पर खेल एकेडमी जो कृत्रिम घास (एस्ट्रोटर्फ) का बना हो, की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

52. जैतारण क्षेत्र के सभी राजकीय विद्यालयों में खेल मैदान के आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

53. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के स्कूलों में खेल मैदानों पर हो रहे अतिक्रमण हटाकर चारदीवारी बनाने एवं पूर्व में निर्मित रोजवाडी स्टेडियम की मरम्मत करवाने तथा खेल कूद गतिविधियों को प्रारम्भ करने एवं उनकी देखरेख करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

54. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के सभी राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के खेल मैदानों के चार दीवारी के निर्माण हेतु बजट आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

55. बालकृष्ण बिहाणी स्टेडियम नोहर में इनडोर स्टेडियम के निर्माण, स्टेडियम, पवेलियन दर्शक दीर्घा के निर्माण हेतु व फुटबॉल कोच की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा):

56. राजाखेड़ा में स्टेडियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

57. विधान सभा क्षेत्र आमेर के समस्त राजकीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए खेल मैदान व एथलेटिक्स ट्रेक एवं गतिविधियों की स्थापना एवं संचालन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र आमेर में युवाओं को शारीरिक सौष्ठव के लिए ओपन जिम प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र आमेर के समस्त राजकीय विद्यालयों में खेल मैदान विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र आमेर के युवाओं को सेना में भर्ती की तैयारी हेतु इच्छुक युवाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र आमेर में विद्यालयों में खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए और शारीरिक शिक्षकों के पद स्वीकृत किये जाने तथा खेल सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

62. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के नौजवानों को सेना में भर्ती की तैयारी हेतु इच्छुक विद्यार्थियों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के प्रत्येक गांव में खेल मैदान बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में S.C./S.T. के युवाओं को पृथक से अधिक सुविधाओं की व खेल प्रशिक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में खेल वातावरण बनाने हेतु प्रतिवर्ष एक बड़ा खेल आयोजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के बुद्धमल दूगड़ राजकीय स्टेडियम के विकास हेतु और अधिक अनुदान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

67. प्रदेश के बालकों के शारीरिक विकास हेतु विद्यालयों में खेल मैदान विकसित करने, शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने एवं खेलकूद सामग्री उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

68. विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के विद्यालयों में खेल स्टेडियम के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

69. विधान सभा क्षेत्र आहोर के रा.मा.वि. ओडवाडा में खेल मैदान को विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

70. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में खेलकूद एवं युवा सेवाएं के संबंध में उप खण्ड कार्यालय में पृथक से शाखा खोलने तथा खिलाड़ियों को सम्मानित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में राजकीय सी.उ.मा. विद्यालय के खेल मैदान की बाउंड्रीवाल के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

72. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में खेल स्टेडियम का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं):

73. झुन्झुनूं में खेल विश्वविद्यालय को शीघ्र चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं की विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्टेडियम स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

75. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में खेल स्टेडियम का निर्माण किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

76. प्रदेश में उप खण्ड मुख्यालयों पर स्टेडियम निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना):

77. मनोहरथाना पंचायत समिति स्तर पर नये खेल स्टेडियम का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक (खण्डार):

78. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के विकास एवं चौथ का बरवाड़ा में खेल स्टेडियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

79. डूंगरपुर जिले में प्रतिभावान खिलाड़ी तीरंदाजी व हाकी जैसे खेल खेलने वालों को खेल सामग्री दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी):

80. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के स्कूलों में खेलकूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर):

81. जोधपुर में विभिन्न खेल प्रवृत्तियों के संचालन हेतु प्रशिक्षकों के पद सृजित करने और शाला क्रीड़ा संगम, गौशाला मैदान में गैर सरकारी खेल एसोसिएशनों को लाभ देने की प्रवृत्तियों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. प्रदेश में खेल प्रवृत्तियों के विकास और प्रोत्साहन हेतु खेल एवं युवा मामलात विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाकर क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा):

83. प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में युवाओं के एथेलेटिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

84. युवाओं को प्रोत्साहन कर खेलों से जोड़ने के लिए जनजाति क्षेत्र में प्रत्येक पं.स. गढ़ी, अरथूना, तलवाड़ा में खेलकूद सेन्टर खोलना आवश्यक है, युवाओं को रहने के लिए छात्रावासों का निर्माण आवश्यक है, युवा अपनी प्रतिभा को निखार सके, के संबंध में चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में खेलकूद के मध्यनजर मैदानों का समतलीकरण, चारदीवारी व खेलकूद के आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने तथा प्रा.वि., उ.प्रा.वि., मा.वि., उ.मा.वि. विद्यालयों के मैदानों को सुरक्षित करना एवं प्रत्येक उ.मा.वि. में अखाड़ों का निर्माण आवश्यक है ताकि युवा खेलकूद व अभ्यास कर सके। विभिन्न समाजों द्वारा खेलकूद के आयोजन होते हैं। इसमें उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन कर खेलों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन राम चौधरी (नागौर):

86. विधान सभा क्षेत्र नागौर के जिला मुख्यालय नागौर में सेना में भर्ती की तैयारी हेतु इच्छुक विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा एवं प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र नागौर के राजकीय विद्यालयों में खेल मैदान विकसित करने व खेल सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र नागौर के राजकीय विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

89. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में रा.उ.मा.वि., शेरेरा, लूणकरणसर, शेरपुरा, जैतपुर, सहजरासर, नापासर, कतरियासर, रामसर, डांडूसर, गुस्साईसर, बम्बल, अर्जुनसर स्टेशन, शेखसर, महाजन एवं खिरोरा में खेल मैदान के लिए विशेष बजट आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

90. प्रदेश के सभी खिलाड़ी जो एशियन गेमों व ओलम्पिक में स्वर्ण, कांस्य, सिल्वर पदक जीतते हैं, उनको सरकारी नौकरी दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में खेल स्टेडियम खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

92. प्रदेश के युवाओं को खेलों में अच्छे प्रदर्शन करने के उपरान्त प्रोत्साहन राशि बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

93. युवाओं को खेल में आगे बढ़ने के लिए खासकर वे युवा जो गरीब परिवार से आते हैं उन्हें सरकार अपने बजट से पैसा देकर खिलाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

94. खेलों में राजस्थान को अन्य प्रदेशों की तरह आगे बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज या विशेष कोष बनाकर खेल के क्षेत्र में राजस्थान को आगे बढ़ाने की स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली):

95. पाली शहर की शहीद भगत सिंह बी.पी.एल. कालोनी मंडिया रोड एवं

गणेश नगर (बांडी नदी के पास) बसी नई बस्तियों में अधिकतर अत्यन्त निर्धन परिवार निवास करते हैं, में खेल सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. पाली जिले के उप खण्ड रोहट के विद्यालयों के चारदीवारी विहीन खेल मैदानों की चारदीवारी का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. पाली शहर स्थित रा.मा.वि. पुनायला का खेल मैदान एवं भवन क्षतिग्रस्त हो गया है, के नये भवन एवं खेल मैदान का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):

98. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में स्टेडियम निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया):

99. संगरिया एवं टिब्बी में खेलकूद के प्रोत्साहन के लिए स्टेडियम निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा):

101. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के विद्यालयों में खेल मैदान विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

102. जामडोली में एक खेल मैदान बनवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

103. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में उप खण्ड पर स्थित राजकीय स्टेडियम विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के राजकीय विद्यालयों में खेलकूद हेतु आवश्यक विस्तार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रूपा राम (मकराना) :

105. विधान सभा क्षेत्र मकराना के रा. सीनियर सैकेण्डरी व माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के रिक्त स्थान के संबंध में चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र मकराना जिला नागौर में युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने हेतु बालिका फुटबाल अकादमी एवं बालकों वास्ते कुश्ती हाकी अकादमी खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमर सिंह (बयाना):

107. विधान सभा क्षेत्र बयाना के उप खण्ड रूपवास में राजकीय खेल महाविद्यालय खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र बयाना के उप खण्ड रूपवास में एक खेल स्टेडियम बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर):

109. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इन्डोर स्टेडियम बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर):

110. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में प्रत्येक गांवों में खेल मैदान बनाकर उसकी सुविधाओं में विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर की सभी स्कूलों में खेल मैदान विकसित करने एवं खेल सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

112. तहसील मुख्यालय नोखा के राजकीय बाबा छोटूनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आउटडोर व इनडोर दोनों तरह के स्टेडियम की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

113. पांचू पंचायत समिति मुख्यालय पर स्टेडियम निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र नोखा में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में खेल मैदान हेतु जमीन आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. विधान सभा क्षेत्र नोखा के काकड़ा गांव में शहीद बजरंगलाल डेलू स्टेडियम में आउटडोर व इनडोर खेलों एवं एथलेटिक्स ट्रेक सहित सम्पूर्ण खेल सुविधाओं को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र नोखा एवं पांचू पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदान अगर खेल मैदान की जमीन नहीं है तो जमीन की व्यवस्था करके खेल स्टेडियम व एथलेटिक्स ट्रेक सहित विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद):

117. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में विद्यालय में खेल मैदान विकसित करने व मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

118. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के रा.उ.प्रा.वि. व रा.उ.प्रा. विद्यालयों में खेलकूद मैदान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के सभी रा.मा. विद्यालय व रा.उ.मा. विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के लिए जिम नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के रावला मण्डी में खेल स्टेडियम व अन्य मा. व रा.उ.मा. विद्यालयों में खेल मैदान/स्टेडियम नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर):

121. ग्राम पंचायत गंगूवाला तहसील रायसिंहनगर के गांव 55 RB (रामावाली) में खेल स्टेडियम बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

122. श्री विजयनगर रा.उ.मा.वि. में खेल स्टेडियम बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर):

123. जालोर के स्टेडियम में खेलों के अतिरिक्त गतिविधियों का बार-बार आयोजन होने से खिलाड़ियों को असुविधा होती है तथा खेल मैदानों का रख-रखाव प्रभावित होने से खेलों के अतिरिक्त गतिविधियों के लिए अन्य मैदान उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

124. जिन खेलों में जालोर जिले के खिलाड़ी विगत अनेक दशकों से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उन खेलों की अकादमियां जालोर में खोलकर विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

125. जालोर में जिला खेल अधिकारी एवं खेल प्रशिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा संतोलिया जैसे पारम्परिक खेलों तथा कूडो जैसे आधुनिक खेलों को मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

127. जिला एवं प्रदेश स्तर पर अधिकांश खेल संघ गिने-चुने लोगों की जेबी संस्थाएं बन चुकी हैं अत: खेल संघों में नियुक्ति की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं प्रजातांत्रिक बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

128. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में खेलों के संसाधन उपलब्ध कराने तथा खेल मैदानों की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

129. प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को निखारने व प्रोत्साहन देने के लिए अजमेर में खेल विश्वविद्यालय को खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को खेल प्रशिक्षण देने के लिए शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. राजकीय विद्यालयों में खेल मैदान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

132. उप खण्ड मुख्यालय जहाजपुर में खेल स्टेडियम निर्माण तथा कोटड़ी उप खण्ड मुख्यालय पर नवीन खेल स्टेडियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

133. सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम का निर्माण हेतु 05 करोड़ रुपये का बजट दिलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

134. राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में पंजीकृत क्लबों, पंजीयन के मानदण्डों तथा लम्बित आवेदनों के संबंध में चर्चा के लिये।

135. पं.स. गोविन्दगढ़ खेल स्टेडियम में सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. प्रदेश में राजस्थान क्रीड़ा परिषद् के अधीन कितने स्पोर्ट क्लब पंजीकृत हैं, इन पंजीयन का आधार क्या है तथा वर्तमान में कितने पंजीकृत बाकी है, के संबंध में चर्चा के लिये।

137. प्रदेश के स्कूलों में खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन मात्र औपचारिकता बनकर रह जाने से इन क्रीड़ा प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त बजट आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. स्कूलों में विद्यार्थियों को खेल-भत्ता नाम मात्र का दिया जाता है, इस भत्ते को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

139. शंखवाली गांव में खेल मैदान विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. रा.उ.मा. विद्यालय हरजी के विद्यालय मैदान को खेल के अनुरूप विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा):

141. भीलवाड़ा शहर के कुश्ती एवं जुड़ो के खेल के विकास हेतु राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

142. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद की सभी 44 पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण DMFT के Fund से करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. राज्य स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता हेतु जाने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाओं को बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

144. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) के राजकीय विद्यालयों में स्टूडेण्ट पुलिस कैडेट योजना संचालित करने में विभागीय उदासीनता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

145. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में प्रत्येक पंचायत स्तर पर खेल मैदान तथा मुख्यालय पर स्पोर्ट्स काम्प्लैक्स की एकेडमी का विकास करने के संबंध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-3

मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवाएं (3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान) पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवाएं (3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान) के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

1. वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बाल पत्रिकाओं का पुन: संचालन एवं चल पुस्तकालय चलाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

2. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में वैज्ञानिक तरीके से जांच कर बोरिंग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

3. विधान सभा क्षेत्र भादरा में वैज्ञानिक तरीके से पानी की जांच कर बोर करवाने पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

4. चूरू जिले में शुष्क खेती हेतु आवश्यक अनुसंधान किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।
5. मरुस्थलीय क्षेत्र में उपलब्ध वनस्पति औषधि हेतु आवश्यक अनुसंधान किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

6. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में खनिजों की खोज हेतु हवाई सर्वे करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. राज्य में जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. राज्य में वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु अधिक बजट आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
9. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में विज्ञान एवं तकनीकी सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
10. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में उद्यमिता विकास अनुसंधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

11. राजीव गांधी ग्रामीण I.T. Hub राजगृह को ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

12. कोटा जिले में पर्यावरणीय शिक्षा एवं जागरूकता के लिए विज्ञान एवं तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम आयोजित करने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

13. कोटा जिले के दूरस्थ इटावा उपखण्ड क्षेत्र में उद्यमिता विकास गतिविधियों के संचालन में उदासीनता पर चर्चा के लिये।

14. प्रदूषण रहित पर्यावरण की दृष्टि से कृषि तकनीकी विकसित कर कृषि को लाभप्रद बनाने के लिए अनुसंधान कार्यों में बरती जा रही उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू):

15. पिण्डवाड़ा तहसील में स्कूलों में विज्ञान एवं तकनीकी को बढ़ावा देने के लिये लैब कक्ष बनवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

16. चित्तौड़गढ़ शहर में विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के लिये आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

17. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में उद्यमिता जागृति के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

19. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में धातुओं की वैज्ञानिक सर्वे करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

20. प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुसंधान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. प्रदेश में अन्य प्रदेशों की भांति विज्ञान, नई खोज एवं अनुसंधान को लेकर प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी):

22. नये वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु शिक्षण संख्याओं में व्यवस्था हेतु चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

23. उद्यमिता जागृति के लिये प्रशिक्षण की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये विशेष अनुसंधान की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में वैज्ञानिक क्षेत्र में नई खोज करने के लिए प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

26. ग्रामीण क्षेत्र में अंधविश्वास को दूर करने के लिए वैज्ञानिक शिक्षा पर चर्चा के लिये।

27. तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये विशेष अनुसंधान पर चर्चा के लिये।

28. अन्य प्रदेश की भांति विज्ञान, नई खोज एवं अनुसंधान को लेकर प्रोत्साहन पर चर्चा के लिये।

29. नोखा क्षेत्र के फ्लोराइड युक्त पानी के गांवों का वैज्ञानिक तकनीकी से सर्वे पर चर्चा के लिये।

30. राज्य की वैज्ञानिक प्रतिभाओं को उच्चतम स्तर पर सम्मानित करने पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

31. सौर ऊर्जा से संबंधित उपकरणों की लागत एवं संधारण खर्च में व्यापक कटौती किये जाने हेतु नवीन अनुसंधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. विद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों तथा ग्रामीण कारीगरों द्वारा किये गये नवीन आविष्कारों/नवाचारों को तुरन्त महत्व देते हुए उनका जनहित में सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिये चर्चा के लिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

33. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की उच्च माध्यमिक विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित नवीनतम पुस्तकें नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

34. अनूपगढ़ तहसील मुख्यालय पर वैज्ञानिक अनुसंधान की कार्यशाला नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

35. घड़साना तहसील के मुख्यालय पर विज्ञान पुस्तकालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।